राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 149

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, गुरुवार, 7 नवंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

'महा' खतरे के बीच जवाबी हमले को तैयार भारत

>> 14

सरोकार

घूंघट से निकल लिख दी 'बिग मिलियन सेल' की पटकथा

अलीगढ़ : स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) में पहली बार देश में एक दिन में 12.50 लाख की बिक्री का रिकॉर्ड बना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का टप्पल ब्लॉक सुर्खियों में है। सरकार ने तीन नवंबर को एसवीईपी का पहला 'बिग मिलियन डे' यहां मनाया। (पेज-10)

जागरण विशेष

कीटाहार को पोषाहार बनाने पर वैज्ञानिक कर रहे काम

अल्मोड़ा : भविष्य में खाद्य संकट की चुनौती से निपटने को कीटाहार के विकल्प की संभावना तलाशने और कीटों का वजूद बचाने की दिशा में भारत में अपने तरह का पहला प्रयास शुरू किया गया है। उत्तर-पूर्व के राज्यों में खाने योग्य कीटों पर शोध शुरू कर दिया गया है। (पेज-10)

गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ से चार दिन में पांच बड़े फैसलों की उम्मीद

माला दीक्षित, नई दिल्ली

अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद, सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं का प्रवेश, राफेल लड़ाकू विमान सौदा, देश के प्रमुख राजनैतिक दल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना और भारत के प्रधान न्यायाधीश के दफ्तर में सूचना का अधिकार लागू होने का मुद्दा पांच ऐसे ज्वलंत मामले हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। ये पांचों ऐसे मामले हैं जिनका बड़ा प्रभाव दिख सकता है। इन मामलों की सुनवाई भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने की है। जस्टिस गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे मे छुट्टियां निकाल दी जाए तो गोगोई के पास इन मामलों में फैसला सुनाने के लिए मात्र चार कार्य दिवस बचे हैं।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को हो रहे हैं सेवानिवृत्त

वैसे तो जस्टिस गोगोई के सेवानिवृत्त होने में अभी कुल 11 दिन बाकी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सूची के मुताबिक गुरुवार को इनमें से किसी भी मामले में फैसला नहीं आ रहा है ऐसे में इन मुकदमों के फैसले के लिए मात्र चार कार्य दिवस बचे हैं। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश कार्य दिवस पर ही मुकदमों की सुनवाई करें या फैसला सुनाएं लेकिन सामान्य तौर पर कोर्ट कार्य दिवस पर ही फैसले सुनाता है।

अयोध्या मामला

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम जन्मभूमि पर मालिकाना हक के मुकदमें में सुनवाई पूरी करके गत 16 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 40 दिन तक मैराथन सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

सीजेआइ के आफिस में आरटीआइ

दूसरा अहम फैसला इस मुद्दे पर आना है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश का दफ्तर सूचना कानून के दायरे में आएगा या नहीं। इस मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि वह किसी भी व्यवस्था को अपारदर्शी बनाए रखने का पक्षधर नहीं है लेकिन एक संतुलन कायम करने और रेखा खींचने की जरूरत है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने सीजेआइ आफिस को आरटीआइ के दायरे में घोषित करने और सूचना देने के दिल्ली हाईकोर्ट और सीआइसी के फैसलों को चुनौती दे रखी है। हाईकोर्ट और सीआइसी ने कहा था कि सीजेआइ का दफ्तर पब्लिक अथारिटी माना जाएगा और आरटीआइ उस पर लागू होगा।

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश

कोर्ट ने 28 सितंबर 2018 को केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर लगी पाबंदी को लिंग आधारित भेदभाव बताते हुए रद कर दिया था। महिलाओं पर यह पाबंदी उनके मासिक धर्म के कारण थी। फैसला 4-1 के बहुमत से था। जस्टिस इंदू मल्होत्रा ने बहुमत से असहमति जताई थी। इस फैसले का अयप्पा अनुयायी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिर के भगवान अयप्पा ब्रम्हचारी हैं और इस आयु की महिलाओं के प्रवेश से मंदिर की प्रकृति बदल जाएगी। फैसले के खिलाफ 55 पुनर्विचार सहित कुल 65 याचिकाएं कोर्ट में हैं।

राहुल को माफी पर आना है फैसला

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के 'चौकीदार चोर है' बयान पर उनके खिलाफ लंबित अवमानना मामले में उन्हें माफी दिये जाने पर फैसला आना है। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी को माफी न देने की अपील करते हुए कोर्ट से कहा था कि माफी काफी नहीं है, राहुल को सजा मिलनी चाहिए। दो बार खेद जताने के बाद बिना शर्त माफी मांग चुके राहुल ने कोर्ट से माफी स्वीकार कर अवमानना का केस बंद किये जाने की गुहार लगाई थी।

राफेल सौदे के फैसले पर पुनर्विचार

चुनाव के वक्त बड़ा मुद्दा बने राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर फैसला आना है। कोर्ट ने 36 राफेल विमानों की खरीद के सौदे की निगरानी में जांच कराने की मांग खारिज कर दी थी, जिसे भाजपा के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर चुनौती दी है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल एंड फाइनेंस एक्ट को चुनौती देने के मामले में भी फैसला आना है।

मोदी की मंत्रियों को नसीहत, अयोध्या पर बयानबाजी से बचें

नई दिल्ली, प्रेट्र : अयोध्या राम जन्मभूमि मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से इस मुद्दे पर बेवजह बयानबाजी से बचने और देश में सौहार्द बनाये रखने की अपील की है। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले में फैसले की उम्मीद है और इसलिए देश में सौहार्द बनाए रखने और इस मुद्दे पर बयानबाजी से बचने की हर किसी की जिम्मेदारी है।

अब अफसरों को दंडित करने का वक्त

सख्त रुख ▶ सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मामले में दिल्ली, पंजाब व हरियाणा के मुख्य सचिवों को लगाई फटकार

शीर्ष अदालत ने कहा, शर्म आनी चाहिए, आपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा करोड़ों लोगों के जीने-मरने का सवाल है। शर्म आनी चाहिए... लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। प्रदूषण की स्थिति पर बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की। कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को फटकारते हुए कहा, अफसरों को अब दंडित करने का वक्त आ गया है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता की पीठ ने पराली जलने के मामले नहीं थमने पर अफसरों को फटकारने के साथ ही किसानों के लिए राहत के भी निर्देश दिए। कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और उप्र से अपने ऐसे सभी लघु व सीमांत किसानों को सात दिन के भीतर प्रति क्विंटल सौ रुपये देने के निर्देश दिए, जिन्होंने पराली नहीं जलाई है। पीठ ने कहा, पराली जलाने पर सजा देना पर्याप्त नहीं है। किसानों को मदद और विकल्प देने की जरूरत है। सरकारें पराली की समस्या से निपटने के लिए मशीनें किराए पर लेकर किसानों को मुहैया कराएं। दिल्ली और तीनों राज्यों को तीन माह के भीतर प्रदूषण से निपटने के लिए समग्र योजना तैयार करने का निर्देश भी दिया। कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में जानलेवा प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को तलब किया था।

जिन किसानों ने पराली नहीं जलाई है, उन्हें प्रति क्विंटल सौ रुपये देने का दिया निर्देश

कुछ कर नहीं सकते तो सत्ता में रहने का अधिकार नहीं

सरकारों के शिथिल रवैये पर कोर्ट ने कहा, 'आप इसके लिए तैयार क्यों नहीं थे? आपने इसे रोकने के लिए क्या किया? अगर राज्य सरकारें कुछ कर नहीं सकती हैं, तो फिर उन्हें जाने दो। अगर आपको लोगों की चिंता नहीं है, तो सत्ता में बने रहने का अधिकार भी नहीं है।' प्रदूषण के कारण लोगों को कैंसर, अस्थमा और कई बीमारियां हो रही हैं। राज्य सरकारें कल्याणकारी सरकार का सिद्धांत भूल गई हैं। दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें लाचार लोगों की परवाह नहीं है। कोर्ट ने कहा, 'आप बस इमारतों में बैठकर शासन करना चाहते हैं। क्या आप प्रदूषण के कारण लोगों को मरने के लिए छोड़ सकते हैं? क्या आप देश को 100 साल पीछे ले जाना चाहते हैं?'

सात दिन में नहीं सुधरे हालात, तो आपके टॉप बास को बुला लेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव से कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के लिहाज के 13 हॉट स्पॉट चुने गए हैं। सात दिन में यदि इनके प्रदूषण के स्तर में कमी नहीं आई, तो आपके टॉप बॉस को बुला लेंगे। कोर्ट के इस रुख से अधिकारियों में सन्नाटा छा गया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को तीन महीने के भीतर सड़कों के सारे गड्ढे भरने के निर्देश भी दिए। अदालत ने मुख्य सचिव से कहा, 'आप सड़क की धूल, तोड़-फोड़ और कचरे से निपट नहीं सकते, तो कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? दिल्ली की कॉलोनियों में गए हैं? वहां रोड तक नहीं है।' दिल्ली सरकार पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा, 'राज्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर और विकास के लिए विश्व बैंक से मिलने वाले अनुदान का सरकार करती क्या है? इतना पैसा आता है, आखिरी स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट कहां है?' राज्य के मुख्य सचिव ने कोर्ट को भरोसा दिया कि सात दिन में प्रदूषण कम करेंगे।

पंजाब के मुख्य सचिव से कहा-अभी यहीं निलंबित कर देंगे

कोर्ट ने निर्देश के बाद भी पराली जलाने की घटनाएं नहीं रुकने के बारे में सवाल किया तो पंजाब के मुख्य सचिव ने कहा कि इसके लिए कोई मैजिक नहीं है। वह किसानों को जागरूक कर रहे हैं। उन्हें मशीनें दे रहे हैं। इस जवाब पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा, 'राजनीतिक भाषण मत दीजिए। आप राज्य के सबसे बड़े अधिकारी हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। यह आपकी विफलता है कि आप अपनी मशीनरी को संभाल नहीं पा रहे हैं। अभी तुरंत यहीं पर निलंबित कर देंगे।'

केंद्र के तर्कों से कोर्ट असहमत

कोर्ट ने अटार्नी जनरल वेणुगोपाल के तर्कों से भी असहमति जताई और कहा, लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार कैसे कह सकती है कि कुछ नहीं किया जा सकता है। पराली को जलाना ही एक मात्र समाधान क्यों है? वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा था कि किसान पराली जलाने से रोकने के खिलाफ हैं। वे कहते हैं कि उनके पास दूसरा विकल्प नहीं है। कोर्ट ने कहा, किसी देश में पराली जलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आप चाहते हैं कि किसानों को दंडित किया जाए।

हरियाणा और उत्तर प्रदेश को भी सख्त चेतावनी

कोर्ट ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश को भी सख्त चेतावनी दी और कहा कि पराली बिल्कुल भी नहीं जलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने बताया कि उनके यहां पंजाब और हरियाणा के मुकाबले सिर्फ एक फीसद ही पराली जलती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस तरह की तुलना नहीं कर सकते हैं। वहीं हरियाणा को भी सख्ती से इस प्रथा को बंद करने के निर्देश दिए।

तीस हजारी मामले में हाई कोर्ट अपने आदेश पर कायम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस का आवेदन ठुकराया
- दो नवंबर को हुई घटना की जांच तक वकीलों पर नहीं होगी कार्रवाई

दिल्ली की तीस हजारी अदालत में पुलिसकर्मियों और वकीलों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में हाई कोर्ट अपने फैसले पर कायम है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की पीठ ने कहा, 3 नवंबर का आदेश स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। उसमें साफ कहा गया था कि 2 नवंबर को हुई घटना के संबंध में दर्ज एफआइआर के आधार पर वकीलों के खिलाफ जांच पूरी होने तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर आचार्य ने मंगलवार को अर्जी दायर कर 3 नवंबर के आदेश को स्पष्ट करने की मांग की थी ताकि 4 नवंबर को साकेत कोर्ट के बाहर पुलिसकर्मी और एक नागरिक की पिटाई के मामले में आरोपित वकील पर कार्रवाई की जा सके। दूसरा आवेदन बुधवार को दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया, जिसमें विशेष आयुक्त (कानून-व्यवस्था, उत्तरी) संजय सिंह और अतिरिक्त उपायुक्त (उत्तरी) हरेंद्र कुमार सिंह के तबादले के फैसले समेत अन्य निर्देशों में संशोधन की मांग की गई। पीठ ने कहा, लाठीचार्ज व फायरिंग का आदेश देने के आरोप में वरिष्ठ अफसरों के तबादले के संबंध में दिया गया आदेश प्राथमिक है। हालांकि, दोनों तथ्यों को घटना के सुबूतों के आधार पर जांच में साबित करना होगा और यह न्यायिक जांच का हिस्सा है।

वहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा, किसी एक व्यक्ति ने पुलिस का थप्पड़ मारा और हमें यह भी नहीं पता कि वह वकील था भी या नहीं। वकीलों पर गोली चलाने वाले पीड़ित बनकर प्रदर्शन व अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। पुलिस को यह हक नहीं दिया जाना चाहिए वह किसी वकील पर केस कर सके।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित माथुर ने कहा, जिस तरह से पुलिस ने फैसले में बदलाव के लिए आवेदन दिया है उससे उसकी मंशा जाहिर होती है। जब साकेत कोर्ट के बाहर हुई घटना के मामले में पहले ही एफआइआर दर्ज कर ली गई है तो फिर इस आवेदन का क्या मतलब है। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष केसी मित्तल ने कहा कि मंगलवार को प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों के मामले का संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए।

मीडिया कवरेज पर रोक से इन्कार : सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सुनवाई के दौरान मीडिया कवरेज पर रोक की मांग करते हुए कहा, वकीलों को निशाना बनाया जा रहा है। उनकी छवि खराब हो रही है। कोर्ट ने मीडिया कवरेज पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया।

यह था मामला : 2 नवंबर को तीस हजारी कोर्ट परिसर में पार्किंग विवाद के बाद पुलिस और वकीलों में हिंसक झड़प हुई थी। इस दौरान पुलिस की ओर से चलाई गई गोली लगने से अधिवक्ता घायल हो गया था। स्वतः संज्ञान लेते हुए रविवार को मुख्य पीठ ने जस्टिस एसपी गर्ग के नेतृत्व में न्यायिक जांच का आदेश दिया था। (पेज-2 भी देखें)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 4

महाराष्ट्र में सभी सियासी दल अपने-अपने रुख पर कायम

मुंबई : राकांपा अध्यक्ष शरद पवार महाराष्ट्र में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए शिवसेना के साथ सरकार बनाने को तैयार है। शिवसेना नई शर्तें भाजपा पर लादती जा रही है, लेकिन नई सरकार कब व किसकी बनेगी, इसका निर्णय नहीं हो पा रहा है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 5

राम रहीम की राजदार हनीप्रीत आई सलाखों के बाहर

पंचकूला : राजद्रोह की धाराओं को कोर्ट द्वारा निरस्त किए जाने के बाद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत की कथित दत्तक पुत्री हनीप्रीत की जमानत याचिका जिला जज ने बुधवार को स्वीकार कर ली। हनीप्रीत को एक लाख रुपये के मुचलके पर छोड़ा गया है। शाम को वह जेल से बाहर भी आ गई।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

जेपी इन्फ्रा के लिए बोली नहीं लगा सकेगा जेपी ग्रुप

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड की बोली में शामिल होने की जेपी ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया है। बुधवार को अदालत ने 90 दिन में प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया और कहा कि सिर्फ एनबीसीसी और सुरक्षा रियल्टी से ही संशोधित रिजॉल्यूशन प्लान स्वीकार किए जाएंगे।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

आइएस-खुरासान ने भारत पर की थी हमले की कोशिश

वाशिंगटन : आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) के खुरासान ग्रुप ने पिछले साल भारत में आत्मघाती हमला किया था। हालांकि यह विफल रहा था। अमेरिकी सांसदों को यह जानकारी एक आतंकवाद रोधी अमेरिकी अफसर ने दी है।

दांव पर साख
दूसरा टी-20 | स्थान : राजकोट
भारत vs बांग्लादेश
शाम 7:00 बजे से | स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

चार्जशीट कोर्ट में दाखिल, चिन्मयानंद पर दुष्कर्म के आरोप सही

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर

- ब्लैकमेलिंग में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष के भाई, भाजयुमो के पूर्व जिला महामंत्री, छात्रा व उसके तीन दोस्तों का नाम

स्वामी चिन्मयानंद पर दुष्कर्म के आरोप को सही बताते हुए विशेष जांच दल (एसआइटी) ने बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट में दाखिल दूसरी चार्जशीट में चिन्मयानंद से ब्लैकमेलिंग के आरोप में छह नाम शामिल किए गए हैं। जिनमें डीसीबी चेयरमैन डीपीएस राठौर, भाजयुमो के पूर्व जिला महामंत्री अजीत सिंह, छात्रा, संजय सिंह, विक्रम व सचिन सेंगर शामिल हैं। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री डीपीएस राठौर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर के भाई हैं। दोनों ही चार्जशीट को लेकर कोर्ट में चिन्मयांनद, छात्रा, संजय, विक्रम व सचिन को पेश किया गया। बाकी दोनों आरोपितों को समन के जरिये तलब किया जाएगा।

एसआइटी ने चिन्मयानंद पर दुष्कर्म व उनसे ब्लैकमेलिंग प्रकरण के दो अलग मुकदमों की जांच शुरू की थी। दो माह जांच के बाद दो चार्जशीट तैयार की। बुधवार सुबह साढ़े दस बजे एसआइटी के विवेचक दलवीर सिंह टीम के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमवीर के कोर्ट में पहुंचे और 4700 पेज की केस डायरी व चार्जशीट सौंपी। करीब 11 बजे जेल से पूर्व मंत्री चिन्मयानंद को कोर्ट लाया गया, जहां आरोप बताते हुए चिन्मयानंद से चार्जशीट पर हस्ताक्षर कराए गए। इसके बाद ब्लैकमेलिंग के सभी आरोपितों को पेश किया गया।

डीपी और अजीत को जाएगा समन पेज>>5

अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बनेगा 25 हजार करोड़ का फंड

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सरकार ने देशभर में 1600 के करीब अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए 25 हजार करोड़ के वैकल्पिक निवेश फंड की स्थापना का निर्णय लिया है। इसका मकसद परियोजना प्रमोटरों को कर्ज के जरिये राहत देना है ताकि वे मध्यम वर्ग के हजारों लोगों के अधूरे मकानों को जल्द से जल्द उनके सुपुर्द कर सकें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस वैकल्पिक निवेश कोष (एआइएफ) में सरकार 10 हजार करोड़ रुपये का योगदान करेगी। बाकी का योगदान एसबीआइ और एलआइसी की तरफ से होगा। जब इस कोष में सरकार और पेंशन फंडों की भागीदारी बढ़ेगी तब कोष का आकार बढ़ेगा। सेबी में पंजीकृत फंड के प्रबंधन की जिम्मेदारी एसबीआइ कैप को सौंपी गई है।

रियल एस्टेट को बड़ी राहत

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने लिया फैसला
- 1600 परियोजनाओं के 4.58 लाख मकानों के जल्द निर्माण का रास्ता साफ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को कैबिनेट के फैसले की जानकारी देती हुईं। एएनआइ

सीतारमण के अनुसार इस कोष के जरिये देशभर में अटकी 1,600 आवासीय परियोजनाओं में 4.58 लाख मकानों को पूरा करने के लिए प्रमोटरों को कर्ज दिया जाएगा। इस कदम से देश में रोजगार सृजन की स्थिति सुधरने के साथ-साथ सीमेंट, लोहा, स्टील उद्योग में मांग बढ़ने की आशा है। इस कोष का इस्तेमाल उन परियोजनाओं में भी किया जा सकेगा जिन्हें नॉन-परफार्मिंग असेट्स या एनपीए घोषित किया जा चुका है अथवा जो दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही हैं।

इस कोष का इस्तेमाल रेरा द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। पेशेवर प्रबंधक परियोजनाओं की पहचान कर उनके लिए निवेश की आवश्यकता तय कर करेंगे। कैबिनेट ने कोष के जिस नए ढांचे को मंजूरी दी है उसमें पहले की दो शर्तों को हटा दिया गया है। इसके लिए अलग-अलग आरबीआइ और बैंकों के अलावा बिल्डरों से भी व्यापक चर्चा की गई। हमने सुनिश्चित किया है कि इसका लाभ सभी वास्तविक अटकी परियोजनाओं को मिले। लेकिन दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रहे बहुत बिगड़े मामलों का समाधान एनसीएलटी के जरिये ही होगा।

इससे पहले सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए कई कदम उठा चुकी है। इनके तहत 31 मार्च, 2020 तक 45 लाख रुपये तक के मकान के होम लोन पर डेढ़ लाख रुपये तक के ब्याज डिडक्शन की सुविधा दी गई है। इसके अलावा बैंकों द्वारा रेपो रेट व एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड उत्पाद लांच किए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासीय परियोजनाओं के लिए 1.42 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता मंजूर की जा चुकी है। नेशनल हाउसिंग बैंक 30 हजार करोड़ रुपये की नकदी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को उपलब्ध करा चुका है। जबकि वित्तीय रूप से सक्षम एनबीएफसी की एक लाख करोड़ की परिसंपत्तियों के लिए सरकारी बैंकों को नुकसान की भरपाई के लिए छह माह के लिए एकमुश्त आंशिक कर्ज गारंटी की एक स्कीम भी लांच की गई है। हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर को भी कम कर दिया गया है।

नापाक मंशा

भारत ने कड़ी आपत्ति जताई, वीडियो से आतंकियों की तस्वीरें हटाने को कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, पाकिस्तान का गुप्त एजेंडा आया सामने

करतारपुर पर पाक के वीडियो में भिंडरांवाले समेत तीन आतंकी

नई दिल्ली, एजेंसियां : करतारपुर कॉरिडोर खोलने के पीछे पाकिस्तान की असल मंशा धीरे-धीरे सामने आने लगी है। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से एक गाना जारी किया है। गाने के इस वीडियो में आतंकी जनरैल सिंह भिंडरांवाले समेत तीन खालिस्तानी आतंकियों की तस्वीरें नजर आ रही हैं। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और पाकिस्तान से तत्काल इस वीडियो से आतंकियों की तस्वीरें हटाने को कहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस वीडियो से कॉरिडोर खोलने के पीछे पाकिस्तान का गुप्त एजेंडा सामने आ गया है।

पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से सोमवार को जारी वीडियो में भिंडरांवाले के अलावा मेजर जनरल शाहबेग सिंह और अमरीक सिंह खालसा के पोस्टर भी हैं। ये तीनों आतंकी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे में जून, 1984 में हुए ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार में सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए थे। भिंडरांवाले आतंकी संगठन दमदमी टकसाल का मुखिया था। शाहबेग सिंह भ्रष्टाचार के मामले में कोर्टमार्शल के बाद खालिस्तानी आतंकी अभियान में शामिल हो गया था। अमरीक सिंह खालसा आल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन का नेता था।

कैप्टन अमरिंदर सिंह फाइल फोटो

चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि इस कॉरिडोर को खोलने के पीछे पाकिस्तान का गुप्त एजेंडा है। उन्होंने पहले भी आशंका जताई थी कि पाकिस्तान इसके जरिए पंजाब में सिख आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा भारतीय खुफिया एजेंसियों ने भी इस तरह की आशंकाएं जताई हैं।

पाकिस्तान की तरफ से जारी एक अन्य वीडियो में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी भिंडरांवाले के बैनर के साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो में अमेरिका के एक अनाम खालिस्तानी ग्रुप 'सिख फॉर जस्टिस' का पोस्टर भी नजर आ रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ की सह पर यह ग्रुप कथित रूप से अलगाववादी मूवमेंट 'रेफरेंडम 2020' को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले पाकिस्तान ने खालिस्तान समर्थक गोपाल सिंह चावला को कॉरिडोर के लिए गठित बोर्ड में रखा था। भारत के विरोध के बाद उसे हटाया।

पासपोर्ट पर पाक से भारत ने मांगा जवाब

भारत ने पाकिस्तान से यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि करतारपुर जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होगी या नहीं। सरकारी सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। दरअसल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दो दिन पहले ट्वीट कर कहा था कि पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन दोनों देशों के बीच हुए समझौते के मुताबिक श्रद्धालुओं को पासपोर्ट ले जाना पड़ेगा।

इस बीच, पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के धार्मिक स्थलों के प्रबंधन का काम देखने वाले इवेकू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने कहा है कि धार्मिक यात्रा आने वाले श्रद्धालुओं के किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने पर सख्त पाबंदी है। अगर कोई ऐसा करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

कॉरिडोर के रास्ते पहले जत्थे को मंजूरी की जरूरत नहीं : करतारपुर कॉरिडोर के नौ नवंबर को उद्घाटन के बाद भारत से 550 श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना होगा। सूत्रों ने बताया कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान जाने वाले इस जत्थे में शामिल श्रद्धालुओं के लिए राजनीतिक मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल हैं। इमरान खान के निमंत्रण पर वाघा बार्डर के रास्ते पाकिस्तान जा रहे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को मंजूरी लेनी पड़ेगी। उन्होंने सरकार से मंजूरी मांगी भी है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सरकार ने पाकिस्तान से पहले जत्थे के लिए सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम करने को कहा है। (पेज-6, 7 देखें)

घोटाले में घिरे आइएएस अफसरों पर हाथ डालने से बच रही सरकार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- पीएफ घोटाले में आइएएस संजय अग्रवाल पर कार्रवाई न होने से उठ रहे सवाल
- खनन घोटाले में आइएएस अभय और डीएस उपाध्याय सिर्फ पद से हटाए गए

भविष्य निधि (पीएफ) घोटाले में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के वरिष्ठ अधिकारी संजय अग्रवाल का नाम आने के बाद यह सवाल उठने लगा है कि आखिर एक ही मामले में तीन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन अग्रवाल के नाम पर चुप्पी क्यों है। दरअसल, सरकार वित्तीय घोटालों और भ्रष्टाचार में दूसरे संवर्ग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन आइएएस अधिकरियों पर हाथ डालने से बच रही है।

खनन घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) की छापेमारी में आइएएस अफसर अभय और डीएस उपाध्याय के घर से जांच एजेंसी ने बड़ी रकम बरामद की थी। इसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। छापेमारी के समय अभय बुलंदशहर के जिलाधिकारी (डीएम) और उपाध्याय आजमगढ़ के सीडीओ (मुख्य विकास अधिकारी) थे। इन अफसरों को सरकार ने कोई तैनाती भले ही नहीं दी, लेकिन इन पर कार्रवाई न होने से हैरत हो रही है। अभय ने यह दावा भी कर दिया कि उनके घर से बरामद एक-एक पैसे का उनके पास हिसाब है।

केंद्र में तैनात आइएएस अफसर जीवेश नंदन और प्रदेश में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रहे संतोष कुमार राय, विवेक और पवन कुमार को हटाकर प्रतीक्षारत कर दिया गया, लेकिन इन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। राज्य के दूसरे संवर्ग के अधिकारी नाम न छापने की शर्त पर कहते भी हैं कि एक ही तरह की शिकायत और जांच में आइएएस अधिकारियों को सरकार से

709 चालान काटे गए हैं ऑड-इवेन के तीसरे दिन बुधवार को। योजना का उल्लंघन करने पर दूसरे दिन 562 और पहले दिन 271 चालान काटे गए थे।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 7 नवंबर 2019

हिंडन एयरपोर्ट से वाया हुबली जाइए बेंगलुरु

सौरभ पांडेय, साहिबाबाद (गाजियाबाद) : दिल्ली-एनसीआर के दूसरे एयरपोर्ट हिंडन से बुधवार को कर्नाटक के हुबली और बेंगलुरु के लिए भी यात्री विमान सेवा की शुरुआत हो गई। 50 सीटर विमान से यात्रियों ने हुबली और बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी। एयरपोर्ट अथॉरिटी और स्टार एयर के अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर विमान को रवाना किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही हिंडन से देश के कई अन्य शहरों के लिए भी फ्लाइट सेवा शुरू की जाएगी।

आठ मार्च को प्रधानमंत्री ने हिंडन एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। 11 अक्टूबर को यहां से पहला विमान पिथौरागढ़ के लिए उड़ा था। अब बुधवार को हिंडन से दूसरी फ्लाइट हुबली-बेंगलुरु के लिए शुरू की गई है। बेंगलुरु से वाया हुबली यात्री शाम चार बजे हिंडन पहुंचे। इसके बाद करीब 4:10 बजे फ्लाइट को वापस वाया हुबली, बेंगलुरु जाना था, लेकिन यह करीब आधा घंटा देर से उड़ान भर सका। एयरपोर्ट अथॉरिटी के नॉर्दर्न इंडिया के महाप्रबंधक मनोज बेहरा ने बताया कि एक माह के अंदर हिंडन से दो स्थानों के लिए विमान सेवा शुरू हो चुकी है।

न्यूज गैलरी

सीबीएसई की प्रायोगिक परीक्षाएं एक से सात फरवरी तक

नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने प्रायोगिक परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा और 10वीं का प्रोजेक्ट व इंटरनल असेसमेंट एक से सात फरवरी तक चलेगा। इस संबंध में एक एप भी बना है, जिसे सभी स्कूलों को डाउनलोड करना है। बोर्ड की तरफ से हर केंद्रों पर प्रायोगिक परीक्षा के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे। परीक्षा की जानकारी स्कूलों को देनी होगी। स्कूल की डेट शीट के अनुसार बोर्ड हर केंद्र पर ऑब्जर्वर और बाहरी परीक्षक नियुक्त करेगा। स्किल विषयों और वोकेशनल कोर्स की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी। असेसमेंट के बाद अंकों को भी जल्द अपलोड करना होगा। इस बार प्रायोगिक परीक्षा की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, ताकि उसमें होने वाले गड़बड़ियां रोकी जा सकें। बोर्ड को अब परीक्षा की जगह, तिथि, छात्रों की संख्या सब कुछ सेटेलाइट से पता चल जाएगा। स्कूलों को प्रायोगिक परीक्षा की तस्वीर, बैच, समय और छात्रों की संख्या बोर्ड के एप पर अपलोड करना होगा। तस्वीर में सभी छात्र, परीक्षक व आब्जर्वर शामिल होंगे। यह तस्वीर प्रायोगिक लैब में ही लेने के आदेश दिए गए हैं। (जासं)

पीएम की आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने पर गिरफ्तार

नोएडा : प्रधानमंत्री के संबंध में आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में कोतवाली फेज-दो पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपित राजा कबाड़ी उर्फ जावेद मूलरूप से पश्चिम बंगाल के हावड़ा का रहने वाला है। वह यहां याकूबपुर गांव में रहता है। पुलिस ने आरोपित के पास से मोबाइल बरामद किया है। इसके जरिये उसने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की थी। मालूम हो कि पिछले दिनों याकूबपुर गांव निवासी एक व्यक्ति ने फेज-दो कोतवाली पुलिस से शिकायत की थी कि एक कबाड़ी ने वॉट्सएप व फेसबुक पर प्रधानमंत्री की आपत्तिजनक फोटो पोस्ट की है। पुलिस ने आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने वाले व्यक्ति को आइटी एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है। (जासं)

रतन टाटा को आज मिलेगी डॉक्टरेट की डिग्री

नोएडा : सेक्टर-125 स्थित एमिटी विश्वविद्यालय में आज 15वां दीक्षा समारोह का आयोजन होने जा रहा है। इसमें जाने-माने उद्योगपति रतन टाटा डॉक्टरेट की डिग्री लेने आएंगे। एक और बड़ी शख्सियत जीएमआर ग्रुप के अध्यक्ष जीएम राव भी डॉक्टरेट की डिग्री लेने नोएडा पहुंचेंगे। तीन दिवसीय समारोह में पहले दिन रतन टाटा समेत अन्य कई उद्योगपति शामिल होंगे। नौ नवंबर तक चलने वाले समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा के 15 हजार छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। एमिटी विवि की उपाध्यक्ष सविता मेहता ने बताया कि गुरुवा को 6947 छात्रों को डिग्री प्रदान की जानी है। डिस्टेंस और ऑनलाइन कार्यक्रम के साथ अन्य पाठ्यक्रम में प्रबंधन कार्यक्रम करने वाले छात्रों को डिग्री दी जाएगी। (जासं)

तीस हजारी मामला ▶ आक्रोशित अधिवक्ताओं ने जिला अदालतों में किया प्रदर्शन

वकीलों ने कोर्ट परिसर के गेट किए बंद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

राजधानी में मंगलवार को पुलिसकर्मियों के प्रदर्शन के बाद बुधवार को वकीलों ने जिला अदालतों में प्रदर्शन किया। हड़ताल जारी रखते हुए वकीलों ने कोर्ट परिसर में प्रवेश के गेट बंद कर दिए। इससे विभिन्न मामलों की सुनवाई और पेशी पर आने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई। लोगों ने गेट खुलने का घंटों इंतजार किया, लेकिन आखिर में मायूस होकर घर लौटना पड़ा। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग शामिल थे, जो दिल्ली के बाहर से आए हुए थे। हालांकि उन्हें अगली तारीख मिल गई है।

पटियाला हाउस और साकेत कोर्ट परिसर के सभी गेटों पर वकीलों ने ताले जड़ दिए थे। जिस कारण कोर्ट में विभिन्न कार्यों से आने वाले लोगों को अंदर जाने का मौका तक नहीं मिला। तीस हजारी कोर्ट के गेट खुले रहे, लेकिन वकील हड़ताल पर रहे। जिन लोगों के मामलों की सुनवाई थी, उन्हें जाने दिया गया, लेकिन हड़ताल की जानकारी होने के चलते भीड़ सामान्य दिनों की अपेक्षा कम रही। राउज एवेन्यू कोर्ट में काम नहीं हुआ, लेकिन यहां आम जन नहीं आएं, क्योंकि यहां सामान्य मामलों की सुनवाई होने के बजाय विशेष मामलों की सुनवाई होती है।

द्वारका और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लोगों की आवाजाही बेहद कम रही। वकीलों के हड़ताल पर होने के कारण जिन लोगों को तारीख मिली थी, उन्हें अब अगली तारीख दी गई। इनमें से अधिकतर ऐसे लोग थे जो दिल्ली के बाहर के थे। उन्हें दिल्ली में वकीलों की हड़ताल के बारे में पता नहीं था। ये लोग कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराने के बाद वापस चले गए। लोगों का कहना था कि यदि उन्हें हड़ताल के बारे में जानकारी होती तो वे तारीख पर आने से पहले ही अपने वकील से बात कर वस्तुस्थिति की जानकारी ले लेते।

कड़कड़डूमा कोर्ट में वकीलों की हड़ताल बुधवार को भी जारी रही। न्यायाधीशों ने कोर्ट में पहुंचकर काम किया, लेकिन कोई भी वकील कोर्ट रूम में नहीं गया। बहुत ही कम संख्या में वे लोग पहुंचे, जिनके केस कोर्ट में चल रहे हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई किए बिना ही उन्हें केस की अगली तारीख दे दी।

तीस हजारी कोर्ट परिसर में दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते वकील। जागरण

अदालतों व पुलिस मुख्यालय के बाहर बढ़ाई सुरक्षा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

तीस हजारी व साकेत कोर्ट परिसर के बाहर मारपीट की घटना के बाद दिल्ली पुलिस व वकीलों के बीच टकराव की स्थिति अब भी बनी हुई है। इसका बुरा असर अदालतों पर पड़ रहा है। अदालतों में हड़ताल के कारण किसी भी केस की सुनवाई नहीं हो पा रही है। कामकाज ठप है। सभी अदालत परिसर के अंदर से पुलिस की सुरक्षा हटा ली गई है। केवल अदालतों के बाहर पुलिस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुराने व नए दोनों पुलिस मुख्यालयों के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

आइटीओ स्थित पुराने मुख्यालय के बाहर बुधवार सुबह पैरा मिलिट्री की तैनाती कर दी गई थी, जिसे कुछ घंटे बाद हटाकर दोबारा से दिल्ली पुलिस की तैनाती की गई। मंगलवार को हजारों पुलिसकर्मियों ने मुख्यालय के बाहर पहुंच कर न्याय के लिए प्रदर्शन किया था। वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। वे बिना अनुमित के मुख्यालय पहुंच गए थे और धीरे-धीरे धरना प्रदर्शन ने विशाल रूप ले लिया था। इसलिए बुधवार को एहतियात के तौर पर मुख्यालय के बाहर सुरक्षा कड़ी रही। वर्दी के अलावा सिविल ड्रेस में भी महिला व पुरुष कर्मियों की तैनाती की गई। नए मुख्यालय के अंदर व बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई।

तीस हजारी व साकेत कोर्ट परिसर के बाहर हुई घटना में अब तक आठ एफआइआर दर्ज हो चुकी हैं। छह मुकदमे तीस हजारी मामले को लेकर सब्जी मंडी थाने में दर्ज किए गए। उक्त सभी मामलों की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। क्राइम ब्रांच में जांच के लिए विशेष आयुक्त अपराध शाखा सतीश गोलचा व डीसीपी ज्वॉय टिर्की के नेतृत्व में एसआइटी बना दी गई है। एसआइटी कई बार तीस हजारी कोर्ट परिसर का मुआयना कर चुकी है। वहां से सीसीटीवी कैमरे के फुटेज इकट्ठा किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि कोर्ट में करीब 300 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कई कैमरों में घटना की तस्वीरें कैद हो गई हैं। एसआइटी एक-एक कर फुटेज जमा कर रही है। इसके बाद जांच आगे बढ़ेगी।

उधर, साकेत कोर्ट परिसर के बाहर पुलिसकर्मी व ऑटो चालक की शिकायत पर दर्ज दो एफआइआर की जांच स्थानीय साकेत थाना पुलिस ही करेगी। उक्त दोनों मामले अभी क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर नहीं किए गए हैं।

पुलिस-अधिवक्ता एक ही सिक्के के दो पहलू, बैठकर सुलझाएं मसला : हाई कोर्ट

▶ दिया सुझाव, अधिवक्ता और पुलिस की तरफ से जिम्मेदार लोग संयुक्त बैठक करें और विवाद को बातचीत व सकारात्मक नजरिये से हल करने की कोशिश करें

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली : तीस हजारी मामले पर हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि पुलिस और अधिवक्ता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए आपस में बैठ कर मसले को सुलझा लें। लोकतांत्रिक व्यवस्था में दिल्ली पुलिस और बार एसोसिएशन कानून की रक्षा करने वाले और समाज को उपद्रवियों से बचाने वाले हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि वे आपस में सामंजस्य बनाकर काम करें।

मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की मुख्य पीठ ने कहा कि पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच किसी भी प्रकार का मतभेद या टकराव शांति और सौहार्द के लिए हानिकारक है। यह आम नागरिकों के भी हित में नहीं है। इसलिए पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत का यही सुझाव है कि अधिवक्ता और पुलिस की तरफ से जिम्मेदार लोग संयुक्त बैठक करें और दोनों के बीच पैदा हुए विवाद को बातचीत और सकारात्मक नजरिये से हल करने की कोशिश करें। पीठ का मानना है कि बीते कुछ दिनों से चल रहा विवाद पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच वार्तालाप में कमी के कारण है।

पीठ को यह उम्मीद है कि अगर ईमानदारी से कदम उठाया जाए तो शांति और सौहार्द दोबारा से कायम हो सकता है। इस बीच पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि पूरे मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से होगी और घटना से जुड़े सुबूतों के आधार पर इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि तीन नवंबर को उनके द्वारा दिया गया आदेश प्राथमिक है। इसलिए जांच के दौरान सामने आने वाले सुबूतों के आधार पर दोनों पक्षों को आरोप साबित करने होंगे।

'पुलिस का धरना इतिहास में काला दिन, एक सप्ताह में हो गिरफ्तारी'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) ने बुधवार को जारी एक पत्र में कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया विरोध राजनीति से प्रेरित लगता है। आरोपितों को एक सप्ताह के भीतर गिरफ्तार किया जाए। मंगलवार का दिन इतिहास का काला दिन रहा।

बीसीआइ के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि पहले बार एसोसिएशन ऑफ दिल्ली ने हड़ताल खत्म करने के लिए कहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस के आचरण को देखने के बाद इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ सकते। पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य से पीछे हटे, नारे लगाए और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। बीसीआइ ने पत्र में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की मांग कहते हुए कहा कि समिति यह पता लगाए कि मंगलवार को पुलिस के अवैध विरोध प्रदर्शन में कौन लोग शामिल थे? दिल्ली पुलिस का विरोध प्रदर्शन सुनियोजित था। पत्र में यह भी कहा गया है कि पुलिसकर्मी मांग कर रहे थे कि वे न्यायाधीशों की सुरक्षा से हटेंगे और यहां तक कि न्यायिक अधिकारियों की भी सुरक्षा नहीं करेंगे। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए वास्तव में यह परेशान करने वाली सोच है। पत्र में यह भी कहा गया है कि हमारे देश में पुलिस या सशस्त्र बलों के किसी भी तरह की यूनियन बनाने के लिए कानून में कोई अनुमति नहीं है। बीसीआइ ने मांग की है कि जो लोग धरने पर बैठे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिन्होंने न्यायपालिका को चुनौती देते हुए नारेबाजी की, उन्हें बर्खास्त किया जाए।

पुलिस को चाय पिलाकर वकीलों ने रिश्तों में घोली मिठास

शुजाउद्दीन, नई दिल्ली

तीस हजारी कोर्ट में हुए बवाल के बाद दिल्ली पुलिस और वकील आमने- सामने हैं। लेकिन कड़कड़डूमा कोर्ट में अधिवक्ताओं ने पुलिसकर्मियों को चाय पिलाकर न सिर्फ रिश्तों में मिठास घोली, बल्कि एक-दूसरे से हाथ भी मिलाया। अधिवक्ताओं ने कहा कि कोर्ट परिसर के पुलिसकर्मी मेरे अपने हैं और इनसे हमें कोई शिकायत नहीं है। हालांकि तीस हजारी में हुई घटना के विरोध में उनका शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं पुलिसकर्मियों ने भी अधिवक्ताओं को पूरी सुरक्षा देने का आश्वासन दिया।

शाहदरा बार एसोसिएशन के बैनर तले कड़कड़डूमा कोर्ट में वकीलों ने बुधवार को भी हड़ताल जारी रखी। सुबह से लेकर शाम तक कोर्ट परिसर में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। मंगलवार को पुलिस मुख्यालय पर हुए प्रदर्शन के चलते यहां भी स्थितियां तनावपूर्ण होने की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन बार एसोसिएशन के सदस्यों ने कोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से न सिर्फ हाथ मिलाया, बल्कि चाय भी पिलाई और उनका हाल चाल जाना। पुलिसकर्मियों ने भी वकीलों से कहा कि वे उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने देंगे। इसके बाद पुलिस और वकीलों ने जमकर ठहाके भी लगे। यह नजारा देखकर एक बार तो ऐसा लगा कि इनके बीच कुछ हुआ ही नहीं है। यही नहीं कड़कड़डूमा कोर्ट की चौकी में कार्यरत करीब सौ पुलिसकर्मियों ने सादी वर्दी में अपनी ड्यूटी निभाई। पुलिसकर्मियों ने कहा कि विरोध अपनी जगह है, लेकिन लोगों की सुरक्षा करना उनका कर्तव्य है। चौकी इंचार्ज गिरीश जैन भी सादी वर्दी में रहे और आम दिनों की तरह परिसर में घूमकर सुरक्षा का जायजा लेते रहे।

> बार एसोसिएशन ने पुलिसकर्मियों व कोर्ट के कर्मचारियों को चाय पिलाई है। तीस हजारी घटना को लेकर कोर्ट में शांतिपूर्ण तरीके से वकील अपना विरोध जता रहे हैं। दोषी पुलिसकर्मियों की जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। कड़कड़डूमा कोर्ट चौकी में तैनात पुलिसकर्मी हमारे अपने हैं। इनसे किसी तरह की शिकायत नहीं है।
>
> **-प्रमोद नागर, अध्यक्ष शाहदरा बार एसोसिएशन**

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए चार कंपनियों ने की बिड

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ऑनलाइन तकनीकी बिड बुधवार को खोली गई। एयरपोर्ट के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट एजी, अडानी समूह, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड व बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बिड की है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड (नियाल) बिड करने वाली कंपनियों के दस्तावेज का अध्ययन करेगी। इसके बाद तकनीकी बिड में सफल कंपनियों के फाइनेंशियल बिड में शामिल होने का फैसला होगा।

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बिड करने वाली कंपनियों ने परियोजना के लिए किसी अन्य कंपनी के साथ कंसोर्टियम नहीं बनाया है। इन कंपनियों ने सौ फीसद हिस्सेदारी के साथ बिड की है। नियाल ने तकनीकी बिड के लिए कंपनियों की ओर से पेश दस्तावेज की जांच की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूसी को सौंपी है। एजेंसी एक सप्ताह में रिपोर्ट नियाल को देगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिड करने वाली कंपनियों ने सभी शर्तों को पूरा किया है या नहीं। इसकी जानकारी प्रदेश की परियोजना निगरानी एवं क्रियान्वयन समिति की 13 नवंबर को होने वाली बैठक में दी जाएगी। कंपनियों को दस्तावेजी कमियों को दूर करने का मौका भी मिल सकता है। बिड की शर्तों को पूरा करने वाली कंपनियों को फाइनेंशियल बिड में शामिल किया जाएगा। एयरपोर्ट के लिए फाइनेंशियल बिड 29 नवंबर को खुलेगी।

नियाल के नोडल अफसर शैलेंद्र भाटिया ने बताया है कि बिड खोलने की प्रक्रिया ग्रेटर नोएडा स्थित नियाल कार्यालय में कंपनियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुई है।

पराली जलाने में फंसे पूर्व सीएम बादल के दामाद

जागरण संवाददाता, डेराबस्सी (मोहाली) : पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री आदेश प्रताप सिंह कैरों भी खेतों में पराली जलाने के मामले में फंस गए हैं। 15 हजार रुपये का चालान काटा गया है और एफआइआर दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

आदेश प्रताप सिंह कैरों पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के दामाद हैं। वह वेब पट्टी विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। जीरकपुर के किशनपुरा में उनका फार्म हाउस और कई एकड़ खेत है। उनके खेत में केयरटेकर द्वारा पराली जलाए जाने की शिकायत आई थी। मालिक होने के कारण कैरों पर कार्रवाई हो रही है। एसडीएम डेराबस्सी पूजा स्याल के अनुसार एयर पॉल्यूशन एक्ट के तहत सबडिवीजन में 44 डिफाल्टर्स के खिलाफ एफआइआर दर्ज की जा रही हैं। इससे पहले तीन बड़े जमींदारों के खिलाफ भी डेराबस्सी में केस दर्ज कर कराया जा चुका है।

ग्रांड वेनिस मॉल के निदेशक को जमानत

▶ सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा स्थित मॉल के निदेशक को दी राहत

▶ 50 करोड़ रुपये रजिस्ट्री में जमा कराने का दिया आदेश

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा स्थित ग्रांड वेनिस मॉल के निदेशक को कुछ दुकानों के आवंटियों की शिकायत से संबंधित मामले में जमानत दे दी। उन्हें 50 करोड़ रुपये रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश दिया गया है। इस मॉल के निदेशक सतिंदर सिंह भसीन को धोखाधड़ी और छल से कई व्यक्तियों को संपत्तियां बेचने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था।

भसीन ने अंतरिम राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। भसीन ने न्यायालय से अनुरोध किया था कि 'ग्रांड वेनिस' परियोजना, विशेषकर मॉल और व्यावसायिक टावर के संबंध में उत्तर प्रदेश और दिल्ली में उसके खिलाफ दर्ज सारी प्राथमिकी की जांच सीबीआइ को सौंप दी जाए। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने भसीन को निर्देश दिया कि वह जमानत की शर्त के तहत 50 करोड़ रुपये न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा कराए। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि हम याचिकाकर्ता को याचिका में शामिल सारे मामलों और इस परियोजना के सिलसिले में गौतमबुद्ध नगर के थाना कासना या उप्र के किसी अन्य थाने में दर्ज होने वाली प्राथमिकी और दिल्ली के संसद मार्ग थाने तथा दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकियों के मामले में सीधे जमानत दे रहे हैं। शीर्ष अदालत ने प्रत्येक प्राथमिकी के मामले में अलग-अलग पांच लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि का जमानती देने का निर्देश भसीन को दिया है। न्यायालय ने नई दिल्ली के संसद मार्ग थाने या आर्थिक अपराध शाखा या पहले से दर्ज किसी अन्य प्राथमिकी या ग्रांड वेनिस परियोजना के संबंध में भविष्य में दर्ज होने वाली प्राथमिकी के मामलों में कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।

सिर्फ नई दिल्ली में दर्ज रिपोर्टों की कार्यवाही पर लगी है रोक : शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वह सिर्फ नई दिल्ली में दर्ज रिपोर्टों की कार्यवाही पर रोक लगा रही है, क्योंकि दिल्ली में दर्ज रिपोर्ट और दोनों स्थानों पर दायर 72 शिकायतों में आरोप एक जैसे हैं। कोर्ट ने सारी प्राथमिकियों की जांच सीबीआइ को सौंपने से इन्कार करते हुए कहा कि इस मामले के तथ्यों के लिए ऐसी राहत की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने इस तथ्य का भी जिक्र किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 37 मामले दर्ज हैं और उसे 11 मामलों में जमानत दी गई है जबकि आठ में अभी भी जांच चल रही है। शीर्ष अदालत ने इस तथ्य का भी जिक्र किया कि शिकायतकर्ता के खिलाफ दिल्ली में पांच प्राथमिकियां दर्ज हैं। इनमें से तीन संसद मार्ग थाने में और दो आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के यहां हैं। इन मामलों में से याचिकाकर्ता को तीन मामलों में संबंधित अदालत जमानत दे चुकी है।

नई दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण के कारण बंद किए गए स्कूल बुधवार को खुल गए। सिविल लाइंस क्षेत्र में छात्र-छात्राएं मास्क लगाए नजर आए। जागरण

प्रदूषण-जाम पर लगाम लगा रहा ऑड-इवेन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

ऑड-इवेन का तीसरा दिन भी सफलतापूर्वक गुजरा है। बुधवार को भी दिल्ली के लोगों को जाम की समस्या से जूझना नहीं पड़ा। योजना को लेकर दिल्ली सचिवालय में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि दिल्ली के लोग सरकार के साथ हैं। उनके समर्थन से ऑड-इवेन सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने बताया कि ऑड-इवेन के दौरान प्रदूषण लगातार नीचे आ रहा है। बुधवार को दोपहर 2 बजे पीएम-2.5 का स्तर 39 रहा और पीएम-10 घटकर 96 रह गया। उन्होंने कहा कि ऑड-इवेन के तीसरे दिन इसका पालन कराने वाली एजेंसियों ने कुछ सख्ती दिखाई। मगर ऑड-इवेन का पालन न करने वालों की संख्या बहुत अधिक नहीं बढ़ी है।

सोमवार और मंगलवार को मिल सकती है छूट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : सिख समुदाय ने गुरुपर्व व नगर कीर्तन के दौरान 11 और 12 नवंबर को ऑड-इवेन से छूट की मांग दिल्ली सरकार से की है। दिल्ली सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस संबंध में बुधवार को सिखों का एक प्रतिनिधिमंडल तिलक नगर से विधायक जरनैल सिंह के साथ परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से मिला। गहलौत ने कहा है कि सरकार इस बारे में सकारात्मक रूप से सोच रही है। जल्द ही वह इसे लेकर मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि जनता को सोमवार और मंगलवार को ऑड-इवेन से छूट मिल सकती है। रविवार को ऑड-इवेन लागू नहीं होता है।

उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों से ये तो पता चल रहा है कि दिल्ली पर जो धुंए का संकट था, वह लगभग खत्म हो चुका है। एक सवाल के जवाब में गहलोत ने कहा कि आने वाले समय में ऑड-इवेन के दौरान बसों में सभी को मुफ्त सफर कराने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस बार समय निकल चुका है। अब अगर फाइल चलेगी तो ऑड-इवेन समाप्त हो जाने पर भी इस बारे में फैसला नहीं हो सकेगा। गहलोत से पूछा गया था कि दसरे देशों में ऑड-इवेन के दौरान सार्वजनिक परिवहन की सरकारी सेवाओं को मुफ्त रखा जाता है। क्या दिल्ली में भी इसे किया जा सकता है? इस पर गहलोत ने कहा कि सुझाव अच्छा है। बसों में सफर करने के लिए यह व्यवस्था लोगों को प्रेरित कर सकती है।

तेज हवा से कम हुआ प्रदूषण, पहुंचा खराब श्रेणी में

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : बुधवार को दिल्ली-एनसीआर वासियों ने करीब दस दिन बाद खुलकर सांस ली। पश्चिमी विक्षोभ से बनी तेज हवा ने पराली के धुएं को हटाकर दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिलाई। हालांकि पराली अब भी जलाई जा रही है, लेकिन तेज हवा के कारण इसका धुआं टिक नहीं पा रहा। वायु प्रदूषण अब खराब स्तर तक आ चुका है। गुरुवार को हवा का दक्षिणी रुख रहेगा, इसलिए वायु प्रदूषण स्तर कम ही रहेगा। शुक्रवार को हवा की दिशा में परिवर्तन होने से इसमें आंशिक वृद्धि हो सकती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी (सीपीसीबी) द्वारा जारी एयर बुलेटिन के अनुसार बुधवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) सिर्फ 216 रहा। एनसीआर के शहर भी अपेक्षाकृत कम प्रदूषित नजर आए। फरीदाबाद का एयर इंडेक्स 205, गाजियाबाद का 294, ग्रेटर नोएडा का 247, गुरुग्राम का 168 और नोएडा का 237 रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार को हवा इससे भी अधिक साफ हो सकती है। हल्की बारिश और तेज हवा की वजह से प्रदूषण स्तर सामान्य स्तर पर पहुंच सकता है। प्रदूषण में आई कमी की वजह इस समय हवा का दिशा बदल लेना, तेज धूप और तेज हवा है, जिसके कारण प्रदूषक तत्वों को हवा में जमने की जगह नहीं मिल रही है।

सफर के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ से दिल्ली की ओर आने वाली तेज हवा के कारण प्रदूषण स्तर में अप्रत्याशित कमी आई है। आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में आज पीएम 10 का स्तर 170 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा जो ठीक श्रेणी है। पीएम 2.5 का स्तर 101 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा जो खराब श्रेणी में है। गुरुवार को और सुधार के साथ पीएम 10 का स्तर 148 और पीएम 2.5 का स्तर 88 पर रहने का अनुमान है। सफर ने बताया कि दिल्ली की ओर बढ़ रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा की दिशा बदल गई। इससे पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से पैदा प्रदूषक कणों को साथ लेकर आने वाली हवा से राजधानीवासियों को मुक्ति मिली।

मिलेगी मदद

वेबसाइट में समेटा गया है 1905 से 2019 तक के वायु प्रदूषण का इतिहास, इसके प्रारंभिक चरण में 1,215 शोध आलेख, 170 रिपोर्ट, 100 केस आदि उपलब्ध हैं

'इंड एयर' पर मिलेगा प्रदूषण से जुड़ा 115 साल का इतिहास

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर सहित देशभर में वायु प्रदूषण की समस्या कब से उत्पन्न हुई, किस तरह बढ़ी, क्यों नहीं इसे शुरू में ही थामने का प्रयास किया गया। इस समस्या पर पूर्व में क्या शोध हुए या इस पर नियंत्रण के क्या एक्शन प्लान बनाए गए? इत्यादि सवालों का जवाब खोजना अब आसान होगा। इसके लिए किसी लाइब्रेरी में जाकर इतिहास की किसी किताब के पन्ने नहीं पलटने होंगे। यह पूरी जानकारी अब बस एक क्लिक पर आपके कंप्यूटर पर मिल जाएगी।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) ने वायु प्रदूषण के एक सदी से अधिक पुराने इतिहास को डिजिटल रूप में समेटा है। 'इंड एयर' नाम से ऐसी वेबसाइट तैयार की गई है, जिससे करीब 115 साल के प्रदूषण के आंकड़े और इतिहास की जानकारी हासिल की जा सकती है।

50 लाख से ज्यादा के बजट और अमेरिकन संस्था एन्वायरमेंट डिफेंस फंड (ईडीएफ) के साथ समझौता कर यह वेबसाइट तैयार की गई है। बुधवार को इसे दिल्ली की भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में लांच किया गया। इसे औपचारिक रूप से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के चेयरमैन एसपी सिंह परिहार और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में संयुक्त सचिव निधि खरे ने लांच किया। इसमें 1905 से 2019 तक के वायु प्रदूषण का इतिहास समेटा गया है। इसके प्रारंभिक चरण में 1,215 शोध आलेख, 170 रिपोर्ट, 100 केस, दो हजार स्टेटस सहित इंटरनेट से पूर्व (1950-1999) के समय की भी सात सौ रिपोर्ट स्कैन करके डाली गई हैं।

तीन श्रेणियों में बांटी गई है वेबसाइट : इंड एयर वेबसाइट को मुख्यतया तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में 1905 तक से उपलब्ध प्रदूषण मापक यंत्रों, नियम कायदों और मानकों की की जानकारी दी गई है। दूसरी श्रेणी में विभिन्न पर्यावरण संस्थाओं, शैक्षिक संस्थानों और विशेषज्ञों के द्वारा किए गए अध्ययन की रिपोर्ट डाली गई हैं। तीसरी श्रेणी में पर्यावरण प्रदूषण पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऐसे अध्ययन है, जो भुगतान करने पर ही मिल पाते हैं।

1960-70 से 10 गुना कम है मौजूदा प्रदूषण : दिल्ली एनसीआर के पिछले कुछ सालों के प्रदूषण पर देश- विदेश में हाय तौबा मची हुई है, लेकिन यह वेबसाइट बताती है कि 1960 और 1970 के प्रदूषण से मौजूदा प्रदूषण 10 गुना तक कम है। इस पर जानकारी दी गई है कि चैंबूर तो आज से 50 साल

13 से 21 नवंबर के बीच आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और काकीनाडा के पास भारत और अमेरिका की सेनाएं करेंगी संयुक्त युद्धाभ्यास।

1200 भारतीयों के साथ 500 अमेरिकी सैनिक हिस्सा लेंगे 'टाइगर ट्रायम्फ' नामक इस युद्धाभ्यास में। दोनों देशों की तीनों सेनाएं इसमें होंगी शामिल।

'प्रगति' की बैठक में उठा वायु प्रदूषण का मुद्दा

दिशा-निर्देश जारी ▸ किसानों के बीच उपकरण वितरण को प्राथमिकता देने पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जोर

इनकी मदद से किसान पराली का कर सकते हैं बेहतर उपयोग, बढ़ेगी आमदनी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लंबित योजनाओं में तेजी लाने के लिए होने वाली 'प्रगति' की बैठक में दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए शुरू की गई योजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पराली जलाने से रोकने और उसका सदुपयोग करने के लिए किसानों के बीच संबंधित उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की योजना पर विस्तृत चर्चा हुई। गौरतलब है कि मंगलवार को भी प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वायु प्रदूषण के ताजा हालात पर चर्चा की थी।

सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच पराली के सदुपयोग के लिए जरूरी उपकरणों का वितरण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। इन तीनों राज्यों में धान कटने के बाद बड़े पैमाने पर अवशेष जलाने की घटनाएं होती हैं। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में वायु प्रदूषण के भयावह स्तर पर पहुंचने में इसे प्रमुख कारण माना जा रहा है।

नरेंद्र मोदी। फाइल फोटो

इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे के निर्माण की भी समीक्षा की और इसे मई 2020 तक पूरा करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने कटरा-बनिहाल रेल लाइन के अगले साल तक पूरा करने के लिए जरूरी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने राज्यों में लंबे समय से लंबित योजनाओं पर नजर रखने और उनकी प्रगति की रिपोर्ट पीएमओ में भेजने को कहा। इसके अलावा ऊर्जा और कृषि क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं की भी समीक्षा की। खासतौर पर उन्होंने राज्यों के बीच कृषि उपज की बेहतर कीमत सुनिश्चित करने लिए बनाए जा रहे राष्ट्रीय कृषि मार्केट प्लेटफार्म को जल्द पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने कृषि मंत्रालय और परिवहन, सड़क व राजमार्ग मंत्रालय को एक राज्य से दूसरे राज्य तक कृषि उपज की सुगम आवाजाही के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया।

जलवायु परिवर्तन मानव जीवन के लिए घातक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- दुनिया भर के वैज्ञानिक संगठनों ने जताई चिंता, सम्मेलन शुरू
- वैश्विक स्तर पर सीमित हो रहे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर

जलवायु परिवर्तन का बढ़ता असर समूचे मानव जाति के लिए घातक होने लगा है। दुनियाभर के वैज्ञानिकों ने सीमित होते प्राकृतिक संसाधनों पर गंभीर चिंता जताई है। राजधानी दिल्ली में शुरू हुए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने मिट्टी व जल संरक्षण पर सबसे ज्यादा जोर देते हुए वैश्विक स्तर पर मिट्टी के क्षरण और जल के अंधाधुंध दोहन पर चिंता जताई।

'वैश्विक खाद्य व आजीविका सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के दौर में मिट्टी व जल स्रोत प्रबंधन' विषय पर आयोजित पांच दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (आइसीएआर) के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र ने कहा 'यह केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है। जलवायु परिवर्तन से बढ़ता तापमान सबसे ज्यादा घातक है, जो मानव जीवन के लिए भी खतरा बन सकता है।'

वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ स्वायल एंड वाटर कंजरवेशन (डब्ल्यूएएसडब्ल्यूएसी) के अध्यक्ष प्रोफेसर ली रुई ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और तापमान के बढ़ने से भूमि के बंजर होने का सबसे अधिक जोखिम है। जमीन के बंजर होने से आर्थिक और इकोलॉजी पर सर्वाधिक विपरीत असर पड़ सकता है। जमीन के बंजर होने की वजह से दुनियाभर में तकरीबन 1.5 बिलियन आबादी प्रभावित हुई है। इन समस्याओं पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं।

स्वायल कंजरवेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसीडेंट डॉक्टर सूरजभान ने कहा कि आजीविका सुरक्षा के लिए कृषि के सतत विकास की जरूरत होगी, जो मिट्टी और जल के संरक्षण से ही संभव होगा। डॉक्टर भान ने कहा कि घरेलू स्तर पर पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर घर नल से पानी पहुंचाने की तैयारी कर ली गई है। भारत में बरसात के जल का संरक्षण करना सबसे उपयुक्त तरीका है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने से हालात गंभीर हो गए हैं, जिससे निपटने के लिए पूरी दुनिया को साझा प्रयास करना होगा। सम्मेलन के आखिरी दिन सिफारिशें प्रस्तुत की जाएंगी, जिसे दुनिया के हर फोरम को भेजा जाएगा।

वैज्ञानिकों ने की वैश्विक जलवायु आपातकाल की घोषणा

नई दिल्ली, प्रेट्र : दुनियाभर के 153 देशों के 11,000 से अधिक वैज्ञानिकों ने वैश्विक जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि उन मानव गतिविधियों में व्यापक और स्थाई बदलाव के बिना बहुत बड़ा नुकसान होना तय है जिनका योगदान ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित अन्य कारकों में होता है। 'बायोसाइंस' नामक पत्रिका में मंगलवार को प्रकाशित एक शोध-पत्र में, भारत से 69 सहित 11,258 हस्ताक्षरकर्ताओं ने जलवायु परिवर्तन के वर्तमान लक्षण को प्रस्तुत किया है और इससे निपटने के लिए उठाए जा सकने वाले प्रभावी कदमों का उल्लेख किया है। जलवायु आपातकाल की घोषणा ऊर्जा उपयोग, पृथ्वी के तापमान, जनसंख्या वृद्धि, भूमि क्षरण, पेड़ों की कटाई, ध्रुवीय बर्फ द्रव्यमान, उत्पादन दर, सकल घरेलू उत्पाद और कार्बन उत्सर्जन सहित एक व्यापक क्षेत्र को कवर करने वाले सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डाटा के 40 से अधिक वर्षों के वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है। अमेरिका के ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी (ओएसयू) के कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री में इकोलॉजी के एक प्रोफेसर विलियम जे रिप्पल ने कहा, '40 साल से चल रही प्रमुख वैश्विक वार्ताओं के बावजूद, हमने हमेशा की तरह व्यापार करना जारी रखा है और इस संकट को दूर करने में असफल रहे हैं।'

सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार से कहा, वजन कम होना बीमारी नहीं

- एम्स को चार सप्ताह में सज्जन कुमार के स्वास्थ्य की जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में उम्रकैद की सजा भुगत रहे पूर्व सांसद नेता सज्जन कुमार से कहा कि वजन कम होने का मतलब बीमार होना नहीं है। शीर्ष कोर्ट ने बुधवार को कहा कि याची के स्वास्थ्य की जांच एम्स के चिकित्सकों का एक दल करेगा। कोर्ट ने सज्जन कुमार द्वारा गिरते स्वास्थ्य के आधार पर जमानत का अनुरोध किए जाने पर यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि एम्स के निदेशक सज्जन कुमार के स्वास्थ का परीक्षण करने के लिए चिकित्सकों का दल गठित करें और वह इस बारे में चार सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दे।

जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सज्जन कुमार की जमानत की अर्जी पर अगले साल ग्रीष्मावकाश के दौरान विचार किया जाएगा। पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'हमारा विचार है कि याची (कुमार) के स्वास्थ्य की जांच एम्स के निदेशक द्वारा गठित चिकित्सकों का एक दल करे। इस बारे में चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश की जाए।'

इससे पहले, सज्जन कुमार की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि पूर्व सांसद पिछले 11 महीने से जेल में हैं और उनका वजन आठ से 10 किलो कम हो गया है। उन्होंने कहा कि सज्जन कुमार कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। इस पर पीठ ने कहा कि वजन कम होने का मतलब यह नहीं है कि वह अस्वस्थ हैं लेकिन फिर भी हम

सज्जन कुमार फाइल फोटो

चिकित्सकों के दल द्वारा उनके स्वास्थ का परीक्षण करने का आदेश देंगे।

जस्टिस बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने पांच अगस्त को कहा था कि सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर मई, 2020 में सुनवाई की जाएगी क्योंकि यह 'साधारण मामला' नहीं है और इसमें कोई भी आदेश देने से पहले विस्तार से सुनवाई की आवश्यकता है।

कांग्रेस के पूर्व नेता कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल 17 दिसंबर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने इस मामले में सज्जन कुमार को बरी करने का निचली अदालत का 2010 का फैसला निरस्त कर दिया था। कुमार ने हाई कोर्ट के इस फैसले को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दे रखी है। पूर्व सांसद ने हाई कोर्ट के आदेश के मद्देनजर कोर्ट में समर्पण करने से पहले कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था।

मंदी व रोजगार संकट पर एक दिसंबर को कांग्रेस की रैली

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- मोदी सरकार की दूसरी पारी में पार्टी के पहले सियासी आंदोलन को लेकर नेतृत्व गंभीर

कांग्रेस सुस्त अर्थव्यवस्था और रोजगार संकट पर सरकार के खिलाफ अपने विरोध आंदोलन की परिणति दिल्ली में एक बड़ी रैली के जरिये करेगी। संसद सत्र के दौरान एक दिसंबर को पार्टी की यह रैली होगी जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत उसके तमाम दिग्गज नेता शिरकत करेंगे।

आर्थिक मंदी के साथ रोजगार संकट के मुद्दे को सियासी गरमी देने के लिए कांग्रेस ने संसद सत्र के दौरान ही रैली करने का फैसला लिया है। संसद का शीत सत्र 18 नवंबर से शुरू हो रहा और यह 13 दिसंबर तक चलेगा। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस को सियासी अखाड़े में फिर से उठ कर खड़े होने की संभावनाएं दिखने लगी हैं। इसीलिए पार्टी अब प्रधानमंत्री पर सीधे हमले की बजाय उन मुद्दों पर सरकार की घेरेबंदी कर रही है जिन पर वह चुनौतियों से जूझ रही है। आर्थिक मंदी, बढ़ती बेरोजगारी और किसानों को एमएसपी नहीं मिल पाने के मुद्दे पर पांच नवंबर से देश भर में शुरू हुआ कांग्रेस का विरोध आंदोलन इसी रणनीति का हिस्सा है। सभी जिलों में 15 नवंबर तक चलने वाले इस विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस सभी प्रदेशों की राजधानी में एक रैली करेगी और

सोनिया गांधी फाइल फोटो

दिल्ली की बड़ी रैली से कांग्रेस का शिखर नेतृत्व सीधे सरकार पर प्रहार करेगा।

पार्टी के इस आंदोलन को राज्यों में कारगर बनाने के लिए सोनिया गांधी ने केंद्रीय स्तर पर इसकी मानीटरिंग कराने का भी फैसला किया है। इसके लिए कांग्रेस ने राज्यों में 21 से ज्यादा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं ताकि आंदोलन की निगरानी और समीक्षा चलती रहे। मोदी सरकार के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद कांग्रेस का यह सरकार के खिलाफ पहला बड़ा राजनीतिक आंदोलन है और पार्टी नेतृत्व के लिए इसको कामयाब बनाना चुनौती है।

कोलेजियम प्रणाली की समीक्षा से सुप्रीम कोर्ट ने किया इन्कार

- पांच जजों की पीठ ने कोर्ट के चैंबर में समीक्षा याचिका खारिज की
- याचिका दायर करने में वर्षों की देरी को बताया आधार

नई दिल्ली, प्रेट्र : वर्ष 1993 के नौ जजों की बेंच के ऐतिहासिक फैसले की समीक्षा से सुप्रीम कोर्ट ने इन्कार कर दिया है जिससे 26 साल पहले जजों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली लागू हुई थी। इससे पहले सरकार सीधे तौर पर जजों की नियुक्ति करती थी।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में तीन जजों की खंडपीठ में जस्टिस एसए बोबडे और एनवी रमन्ना ने कोर्ट के चैंबर में यह फैसला दिया। अदालत ने नेशनल लायर्स कैंपेन फॉर ज्यूडीशियल रिफार्म एंड ट्रांसपिरेंसी (एनएलसीजेआरटी) की समीक्षा याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि इस फैसले की कोई समीक्षा नहीं होगी। खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में याचिका दायर करने में 9071 दिनों (24 साल से अधिक) की देरी हुई है। याचिकाकर्ता ने इस देरी के लिए कोई वाजिब स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है। इसलिए मौजूदा समीक्षा याचिका को देरी से दायर किए जाने के आधार पर खारिज किया जाता है। इसके बावजूद हमने इस मामले में सावधानीपूर्वक समीक्षा याचिका और उसके दस्तावेजों पर गौर किया है। उल्लेखनीय है कि विगत 16 अक्टूबर को समीक्षा याचिका खारिज की गई थी। लेकिन

रंजन गोगोई फाइल फोटो

कोलेजियम मामले में समीक्षा याचिका खारिज करने के फैसले को बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

एनएलसीजेआरटी के अध्यक्ष और वकील मैथ्यूज जे. नेदुम्पारा अपनी याचिका के पक्ष में कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए वर्ष 1993 से पहले की व्यवस्था लागू कर दी जाए। इस व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्त और तबादले केंद्र सरकार करती थी।

संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के तहत राष्ट्रपति को सीजेआइ के परामर्श से जजों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार मिलता है। 1993 में नौ जजों की पीठ ने अपने फैसले में 'परामर्श' को देश के मुख्य न्यायाधीश की अनिवार्य सहमति करार दिया था। जबकि इससे पहले की व्यवस्था में जजों की नियुक्ति और तबादले के लिए सरकार का फैसला ही अहम होता था।

लेकिन इसके बाद वर्ष 1998 में राष्ट्रपति के 'ध्यानाकर्षण' पर सुप्रीम कोर्ट में नौ अन्य जजों की बेंच ने 1993 के फैसले को सही ठहराते हुए कोलेजियम प्रणाली में जजों की नियुक्ति को सीजेआइ के नेतृत्व वाले कोलेजियम के अधीन ही कर दिया। इसके बाद वर्ष 2015 में जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता में पांच जजों की संविधान पीठ ने नेशनल ज्यूडिशियल एप्वाइंटमेंट्स कमिशन (एनजेएसी) को खारिज कर दिया। लिहाजा, मौजूदा कोलेजियम प्रणाली को हटाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा।

सूचना आयोगों में नियुक्ति पर केंद्र और नौ राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी

- याचिकाकर्ताओं ने कहा, शीर्ष कोर्ट के पहले के आदेश का पालन नहीं हुआ

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और नौ राज्यों से केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) तथा राज्य सूचना आयोगों (एसआइसी) में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के संबंध में दिए गए अपने पूर्व के आदेश के अनुपालन में स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को यह आदेश उस समय दिया जब आरटीआइ कार्यकर्ता अंजली भारद्वाज और अन्य ने कहा कि शीर्ष कोर्ट के पहले के आदेशों पर अभी तक अमल नहीं किया गया है।

याचिका दायर करने वाली भारद्वाज और अन्य की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि शीर्ष कोर्ट के आदेश के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारों ने चयनित उम्मीदवारों के नाम अभी तक अपनी वेबसाइट पर जारी नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों को केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में रिक्त स्थानों पर अभी नियुक्तियां करनी है।

शीर्ष कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के बारे में कई निर्देश दिए थे और कहा था कि इनमें नियुक्ति की प्रक्रिया पद रिक्त होने से एक से दो महीने पहले ही शुरू की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि मुख्य सूचना आयुक्त का पद ऊंचे पायदान पर

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

होता है और इस पद के लिए भी नियुक्ति की प्रक्रिया उन्हीं शर्तों के अनुसार होनी चाहिए जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के मामले में अपनाई जाती है।

कोर्ट ने सात राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, केरल, ओडिशा और कर्नाटक से जानना चाहा था कि वे कितने समय में अपने यहां सूचना आयोगों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर लेंगे। याचिका दायर करने वालों ने कहा था कि गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कई सूचना आयोग मुख्य सूचना आयुक्त के बगैर ही काम कर रहे हैं, जबकि सूचना के अधिकार कानून में इस पद को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है जिस पर आयोग के प्रशासन और अधीक्षण की जिम्मेदारी होती है।

26 नवंबर को संसद की संयुक्त बैठक

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत के संविधान को अंगीकार किए जाने की 70वीं वर्षगांठ पर 26 नवंबर को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। संसद के सेंट्रल हॉल में यह बैठक होगी। सूत्रों ने बताया कि संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित इस बैठक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं। बता दें कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया था। हालांकि, यह प्रभावी 26 जनवरी 1950 से हुआ था।

सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा के सभापति एवं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इसे संबोधित कर सकते हैं। 26 नवंबर को पूर्वाह्न शुरू होने वाली इस संयुक्त बैठक के दो घंटे से अधिक समय तक चलने की संभावना है। इसमें दोनों सदनों के सदस्यों के अलावा पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्रियों के मौजूद रहने की संभावना है। यह बैठक ठीक वैसी ही होगी जैसी जून 2017 में जीएसटी पेश करने के अवसर पर बुलाई गई थी। इसी तरह 1997 में देश की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भी बुलाई गई थी।

अहमद पटेल ने गडकरी से विभिन्न परियोजनाओं पर बातचीत की

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने बुधवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने गुजरात में सड़क तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में सरकार गठन में गतिरोध के बीच हुई इस मुलाकात को लेकर अनुमानों का बाजार गर्म हो गया है।

मुलाकात के बाद कांग्रेस के कोषाध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि केंद्रीय मंत्री के साथ राजनीति पर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वह किसानों के मुद्दे पर बातचीत करने पहुंचे थे। उन्होंने गडकरी को गुजरात के एमएसएमई सेक्टर के संबंध में लिखा गया पत्र भी जारी किया। गुजरात से राज्यसभा सदस्य पटेल ने गडकरी से उनके कार्यालय में मुलाकात की और अपने राज्य में सड़क तथा बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में कुछ देरी की ओर ध्यान दिलाया और साथ ही गुजरात में सड़क परियोजनाओं को बेहतर बनाने की मांग भी

अहमद पटेल और नितिन गडकरी। फाइल फोटो

उठाई। मुंबई में राकांपा प्रमुख शरद पवार ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल के बीच हुई मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर कहा, 'जरूर सड़क से संबंधित कोई काम होगा।'

गडकरी से पटेल की मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह भेंट ऐसे समय पर हुई है, जब महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर गतिरोध जारी है। महाराष्ट्र में 24 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा की गई थी, जिसके 13 दिन बाद भी कोई पार्टी सरकार गठन के लिए आवश्यक 145 सीटें नहीं जुटा पाई है। विधानसभा चुनाव में भाजपा को 105 सीटें और शिवसेना को 56 सीटें मिलीं।

नीरव मोदी की जमानत अर्जी चौथी बार खारिज

- ब्रिटिश कोर्ट में मोदी ने 37 करोड़ की जमानत राशि देने की पेशकश की

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन की अदालत से दो अरब डॉलर के पीएनबी घोटाले में मुख्य आरोपित नीरव मोदी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कड़ी चेतावनी देने के बाद भगोड़े हीरा कारोबारी की जमानत अर्जी फिर खारिज कर दी गई है। मोदी ने इस बार अजब किस्म के 'जमानत पैकेज' की पेशकश की थी। उसने 40 लाख पाउंड (करीब 37 करोड़ रुपये) की जमानत राशि और अपने आलीशान घर में नजरबंद करने का प्रस्ताव रखा था।

भारत में वांछित 48 वर्षीय नीरव ब्रिटेन की अदालत में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ भी केस लड़ रहा है। उसे बुधवार को वेस्टमिंस्टर मेजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत लेने का चौथा प्रयास मुख्य मजिस्ट्रेट एमा अर्बुथनॉट ने खारिज कर दिया। सफेद शर्ट और नीले स्वेटर में नीरव सुनवाई के दौरान पिछली सुनवाई के मुकाबले बेहतर लगा। उसके बाद उसे दक्षिण-पश्चिम लंदन की जेल वांड्सवर्थ भेज दिया गया। अब उसकी अगली पेशी इसी अदालत में चार दिसंबर को होगी। वह इस पेशी में भी हमेशा की तरह वीडियो लिंक के जरिये अदालत में हाजिर होगा।

मुख्य मजिस्ट्रेट एमा अर्बुथनॉट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, भूतकाल इस बात की

नीरव मोदी फाइल फोटो

तस्वीर खींचता है कि भविष्य में क्या हो सकता है। वह इस से भी सहमत नहीं हुईं कि मई 2020 में होने वाली भारत प्रत्यर्पण की सुनवाई से पहले वह अदालत में पेश होगा और गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। उन्होंने कहा, नीरव के अवसाद में होने की बात भी उन्हें जमानत के लिए फैसला बदलने को मजबूर नहीं कर सकती है।

हालांकि नीरव के मानसिक स्वास्थ्य की गुप्त रिपोर्ट को लेकर पिछले माह दायर की गई जमानत याचिका की जानकारी मीडिया में लीक किए जाने से भी वह बेहद नाराज नजर आईं। लेकिन बचाव पक्ष की वकीलों की टीम ने इस रिपोर्ट के लीक होने की बात भारतीय जांच एजेंसियों पर थोप दी। मोदी के वकीलों ने अपनी दलीलों के पक्ष में 30 अक्टूबर को प्रकाशित प्रेस रिपोर्टों को भी कोर्ट में रखा।

जज ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि डॉक्टरों की रिपोर्ट लीक कर दी गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे अदालत का विश्वास भारत सरकार के प्रति कम होता है। इस पर भारत सरकार की ओर से प्रत्यर्पण केस लड़ रही क्राउस प्रॉसीक्यूशन सर्विस (सीपीएस) के जेम्स लेविस ने कहा, खबर लीक जरूर हुई लेकिन इसके पीछे भारतीय पक्ष नहीं है।

सीपीएस के जेम्स लेविस ने नई जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा, नीरव का इरादा ब्रिटेन से भागने का है। उसका कहना है कि अगर उसे भारत भेजा गया तो वह खुदकशी कर लेगा। इससे साफ है कि उसका इरादा फरार होने का है। मोदी के वकील ह्यूगो कीथ ने कहा, वह पिछली बार के 20 लाख पाउंड के सुरक्षा बांड की जगह इस बार दोगुनी राशि यानी 40 लाख पाउंड जमा करेंगे। इसके अलावा वह खुद पर निगरानी के लिए अपने खर्च पर निजी गार्ड सेवा के साथ ही इलेक्ट्रानिक टैगिंग का इस्तेमाल करेंगे।

सुबूत ईडी के पास, नहीं हो सकती छेड़छाड़ : चिदंबरम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : आइएनएक्स मीडिया डील में मनी लांड्रिंग के मामले में नियमित जमानत के लिए याचिका पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की तरफ से बुधवार को जिरह पूरी हो गई। चिदंबरम ने कहा कि मामले से जुड़े सभी दस्तावेज जांच एजेंसी के पास हैं और इसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।

चिदंबरम की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि अभियोजन पक्ष का आरोपपत्र अदालत में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दायर नहीं किया गया है। जांच एजेंसी का रवैया शुरू से ही यह नहीं था कि चिदंबरम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। अक्टूबर में चिदंबरम को हिरासत में लिए जाने के बाद अचानक जांच एजेंसी ने कहना शुरू कर दिया कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

अदालत ने चिदंबरम की तरफ से जिरह पूरी होने के बाद सुनवाई को 8 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। अब 8 नवंबर को ईडी की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा। हालांकि, अधिवक्ता अमित महाजन व रजत नायर के माध्यम से जवाब दाखिल कर ईडी ने जमानत याचिका का विरोध किया।

वाट्सएप जासूसी प्रकरण

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा, अपने डाटा और उसके व्यावसायिक उपयोग पर खुद का नियंत्रण होना चाहिए

निजता को लेकर भारत गंभीर, डाटा एकाधिकार मंजूर नहीं : प्रसाद

नई दिल्ली, प्रेट्र : वाट्सएप जासूसी मामले को लेकर बढ़ी हलचल के बीच सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को निजता के अधिकार की रक्षा को लेकर भारत की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि देश निजता के अधिकार को गंभीरता से लेता है और सूचना की निजता इसी का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत डाटा के क्षेत्र में उपनिवेशवाद को स्वीकार नहीं करेगा।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोलंबो (श्रीलंका) में राष्ट्रमंडल देशों के विधि मंत्रियों के एक सम्मेलन में प्रसाद ने डाटा संरक्षण पर भारत का सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि आंकड़ों (डाटा) पर कुछ देशों या कंपनियों के एकाधिकार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में डाटा डिजिटल अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। प्रसाद ने कहा, 'भारत में हम निजता के अधिकार की रक्षा को गंभीरता से लेते हैं और सूचना की निजता इसका अभिन्न अंग है। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति का अपने डाटा और उसके व्यावसायिक उपयोग पर अपना नियंत्रण होना चाहिए।' ऐसे समय में प्रसाद की यह टिप्पणी काफी अहमियत रखती है जब वाट्सएप ने हाल ही में कहा था इजराइली स्पाइयर 'पेगासस' से वैश्विक स्तर पर जासूसी की गई। भारत

रविशंकर प्रसाद। फाइल फोटो

के कुछ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस जासूसी का शिकार बने हैं। प्रसाद ने सम्मेलन में कहा कि आंकड़ों पर आधारित अर्थव्यवस्था वाणिज्यिक उपयोग और रोजगार दोनों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत इस तथ्य को स्वीकार करता है कि विकासशील और अल्पविकसित देशों में बड़े पैमाने पर आंकड़ों का सृजन हो रहा है लेकिन उनके प्रसंस्करण का दावा सिर्फ बड़े देश ही कर रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि कुछ कंपनियों या देशों का आंकड़ों (डाटा) पर एकाधिकार कायम करने की कोशिश या डाटा आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रसाद ने कहा कि बड़े देश हो या छोटे दोनों के आंकड़ों की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए।

संसदीय समिति करेगी मामले पर चर्चा

- कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता में 20 नवंबर को होगी बैठक

नई दिल्ली, प्रेट्र : वाट्सएप जासूसी मामले पर कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति 20 नवंबर को चर्चा करेगी। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

शशि थरूर सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। थरूर ने समिति के सदस्यों को लिखे पत्र में कहा है कि भारतीयों की जासूसी के लिए प्रौद्योगिकी के कथित इस्तेमाल का मामला गंभीर है। इस पर 20 नवंबर को समिति की अगली बैठक में चर्चा की जाएगी।

फेसबुक की स्वामित्व वाली कंपनी वाट्सएप ने 31 अक्टूबर को यह ऐलान कर हलचल मचा दी थी कि अज्ञात इकाइयों द्वारा इजरायली स्पाइवेयर पेगासस के इस्तेमाल से दुनिया भर में पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। इनमें भारतीय पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक थरूर ने पत्र में कहा है कि लोकतांत्रिक गणराज्य होने के

प्रतीकात्मक

नाते हमें अधिशासी अधिकारों के अनधिकृत तरीके या गलत मकसद से इस्तेमाल को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करने होंगे। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी निजता को मौलिक अधिकार माना है। इसलिए इस अधिकार का उल्लंघन करने वाली किसी भी तरह की कार्रवाई की कानूनी वैधता और जरूरत का विश्लेषण किए जाने की जरूरत है।

कह के रहेंगे माधव जोशी

ऑफिस में कोई इसलिए नहीं है, क्योंकि सभी नए म

2014 में झारखंड विधानसभा चुनाव में 31.8 फीसद वोट के साथ भाजपा ने 37 सीटें जीती थीं, वहीं झामुमो को 20.8 फीसद वोट के साथ 19 सीटें मिली थीं। 10.6 फीसद वोट के साथ छह सीटें कांग्रेस के खाते में आई थीं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 7 नवंबर 2019

महाराष्ट्र में सभी पक्ष अपने-अपने रुख पर कायम

खींचतान जारी ▸ पवार ने कहा-पावर से दूर रहेंगे, भाजपा-शिवसेना सरकार बनाएं, शिवसेना अपने सीएम और अपनी सरकार के दावे पर अड़ी

भाजपा का प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल से मिलेगा

राज्य ब्यूरो, मुंबई

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार महाराष्ट्र में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस विधायकों का एक गुट भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए शिवसेना के साथ सरकार बनाने को तैयार है, वहीं शिवसेना अपनी नई-नई शर्तें भाजपा पर लादती जा रही है। इन सबके बीच महाराष्ट्र को नई सरकार कब और किसकी मिलेगी, इसका निर्णय बुधवार को भी नहीं हो सका। हालांकि, नौ नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के चलते गुरुवार को भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी से मुलाकात करने जा रहा है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार ने बुधवार को सीएम आवास वर्षा के बाहर बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के संदेश को लेकर महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से विस्तृत बैठक करेगा। पार्टी ने राज्य में नया पार्टी अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अगली कैबिनेट में चंद्रकांत पाटिल शामिल होंगे। अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया को 31 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। पाटिल को अमित शाह का करीबी माना जाता है। सुधीर मुनगंटीवार ने जल्दी ही शुभ समाचार मिलने के संकेत दिए हैं, लेकिन उनकी बात का मजाक उड़ाते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि वह शिवसेना के मुख्यमंत्री बनने का ही शुभ समाचार देने वाले होंगे।

संजय राउत ने भाजपा को यह चुनौती भी दी है कि वह राज्यपाल के पास 145 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा करे और सरकार बनाकर दिखाए। सूत्रों के अनुसार, शिवसेना की मांगें अब ढाई-ढाई साल के मुख्यमंत्री तक ही सीमित नहीं हैं। अब वह पहले ढाई साल अपना मुख्यमंत्री बनाने की बात भी करने लगी है। इसके अलावा मंत्रालयों के बंटवारे में बराबर की संख्या में मंत्री एवं महामंडलों और निगमों में आधे-आधे का बंटवारा चाहती है। उसका यह भी कहना है कि भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े साथी दलों को भाजपा अपने कोटे से ही मंत्रालय दे। जाहिर है, भाजपा के लिए ये शर्तें मानना आसान नहीं होगा।

पवार बोले-विपक्ष में ही रहेंगे : कांग्रेस-राकांपा के भरोसे 175 विधायकों के समर्थन का दावा करती आ रही शिवसेना के नेता संजय राउत से मुलाकात के कुछ ही मिनटों बाद राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने एक संवाददाता सम्मेलन में स्पष्ट कर दिया कि जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है। वे महाराष्ट्र में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने भाजपा और शिवसेना को जल्द सरकार बनाकर बरसात से परेशान किसानों को मदद पहुंचाने की भी सलाह दी। पवार ने यह भी स्पष्ट किया कि संजय राउत ने उन्हें सरकार बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। न ही उनकी पार्टी ने शिवसेना को समर्थन का कोई आश्वासन दिया है। पवार कहते हैं कि राकांपा और कांग्रेस मिलकर भी 100 से आगे नहीं जा रहे हैं, तो हमारी सरकार बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शरद पवार ने भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए उनके स्वयं सीएम बनने के आसार को खारिज करते हुए कहा कि वह चार बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब वह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे।

सरकार बनाने की कवायद से इतर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फड़नवीस ने बेमौसम बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले मंत्रियों के साथ बैठक की। प्रेट्र

राकांपा प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को मुंबई में प्रेसवार्ता की। एएनआइ

कांग्रेस का रुख है अलग

कांग्रेस का रुख अब पवार की मंशा से भिन्न नजर आया। कांग्रेस का एक गुट भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए शिवसेना को समर्थन देने अथवा उसके साथ मिलकर सरकार बनाने को भी तैयार दिख रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चह्वाण एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहब थोरात ने भी माना कि उनकी पार्टी के कुछ विधायक शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने के इच्छुक हैं। कांग्रेस की एक विधायक यशोमती ठाकुर बुधवार सुबह ही राकांपा अध्यक्ष शरद पवार से उनके घर जाकर मिलीं और कांग्रेस-राकांपा को मिलकर शिवसेनानीत सरकार को समर्थन देने का सुझाव दिया, जबकि शाम को कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हुसैन दलवई शिवसेना मुखपत्र सामना के कार्यालय में जाकर शिवसेना नेता संजय राउत से मिले और वहां से निकलकर विश्वासपूर्वक बयान दिया कि भाजपा की सरकार नहीं बनने वाली, जबकि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इससे पहले सरकार बनाने की प्रक्रिया से दूर रहते हुए विपक्ष में बैठने की बात कर चुके हैं।

मप्र में भाजपा ने चेताया-विधायकों से सतत संपर्क बनाएं पार्टी पदाधिकारी

धनंजय प्रताप सिंह, भोपाल

- आपराधिक मामले के चलते एक विधायक की सदस्यता खत्म होने से घबराई
- कहा-संगठन को भेजें अदालती मामलों की जानकारी

मध्य प्रदेश में ब्यौहारी के भाजपा विधायक शरद कोल द्वारा एक बार फिर कांग्रेस के प्रति रुझान दिखाए जाने के बाद भाजपा ने सारे संगठन पदाधिकारियों से कहा है कि वे स्थानीय विधायकों से सतत संपर्क बनाए रखें और निरंतर संवाद करते रहें। खासतौर से ऐसे विधायकों पर भी पार्टी नजर रख रही है, जो विभिन्न आपराधिक मामलों में फंसे हैं। उन पर दर्ज मामलों की स्थिति की जानकारी भी संगठन ने मांगी है। दरअसल, आपराधिक मामले के चलते एक विधायक की सदस्यता खत्म किए जाने के बाद भाजपा ने मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और मंत्री डॉ. गोविंद सिंह के उस बयान को गंभीरता से लिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा के विधायकों की संख्या और घटने वाली है। इसके बाद भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह अगले चार दिन के लिए भोपाल में डेरा डाल रहे हैं। वह सारे विधायकों के बात करेंगे।

भाजपा विधायकों के एक के बाद एक विकेट गिरने से इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। पहले झाबुआ उप चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा विधायकों की संख्या 109 से घटकर 108 हो गई थी। कुछ दिन पहले पवई से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी को हुई दो साल की सजा के बाद सदस्यता समाप्त किए जाने से एक और विधायक घट गया। लोधी का मामला हाई कोर्ट में लंबित है, यदि राहत मिली तो ठीक वरना भाजपा विधायकों की संख्या 107 बचेगी। पार्टी के सामने बागी विधायकों ने भी मुसीबत खड़ी कर रखी है। भाजपा विधायक शरद कोल और सतना जिले के मैहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने जुलाई में आयोजित विधानसभा सत्र में एक विधेयक पर हुए मत विभाजन में कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था। त्रिपाठी तो भाजपा के खेमे में वापस आ गए, लेकिन कोल अब भी कमलनाथ सरकार के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे हालात में पार्टी को डर है कि कांग्रेस और भी विधायकों को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर सकती है। इन परिस्थितियों को देखकर पार्टी ने संगठन को चेताया है।

कमलनाथ सरकार की नजर भाजपा के उन विधायकों पर है, जिन पर कई तरह के आपराधिक मामले चल रहे हैं। भाजपा को डर है कि सरकार ऐसे मामलों में जल्द चालान पेश करवा सकती है। ऐसा हुआ तो कुछ संगीन मामलों से घिरे विधायकों को सजा हो सकती है। भाजपा ऐसे सारे विधायकों का ब्योरा जुटा रही है।

> कांग्रेस सरकार षड्यंत्र और दांव-पेच से बहुमत जुगाड़ने की अनैतिक कोशिश में लगी है। भाजपा न केवल सतर्क है, बल्कि हम नो बॉल पर भी छक्का ठोकेंगे।
> -रजनीश अग्रवाल, प्रवक्ता, भाजपा मप्र

समझौते के लिए तैयार हुआ झामुमो पर झाविमो अड़ा

झारखंड विधानसभा चुनाव

- हेमंत सोरेन चुनाव परिणाम के बाद नेतृत्व पर विचार करने को भी राजी
- तैयार नहीं हुए बाबूलाल तो उनके बगैर होगी विपक्षी महागठबंधन की घोषणा

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड में विधानसभा चुनाव में नेतृत्व करने की बात कर रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) अब अपनी जिद छोड़ता दिख रहा है। पार्टी नेतृत्व महागठबंधन के दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने और नेतृत्व की बात पर चुनाव परिणाम के बाद विचार करने पर भी राजी है, लेकिन झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) प्रमुख बाबूलाल मरांडी अभी भी 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े हैं।

इस बीच, कांग्रेस ने संभावित फैसले को एक दिन टालते हुए शनिवार 9 नवंबर को चुनाव समिति की बैठक बुलाई है जिसमें सीटों के बंटवारे पर मुहर लगेगी। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान बाबूलाल मरांडी को मनाने का अंतिम प्रयास होगा।

बाबूलाल कई बार सार्वजनिक तौर पर राज्य की सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी कर चुके हैं। उधर महागठबंधन के सभी दलों की सहमति को लेकर कांग्रेस उम्मीद बांधे हुए है और दिल्ली से पूरी कोशिशें की जा रही हैं। बुधवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने अन्य नेताओं के साथ इस मसले पर विस्तार से चर्चा भी की।

42 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगा झामुमो : हेमंत

झामुमो 42 से अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगा। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने बुधवार को कार्यकारिणी की बैठक के बाद इसकी घोषणा की। हालांकि, उन्होंने गठबंधन के प्रयास जारी रखने की भी बात कही। शिबू सोरेन के आवास पर आयोजित कार्यकारिणी की बैठक के बाद हेमंत सोरेन मीडिया से मुखातिब थे। 8 नवंबर को पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेंगे।

पूर्व मंत्री राजा पीटर जेल से लड़ेंगे चुनाव, मिली इजाजत

एनआइए की विशेष अदालत ने बुधवार को जेल में बंद पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर को विधानसभा चुनाव लड़ने की सशर्त अनुमति दे दी है। विशेष जज नवनीत कुमार की अदालत ने नामांकन के लिए 12 नवंबर की तिथि तय की है। पीटर तमाड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पीटर तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या कराने के मामले में जेल में बंद हैं।

ममता ने केंद्र सरकार से पूछा, जेईई-मेंस में गुजराती ही क्यों

कई ट्वीट कर बंगाल की मुख्यमंत्री ने केंद्र पर बांग्ला सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के अपमान का लगाया आरोप

जागरण संवाददाता, कोलकाता

इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए ली जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई-मेंस में हिंदी व अंग्रेजी के अलावा अब गुजराती को भी वैकल्पिक भाषा के रूप में शामिल करने का केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। केंद्र के इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी आलोचना की है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को एक के बाद एक कई ट्वीट कर इस फैसले पर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार पर बांग्ला सहित विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि जेईई-मेंस में सिर्फ गुजराती ही क्यों, अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को क्यों नहीं शामिल किया गया?

ममता का ट्वीट वार

पहला ट्वीट : हमारा देश भारत जो इतने सारे धर्मों, संस्कृतियों, भाषाओं, पंथों और समुदायों वाला है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार की मंशा सभी क्षेत्रों और क्षेत्रीय भाषाओं को अपमानित करना है।

दूसरा ट्वीट : अब तक संयुक्त प्रवेश परीक्षा केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होती रही है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अब क्षेत्रीय भाषा के रूप में सिर्फ गुजराती को इसमें जोड़ा गया है। इस कदम की किसी भी तरह से प्रशंसा नहीं की जा सकती है। ममता ने आगे कहा कि मुझे गुजराती भाषा से प्यार है, लेकिन केवल गुजराती भाषा को इसमें शामिल कर बांग्ला सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का अपमान क्यों किया जा रहा है?

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फाइल

तीसरा ट्वीट : अगर गुजराती भाषा को इसमें शामिल किया गया है तो बांग्ला सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

चौथा व आखिरी ट्वीट : अगर इसे तुरंत वापस नहीं लिया गया तो इस अन्याय के खिलाफ तीखा विरोध प्रदर्शन व आंदोलन किया जाएगा।

यह है विवाद : अखिल भारतीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का प्रश्नपत्र पहले सिर्फ अंग्रेजी व हिंदी में तैयार होता था। परीक्षार्थी इन दोनों भाषाओं में से किसी में उत्तर दे सकते थे, लेकिन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत नवगठित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने अगले साल आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए हिंदी व अंग्रेजी के अलावा गुजराती को भी वैकल्पिक भाषा के रूप में शामिल करने का फैसला किया है।

ममता के सांसद भतीजे ने भी जताया विरोध : ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी सिर्फ गुजराती भाषा को शामिल करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्र की आलोचना की है। अभिषेक ने ट्वीट कर कहा कि संविधान में सभी को समान अधिकार है। ऐसे में हिंदी, अंग्रेजी व गुजराती में ही परीक्षा क्यों हो? यह असंवैधानिक है।

माकपा व कांग्रेस ने भी साधा निशाना : माकपा नेता सुजन चक्रवर्ती ने इस फैसले की आलोचना करते हुए ट्वीट किया, जेईई-मेंस परीक्षा का पेपर सिर्फ तीन भाषाओं-हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में ही कैसे हो सकता है? गुजरात की तुलना में बंगाल में दो गुना और महाराष्ट्र में तीन गुना परीक्षार्थी हैं। क्षेत्रीय भेदभाव की यह नीति खत्म होनी चाहिए। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रदीप भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि यह सब गुजराती का आधिपत्य स्थापित करने के लिए किया जा रहा है।

भाजपा सांसद ने भी किया विरोध : भाजपा के सांसद स्वपन दासगुप्ता ने इस विरोध का समर्थन करते हुए कहा, सभी मुख्य क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देना चाहिए। खासकर तमिल और बांग्ला को जरूर शामिल किया जाना चाहिए।

अब राज्यपाल ने ट्वीट कर ममता पर साधा निशाना

जागरण संवाददाता, कोलकाता

टकराव

- सीएम ने कॉलेज व विवि शिक्षकों से संवाद के दौरान हर किसी को तवज्जो नहीं देने की कही थी बात

बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में एक और जंग की तैयारी दिख रही है। बुधवार को एक ट्वीट कर राज्यपाल ने कहा कि वह कॉलेज व विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को दी गई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस सलाह के निहितार्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने शिक्षकों को कोई भी समस्या होने पर सीएम तक जाने की सलाह दी है और कहा है कि कोई और क्या कहता है, इसकी उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टैग करते हुए उन्होंने लिखा है कि एक राज्यपाल और एक कुलाधिपति के तौर पर मेरा कृत्य संविधान और यूनिवर्सिटी एक्ट के अनुरूप है।

मंगलवार को कॉलेज व विश्वविद्यालय शिक्षकों के एक आधिकारिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर कोई आपसे कुछ कहता है तो इसके लिए आपको नाहक परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि, उन्होंने सीधे तौर पर राज्यपाल का नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उनका इशारा राज्यपाल की ही तरफ था, जो विश्वविद्यालयों को मामले में फिलहाल अति सक्रिय हैं। मौके पर सीएम ने शिक्षकों के सामने यह भी दोहराया कि उनकी सरकार भी केंद्र सरकार की तरह जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। उन्होंने कहा कि संविधान ने चयनित सरकारों को कुछ क्षमताएं दी हैं। इसलिए आपको कोई भी समस्या हो आप सीधे हमसे कहें।

बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ फाइल

पहले ही तल्ख हैं रिश्ते : वैसे ममता सरकार के साथ राज्यपाल धनखड़ के तल्ख रिश्तों की शुरुआत ही एक विश्वविद्यालय के मुद्दे से हुई थी, जहां प्रदर्शनकारी छात्रों से घिरे केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को बचाने के लिए राज्यपाल खुद पहुंच गए थे। तब तृणमूल सरकार ने राज्यपाल के इस कृत्य को हैरान करने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया था। तब से शुरू हुई तल्खी गाहे-बगाहे सामने आ रही है।

भाजपा ने तैयार की प्रत्याशियों की सूची

राज्य ब्यूरो, रांची : चुनाव के लिए भाजपा में प्रत्याशियों के चयन को लेकर बुधवार को हुई प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के साथ ही टिकटों की टिकटिक अब दिल्ली शिफ्ट हो गई है। दिल्ली में गुरुवार से प्रदेश की कोर टीम का केंद्रीय नेताओं के साथ बैठकों का दौर शुरू होगा। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक भी संभावित है, जिसमें राज्य के भाजपा सांसद भी भाग लेंगे। बैठक में विधानसभावार प्रत्याशियों पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। वहीं, 8 नवंबर को केंद्रीय चुनाव समिति के साथ प्रदेश के शीर्ष नेताओं की बैठक होने की बात कही जा रही है। बैठकों से निकले निष्कर्ष पर यदि जिच की स्थिति नहीं बनीं तो 8 नवंबर को ही पार्टी के संसदीय बोर्ड के स्तर से प्रत्याशियों पर मुहर लगा दी जाएगी।

पहले चरण की 13 सीटों पर अधिसूचना जारी

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण की 13 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी हुई। इसी के साथ इन सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। हालांकि, पहले दिन किसी भी सीट पर कोई नामांकन की सूचना नहीं है। पहले चरण की जिन 13 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है, उनमें एसटी के लिए आरक्षित गुमला, बिशुनपुर, लोहरदगा व मनिका तथा एससी के लिए आरक्षित चतरा, लातेहार व छतरपुर सीटें शामिल हैं। शेष सीटें अनारक्षित हैं, जिनमें पांकी, डालटनगंज, विश्रामपुर, गढ़वा, हुसैनाबाद तथा भवनाथपुर शामिल हैं। इन विधानसभा सीटों पर 30 नवंबर को मतदान होना है, जबकि नामांकन की अंतिम तिथि 13 नवंबर है। 14 को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं उम्मीदवार 16 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। इसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न भी आवंटित किए जाएंगे।

गुजरात में एक बार फिर से आरक्षण आंदोलन की तैयारी

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर गुजरात में एक बार फिर से आंदोलन की जमीन तैयार हो रही है। करणी सेना इसी संबंध में 15 दिसंबर को गांधीनगर में महारैली करेगी। सेना ने एससी-एसटी एट्रोसिटी एक्ट के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसकी धारा-18 ए को हटाने तथा गलत केस दर्ज कराने पर सजा का प्रावधान करने की भी मांग की है।

दरअसल, राज्य ने लंबे समय तक पाटीदार आरक्षण आंदोलन देखा। इसी दौरान ओबीसी और अनुसूचित जाति के लोगों ने भी आंदोलन किए, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद सब कुछ शांत हो गया तथा आंदोलनकारी नेता भी अलग-अलग राजनीतिक दलों में चले गए। अब आरक्षण को लेकर एक बार फिर करणी सेना ने कमर कस ली है। सेना की मांग है कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर करणी सेना ने 15 दिसंबर को गांधीनगर में एक महारैली का आयोजन किया है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी भी इसमें शामिल होंगे। करणी सेना ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो यह आंदोलन पूरे देश में किया जाएगा। करणी सेना गुजरात के अध्यक्ष राज शेखावत बताते हैं कि गुजरात के कच्छ में सरकार की ओर से अनुसूचित जाति के लोगों को जमीन आवंटित की गई थी। इसको लेकर क्षत्रिय और अनुसूचित जाति के समुदाय के बीच माहौल गर्म है। उन्होंने इसको लेकर गत 30 अक्टूबर को एक सभा को संबोधित किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दायर करा दिया गया।

गुजरात सरकार ने सीएम और वीआइपी के लिए खरीदा 191 करोड़ का विमान

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

गुजरात की भाजपा सरकार ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और अन्य वीआइपी की हवाई यात्राओं के लिए 191 करोड़ रुपये कीमत का एक नया विमान खरीदा है। 12 सीटर यह विमान एक बार में सात हजार किलोमीटर (चीन तक) तक का सफर कर सकता है। पांच साल पहले इस विमान को खरीदने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और तीसरी बिड में इसे खरीदा जा सका।

गुजरात के नागर विमानन विभाग के निदेशक कैप्टन अजय चौहान ने बताया कि दो इंजन वाले बांबार्डियर चैलेंजर 650 नामक इस विमान को खरीदने संबंधी सभी तरह की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। नवंबर के तीसरे सप्ताह में इसकी डिलीवरी प्रदेश सरकार को मिल जाएगी। हालांकि, इसको प्रयोग में लाने के लिए दो महीने का समय और लगेगा क्योंकि इसके लिए कस्टम से कुछ जरूरी अनुमति लेनी होगी। यह चैलेंजर सीरीज का पांचवां विमान है, जो 870 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। वर्तमान में प्रदेश सरकार 'बीचक्राफ्ट सुपर किंग टर्बोप्रोप' विमान का प्रयोग कर रही है, जिसमें एक बार में नौ लोग सफर कर सकते हैं। नए विमान की जरूरत पर चौहान ने बताया कि 'बीचक्राफ्ट सुपर किंग' विमान बहुत अधिक दूरी तक उड़ान नहीं भर सकता था। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री समेत किसी वीआइपी को लंबी दूरी की यात्रा करनी होती थी तो निजी विमान किराए पर लेना पड़ता था। इसके लिए एक लाख रुपये प्रति घंटे या उससे अधिक कंपनी को चुकाने पड़ते थे। 'बीचक्राफ्ट सुपर किंग' पुराना वर्जन था, जिसके चलते अहमदाबाद से गुवाहाटी जाने में विमान को पांच घंटे का समय लगता था। नया विमान यही दूरी मात्र एक घंटा चालीस मिनट में तय कर लेगा और दोबारा ईंधन भी नहीं भरना पड़ेगा।

विजय रूपाणी फाइल

हरियाणा में विधानसभा के विशेष सत्र के बाद शुरू हुए नई कैबिनेट के गठन के प्रयास

बिजेंद्र बंसल, नई दिल्ली

- महाराष्ट्र में फंसे राजनीतिक पेच की वजह से अटका है कैबिनेट का विस्तार
- शीर्ष नेतृत्व से नई कैबिनेट पर अंतिम मुहर लगवाने दिल्ली पहुंचे सीएम मनोहर

तीन दिन चले हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र की समाप्ति के बाद नई कैबिनेट के गठन के प्रयास शुरू हो गए हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा सत्र से पहले नई कैबिनेट पर आपसी सहमति कर ली है, लेकिन इस पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की मुहर नहीं लगी है। असल में महाराष्ट्र में फंसे राजनीतिक पेच की वजह से हरियाणा कैबिनेट का विस्तार अटका हुआ है।

शीर्ष नेतृत्व से कैबिनेट के नए प्रारूप पर अंतिम मुहर लगवाने के लिए खुद मुख्यमंत्री बुधवार शाम चंडीगढ़ से नई दिल्ली पहुंच गए। मुख्यमंत्री की इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से पार्टी मुख्यालय में मंत्रिमंडल के आकार और विधायकों के नाम को लेकर करीब एक घंटे तक चर्चा हुई। हालांकि, राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात नहीं हो पाई। सूत्र बताते हैं कि गुरुवार को दिन में उनकी अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। शाह की मुहर के बाद हरियाणा कैबिनेट के विस्तार की तारीख तय कर दी जाएगी। कैबिनेट विस्तार में मनोहर-दुष्यंत की तरफ से कोई देरी नहीं की जाएगी। यह विस्तार नौ या 10 नवंबर को हो सकता है।

जातीय संतुलन साधते हुए मंत्री बनाएंगे मनोहर और दुष्यंत : मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नए मंत्रिमंडल का जो खाका तैयार किया है, उसमें जातीय व क्षेत्रीय संतुलन को साधा गया है। सूत्र बताते हैं कि विधानसभा के विशेष सत्र में मंत्रियों के अनुसार ही उनकी सीट भी आवंटित की गई हैं। पिछली बार जहां मंत्री बैठते थे, उन सीटों को इस बार संभावित मंत्रियों को ही आवंटित किया गया है। इस बार दक्षिण हरियाणा के अहीरवाल से डॉ. अभय सिंह यादव, डॉ. बनवारी लाल सहित पलवल के विधायक दीपक मंगला, फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता सहित बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा, तिगांव के विधायक राजेश नागर, बड़खल की विधायक सीमा त्रिखा के बीच मंत्री पद झूल रहे हैं। जीटी रोड बेल्ट पर अंबाला के अनिल विज, जगाधरी के कंवरपाल गुर्जर का मंत्री बनना तय है। जजपा के कोटे से नारनौंद के विधायक रामकुमार गौतम और अनूप धानक को मंत्री बनाया जा सकता है। ज्ञानचंद गुप्ता को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कमल गुप्ता को मुख्य सचेतक या संसदीय कार्य मंत्री भी बनाया जा सकता है। सोनीपत के गन्नौर से जीती निर्मल रानी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। करनाल जिला से हरविंद्र कल्याण और कैथल जिला में कलायत से जीतीं कमलेश ढांडा को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है।

आजम को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश

जागरण संवाददाता, रामपुर : सेना पर विवादित बयान देने और पड़ोसी को धमकाने के मामले में सुनवाई कर रही अदालत ने सांसद आजम खां को तलब कर लिया है। अदालत ने उन्हें समन जारी कर 21 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए हैं। भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने जून 2017 में सिविल लाइंस कोतवाली में सपा सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें सांसद पर भारतीय सेना के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप है। इसके अलावा सांसद के पड़ोसी आरिफ रजा ने भी गंज कोतवाली में एक मुकदमा कराया था। उनका आरोप है कि सांसद और उनके समर्थकों ने रास्ते में रोककर गाली गलौज की थी। जान से मारने की धमकी दी थी। इस मुकदमे में सांसद समेत छह लोग आरोपित हैं। पुलिस ने दोनों मामलों में विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।

एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में हुड्डा और वोरा को जमानत

जागरण संवाददाता, पंचकूला

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) प्लॉट आवंटन मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा को जमानत दे दी है। ईडी ने दोनों के खिलाफ इस साल अगस्त में एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत शिकायत दर्ज की थी। हुड्डा और वोरा बुधवार को अदालत में पेश हुए।

पिछली सुनवाई पर नियमित याचिका दाखिल करते हुए आरोपितों ने कहा था कि उन्होंने जांच एजेंसी के साथ पूरी तरह से सहयोग किया है और जांच के दौरान उनका आचरण पारदर्शी था। ईडी ने उन्हें मामले में मुख्य रूप से दस्तावेजी सुबूतों के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया, जो जांच एजेंसी के कब्जे में थे। उनके खिलाफ व्यक्तिगत संवर्धन का भी कोई आरोप नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। गौरतलब है कि एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पंचकूला स्थित विशेष अदालत ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोती लाल वोरा और नेशनल हेराल्ड को नोटिस जारी कर 30 अक्टूबर को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए थे। हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने 64.93 करोड़ रुपये का प्लॉट एजेएल को 69 लाख 39 हजार रुपये में दिया था। पंचकूला स्थित यह भूखंड सेक्टर 6 में सी-17 नंबर एजेएल को आवंटित किया गया था। इसे पिछले साल ईडी ने कुर्क कर लिया था। ईडी की जांच में पाया गया है कि मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए हुड्डा ने यह भूखंड पुनः आवंटन की आड़ में नए सिरे से एजेएल को 1982 की दर (91 रुपये प्रति वर्ग मीटर) और ब्याज के साथ फर्जी तरीके से आवंटित कर दिया। एजेंसी ने कहा था कि 2005 में इस पुनः आवंटन से एजेएल को अनुचित फायदा हुआ। ईडी के मुताबिक, इस भूखंड का बाजार मूल्य 64.93 करोड़ रुपये था, जबकि इसे हुड्डा को 69.39 लाख रुपये में आवंटित कर दिया था

1608 से 1611 के बीच अयोध्या आए विदेशी यात्री विलियम फिंच ने कहा था कि वहां एक जगह रामचंद्र का किला है, जिसे उनका जन्मस्थान माना जाता है। इस बारे में दूसरा दस्तावेज 1766 से 1771 के बीच आस्ट्रेलियन यात्री टिफिनथेलर का हैं। जिसमें विवादित भूमि का जिक्र है।

अयोध्या के संभावित फैसले के चलते भोपाल में एक पर रासुका, 27 जिलाबदर

नईदुनिया, भोपाल : अयोध्या मामले में फैसला आने से पहले भोपाल में अमन और शांति कायम करने के लिए कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने एक अपराधी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की है। 27 अपराधियों को तीन माह के लिए जिलाबदर कर दिया है। जिलाबदर अपराधी को भोपाल और आसपास के जिले होशंगाबाद, सीहोर, विदिशा, राजगढ़ व रायसेन की सीमाओं से भी बाहर जाने के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर ने बताया कि मनीष भदौरिया थाना टीटी नगर के खिलाफ 22 से ज्यादा अपराध दर्ज हैं। इनमें मकान जलाने, हत्या की कोशिश सहित अन्य गंभीर अपराध हैं। इसके चलते रासुका के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। उधर, शहर में धारा 144 लगा दी गई है, वहीं संवेदनशील स्थानों को चिह्नित कर अपराधियों के खिलाफ बांड ओवर की कार्रवाई भी की जा रही है।

अयोध्या में बनाई जा रहीं अस्थायी जेलें

रविप्रकाश श्रीवास्तव, अयोध्या : असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए अस्थायी जेलें बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। प्रशासन और पुलिस ने इसके लिए अब तक 12 स्थान चिह्नित किए हैं। इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम को भी अस्थायी जेल बनाया जाना प्रस्तावित है। स्टेडियम की क्षमता दस हजार से अधिक लोगों को समाहित करने की है। यह सबसे बड़ी अस्थायी जेल होगी, जिसकी सुरक्षा के लिए अभी से ही पुलिसकर्मी निगरानी में लगा दिए गए हैं। मंडल कारागार की क्षमता कम होने की वजह से अस्थायी जेलें बनवाई जा रही हैं। अस्थायी जेलों को सुप्रीम फैसले के सिक्योरिटी प्लान में शामिल किया गया है। सिक्योरिटी प्लान में उत्तेजक भीड़ को नियंत्रित करने पर खास ध्यान दिया गया है।

डीडीसी की कमेटी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगी

जागरण संवाददाता, अयोध्या : मंदिर-मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट से आने वाले फैसले का अध्ययन छह सदस्यीय कमेटी करेगी। डीएम अनुज कुमार झा ने उप संचालक चकबंदी तरुण कुमार मिश्र की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। छह सदस्यीय कमेटी में डीडीसी चकबंदी के अलावा संयुक्त निदेशक अभियोजन, जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) अनिल अग्रवाल, जिला शासकीय अधिवक्ता दीवानी रामकुमार राय, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामकृष्ण तिवारी व चकबंदी अधिकारी राकेश खन्ना शामिल हैं। यही कमेटी डीएम को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्रियान्वयन के लिए विधिक राय देगी। फैसला आने के बाद यह कमेटी स्वत: प्रभावी हो जाएगी। बताते हैं कि डीएम कमेटी के साथ एक बैठक भी कर चुके हैं।

मंदिर तोड़कर बनाई गई थी मस्जिद

कानून की कसौटी ▸ हाई कोर्ट के फैसले में इस निष्कर्ष का आधार एएसआइ की रिपोर्ट थी

तीन में से दो जजों ने कहा था-मस्जिद बनाने में मंदिर के अवशेषों का प्रयोग हुआ था

माला दीक्षित, नई दिल्ली

राम जन्मभूमि मुकदमे में विवाद का एक मूल बिंदु है कि क्या मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद का निर्माण किया गया था। इस सवाल पर हाईकोर्ट का बहुमत का फैसला था कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ था। फैसला देने वाले तीन में से दो न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल और धर्मवीर शर्मा इसी मत के थे। दोनों न्यायाधीशों के इस निष्कर्ष का आधार एएसआइ की रिपोर्ट थी। हालांकि तीसरे न्यायाधीश एसयू खान ने इससे इन्कार करते हुए कहा था कि मस्जिद बनाने के लिए कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया था, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि मस्जिद का निर्माण लंबे समय से वहां पड़े मंदिर के भग्नावशेषों पर हुआ था और मस्जिद के निर्माण में उन अवशेषों की कुछ सामग्री का उपयोग हुआ था। हिंदू पक्षों ने अपनी दलील के समर्थन में ऐतिहासिक साक्ष्य, धर्मशास्त्र, सरकारी गैजेटियर और विदेशी यात्रियों के वर्णन को आधार बनाया था लेकिन बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआइ ने विवादित स्थल की खोदाई करके रिपोर्ट भी दे दी थी। हाईकोर्ट ने एएसआइ से पता लगाने को कहा था कि क्या विवादित स्थल पर पहले कोई मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। एएसआइ ने रिपोर्ट में कहा था कि विवादित स्थल के नीचे एक विशाल संरचना मिली है जो कि उत्तर भारत के मंदिरों से मेल खाती है। उन तथ्यों के आधार पर ही जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने अपने फैसले में कहा था कि एएसआइ रिपोर्ट में इस बात का पर्याप्त संकेत मिलता है कि विवादित ढांचे की अपनी कोई नींव नहीं थी बल्कि वह पहले से मौजूद दीवार पर खड़ा था। अगर किसी नई इमारत के निर्माण से पहले कोई इमारत मौजूद नहीं होती तो नई इमारत बनाने वाला यह जाने बगैर पुरानी इमारत की नींव इस्तेमाल नहीं कर सकता कि पुरानी नींव नए ढांचे का बोझ उठाने की क्षमता रखती है कि नहीं। जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि विवादित इमारत की फर्श ठीक पूर्व इमारत की फर्श के ऊपर थी। वहां कई खंभों के आधारों की मौजूदगी, यह सब मिलकर साबित करती हैं कि वहां पहले एक बढ़ा ढांचा मौजूद था। जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि हिंदू मंदिर तोड़कर विवादित ढांचे का निर्माण किए जाने का हिंदुओं का दावा विश्वास और भरोसे लायक है। आज तक हिंदुओं को छोड़ कर और किसी धर्म के व्यक्ति ने भगवान राम का जन्मस्थान बताते हुए लगातार अपना दावा नहीं कायम रखा है।

इन आधारों पर निकाला निष्कर्ष

- विवादित ढांचा खाली पड़ी या बगैर कब्जे वाली जमीन पर नहीं बना था।
- विवादित स्थल पर पहले से एक बड़ा ढांचा मौजूद था जो कि विवादित ढांचे से बहुत बड़ा नहीं तो भी उसके बराबर का रहा होगा।
- नए ढांचे का निर्माण करने वाले बिल्डर को पुराने ढांचे के बारे में मालूम था। वह उसकी मजबूती, क्षमता और दीवारों के आकार से परिचित था। इसीलिए उसे बिना कोई रद्दोबदल किए हुए पुरानी दीवार का प्रयोग करने में संकोच नहीं हुआ।
- पुराना ढांचा धार्मिक इमारत थी और वह गैर इस्लामिक इमारत थी।
- विवादित ढांचे के निर्माण में पुरानी इमारत की ईंटे, पत्थर और खंभे इस्तेमाल किये गए थे।
- खोदाई में प्राप्त कलाकृतियां ज्यादातर गैर इस्लामिक हैं।

अयोध्या धाम के कण-कण में तलाश रहे 'राम'

चौदह और पंचकोसी परिक्रमा के लिए देशभर से लोग अयोध्या में जुटे हैं। बुधवार को रामनगरी का नजारा आम वर्षों से बिल्कुल अलग दिखा। श्रद्धालुओं का रुख मंदिर निर्माण कार्यशाला की ओर ज्यादा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनकी निगाहें शिलाओं में भी श्रीराम को तलाश रही हैं। जीतू निषाद

रमाशरण अवस्थी, अयोध्या

श्रद्धालुओं के दल में शामिल श्रावस्ती के किसान विक्रमादित्य सिंह मंदिर के मॉडल के बगल में तराशे जा चुके उन स्तंभों को निहारते हैं, जिन्हें प्रस्तावित मंदिर में लगना है। स्तंभों में उत्कीर्ण अनावृत मूर्तियों को देखकर रोमांचित हो उठते हैं। हालांकि अगले पल उनकी दुविधा का निराकरण होता है, जब वह सुनते हैं कि ये मूर्तियां यक्ष-यक्षणियों की हैं।

चूंकि, लोगों के दिल में तो बस राम बसे हैं। लिहाजा, तुरंत सवाल आता है-रामलला कहां विराजमान होंगे। तब तक कार्यशाला में पहुंच चुके युवा उद्यमी और स्थानीय भाजपा नेता मनप्रीत सिंह मॉडल के सबसे पीछे स्थित कक्ष की अनुकृति की ओर इशारा करते हुए बताते हैं- प्रथम तल के गर्भगृह में रामलला और दूसरे तल पर रामदरबार की स्थापना होनी है। विक्रमादित्य को जैसे सारे सवालों के जवाब मिल गए और जय सियाराम बुदबुदाते हुए आगे बढ़ जाते हैं...। श्रीराम की नगरी अयोध्या में चौदह कोसी परिक्रमा समाप्त होते ही बुधवार को पंच कोसी परिक्रमा का पहला दिन था।

यहीं पर राम नाम के मतवालों की भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस के साथ ही युवा भाजपा नेता आकाशमणि भी जुटे हैं। मकसद सिर्फ एक ही है, किसी की श्रद्धा को न लगने पाए चोट। लोगों के उत्साह से गदगद भी हैं। कहते हैं-14 कोसी परिक्रमा थमने के बाद परिधि से वापस लौटे श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ गया है। प्रमुख मंदिरों के साथ श्रद्धालुओं की भावनाओं का ज्वार कार्यशाला में उमड़ेगा, यह अनुमान पहले से था। लेकिन इस कदर...यह साबित करता है कि फैसले के इंतजार में भावनाएं किस तरह हिलोरें मार रही हैं।

सबसे बड़े विवाद की प्रतीक्षा भी श्रद्धालुओं के चेहरे पर साफ पढ़ी जा सकती है। यह सच्चाई रामघाट स्थित मंदिर निर्माण कार्यशाला में तराशी जा रही शिलाओं से बयां होती है। आम दिनों की अपेक्षा कार्यशाला में बुधवार को श्रद्धालुओं की 10 गुना अधिक भीड़ नजर आती है। वे शिलाओं को हसरत भरी निगाहों से निहार ही रहे नहीं होते हैं, बल्कि उनमें श्रद्धापूर्वक स्पर्श करने की ललक और होड़ सी मची है। कार्यशाला में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में कुछ ऐसे भी होते हैं, जो यह जानना चाहते हैं कि प्रस्तावित मंदिर किस तरह का होगा। अगले पल ही उनका उत्साह सातवें आसमान पर होता है, जब एक स्थानीय गाइड उन्हें प्रस्तावित मंदिर के मॉडल के आगे ले जाकर खड़ा करता है।

वे अकेले नहीं हैं। इस साध को पूरी करने की लालसा में भावनाओं का ज्वार पूरे उफान पर है। नगरी का बड़ा हिस्सा श्रद्धालुओं के प्रवाह से पटा है। कुछ जत्थे ऐसे भी गुजरते हैं, जिनके हाथों में भगवा और तिरंगा झंडा है। ऐसे ही जत्थे में शामिल गोरखपुर के राजाराम निषाद कहते हैं- हम राममंदिर के साथ राष्ट्रमंदिर के भी उपासक हैं। पूरे संयम से फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उन्हीं के बगल चल रहे शिखाधारी विवेक शुक्ल कहते हैं कि हमारी साधना जाया नहीं जाएगी। फैसला अनुकूल आएगा।

फैसले का इंतजार श्रद्धालुओं को ही नहीं, उनकी आवभगत करने वालों को भी उत्साहित कर रहा है। इस अहम दौर में परिक्रमा करने वालों को स्वादिष्ट भोजन मिल सके, इसके लिए अग्रवाल समाज की ओर से सआदतगंज हनुमानगढ़ी पर भव्य सेवा शिविर लगाया गया। इस दौरान एक लाख परिक्रमा करने वालों को भोजन भी कराया गया। मान्यताओं के मुताबिक चौदह कोसी परिक्रमा का संबंध भगवान श्रीराम के चौदह वर्ष के वनवास से बताया जाता है।

▸ रामघाट स्थित मंदिर निर्माण कार्यशाला में श्रद्धालुओं की 10 गुना अधिक भीड़

14 कोसी परिक्रमा समाप्त होते ही आस्था मंदिरों की ओर उन्मुख

राममंदिर पर फैसला जो भी हो देश में अमन जरूरी : मदनी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : राम जन्मभूमि मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की संभावनाओं के बीच अमन-शांति बनाए रखने को लेकर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ देश का प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत-उलेमा-ए-हिंद भी आगे आया है। जमीयत ने लोगों से कोर्ट के फैसले को मानने और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। बुधवार को कांस्टीट्यूशन क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जमीयत के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि देश में शांति और अमन बना रहे, इसे लेकर वह केंद्र सरकार और संघ के साथ हैं। यह मुल्क हमारा है। कानून हमारा है और सुप्रीम कोर्ट हमारा है। इसलिए हम उसके किसी भी फैसले का सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा कि इसको लेकर हमारी सर संघचालक मोहन भागवत से मुलाकात हुई थी और आगे भी होगी। सब कुछ ठीक रहा तो वे दोनों एक मंच पर भी आएंगे। मदनी ने कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर जमीयत अपना दावा नहीं छोड़ने वाला है। वहां 400 साल से मस्जिद थी और कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। वह देश के कानून का सम्मान करते हैं। इसलिए मस्जिद की लड़ाई सड़क पर नहीं लड़ी, बल्कि कोर्ट में गए। ऐसे में अब ऐतिहासिक तथ्यों, सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर जो भी कानूनी फैसला आएगा, उसका सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा कि जमीयत आजादी के पहले से देश में एकता का हिमायती रहा है और इस दिशा में तब से लगा हुआ है। यहां सभी मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम इस एकता को बनाए रखें। उन्होंने कहा कि वह एनआरसी के विरोध में नहीं हैं। पर धार्मिक आधार पर भेदभाव न हो।

अमन का पैगाम ले दलों के द्वार पर जा रहा संघ

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली

▸ मुस्लिम संगठनों के साथ देशभर के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं संघ के पदाधिकारी

▸ राज्यों के मुख्यमंत्रियों और क्षेत्रीय दलों के प्रभावी नेताओं से भी की जा रही मुलाकात

अयोध्या में राममंदिर निर्माण को लेकर आंदोलन करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने अपने लक्ष्य को वृहद कर लिया है। वह पूरी शिद्दत के साथ देश में सौहार्द बनाए रखने के अभियान में जुटा है। पूरी कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद देश में गंगा-यमुना तहजीब का ताना-बाना न बिगड़े। इसलिए संघ का मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ ही राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकातों का क्रम जारी है। इसके लिए वरिष्ठ पदाधिकारी कांग्रेस समेत अन्य दलों के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्रियों और राज्यों में प्रभावी नेताओं से भी मिल रहे हैं।

फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों से संघ ने अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो भी फैसला सुनाए उसे खुले मन से स्वीकार करें। उसने स्वयंसेवकों को स्पष्ट संदेश दिया है कि फैसले के बाद न कोई जुलूस निकलना चाहिए न प्रदर्शन होना चाहिए। संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि इन मुलाकातों में राममंदिर पर आने वाले फैसले पर संयमित व्यवहार की अपील की जा रही है।

संघ पदाधिकारी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसे दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। हालांकि संघ परिवार पर हमलावर गांधी परिवार से मिलने से परहेज किया गया है, पर उनके नजदीकी नेताओं से मुलाकात का क्रम जारी है। इन मेल-मुलाकातों में संघ के अनुषांगिक संगठनों के लोग भी लगे हैं।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के आवास पर मंगलवार को एक अहम बैठक हुई, जिसमें संघ के सह सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल, अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख रामलाल, भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन के साथ साथ जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के महासचिव महमूद मदनी, शिया धर्म गुरु कल्बे जव्वाद, अजमेर शरीफ के अध्यक्ष मोईनुद्दीन चिश्ती समेत अन्य शामिल थे।

समाज में सद्भाव बनाए रखने को लेकर ही छतरपुर में तीन दिनों तक संघ परिवार की चली शीर्ष बैठक में इसे लेकर व्यापक रणनीति तय की गई। इस बैठक में सर संघचालक मोहन भागवत, संघ व आनुषांगिक संगठनों के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा केंद्रीय गृहमंत्री व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल हुए थे। बैठक में समाज में प्रभावी हर वर्ग से मिलने का खाका तैयार किया गया है।

फिर चर्चा में मीर बाकी की मजार

आनंदमोहन, अयोध्या : रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के केंद्र में रहे मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी की मजार कहीं और नहीं अयोध्या के निकट सहनवा गांव में है। अब जबकि इस मसले का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आने को है, यह गांव और मजार भी चर्चा में है।

सहनवां गांव पूराबाजार ब्लॉक की ग्राम पंचायत है। जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी मजार देखने से यह नहीं लगता कि ये उसी मीर बाकी की है, जिसकी वजह से पांच सौ वर्ष पुराना विवाद देश झेल रहा है। यहां के निवासी अधिवक्ता रजी हसन अपने कुनबे का सजरा मीर बाकी की बेटी से जोड़ते हैं। सुबूत में सजरा 1528 से 2017 तक का दिखाते हैं, जिसमें उनका नाम भी है। यही नहीं, 28 दिसंबर 1990 को नबी हसन (पिता) के नाम आए पत्र को भी सुबूत के तौर पर दिखाने से नहीं चूकते। अधिवक्ता रजी हसन के पिता अब नहीं हैं। यह पत्र आल इंडिया शिया कांफ्रेंस के प्रेसीडेंट अंजुम कदीर का है, जिन्हें विवाद के समाधान के लिए आयोजित कांफ्रेंस में बुलाया गया था। यह कांफ्रेस 12 जनवरी 1991 को अशोका होटल नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। कांफ्रेंस के लिए आए पत्र में जस्टिस से लेकर विभिन्न क्षेत्रों के तमाम नामचीनों का नाम है।

अधिवक्ता रजी इसी आधार पर बाबर के सेनापति मीर बाकी का नाम सहनवां से जोड़ते हैं। वह दावा करते है कि अयोध्या विवाद पर पुस्तक लिखने के लिए बिहार धर्मादा बोर्ड ट्रस्ट के चेयरमैन किशोर कुणाल भी आ चुके हैं। उनसे मिलकर मजार का सच जानने के लिए कई सवाल भी किए थे। ग्राम प्रधान अंसार अहमद भी बताते हैं कि बाबर के सेनापति मीर बाकी की मजार होने की अक्सर चर्चा होती है।

राम रहीम की राजदार हनीप्रीत आई सलाखों के बाहर

जागरण संवाददाता, पंचकूला

▸ राजद्रोह की धारा निरस्त होने के बाद मिली जमानत

▸ पंचकूला हिंसा मामले में अंबाला सेंट्रल जेल में थी बंद

▸ एक लाख रुपये के मुचलके पर छोड़ा गया है

अंबाला सेंट्रल जेल से कार में बैठकर जाती हनीप्रीत। जागरण

कुछ दिन पहले राजद्रोह की धाराओं को अदालत द्वारा निरस्त किए जाने के बाद डेरा सच्चा सौदा, सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की कथित दत्तक पुत्री हनीप्रीत की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को स्वीकार कर ली। हनीप्रीत की तरफ से लगभग चार बजे यह आदेश पंचकूला के मुख्य न्यायिक अधिकारी के समक्ष में पेश किए गए और लगभग छह बजे वह अंबाला केंद्रीय जेल से छूटकर बाहर आ गई। हनीप्रीत को एक लाख रुपये के मुचलके पर छोड़ा गया है।

हनीप्रीत को जमानत मिलने के बाद अन्य आरोपितों को भी जल्द ही जमानत मिलने की उम्मीद है। अब हनीप्रीत और बाकी आरोपितों पर 145 (गैरकानूनी तौर पर एकत्र होना), 146 (बलवा करना), 150 (अवैध तौर पर लोगों को एक जगह बुलाना), 151 (पांच या इससे अधिक व्यक्तियों को एकत्र करके बलवा करने के लिए कहना), 152 (लोकसेवक उपद्रव रोकने का प्रयास कर रहा हो तो हमला करना या बाधा पैदा करना) 153 (दंगा भडक़ाने के लिए उकसाना) के तहत केस चलेगा। इन सबमें सात साल से कम सजा का प्रावधान है।

बता दें कि 2 नवंबर को बचाव पक्ष एवं अभियोजन पक्ष के बीच आरोपों पर बहस खत्म होने के बाद अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ने हनीप्रीत को राजद्रोह की धारा 121 (सरकार के खिलाफ युद्ध की कोशिश) और 121ए (अपराधिक षड्यंत्र) से मुक्त कर दिया था। इसके बाद स्पष्ट हो गया था कि अगली सुनवाई पर हनीप्रीत को जमानत मिल जाएगी।

बचाव पक्ष के वकील आरएस चौहान ने बताया कि जमानत के लिए अदालत ने कोई शर्त नहीं रखी है। हनीप्रीत की ओर से जमानत याचिका में कहा गया था कि 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में जब हिंसा हो रही थी, तब वह डेरा प्रमुख गुरमीत के साथ थी। वह उनके साथ हेलीकाप्टर से पंचकूला से सीधा सुनारिया जेल रोहतक चली गई। हिंसा में उसका कहीं कोई रोल नहीं है। उसे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, वह खुद 3 अक्टूबर 2017 को समर्पण करने के लिए आ गई थी। पुलिस द्वारा उससे कोई रिकवरी भी नहीं की गई। उससे ऐसा सामान भी नहीं मिला, जिसका हिंसा के लिए उपयोग किया गया हो। उसका नाम भी एफआइआर में बाद जोड़ दिया गया।

दैनिक जागरण को राष्ट्रीय उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार

जासं, नई दिल्ली : ग्रामीण पत्रकारिता में उत्कृष्ट आयाम प्रस्तुत करने के लिए दैनिक जागरण को भारतीय प्रेस परिषद (प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया) ने राष्ट्रीय उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार-2019 (नेशनल अवाड्र्स फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म) से नवाजा है। बुधवार को इस अति प्रतिष्ठित पुरस्कार की घोषणा की गई। मिनी चंबल घाटी के नाम से चर्चित बुंदेलखंड (उप्र) के 'पाठा' क्षेत्र की बदहाली को सामने लाने वाली दैनिक जागरण की सार्थक रिपोर्टिंग इस पुरस्कार का आधार बनी, जिसके लिए जागरण संवाददाता शिव स्वरूप अवस्थी को उत्कृष्ट ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। शिव स्वरूप चित्रकूट (उप्र) में दैनिक जागरण के वरिष्ठ संवाददाता हैं। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

शिव स्वरूप अवस्थी।

बोकारो में चोरी करते पकड़े गए दो युवक, एक की पीटकर हत्या

जागरण संवाददाता, बोकारो

▸ पुलिस ने महिला समेत पांच लोगों को किया गिरफ्तार

▸ दूसरा युवक गंभीर घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती

झारखंड के बोकारो जिले की सीसीएल गोविंदपुर कॉलोनी में मंगलवार की रात बाइक-कार सर्विस सेंटर से चोरी के आरोप में दो लोगों को पकड़कर उन्मादी भीड़ ने जमकर पीटा। इस घटना में मुबारक अंसारी (45) की मौत हो गई वहीं अख्तर अंसारी (30) बुरी तरह जख्मी हुआ है। घायल अख्तर अंसारी के बयान पर सर्विस सेंटर के मालिक व एक महिला समेत पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों युवकों को हेमलाल महतो के सर्विस सेंटर से मोटर पंप व कार की बैट्री चोरी करते कॉलोनी के युवकों ने पकड़ा था। कुछ देर में ही यह खबर फैल गई और लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान दोनों युवकों के हाथ-पैर रस्सी से बांधकर पीटा गया। पिटाई से मुबारक अंसारी ने दम तोड़ दिया। घायल अख्तर अंसारी को बोकारो थर्मल स्थित डीवीसी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। वहां से बोकारो जेनरल अस्पताल रेफर कर दिया गया।

सर्विस सेंटर के मालिक हेमलाल महतो ने बताया कि नई बस्ती के मुबारक अंसारी एवं अख्तर अंसारी चोरी करने के इरादे से सेंटर में घुसे थे। वे एक गाड़ी से बैट्री और गाड़ी धोने के लिए इस्तेमाल होने वाला पंप खोल रहे थे। इस दौरान हो रही आवाज सुनकर वह जाग गए। चोरों को देखकर शोर मचाया तो कई लोग आ गए। उन लोगों ने दोनों को पकड़ लिया था। इधर स्थानीय लोगों ने बताया कि कॉलोनी के कुछ लोगों और सर्विस सेंटर के मालिक ने पास में ही एक खंभे के सहारे दोनों के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए।

उसके बाद उनकी पिटाई शुरू कर दी गई। इस बीच किसी ने पुलिस को सुचना दी। पुलिस ने उन्मादी भीड़ से दोनों को मुक्त कराया गया। उनको डीवीसी अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सकों ने मुबारक अंसारी को मृत घोषित कर दिया।

पुलिसकर्मियों की पेंशन व अनुकंपा नियुक्ति पर सुनवाई को सहमत सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सरकारी कर्मचारियों की तरह ड्यूटी के दौरान मरने वाले पुलिसकर्मियों की पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति के मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 13 नवंबर को सुनवाई की तारीख तय की है।

एक पुलिस अधिकारी की विधवा की तरफ से पेश हुए वकील एमएल शर्मा ने मामले की तत्काल सुनवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि पुलिसकर्मी की मौत को सरकारी कर्मचारी की तरह नहीं मानना, उसके साथ अन्याय है। याचिका में कहा गया है कि अगर पुलिस नहीं हो तो मंत्री और समाज ही नहीं कोर्ट भी कानून- व्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर सकता है। याचिका में कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत हो जाने पर उसके परिवार को पूरी पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति देकर पुरस्कृत किया जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस कानून-व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उसे यह हक मिलना चाहिए।

चिन्मयानंद प्रकरण में ब्लैकमेलिंग भाजपा नेताओं की साजिश

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर

भाजपा नेता डीपीएस राठौर (बाएं) और भाजयुमो के पूर्व जिला महामंत्री अजीत सिंह। फेसबुक

एसआइटी ने दोनों मामलों की जांच की है। वह चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। इसलिए मुझे इस प्रकरण में कुछ नहीं कहना है। अब आगे की कार्रवाई कोर्ट तय करेगी।

-जेपीएस राठौर, अध्यक्ष राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

मुमुक्ष आश्रम में डीपी का था आना-जाना

चिन्मयानंद 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही फिर से सक्रिय हो गए थे। मुख्यमंत्री भी मुमुक्षु आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। चिन्मयानंद का करीबी होने के कारण डीपी सिंह राठौर का आश्रम में आना-जाना रहता था। प्रकरण में जब एसआइटी ने चिन्मयानंद से पूछताछ की, तभी उन्होंने डीपी सिंह राठौर का नाम भी बता दिया था। जिसके बाद तथ्य जुटाए गए और उन्हें आरोपित बना लिया गया।

अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार में गृह राज्य मंत्री रह चुके चिन्मयानंद से जुड़े प्रकरण में पर्दे के पीछे भाजपा नेताओं ने बड़ा खेल किया। एसआइटी ने जांच की तो ऐसे चेहरे सामने आए, जिन्हें चिन्मयानंद का करीबी कहा जाता था। इन्हीं लोगों ने छात्रा से वीडियो हासिल किए और चिन्मयानंद से सवा करोड़ रुपये की मांग की। तर्क दिया कि रुपये दे दें तो सबकुछ रफा-दफा करा दिया जाएगा।

पर्दे के पीछे ब्लैकमेलिंग का खेल करने वाले ये दो चेहरे हैं- जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन डीपीएस राठौर और अजीत सिंह। डीपीएस राठौर खुद तो कद्दावर हैं ही, वह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर के भाई भी हैं। वहीं अजीत भाजयुमो का जिला महामंत्री रह चुका है। चिन्मयानंद का वह भी करीबी रहा।

वीडियो वायरल होने के बाद छात्रा के संपर्क में रहे : 24 अगस्त को छात्रा ने चिन्मयानंद के वीडियो वायरल किए और दोस्त संजय के साथ राजस्थान के दौसा चली गई। प्रकरण चर्चा में आया, तभी से डीपीएस राठौर छात्रा के संपर्क में आ गए थे। 30 अगस्त को जब एसआइटी ने छात्रा व संजय को दौसा से बरामद किया, उस समय छात्रा ने वहां पहुंचे डीपीएस राठौर व अजीत को वीडियो क्लिप वाली पेन ड्राइव सौंप दी थी। हालांकि चोरी छिपे उसकी एक कॉपी अपने पास भी रख ली थी। डीपीएस राठौर ने उसी वीडियो क्लिप का हवाला देकर चिन्मयानंद से सवा करोड़ रुपये मांगे थे। हालांकि तब तक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था, एसआइटी गठित हो गई। जिसके बाद सौदेबाजी नहीं हो सकी।

चिन्मयानंद ने कहा था, करीबियों का खेल : जब सवा करोड़ मांगने का मामला आया तब चार सितंबर को चिन्मयानंद ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि पूरे प्रकरण में उन्हें बदनाम करने के लिए कुछ अपने ही शामिल हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था।

भाजपा ने किया था किनारा मगर खुद पार्टी के लोग ही शामिल : जब चिन्मयानंद पर दुष्कर्म के आरोप लगे तब भाजपा ने उन्हें अपना सदस्य न बताकर पल्ला झाड़ लिया था। जब एसआइटी की जांच और ब्लैकमेलिंग में भाजपा के ही नेताओं के नाम सामने आए तो जवाब देते नहीं बन रहा। चार्जशीट लगने के बाद से जिले से लेकर हाईकमान तक खलबली मची है। भाजपाइयों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। मामले की शुरुआत में चिन्मयानंद की ओर से भी मुख्यमंत्री तक जानकारी पहुंचाई गई थी कि साजिश में पार्टी के ही कुछ लोग शामिल हैं।

प्रदेश उपाध्यक्ष के भाई का मामला, पार्टी चुप्पी साधे रही : डीपीएस राठौर भाजयुमो के जिलाध्यक्ष, भाजपा के जिला महामंत्री समेत पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। उनके बड़े भाई जेपीएस राठौर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष होने के साथ ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। माना जा रहा है कि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले बड़े भाई की सलाह लेने वाले डीपीएस राठौर के इस कदम की जानकारी कहीं न कहीं जेपीएस को भी दी होगी। लेकिन, एसआइटी जांच के बाद बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। मामला भाजपा नेताओं से जुड़ा होने के चलते स्थानीय नेता चुप्पी साधे रहे। कहा जा रहा है कि छात्रा का दोस्त संजय व अन्य आरोपित भारतीय जनता युवा मोर्चा के ही पू

करतारपुर : कड़वाहट के बीच सद्भाव की मिठास

लाहौर बस सेवा शुरू होने के 20 साल बाद अब कॉरिडोर के जरिये भारत-पाक में बेहतर रिश्तों की उम्मीद

इंद्रप्रीत सिंह • चंडीगढ़

'हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।' दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां 20 साल पहले फरवरी 1999 में दिल्ली-लाहौर बस सेवा 'सदा-ए-सरहद' शुरू करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पढ़ी थीं। कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच नए संबंधों की शुरुआत होने जा रही है।

दरअसल, परमाणु परीक्षण के कारण उस समय दोनों देशों के रिश्तों में काफी कड़वाहट थी, पर 'सदा-ए-सरहद' एक उम्मीद की किरण बनी। अब भी वैसे ही हालात हैं। दोनों देशों ने बातचीत के दरवाजे बंद कर लिए हैं, पर करतारपुर कॉरिडोर के मुद्दे पर न केवल एक-दूसरे की सुन रहे हैं, बल्कि चिंताओं को दूर भी कर रहे हैं। कॉरिडोर को अंधेरे में रोशनदान खुलने की तरह देखा जा सकता है।

अरदास के बाद खुलेगा कॉरिडोर: करतारपुर गुरुद्वारा साहिब में जाकर दर्शन करना सिख श्रद्धालुओं का सपना था। करोड़ों लोग रोज उन गुरुधामों के खुले दर्शन की अरदास करते हैं, जो उनसे बिछुड़ चुके हैं। करतारपुर कॉरिडोर का खुलना उस अरदास के पूरा होने जैसा है। लोग चाहते हैं कि इससे सद्भाव का माहौल बने।

आसान नहीं रही राह: 18 अगस्त 2018 की बात है। पंजाब के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ समारोह में गए थे। वहां पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद ने सिद्धू से कहा कि सरकार करतारपुर कॉरिडोर को खोलने पर विचार कर रही है। भारत तो जैसे इंतजार में बैठा था। सरकार ने न केवल इसका स्वागत किया, बल्कि इस दिशा में कदम भी बढ़ा दिए। डेरा बाबा नानक में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (आइसीपी) बनाने का शिलान्यास उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने किया। भारत की पंजाब सरकार ने डेरा बाबा नानक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाकर क्षेत्र के विकास की शुरुआत कर दी है।

लोगों ने लंबा संघर्ष किया है कॉरिडोर को खुलवाने के लिए

करतारपुर कॉरिडोर बनाने का सुझाव सबसे पहले दिग्गज अकाली नेता कुलदीप सिंह वडाला ने दिया था। उन्होंने इसके लिए लंबा संघर्ष भी किया। स्व. कुलदीप सिंह वडाला के पुत्र और नकोदर से विधायक गुरप्रताप वडाला बताते हैं कि उनके पिता लगातार 18 सालों तक भारत-पाक सीमा पर बने डेरा बाबा नानक के गुरुद्वारा साहिब में जाकर अरदास करते रहे। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के दरवाजे भी खटखटाए। गुरुद्वारा करतारपुर साहिब दर्शन अभिलाषी संस्था भी बनाई। गुरुद्वारा साहिब को जाती सड़क को पक्का कराने के लिए दस एकड़ जमीन भी कब्जे से मुक्त कराई। वह अक्सर कहा करते थे कि मैं रहूं या न रहूं, कॉरिडोर हर हालत में बनेगा। करतारपुर कॉरिडोर के लिए संघर्ष करने वालों में बीएस गुराया भी शामिल हैं। उन्होंने करतारपुर लांघा नाम से एक संगठन बनाया। उनके प्रयासों के चलते ही कुलदीप वडाला ने इस मुद्दे को राजनीतिक मंचों पर उठाया। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान परमजीत सिंह सरना भी लगातार प्रयास करते रहे। उन्होंने पाकिस्तान की अथॉरिटी से भी बात की, लेकिन दोनों मुल्कों में तनाव के कारण विलंब होता रहा। गुरु नानक देव की 17वीं पीढ़ी के वंशज बाबा सरबजोत सिंह बेदी कहते हैं कि भारत को यह जमीन पाकिस्तान से दूसरी जमीन के बदले ले लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुसैनीवाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के समाधि स्थल का भी हस्तांतरण कराया गया था। विभाजन के समय ये समाधि स्थल पाकिस्तान की ओर चले गए थे।

गुरुद्वारा करतारपुर साहिब

कॉरिडोर के लिए कुलदीप सिंह वडाला ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के खटखटाए थे दरवाजे

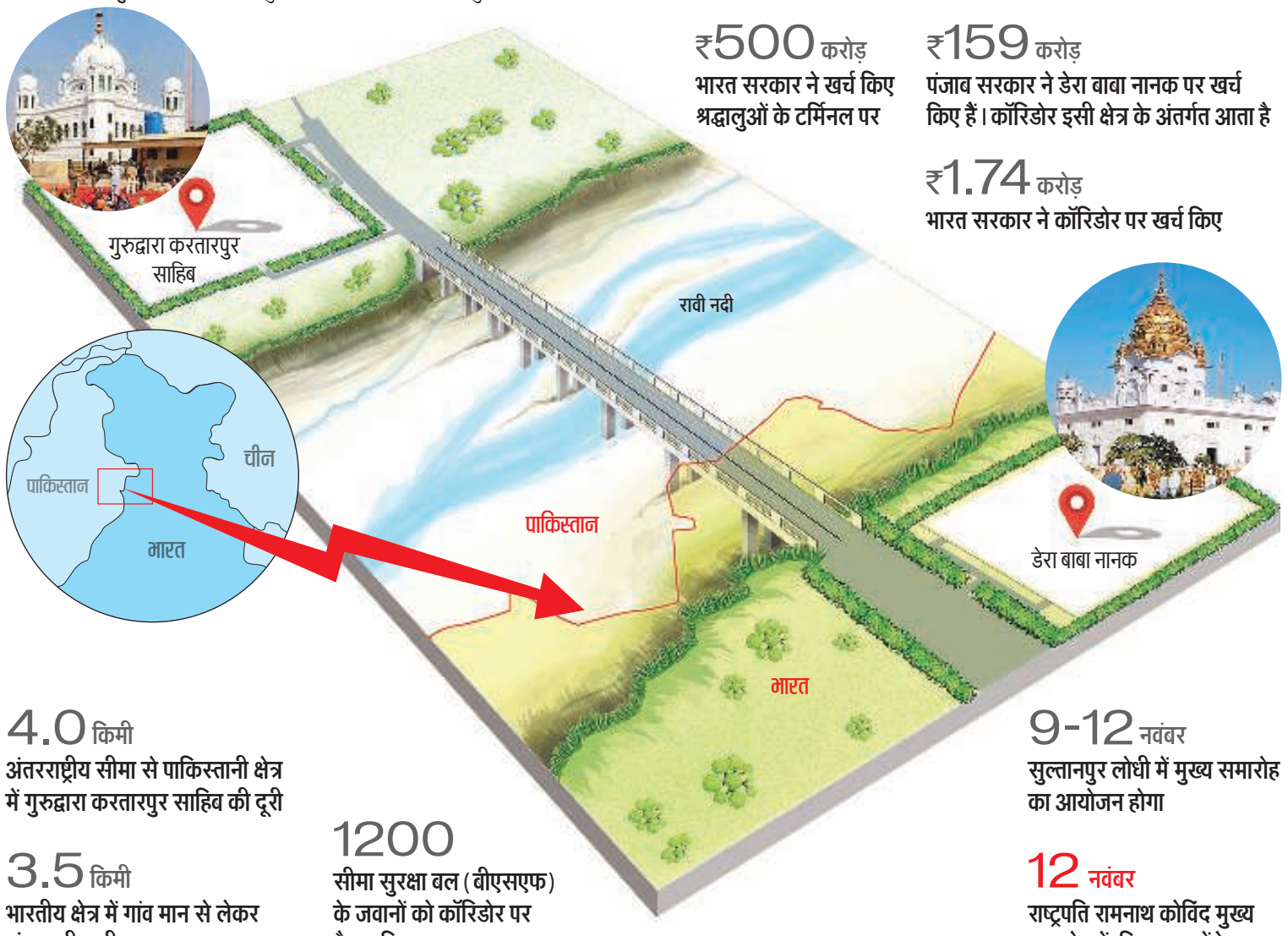

₹500 करोड़
भारत सरकार ने खर्च किए श्रद्धालुओं के टर्मिनल पर

₹159 करोड़
पंजाब सरकार ने डेरा बाबा नानक पर खर्च किए हैं। कॉरिडोर इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है

₹1.74 करोड़
भारत सरकार ने कॉरिडोर पर खर्च किए

4.0 किमी
अंतरराष्ट्रीय सीमा से पाकिस्तानी क्षेत्र में गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की दूरी

3.5 किमी
भारतीय क्षेत्र में गांव मान से लेकर अंतरराष्ट्रीय सीमा तक का दायरा

1200
सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों को कॉरिडोर पर तैनात किया जाएगा

9-12 नवंबर
सुल्तानपुर लोधी में मुख्य समारोह का आयोजन होगा

12 नवंबर
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य समारोह में शिरकत करेंगे

पर्यटन उद्योग को लगेंगे पंख

राजीव शर्मा • लुधियाना

भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर जमी बर्फ के बीच अगर दोनों देश करतारपुर कॉरिडोर खोलने को राजी हैं, तो इसके पीछे कारोबार की अच्छी संभावनाएं हैं। पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए प्रतिदिन हजारों लोग जाएंगे। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा हो रहे हैं। इससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

कॉरिडोर के खुलने पर रोजाना पांच हजार श्रद्धालु आएंगे। बाद में यह संख्या बढ़ा कर दस हजार प्रतिदिन करने की योजना है। ऐसा होने पर उद्योग जगत को कारोबारी संभावनाएं नजर आ रही हैं।

पारंपरिक उत्पादों को मिलेगा बाजार: यहां देश-विदेश से श्रद्धालुओं का आना होगा। ज्यादातर लोग अमृतसर एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से डेरा बाबा नानक के लिए जाएंगे। ऐसे में वहां पर टैक्सी कारोबार में काफी इजाफा होगा। इसके अलावा रेस्टोरेंट, ढाबे, गाइड सेवाओं के अलावा पंजाबी पारंपरिक उत्पादों का व्यापार भी विकसित होगा।

दोनों देशों के बीच सीधा कारोबार बंद: पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया और वहां से आयात होने वाले उत्पादों पर 200 फीसद ड्यूटी लगा दी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद-370 खत्म किए जाने पर पाकिस्तान ने द्विपक्षीय व्यापार पर लगाम लगा कर कारोबारी संबंध तोड़ लिए।

डेरा बाबा नानक में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होंगे। ऐसे में उनके खाने, रहने के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट की जरूरत होगी। साफ है कि इससे इलाके में नए-नए होटल एवं रेस्टोरेंट और ढाबे खुल रहे हैं। इससे कारोबारी विस्तार होगा। होटल कारोबारी भी इन संभावना को खंगालने में लगे हैं।

अमरवीर सिंह, अध्यक्ष, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ पंजाब

आपसी तल्खी के चलते भारत और पाक के बीच सीधा करोबार नाममात्र ही है। लेकिन, करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत होने से डेरा बाबा नानक में पर्यटन से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। इसके निर्माण से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है।

गुनबीर सिंह, पूर्व अध्यक्ष, पंजाब स्टेट काउंसिल, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज

कब-कितने का कारोबार: भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 2016-17 में पंद्रह हजार करोड़ का कारोबार हुआ था। वर्ष 2017-18 में 16,400 करोड़ रुपये और वर्ष 2018-19 में 18 हजार करोड़ का द्विपक्षीय कारोबार हुआ। इसमें भारत से पाकिस्तान को निर्यात अस्सी फीसद एवं पाक से आयात बीस फीसद था। यहां से केमिकल, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, रबर, सब्जियां, मशीनरी पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल उत्पाद आदि भेजे जाते थे। पाकिस्तान से मिनरल उत्पाद, सब्जियां, लेदर, केमिकल एवं टेक्सटाइल आता था।

जनेऊ पहनने से इन्कार

हरनेक सिंह जैनपुरी, कपूरथला: सिखों के पहले गुरु श्री गुरुनानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा पर 1469 ई. को लाहौर के पश्चिम तलवंडी गांव में हुआ। अब यह स्थान 'ननकाना साहब' कहलाता है। पिता कालू और मां तृप्ता थीं। बचपन में ही उन्होंने जनेऊ पहनने से इन्कार कर महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने के लिए आवाज उठाई। 14 साल की आयु में बहन बेबे नानकी के पास सुल्तानपुर लोधी (कपूरथला) पहुंचे और इसी धरती को अपनी कर्म स्थली बनाया। यहां गुरुद्वारा संत घाट में प्रकट होकर मूल मंत्र 'एक ओंकार' का उच्चारण किया। यहीं पर उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बुनियाद रखी। गुरुद्वारा श्री बेर साहिब में गुरु जी 14 साल 9 महीने 13 दिन तक प्रभु की भक्ति में लीन रहे। इसी धरती से उन्होंने विश्व कल्याण के लिए पवित्र यात्राओं (उदासियों) का आगाज किया। उनका विवाह बटाला की माता सुलखणी से हुआ। उनसे दो बेटे श्री चंद और लखमी दास हुए। यहीं पर नवाब दौलत खां के मोदीखाना में 'तेरा-तेरा' का संदेश दिया। जीवन के अंतिम 18 साल उन्होंने पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब में बिताए। 1539 में श्री गुरु अंगद देव जी को गुरु की गद्दी सौंप कर ज्योति जोत समा गए।

यहां सिख समुदाय को किया था एकजुट

हृदय नारायण मिश्र • जालंधर

सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने करतारपुर साहिब में ही सिख समुदाय को एकजुट किया था। श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की नींव उन्होंने स्वयं संवत् 1522 में रखी थी। यहीं से लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। 1539 में ज्योति जोत समाने तक वह 18 साल यहां रहे थे। यहीं पर उन्होंने 'किरत करो, नाम जपो, वंड छको' (नाम जपें, मेहनत करें और बांटकर खाएं) का उपदेश दिया।

गुरु नानक देव जी के आने से पहले यहां की जमीन उपजाऊ नहीं थी। दुनी चंद नामक व्यक्ति ने सौ एकड़ जमीन उन्हें खेती के लिए दे दी। गुरु जी ने यहां खेती की तो फसलें लहलहाने लगीं और पैदावार काफी बढ़ गई। इसी अनाज से उन्होंने लंगर शुरू किया। बताते हैं कि उनके उपदेशों से प्रभावित होकर लोगों ने उन्हें गुरु का दर्जा दे दिया। गुरुद्वारा परिसर में तीन कुएं हैं। एक कुआं अंदर है जिसके बारे में माना जाता है कि यह गुरु नानक देव जी के समय से है। इस कुएं को लेकर श्रद्धालुओं में अगाध श्रद्धाभाव है। इसके पास ही एक बम का टुकड़ा भी सहेजकर शीशे में रखा गया है। बताया जाता है कि 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय यह बम कुएं में गिरा था और इस कारण यह इलाका तबाह होने से बच गया था। गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब की दूसरी मंजिल पर श्री दरबार साहिब स्थित है। यहीं पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सुशोभित हैं। यहां गुरु नानक देव जी की दो समाधियां हैं। एक सिखों और हिंदुओं ने मिलकर बनाई हैं जबकि दूसरी मुस्लिम समुदाय की तरफ से बनाई गई है, जहां वे सजदा करते हैं। दोनों धर्म के लोग सेवा करते हैं। सिख रूमाला साहिब बांधकर अंदर जाते हैं तो मुस्लिम टोपी पहन कर दर्शन करते हैं।

पटियाला के महाराजा ने कराया पुनर्निर्माण: श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा रावी नदी के पास स्थित है। नदी में आई बाढ़ की वजह से गुरुद्वारे को काफी नुकसान पहुंचा था। 1920 से 1929 के बीच पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह ने इसे फिर से बनवाया था। तब इस पर 1.36 लाख रुपये से ज्यादा खर्च आया था।

कहां है स्थित: करतारपुर का पवित्र गुरुद्वारा पाकिस्तान के नारोवाल जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। लाहौर से इसकी दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा से इसकी दूरी चार किलोमीटर है।

38 हजार मील की पैदल यात्राओं से दिया 'सरबत दा भला' का संदेश

हरनेक सिंह जैनपुरी • कपूरथला

तमाम समस्याओं से घिरे तत्कालीन समाज को जगाने के लिए श्री गुरु नानक देव जी ने 38 हजार मील की पैदल यात्रा कर चार उदासियां (पवित्र यात्राएं) की और दुनिया को सद्भावना और 'सरबत दा भला' का संदेश दिया। उन्होंने कर्म-कांड और जात-पात के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। श्री गुरु नानक देव ने दर्जनभर देशों के 248 प्रमुख नगरों का भ्रमण कर समाज के उत्थान के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए। भाई मर्दाना को साथ लेकर पहला प्रहार जाति बंधन पर किया। पहले चरण में 79, दूसरे में 75, तीसरे में 35 और चौथे में 59 स्थलों की यात्रा कर 'परमात्मा एक' का उपदेश दिया।

पहली उदासी

सफर की शुरुआत 1500 ई. में श्री गोइंदवाल साहिब (अमृतसर) के छांगा-मांगा के जंगलों से की। इसके बाद गुजरावालां होते हुए लाहौर पहुंचे। वहां से कुरुक्षेत्र, करनाल, हरिद्वार, दिल्ली आगरा, मथुरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, इलाहाबाद, प्रयाग, बनारस, छपरा, हाजीपुर, पटना से गया गए। वहां से भागलपुर, गुवाहाटी, इंफाल, अगरतला, ढाका, जबलपुर, चित्रकूट, सागर, भोपाल, धौलपुर, भरतपुर, जींद, कैथल होते हुए पांच साल बाद 1505 ई. में वापस सुल्तानपुर लोधी पहुंचे।

दूसरी उदासी

सुल्तानपुर लोधी की धरती से दूसरी उदासी 1506 ई. में शुरू की। सबसे पहले वह बठिंडा व सिरसा से होते हुए बीकानेर पहुंचे। वहा से जैसलमेर, जोधपुर, पुष्कर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उज्जैन, अहमदाबाद, बांसवाड़ा, इंदौर, होशंगाबाद, अमरावती, अकोला, बीदर, गोलकुंडा, हैदराबाद, विजयवाड़ा, तिरुपति, मद्रास, पुडुचेरी, तंजोर, तिरुचिरापल्ली, रामेश्वर, ट्रिकोमाली (श्रीलंका), त्रिवेंद्रम, कोचीन, कोयंबटूर, कालीकट, मैसूर, बेंगलुरु, गोवा, पुणे, मुंबई, सूरत, बड़ौदा, जूनागढ़, सोमनाथ, द्वारका, मुलतान, पाकपटन व तलवंडी होते हुए 1509 ई. को सुल्तानपुर लोधी वापस पहुंचे।

तीसरी उदासी

1514 ई. को तीसरी उदासी श्री करतापुर से कलानौर, कांगड़ा से होते हुए पालमपुर पहुंचे और वहा से चंबा, कुल्लू, मंडी, रिवालसर, रोपड़, देहरादून, मसूरी, गंगोत्री, बद्रीनाथ, अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, श्रीनगर, गोरखपुर, सीतामढ़ी, काठमांडू, मानसरोवर, लेह, ताशकंद, किश्तवाड़, भद्रवाह, वैष्णोदेवी, रियासी, जम्मू, होते हुए 1516 ई. को वापस करतारपुर पहुंचे।

चौथी उदासी

1518 ई. से अपनी चौथी उदासी करतारपुर से शुरू की और हैदराबाद, (सिंध), देवल (कराची), मक्का, जद्दा, मदीना, यरुशलम, दमिश्क, पाराचिनार (पेशावर) से होते हुए बगदाद पहुंचे। वहां से तेहरान, समरकंद, काबुल, कंधार, पेशावर से होकर वापस करतारपुर लौटे थे।

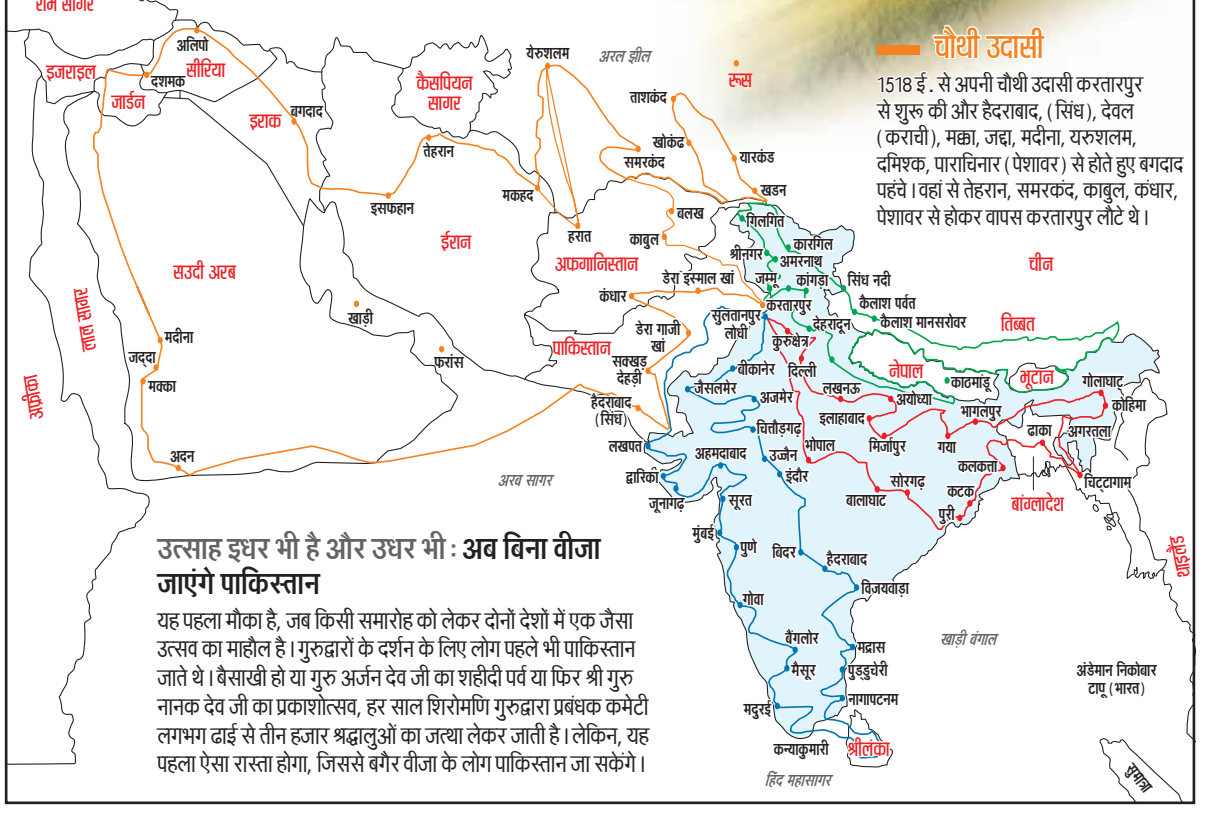

उत्साह इधर भी है और उधर भी : अब बिना वीजा जाएंगे पाकिस्तान

यह पहला मौका है, जब किसी समारोह को लेकर दोनों देशों में एक जैसा उत्सव का माहौल है। गुरुद्वारों के दर्शन के लिए लोग पहले भी पाकिस्तान जाते थे। बैसाखी हो या गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पर्व या फिर श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव, हर साल शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लगभग ढाई से तीन हजार श्रद्धालुओं का जत्था लेकर जाती है। लेकिन, यह पहला ऐसा रास्ता होगा, जिससे बगैर वीजा के लोग पाकिस्तान जा सकेंगे।

बंटवारे से लेकर अब तक, कब और क्या

14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ। इससे पहले जुलाई 1947 में बाउंड्री कमीशन बना और इसका चेयरमैन साइरिल रेडक्लिफ को बनाया गया। रेडक्लिफ ने करतारपुर पाकस्तिान के हिस्से में दे दिया।

1947 — पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की, तब कॉरिडोर नहीं बना था।

1971 — देश के विभाजन के दौरान गुरदासपुर जिला दो हिस्सों में बंट गया और गुरुद्वारा करतारपुर साहिब पाकिस्तान के नारोवाल जिले में चला गया।

पाकिस्तान के नारोवाल और भारत के गुरदासपुर को जोड़ने वाला रावी नदी पर बना पुल दोनों देशों के बीच हुई जंग में तबाह हो गया।

2000 — पाकिस्तान ने पहली बार भारतीय जत्थे को करतारपुर साहिब जाने की अनुमति दी।

2001 — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 9 नवंबर को कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इसी दिन इमरान खान भी अपने क्षेत्र में कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे।

2008 — तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने डेरा बाबा नानक का दौरा किया और फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने की बात कही।

2018 — 17 अगस्त को प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह के बाद पाक सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने नवजोत सिंह सिद्धू से बातचीत में मार्ग खोलने का भरोसा दिया।

- 7 सितंबर को पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कॉरिडोर खोलने की घोषणा की।
- भारत सरकार ने 22 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के 549वें प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा करतारपुर साहिब जाने के लिए कॉरिडोर बनाने का फैसला किया। इसके कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान सरकार ने भी अपने क्षेत्र में कॉरिडोर बनाने की घोषणा कर दी।
- भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 26 नवंबर को कॉरिडोर की आधारशिला रखी। इसके दो दिन बाद 28 नवंबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने क्षेत्र में इसके लिए आधारशिला रखी।

2019 — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 9 नवंबर को कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इसी दिन इमरान खान भी अपने क्षेत्र में कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे।

670 श्रद्धालु शामिल होंगे करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए रवाना होने वाले पहले जत्थे में। इस पहले जत्थे में बड़ी संख्या में विधायक, मंत्री भी शिरकत करेंगे। कॉरिडोर में निजी वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

सुल्तानपुर लोधी में पंगत के लिए सज गए लंगर

सेवा भाव की यह अद्भुत मिसाल है। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा था 'किरत करो, वंड छको'। यानी मेहनत करो और मिल बांट कर खाओ। उन्हीं की बाणी पर लंगरों की परंपरा शुरू हुई और आज उनकी कर्मस्थली सुल्तानपुर लोधी 550वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में विशालतम लंगरों की व्यवस्था कर रही है। पूरा शहर संगत के स्वागत की तैयारियों में एक महीने से जुटा है। मात्र 18 हजार आबादी वाले इस शहर में 70 से अधिक बड़े लंगर लग गए हैं, जहां एक समय में हजारों लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। इन लंगरों में पकवानों की भी कोई कमी नहीं। एक से एक बढ़कर लजीज व्यंजन। कहीं सरसों का साग व मक्की की रोटी, तो कहीं तंदूरी रोटी व मटर पनीर। पिज्जा से लेकर नूडल, बर्गर, समोसा भी है। एक अनुमान के मुताबिक रोज डेढ़ से दो लाख के करीब संगत यहां अभी से पहुंचने लगी है। सभी के लिए भोजन की व्यवस्था इन लंगरों में है। आने वाले दिनों में संगत के रोजाना पांच लाख से ज्यादा होने की उम्मीद है। लंगर स्थल पर सब्जियों व राशन के भंडार लग गए हैं। अकेले सुल्तानपुर लोधी में इतनी सब्जी पहुंच चुकी है जितनी किसी बड़े शहर की मंडी में भी नहीं पहुंचती। हर घर से बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सेवा भाव से लंगर तैयार करने में जुटे हैं। फोटोः पवन यादव

न्यूज गैलरी

एयर इंडिया विमान के शौचालय में मिला 2.24 करोड़ का सोना

चेन्नई : सीमा शुल्क अधिकारियों ने मंगलवार को दुबई से यहां पहुंचे एयर इंडिया के विमान से 2.24 करोड़ रुपये कीमत की लावारिस सोने की छड़ें जब्त कीं। इन्हें विमान के पिछले शौचालय में छिपाकर रखा गया था। एक बयान में कहा गया कि दुबई से आ रहे विमान में सोना तस्करी की सूचना मिली थी। इसके बाद सीमा शुल्क अधिकारियों ने तलाशी ली और फ्लाइट के पिछले शौचालय में टेप से लिपटी हुई विदेशी छाप वाली पच्चीस सोने की छड़ें बरामद कीं। 5.6 किलोग्राम की छड़ों की कीमत 2.24 करोड़ रुपये है। बता दें कि विमान के चेन्नई में लैंड करने के बाद इसे घरेलू उड़ान के तहत दिल्ली जाना था। (प्रेट्र)

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मुठभेड़, नक्सली कैंप ध्वस्त

दंतेवाड़ा : छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बुधवार को झिरका जंगल में देर शाम नक्सलियों और डिस्ट्रिक रिजर्व गार्ड के जवानों के बीच मुठभेड़ हो गई। काफी देर तक फायरिंग होती रही, लेकिन खुद को कमजोर पाता देख नक्सली भाग निकले। तलाशी में बड़ी मात्रा में नक्सली साहित्य और अन्य सामान मिला है। जवानों ने नक्सली कैंप ध्वस्त कर दिया है। एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव ने बताया कि नक्सली नेता चंद्राया, सीतू, कमलू आदि की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी की टीम भेजी गई थी। मौके से लौटे जवानों के अनुसार जंगल में नक्सलियों के सात टेंट बने थे। कुछ नक्सलियों के घायल होने का दावा भी जवान कर रहे हैं। (नईदुनिया)

कश्मीर में संचार सेवाओं पर रोक अस्थाई उपाय नहीं

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट को बुधवार को बताया गया कि जम्मू-कश्मीर में मोबाइल, लैंडलाइन, इंटरनेट सेवाओं को तीन महीने से बंद करना अस्थायी उपाय नहीं है। जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की तरफ से पेश वकील वृंदा ग्रोहर ने कहा कि कश्मीर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक के आदेश पर संचार सेवाओं पर रोक लगाई गई है, जो प्रथम दृष्टया गैरकानूनी है। गृह सचिव रैंक के अधिकारी को संचार सेवाओं पर रोक लगाने संबंधी आदेश पारित करने का अधिकार है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन की तरफ से दायर अतिरिक्त हलफनामे का उल्लेख करते हुए ग्रोवर ने कहा कि लैंडलाइन फोन की सेवाओं को विभिन्न कारणों से रोका गया। (प्रेट्र)

जम्मू-कश्मीर में परिवहन की स्थिति पर केंद्र से जवाब तलब

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को बृहस्पतिवार को यह बताने के लिए कहा कि अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को रद किये जाने के बाद लगाई गई पाबंदियों के दौरान बस और ट्रक जैसे कितने सार्वजनिक वाहन चले। जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की तीन सदस्यीय पीठ ने यह निर्देश उस समय दिया जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर में सार्वजनिक परिवहन वाहनों को परिचालन की इजाजत नहीं दी गई और यह मौलिक अधिकारों का हनन है। पीठ ने कह कल सवेरे, आपका पहला काम यह बताना है कि पिछले दिनों कितनी बसों, ट्रकों का परिचालन हुआ।' (प्रेट्र)

प्रदूषण पर चिंतन का आधार बने गुरु नानक देव के सिद्धांत

विशेष सत्र ▶ 550वें प्रकाश पर्व को समर्पित पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र कई मामलों में रहा खास, गूंजे श्री गुरु नानक देव जी के उपदेश

वेंकैया नायडू बोले- 'पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत' को अपनाना होगा

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

श्री गुरु नानक देव जी के उपदेश हर काल और परिस्थितियों में नई राह दिखाते हैं। 550वें प्रकाश पर्व को समर्पित पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में गुरु जी के सिद्धांत प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए चिंतन का आधार बने। गुरु नानक देव की बाणी 'पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत' को अपनाने पर जोर दिया गया। उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि हमें इस बाणी के महत्व को समझना होगा। पंजाब और हरियाणा के 177 विधायक आयोजन के साक्षी बने।

बुधवार को आयोजित विशेष सत्र के लिए विधानसभा को फूल-मालाओं से सजाया गया था। करीब 55 मिनट तक चले विशेष सत्र में गुरु जी के उपदेश गूंजते रहे। मुख्य अतिथि उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने संबोधित किया। मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले वेंकैया ने पंजाबी में संबोधन शुरू कर सभी का दिल जीत लिया।

उन्होंने कहा, भारत की महान संत बाणी रचनाकारों में से एक गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित सत्र में शामिल होकर बहुत खुशी मिल रही है। गुरु जी के उपदेश जितने प्रासंगिक 550 वर्ष पहले थे, उतने ही आज भी हैं। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण की चिंता करते हुए गुरु जी ने पवन को गुरु, पानी को पिता और धरती को माता समान बताया था। मौजूदा समय में वायु व जल प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या बन गया है।

चंडीगढ़ में बुधवार को पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए। एएनआइ

कॉरिडोर निभा सकता है विश्व शांति में भूमिका

उपराष्ट्रपति ने करतारपुर कॉरिडोर के खुलने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह कॉरिडोर विश्व शांति में अहम भूमिका निभा सकता है। डॉ. मनमोहन सिंह ने भी उम्मीद जताई कि भविष्य में कशमकश को खत्म करने के लिए करतारपुर कॉरिडोर मॉडल सहायक होगा।

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने आदर्श समाज की नींव रखी। उन्होंने कहा था कि किसी भी समाज की सामर्थ्य का पता इससे चलता है कि उसमें औरतों का कितना सम्मान है। उन्होंने कहा कि पंजाब में युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। ऐसे में विचार करना होगा कि गुरु नानक देव जी की विरासत से कैसे जुड़े रह सकते हैं। उल्लेखनीय है कि गुरु जी ने कहा था कि नशा भगवान के नाम का करना चाहिए और इसी की खुमारी हमेशा रहनी चाहिए।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि गुरु साहिब के फलसफे की भावना को कायम रखने की जरूरत है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को वातावरण प्रदूषण के कारण फैलती घातक बीमारियों से बचाया जा सके। इस दौरान सदन में पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर, विधानसभा के स्पीकर राणा केपी सिंह, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत दोनों राज्यों के विधायक भी मौजूद थे।

पाक ने दी भारतीय दल को करतारपुर जाने की अनुमति

नई दिल्ली, आइएएनएस : पाकिस्तान ने बुधवार को भारतीय उच्चायोग के दल को करतारपुर जाने की अनुमति दे दी। यह दल वहां सुरक्षा समेत अन्य इंतजामों का जायजा लेने जाएगा। इस कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद पहले जत्थे में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई वीआइपी करतारपुर जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान ने बुधवार को पहली बार भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को अनुमति दी है। सूत्रों ने बताया कि भारत सरकार ने कहा था कि पूर्व पीएम समेत पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और कई मंत्री भी पहले जत्थे में करतारपुर जाएंगे और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है।

नवजोत सिंह सिद्धू ने पाक जाने के लिए विदेश मंत्री को फिर लिखा पत्र

जागरण टीम, अमृतसर/चंडीगढ़

पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में बुधवार को आयोजित पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में तो नहीं पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान जाने के लिए उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को फिर पत्र लिखा है। सिद्धू ने पाकिस्तान से आए निमंत्रण का हवाला देते हुए पाक जाने के लिए विदेश मंत्री को दो विकल्प सुझाए हैं। पहला विकल्प कॉरिडोर के रास्ते नौ नवंबर को साढ़े नौ बजे जाने का दिया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर को कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। सिद्धू ने लिखा है कि वह नौ नवंबर को सुबह साढ़े नौ बजे कॉरिडोर के जरिये पाकिस्तान जाना चाहते हैं ताकि 11 बजे वहां होने वाले उद्घाटन समारोह में हिस्सा ले सकें। इससे पूर्व वह गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर में शुकराना अदा करेंगे और संगत के साथ लंगर छकेंगे।

नवजोत सिंह सिद्धू। फाइल

उद्घाटन समारोह में शामिल होने के बाद शाम को वापस आ जाएंगे। अगर कॉरिडोर के रास्ते जाने की मंजूरी देना संभव नहीं है तो वह अटारी-वाघा सड़क मार्ग से गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाना चाहेंगे। इसके लिए वह आठ नवंबर को पाक जाएंगे और रात को करतारपुर गुरुद्वारे में रुकेंगे। अगले दिन उद्घाटन समारोह में शिरकत करने के बाद लौट आएंगे। पीएम मोदी नौ नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और पहले जत्थे को रवाना करेंगे।

सिखों को करतारपुर साहिब की मुफ्त यात्रा कराएगा हरियाणा

राब्यू, चंडीगढ़ : गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिख श्रद्धालुओं को बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा सरकार सिख संगत को करतारपुर साहिब की मुफ्त यात्रा कराएगी। इस दौरान आने वाले वाला सारा खर्च सरकार वहन करेगी। मनोहर लाल ने पंजाब विधानसभा में बुधवार को आयोजित विशेष सत्र के बाद यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि करतारपुर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पासपोर्ट मेले भी लगाए जाएंगे ताकि सिख संगत को कोई दिक्कत न हो।

करतारपुर कॉरिडोर ऐतिहासिक, पीढ़ियां रखेंगी याद : शाह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : करतारपुर कॉरिडोर की आड़ में आतंकी गतिविधियां तेज करने की पाकिस्तान की साजिश के आरोपों के बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक बताया है। एक के बाद एक दो ट्वीट कर अमित शाह ने कहा कि पीढ़ियों तक श्रद्धालु इसे याद रखेंगे। पाकिस्तान स्थित करतारपुर गुरुद्वारे तक श्रद्धालुओं को बिना वीजा और पासपोर्ट के दर्शन करने की सुविधा देने वाले कॉरिडोर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार नौ नवंबर को उद्घाटन करेंगे।

अमित शाह के ट्वीट से साफ हो गया है कि करतारपुर कोरिडोर के पीछे पाकिस्तान के नापाक इरादों के बावजूद सुरक्षा को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सुरक्षा के साथ-साथ अमित शाह गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं को करतार साहिब का दर्शन करने के लिए मिलने वाले सुअवसर को ज्यादा अहम मानते हैं।

अमित शाह ने कहा कि इससे लाखों श्रद्धालुओं का वर्षों पुराना सपना साकार होने जा रहा है। अमित शाह ने गुरु नानक देव की शिक्षा को सहेजने और उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी गुरदासपुर स्थित डेरा बाबा नानक से करतारपुर के लिए पहले जत्थे को भी झंडी दिखाकर विदा करेंगे।

डीएचएफसीएल के अधिकारियों से भी होगी पूछताछ

उत्तर प्रदेश पीएफ घोटाला

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

भविष्य निधि घोटाले में आरोपित यूपी पावर कारपोरेशन के पूर्व एमडी एपी मिश्र को हजरतगंज पुलिस ने बुधवार को सीबीसीआइडी के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट क्षितिज पांडेय की कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने एपी मिश्र को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर 16 नवंबर तक के लिए जेल भेजने का आदेश दिया। इस बीच, मामले की तह तक जाने के लिए डीएचएफसीएल के अधिकारियों से भी पूछताछ होगी।

विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने एपी मिश्र के अलावा मामले में पहले गिरफ्तार किए गए आरोपित पूर्व निदेशक (वित्त) सुधांशु द्विवेदी व ट्रस्ट के तत्कालीन सचिव पीके गुप्ता की पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी पर सुनवाई की। हजरतगंज पुलिस सुधांशु व पीके गुप्ता को लेकर भी कोर्ट पहुंची थी। अदालत ने अपने विस्तृत आदेश में आरोपित एपी मिश्र को सात नवंबर की सुबह 10 बजे से 10 नवंबर की सुबह 10 बजे तक के लिए ईओडब्ल्यू को पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने की मंजूरी दी है। पीके गुप्ता व सुधांशु द्विवेदी की पुलिस कस्टडी रिमांड छह नवंबर की शाम चार बजे से नौ नवंबर की शाम चार बजे तक के लिए मंजूर की गई है।

लखनऊ के कैसरबाग स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में भविष्य निधि घोटाले के आरोपी पॉवर कॉरपोरेशन के पूर्व एमडी एपी मिश्रा को पेश करने के लिए लेकर जाते पुलिसकर्मी। जागरण

भविष्य निधि घोटाले की छानबीन में जुटी आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (ईओडब्ल्यू) अब असुरक्षित निवेश की तह तक जाने की तैयारियों में जुट गई है। आरोपित एपी मिश्र, सुधांशु द्विवेदी व पीके गुप्ता की तीन-तीन दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर होने के बाद डीजी ईओडब्ल्यू डॉ. आरपी सिंह ने बुधवार देर शाम ही अहम बैठक की। गिरफ्तार तीनों आरोपितों का गुरुवार को आमना-सामना कराने से पहले ईओडब्ल्यू ने अपनी रणनीति बनाने के साथ ही सवालों की सूची भी तैयार कर ली है। 25 से अधिक बिंदुओं पर तीनों से सवाल किए जायेंगे।

ईओडब्ल्यू ने घोटाले में दर्ज एफआइआर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं की बढ़ोतरी भी कर ली है। 4122.70 करोड़ के इस घोटाले की सीबीआइ जांच की संस्तुति करने के बाद ईओडब्ल्यू ने सीरियस फ्राड इंवेस्टीगेशन आफिस (एसएफआइओ) से भी संपर्क साधा है और उसे प्रकरण की जानकारी दी गई है। जांच के कदम तेजी से बढ़ा रही ईओडब्ल्यू निजी कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफसीएल) के उन अधिकारियों से भी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है, जो बिजली विभाग के कर्मचारियों की भविष्य निधि की रकम का निवेश डीएचएफसीएल में कराने की डील में शामिल थे। हालांकि डीएचएफसीएल को नोटिस देने से पहले ईओडब्ल्यू आरोपित एपी मिश्र, सुधांशु त्रिवेदी व सचिव ट्रस्ट पीके गुप्ता से पूछताछ का इंतजार कर रही है। बताया गया कि ईओडब्ल्यू गुरुवार सुबह तीनों आरोपितों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू करेगी।

किसके इशारे पर किया गया था निवेश: ईओडब्ल्यू ने आरोपित अधिकारियों से पूछताछ के लिए कड़ा होमवर्क किया है। शक्ति भवन स्थित ट्रस्ट कार्यालय से कब्जे में लिए गए दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर सवालों की सूची तैयार की गई है। बताया गया कि खासकर आरोपितों से यह जानने का प्रयास किया जायेगा कि निजी कंपनी में नियम विरुद्ध इतनी बड़ी रकम निवेश करने का निर्णय किसका था। इसके पीछे किनकी भूमिका थी। इसके अलावा 22 मार्च 2017 को हुई ट्रस्ट बोर्ड की बैठक को 24 मार्च 2017 को दिखाए जाने का सवाल सबसे बड़ा होगा। यह जानने का प्रयास होगा कि आखिर बैठक की तारीख किस इरादे से बदली गई थी और इसका लाभ किसको होने वाले था। निवेश की रकम व तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी सिलसिलेवार पूछताछ की तैयारी है। उल्लेखनीय है कि ईओडब्ल्यू की जांच के दायरे में पावर कारपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष संजय अग्रवाल (वर्तमान में केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के सचिव) समेत कई बड़ों की भूमिका है। माना जा रहा है कि उनसे भी पूछताछ होगी।

योगी सरकार में ही डीएचएफएल को दिए गए 4101.70 करोड़

अजय जायसवाल, लखनऊ

बिजलीकर्मियों के भविष्य निधि (पीएफ) घोटाले की नींव भले ही अखिलेश सरकार में रखी गई थी लेकिन, उस पर भ्रष्टाचार की इमारत योगी सरकार में ही खड़ी हुई है। जिस दीवान हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) में बिजलीकर्मियों के पीएफ के 2267.90 करोड़ रुपये फंस गए हैं, उसको भाजपा सरकार के दौरान ही 4101.70 करोड़ रुपये दिए गए हैं। सपा सरकार में तो 21 करोड़ रुपये ही डीएचएफएल तक पहुंचे थे।

दरअसल, उत्तर प्रदेश स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट में बिजलीकर्मियों के जीपीएफ के जमा 2631.20 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन कंट्रीब्यूटरी प्रॉविडेंट फंड ट्रस्ट में सीपीएफ के जमा 1491.50 करोड़ रुपये डीएचएफएल में लगाए हैं। इसमें से कुल 1854.80 करोड़ रुपये तो वापस मिल गए लेकिन, जीपीएफ के 1445.70 करोड़ व सीपीएफ के 822.20 करोड़ रुपये डीएचएफएल में फंस गए हैं। डीएचएफएल को सपा सरकार के दौरान पीएफ के 21 करोड़ रुपये 17 मार्च 2017 को तब दिए गए, जब भाजपा की सरकार बनना तय हो चुका था।

गौर करने की बात यह है कि 19 मार्च को योगी सरकार बनने के हफ्तेभर बाद ही डीएचएफएल को दूसरी किस्त के तौर पर पहले से कहीं अधिक 33 करोड़ रुपये दिए गए। इतना ही नहीं, तीन अप्रैल को 215 करोड़, 15 अप्रैल को 96 करोड़, पहली मई को 220 करोड़, 19 मई को 169 करोड़ रुपये डीएचएफएल को दिए जाते रहे। ट्रस्ट का 65 फीसद से अधिक 4122.70 करोड़ रुपये निवेश करने बाद यह सिलसिला तब थमा, जब डीएचएफएल के सामने दिक्कतें खड़ी होने लगीं और एक शिकायत की जांच पर घोटाला सामने आ गया।

वैसे तो ट्रस्ट की नियमित बैठकें होनी चाहिए लेकिन, उत्तर प्रदेश राज्य पावर सेक्टर इम्प्लॉइज ट्रस्ट के ट्रस्टीज की 21 अप्रैल 2014 को और उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट की 24 मार्च 2017 को बैठक हुई।

दोनों ही बैठकें पावर कारपोरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में हुईं। 2014 की बैठक में तय हुआ कि 'बैंक के निवेश की तरह सुरक्षित एवं अधिक ब्याज वाले विकल्प यदि हों, तो उन पर विचार कर प्रस्तुत किया जाए एवं आवश्यकता पड़ने पर निवेश सलाहकार की सेवाएं लेने के लिए निदेशक (वित्त) को अधिकृत किया गया।'

हालात

गुलमर्ग और सोनमर्ग समेत सभी उच्चपर्वतीय इलाकों में बर्फबारी, श्रीनगर में बारिश, जम्मू में छाए रहे बादल, ठंड भी बढ़ी, राज्य में अगले दो दिन तक तीखे रहेंगे मौसम के मिजाज

हिमपात से मुगल रोड और श्रीनगर-लेह राजमार्ग बंद

जागरण न्यूज नेटवर्क, श्रीनगर

जम्मू कश्मीर में बुधवार को मौसम ने करवट बदली और गुलमर्ग व सोनमर्ग समेत सभी उच्चपर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश शुरू हो गई। भारी हिमपात से जम्मू संभाग के राजौरी-पुंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाला मुगल रोड़ और श्रीनगर-लेह राजमार्ग बंद हो गया है। इससे लद्दाख से सड़क संपर्क पूरी तरह कट गया है। अलबत्ता, जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सुचारू है। इस बीच, श्रीनगर में बारिश जारी रही। इसका असर जम्मू में भी नजर आया और दिनभर बादल छाए रहे। कुछ जगह हल्की बूंदाबादी भी हुई। मौसम में आए इस बदलाव से राज्य में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार, आठ नवंबर तक मौसम के मिजाज तीखे रहेंगे। इस दौरान बर्फबारी व बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है।

कश्मीर में कई दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ था। मंगलवार देर रात वादी में अधिकांश इलाकों में तेज हवा व बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बुधवार तड़के मौसम के मिजाज और बिगड़ गए और ऊपरी इलाकों में हिमपात शुरू हो गया। गुलमर्ग में सात इंच, अफरवट में डेढ़ फीट, सोनमर्ग में डेढ़ फुट, साधनाटॉप में दो फुट और महागुंसटॉप में भी दो फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई। देर शाम तक यह सिलसिला जारी था। मौजूदा सर्दियों में वादी के उच्चपर्वतीय इलाकों में यह चौथा हिमपात है। इस बीच, श्रीनगर में बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे 8.2 व न्यूनतम 3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

जम्मू-कश्मीर में बुधवार को गुलमर्ग व सोनमर्ग समेत सभी उच्चपर्वतीय इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इस दौरान गुलमर्ग में बर्फ से ढंकी सड़क से गुजरते लोग। एएनआइ

हिमस्खलन की चेतावनी : कश्मीर के उच्चपर्वतीय इलाकों बांडीपोरा, बारामुला, कुपवाड़ा, गांदरबल, बड़गाम, अनंतनाग व शोपियां में प्रशासन ने हिमस्खलन की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ ही प्रशासन ने उक्त इलाकों में सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मशीनों को तैयार रखा है। इन इलाकों में बिजली व पानी की आपूर्ति भी सुचारू रखने के प्रबंध किए गए हैं।

बर्फबारी से मुगल रोड बंद: राजौरी-पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाले मुगल रोड पर मंगलवार रात पीर की गली से लेकर छत्तापानी तक जमकर बर्फबारी हुई। इस 15 किलोमीटर मार्ग पर प्रशासन ने लोक निर्माण विभाग की टीम को बर्फ हटाने के कार्य में लगा रखा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश व बर्फबारी के कारण मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। इससे राजौरी व पुंछ दोनों जिलों का संपर्क कश्मीर घाटी से कट गया है। बर्फबारी के कारण रात को फंसे सभी ट्रकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। लोक निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कमलजीत का कहना है कि बर्फ गिरने व बारिश होने से कार्य ठप है।

धमकी भरे पोस्टर लगाने वाले तीन ओजीडब्ल्यू गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा व उसके साथ सटे इलाकों में जबरन बंद लागू कराने के लिए आतंकियों की ओर से जारी धमकी भरे पोस्टर दीवारों पर लगाने वाले तीन ओवरग्राउंड वर्करों (ओजीडब्ल्यू) को बुधवार गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से आतंकी संगठनों के लेटर हेड, पोस्टर व अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पकड़े गए तीनों ओवरग्राउंड वर्कर खिरयु इलाके के रहने वाले हैं।

अवंतीपोरा, खिरयु, लड्डू, पांपोर में बीते कुछ दिनों से लगातार आतंकी संगठनों के बंद संबंधी पोस्टर दीवारों पर लगे हुए पाए जा रहे थे। इन पोस्टरों में स्थानीय लोगों को अपने सभी कारोबार बंद रखने, सुरक्षाबलों से पूरी तरह दूर रहने, बच्चों को स्कूल न भेजने का आतंकी संगठनों ने फरमान सुनाया था। यह पोस्टर हिजबुल और लश्कर द्वारा जारी किए गए थे।

उमर और महबूबा को सरकारी मकान खाली करने का नोटिस

राज्य ब्यूरो श्रीनगर : राज्य प्रशासन ने हिरासत में चल रहे दो पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को सरकारी निवास खाली करने का नोटिस जारी किया है। कई पूर्व विधायकों और पूर्व मंत्रियों को भी सरकारी निवास खाली करने व सरकारी वाहन लौटाने का नोटिस जारी हुआ है। हालांकि नोटिस जारी होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर लेजिसलेचर पेंशन एक्ट 1984 के तहत राज्य में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवासीय सुविधा का प्रावधान था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू होने के साथ ही इसके प्रावधान निष्प्रभावी हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने अपना सरकारी निवास पहले ही खाली कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को गुपकार मार्ग की शुरुआत में स्थित जी-1 बंगला आबंटित है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को फेयर व्यू बंगला मिला है। दोनों के बंगलों में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

दैनिक जागरण

स्वार्थ हित साधने के बजाय अहित अधिक करता है

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती

दिल्ली और उसके आसपास वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ दिल्ली सरकार के मुख्य सचिवों को फटकार लगाते हुए यह सही कहा कि करोड़ों लोगों को यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। उसने इन राज्यों को यह आदेश भी दिया कि वे उन किसानों को सौ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दें जिन्होंने पराली नहीं जलाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वह इस संदर्भ में धन की कमी की बात स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि राज्य सरकारें पैसे की तंगी का रोना रो सकती हैं। वैसे यदि वे सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के बाद पराली के बचे-खुचे अवशेष को जलाए जाने से रोकने में सफल रहती हैं तो भी कहना कठिन है कि वायु प्रदूषण पर लगाम लग जाएगी। चूंकि किसान पराली इसलिए जलाते हैं कि उन्हें अपने खेत खाली कर नई फसल की तैयारी करनी होती है इसलिए उसके निस्तारण की कोई ठोस व्यवस्था तो करनी ही होगी। इसमें संदेह है कि राज्यों ने पराली निस्तारण के कोई ठोस उपाय कर रखे हैं। चूंकि उनके पास कोई उपाय नहीं इसीलिए तमाम चिंता के बाद भी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जली।

केंद्र सरकार के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट को इससे परिचित होना चाहिए था कि राज्य सरकारों ने पराली दहन रोकने के कोई उपाय नहीं कर रखे हैं। उन्हें इससे भी अवगत होना चाहिए कि असल समस्या दिल्ली के पड़ोसी राज्यों और खासकर हरियाणा और पंजाब में जरूरत से ज्यादा धान की खेती होना है। धान की जरूरत से ज्यादा खेती तब हो रही है जब उसमें पानी का कहीं अधिक इस्तेमाल होता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि किसानों को पराली न जलाने के एवज में प्रोत्साहन राशि देने के बजाय उन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जिनके अवशेष जलाने की जरूरत नहीं रहती? निःसंदेह यह भी समझा जाना चाहिए कि पराली दहन प्रदूषण का एकमात्र कारण नहीं। पराली दहन रोकने के साथ-साथ दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य शहरों में बेहिसाब बढ़ते वाहनों की संख्या को भी थामने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त इस पर भी गौर करने की जरूरत है कि यातायात जाम वाहनों के उत्सर्जन को और जहरीला बनाता है। वायु प्रदूषण की एक अन्य बड़ी वजह सड़कों एवं निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल भी है। आखिर प्रदूषण के इन कारणों का निवारण कब होगा? यदि सुप्रीम कोर्ट वायुमंडल को दूषित करने वाले सभी कारणों के निवारण पर ध्यान नहीं देता तो उसका सख्त रवैया कारगर नहीं होने वाला।

हाथियों की सुध

देश की उत्तर पश्चिमी सीमा में हाथियों के अंतिम पड़ाव उत्तराखंड में मनुष्य और हाथियों के बीच बढ़ता टकराव गंभीर चिंता का सबब बन गया है। राज्य में एशियाई हाथियों की प्रमुख सैरगाह राजाजी टाइगर रिजर्व से लगे हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में आबादी वाले इलाके में घुसे हाथी के हमले में दो लोगों की मौत की घटना इसकी तस्दीक करती है। इससे पहले भी हरिद्वार के आबादी वाले क्षेत्र में हाथी के हमलों की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। न सिर्फ हरिद्वार बल्कि देहरादून, कोटद्वार के अलावा कार्बेट रिजर्व से लगे क्षेत्रों में हाथियों के हमले बढ़ रहे हैं। यूं कहें कि जंगल से लगे मैदानी क्षेत्रों में हाथी खतरे का सबब बन गए हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते इस समस्या के कारणों की पड़ताल कर इसके समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएं। समस्या के कारणों की तह में जाएं तो यह बात सामने आती है कि स्वच्छंद आवाजाही के रास्तों में अवरोध की वजह से हाथियों के लिए जंगल में दायरा सिमटा है। उत्तराखंड में यमुना से लेकर शारदा नदी तक का क्षेत्र हाथी बाहुल्य है। शिवालिक एलीफेंट रिजर्व के रूप में घोषित इस क्षेत्र से एक दौर में हाथियों का विचरण यहां से बिहार तक होता था। वन विभाग के अभिलेख इसकी पुष्टि करते हैं। वक्त के साथ ये गलियारे भी सिमटने लगे। बिहार तक विचरण की बात छोड़िए, अब तो इन्हें उत्तराखंड में राजाजी टाइगर रिजर्व से कार्बेट रिजर्व तक आवाजाही में मानवजनित बाधाओं से गुजरना पड़ रहा है। परंपरागत रास्तों में कहीं मानव बस्तियां उग आई हैं तो कहीं सड़क व रेल मार्गों ने दुश्वारियां खड़ी की हैं। राजाजी रिजर्व के चीला-मोतीचूर गलियारे को देखें तो इसकी राह में खांड गांव के साथ ही वहां से गुजर रही सड़क व रेल लाइन ने हाथियों की आवाजाही बाधित की है। इसी प्रकार गौला गलियारा भी संकुचित हुआ है। करीब-करीब ऐसी ही स्थिति राज्य में चिन्हित नौ अन्य हाथी गलियारों की है। ऐसे में हाथियों की लंबी प्रवास यात्राएं सिमटी हैं। साथ ही जंगल की देहरी लांघते ही इनका मनुष्य से टकराव हो रहा है। हालांकि, पूर्व में हाथी गलियारों को निर्बाध करने के साथ ही इनकी आवाजाही के नए रास्ते को खुला रखने को कदम उठाने की बात हुई थी, मगर ये मुहिम परवान नहीं चढ़ पाई। हालांकि, यह किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, मगर अब जबकि पानी सिर से ऊपर बहने लगा है तो इसके लिए गंभीरता से कदम उठाने ही होंगे।

> मनुष्य और हाथियों के बीच टकराव को टालने के लिए जरूरी है कि हाथी गलियारे निर्बाध करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं

बैर बढ़ाने वाला अहं का टकराव

विक्रम सिंह

आखिर जब पुलिस कर्मियों और वकीलों को मिलकर ही काम करना है तब फिर उनके बीच कटुता और टकराव कोई समाधान कैसे हो सकता है?

अवधेश राजपूत

दिल्ली के तीस हजारी न्यायालय परिसर में पुलिस और वकीलों के बीच हुई झड़प ने सारे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आम जनता के लिए यह समझना कठिन है कि इस झगड़े में कौन सही है और कौन गलत, क्योंकि उभय पक्षों द्वारा एक-दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोपों का जवाब प्रत्यारोपों के जरिये दिया जा रहा है। यदि तीस हजारी अदालत परिसर में हुई घटना की समीक्षा करें तो पता चलता है कि एक अधिवक्ता ने न्यायालय परिसर में बंदीघर के समक्ष अनधिकृत क्षेत्र में अपना वाहन खड़ा कर दिया। इसे लेकर पहले तो पुलिस कर्मियों और वकीलों में नोकझोंक हुई, फिर वह उग्र विवाद में बदल गई। कहा जा रहा है कि विवाद बढ़ने पर वकीलों ने अदालत परिसर में मौजूद पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। वकीलों की मानें तो पुलिस कर्मियों ने उनके एक साथी को लॉकअप में बंद कर दिया था, लेकिन उन पर आरोप है कि उन्होंने लॉकअप तोड़ने का प्रयास तो किया ही, पुलिस कर्मियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, सर्विस रिवाल्वर छीनने की कोशिश की, वाहनों में आगजनी की, महिला पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। पुलिस कर्मियों पर भी आरोप है कि उनके द्वारा वकीलों के साथ अभद्र व्यवहार के साथ-साथ मारपीट और छीनाझपटी तो की ही गई, अवांछित बल प्रयोग भी किया गया। एक पुलिस कर्मी की ओर से गोली चलाने की बात भी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई। वकील-पुलिस के बीच हुए हिंसक टकराव के कुछ वीडियो फुटेज सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर उपलब्ध हैं। इन वीडियो से यह इंगित होता है कि हिंसा पूरी तरह से बेलगाम थी और दोनों ही पक्षों की ओर से हिंसक व्यवहार किया गया। ये वीडियो यह भी संकेत करते हैं कि पीड़ित कौन है और हमलावर कौन?

बीते शनिवार को घटी इस घटना का दिल्ली उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और रविवार को त्वरित कार्रवाई करते हुए व्यवस्था दी कि घटना की जांच एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। इस समिति को छह सप्ताह में अपनी आख्या प्रस्तुत करने को कहा गया। उच्च न्यायालय ने घायल अधिवक्ताओं को राहत राशि देने और उनके बयान दर्ज कर प्रथम सूचना रपट दर्ज करने के भी आदेश दिए। इन आदेशों से मामला शांत नहीं हुआ। सोमवार को दिल्ली और साथ ही देश के अन्य शहरों में वकील हड़ताल पर रहे। इस दौरान दिल्ली की कड़कड़डूमा और साकेत अदालत परिसरों में वकीलों की ओर से उग्रता दिखाई गई। इस उग्रता का शिकार पुलिसकर्मी भी बने। इसके अगले दिन बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के कर्मी और उनके परिजन पुलिस मुख्यालय के समक्ष आ जुटे। उनका धरना देर शाम तक चला। जब यह लग रहा था कि पुलिस कर्मी आसानी से धरना खत्म नहीं करने वाले तब उन्होंने पुलिस आयुक्त के व्यक्तिगत आग्रह पर धरना खत्म कर दिया। यदि दोनों पक्ष के अनुभवी लोगों ने समय रहते कार्रवाई की होती तो उक्त अप्रिय प्रसंगों से बचा जा सकता था। तीस हजारी न्यायालय अत्यंत संवेदनशील स्थल है। यदि पुलिस कर्मियों ने वहां किसी अधिवक्ता को अनुचित तरीके से वाहन खड़ा करने से रोका तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। अदालत परिसर में पुलिस अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए ही तैनात की जाती है। अगर उन पुलिस कर्मियों की जगह मैं होता तो वही करता जो उन्होंने किया। यदि पुलिस पर हमला होता है तो उसे समुचित बल प्रयोग करने का अधिकार है।

अगर प्रतिष्ठित अधिवक्ता जैसे आर्यमन सुंदरम, प्रशांत भूषण, महेश जेठमलानी, सोली सोराबजी आदि यह कह रहे हैं कि तीस हजारी की घटना में वकीलों की गलती लगती है तो इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। इसी के साथ इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि दिल्ली पुलिस कर्मी सड़कों पर उतर आए। वे शायद इसलिए सड़क पर उतरे, क्योंकि उनके मन में यह भाव घर कर गया कि पिटे भी वही और निलंबन का शिकार भी वही बने। वे संभवतः इससे भी आहत थे कि पुलिस अधिकारियों की ओर से उनकी कुशलक्षेम नहीं पूछी गई। जो भी हो, परिस्थितियां कुछ भी हों, धरना-प्रदर्शन एवं आंदोलनात्मक कार्रवाई किसी भी अनुशासित बल को शोभा नहीं देता। ऐसा आचरण एक तरह की अनुशासनहीनता है। वकीलों को भी यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान हड़ताल नहीं है।

यह उचित नहीं कि जब देश के कई वरिष्ठ अधिवक्ता नीर-क्षीर विवेक से अपनी बात कह रहे हैं तब कुछ सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी दिल्ली पुलिस को न झुकने और अपने रुख पर डटे रहने की सलाह दे रहे हैं। कुछ रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों की ऐसी सलाह एक तरह से आग में घी डालने वाली है। समझना कठिन है कि उनकी ओर से दिल्ली पुलिस को आंदोलन के लिए उकसाने का काम क्यों किया गया? निःसंदेह दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का रवैया त्रुटिहीन नहीं कहा जा सकता। उन्हें अपने पुलिस कर्मियों को भरोसे में लेकर यह विश्वास दिलाना चाहिए था कि उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी और हर हाल में उनके मान-मर्यादा की रक्षा की जाएगी। शायद ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए पुलिस कर्मी आंदोलित हो उठे। उचित तो यह होता कि वकीलों और पुलिस के बीच मारपीट के बाद पुलिस अधिकारियों की ओर से सारी स्थिति स्पष्ट की जाती और पुलिस कर्मियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाते। अगर पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के बीच संवाद होता रहता तो कदाचित पुलिस के सड़क पर उतरने की नौबत नहीं आती।

वकील-पुलिस के बीच तनातनी का निदान खुद को सही और दूसरे को गलत ठहराने से नहीं होने वाला। दोनों का और साथ ही देश का काम एक-दूसरे के सहयोग के बगैर नहीं चल सकता। जब दोनों को मिलकर ही काम करना है तब बैर भाव बढ़ाने वाला टकराव कोई समाधान नहीं हो सकता। बेहतर हो कि दोनों पक्ष जांच रपट की प्रतीक्षा करें और समाज को यह संदेश दें कि दोनों मिलकर काम करने को तैयार हैं। पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि वे अधिवक्ताओं से समन्वय स्थापित करें। ऐसी किसी पहल में अधिवक्ताओं का सहयोग आवश्यक है। एक-दूसरे को झुकाने और अपनी बात मनवाने वाला रवैया न्यायसंगत नहीं। एक समय पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और अधिवक्ता संगठनों के बीच नियमित बैठकें होती थीं। इन बैठकों में पारस्परिक समस्याओं का निस्तारण होता था। इस परंपरा को नए सिरे से स्थापित और पुष्ट किया जाना चाहिए। इससे भी जरूरी यह है कि दोनों पक्ष अपने अहं को तिलांजलि दें और इस पर गौर करें कि उनके बीच टकराव से दोनों की ही प्रतिष्ठा पर आंच आ रही है। कानून के शासन की रक्षा तभी हो सकती है जब कानून के रक्षक और कानून के सहायक एक-दूसरे के सहयोगी बनेंगे।

(लेखक उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक रहे हैं)

response@jagran.com

नई शिक्षा नीति के प्रारूप की खामियां

निरंजन कुमार

नई शिक्षा नीति प्रारूप की कुछ कमियों को दूर कर लिया जाए तो यह नए भारत के निर्माण की बुनियाद सिद्ध हो सकता है

मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी के संशोधित प्रारूप को अंतिम रूप देकर कैबिनेट के सामने रखने की तैयारी में है। उच्च शिक्षा के संदर्भ में देखें तो इस प्रारूप में आगामी चौथी औद्योगिक क्रांति के मद्देनजर एक नॉलेज सोसाइटी के साथ-साथ आर्थिक शक्ति के रूप में भारत की भावी रूपरेखा का खाका है, लेकिन शिक्षा जगत में इसे लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। उच्च शिक्षा के संदर्भ में यह प्रारूप महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उसमें कुछ खामियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। इनमें एक है एकल कार्यक्रम आधारित संस्थानों की जगह बहु विषयक पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों पर जोर। हमारे 51,000 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों में बड़ी तादाद एकल कार्यक्रमों पर केंद्रित है। इस विरुपित शिक्षा तंत्र के रूप में बीएड कॉलेज, इंजीनियरिंग, लॉ या मैनेजमेंट कॉलेज एकल अनुशासन वाले संस्थानों की भरमार है। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय हों या आधुनिक विश्वविद्यालय उनके अनुभव दर्शाते हैं कि बहु-विषयक शिक्षण-अनुसंधान संस्थान कितने उपयोगी साबित होते हैं।

नई शिक्षा नीति में एक अन्य अभिनव अनुशंसा है शुरुआत से ही शिक्षा-अध्ययन को विशेषज्ञता की ओर उन्मुख करने के बजाय बहुविषयक स्नातक शिक्षा पर बल देना। अर्थात कला और मानविकी के छात्रों को विज्ञान या व्यावसायिक विषयों के पाठ्यक्रम पढ़ने के अवसर दिए जाएंगे तो दूसरी तरफ विज्ञान एवं तकनीक, प्रोफेशनल और वोकेशनल स्नातक कार्यक्रमों यहां तक कि आइआइटी जैसे इंजीनियरिंग स्कूल में भी मानविकी-कला को एकीकृत किया जाएगा। प्राचीन भारतीय परंपरा में 64 कलाओं के ज्ञान की जो चर्चा होती है वह इसी समन्वित और समग्र ज्ञान को रुपायित करती है। इन 64 कलाओं में संगीत, साहित्य और कला आदि से लेकर इंजीनियरिंग, चिकित्सा एवं गणित जैसे वैज्ञानिक विषयों के साथ-साथ कारीगरी-शिल्पकारी भी शामिल थे। आज अमेरिका-यूरोप में स्नातक स्तर की शिक्षा इस प्राचीन भारतीय पद्धति से बहुत मिलती-जुलती है जिसे वे गर्व से 'लिबरल आर्ट्स' कहते हैं। नवीनतम शोध भी दिखाते हैं कि मानविकी और विज्ञान आदि को एकीकृत करने वाली ऐसी स्नातक शिक्षा के परिणाम अत्यंत सकारात्मक होते हैं जो रचनात्मकता, उच्च स्तरीय चिंतन, समस्या-समाधान की क्षमता, टीम वर्क, संचार कौशल आदि की दृष्टि से अत्यंत सहायक हैं। एनईपी के मसौदे में एक सर्वेक्षण का हवाला है कि औसत वैज्ञानिकों की तुलना में नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकों में कलात्मक शौक तीन गुना अधिक था। उच्च शिक्षा प्रणाली में सामुदायिक जुड़ाव, समाज सेवा और विकास आदि को शामिल करने का भी एक प्रस्ताव मसौदे में है। शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में छात्रों को स्थानीय उद्योग और विशेषज्ञों के साथ इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे ताकि छात्र सैद्धांतिक के साथ ही व्यावहारिक ज्ञान से भी लैस हो सकें ताकि उनकी उत्पादकता और क्षमता में सुधार हो। पश्चिमी देशों में यह व्यवस्था कायम है।

प्रारूप की एक सिफारिश है कि विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों के स्नातक कार्यक्रमों में दाखिले के लिए अलग-अलग प्रवेश परीक्षाओं को खत्म करके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के माध्यम से एक परीक्षा हो। इससे विद्यार्थियों को अलग-अलग प्रवेश परीक्षाओं के बोझ से मुक्ति मिलेगी जिससे समय, धन और ऊर्जा तीनों की ही बचत होगी, लेकिन यहां यह भी जरूरी है कि प्रवेश में 12वीं परीक्षा के अंकों की भी अनदेखी न हो। ऐसा इसलिए, क्योंकि एनटीए बहु-विकल्पीय प्रारूप में परीक्षा लेगा जबकि 12वीं की परीक्षा में बोध पर आधारित सब्जेक्टिव प्रश्न भी होते हैं। ऐसे में संतुलित दृष्टि यही होगी कि प्रवेश में दोनों के अंकों को शामिल किया जाए। प्रारूप का एक बिंदु थोड़ा भ्रामक है कि स्नातक की डिग्री या तो तीन अथवा चार साल अवधि की होगी। फिर तो विभिन्न संस्थान अपनी मर्जी से स्नातक पाठ्यक्रम चलाएंगे। इससे अराजक स्थिति उत्पन्न होगी। चाहे इंग्लैंड जैसी तीन वर्षीय अथवा अमेरिका की तर्ज पर चार वर्षीय पाठ्यक्रम चलें, लेकिन यहां देश में एकरूपता जरूरी है। अमेरिका की तरह का चार वर्षीय पाठ्यक्रम अधिक उपयोगी होगा, क्योंकि यह ज्यादा शोधपरक होने के साथ उच्च शिक्षा के लिए बेहतर आधार तैयार करता है।

प्रारूप में व्यावसायिक शिक्षा पर काफी जोर है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार 19 से 24 आयु वर्ग में भारतीय कार्यबल का केवल पांच प्रतिशत व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करता है जबकि विकसित देशों में यह बहुत ज्यादा है। अमेरिका में यह 52 प्रतिशत, जर्मनी में 75 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया 96 प्रतिशत तक है। भारत में इस कमी का एक प्रमुख कारण यह है कि अब तक व्यावसायिक शिक्षा मुख्य रूप से आठवीं से लेकर 11वीं-12वीं तक केंद्रित रही है। प्रारूप में भारतीय मूल्यों के अनुरूप शिक्षा का व्यावसायीकरण न हो, इसकी निगरानी के लिए भी प्रावधान है। निजी क्षेत्र के संस्थानों में बेलगाम बढ़ रही फीस और मुनाफाखोरी के मद्देनजर यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि नई नीति में निजी संस्थानों की फीस के निर्धारण पर नजर रखी जाएगी, लेकिन इसका कोई स्पष्ट खाका नहीं दिया गया है। ऐसे में लागत अनुपात में फीस की एक अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

एक अहम बिंदु अध्ययन-अध्यापन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं अन्य तकनीक का अधिकाधिक उपयोग का है ताकि समय, संसाधन और श्रम का अधिकतम इस्तेमाल हो सके। शिक्षकों के संदर्भ में एक नई बात यह है कि पदोन्नति और वेतन-वृद्धि आदि के लिए उनके शिक्षण और शिक्षाशास्त्र में नवाचार, शोध की गुणवत्ता और प्रभाव, पेशेवर क्रियाकलाप जैसे मापदंडों के अलावा सहकर्मियों और छात्रों द्वारा भी समीक्षा कराई जाएगी। सहकर्मियों-छात्रों द्वारा समीक्षा सैद्धांतिक रूप से जितनी उचित लगती है, व्यावहारिक रूप से यह उतनी ही विवादास्पद होगी। यह अंततः पूरे शैक्षणिक माहौल को खराब करेगी। सहकर्मी और छात्रों द्वारा समीक्षा सही कदम नहीं होगा। नई शिक्षा नीति में उपरोक्त सीमाओं को दूर कर लिया जाए तो इसमें संदेह नहीं कि यह नए भारत के निर्माण की आधारशिला सिद्ध होगी।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

वैमनस्य

यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है कि वह दूसरे पर वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। अक्सर देखा गया है कि यह व्यवहार मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से अपने आसपास की गतिविधियों को देखते ही स्वतः विकसित होने लगता है। यह व्यवहार मनुष्य के दिमाग में इस कदर समाहित हो जाता है कि उसमें आजीवन इसकी उपस्थिति रहती है। सकारात्मक नजरिये से यह प्रगति के लिए आवश्यक है, क्योंकि स्थायित्व और संतुलन का भाव कहीं न कहीं अकर्मण्यता और शून्यता को आमंत्रित करता है तो वहीं दूसरे नजरिये से देखें तो यही वर्चस्ववादी व्यवहार समाज में वैमनस्य को जन्म देता है, इसी कारण आधुनिक प्रगतिशील युग में आपसी वैमनस्यता का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसका दूसरा कारण मनुष्य के अंदर लोभ की प्रवृत्ति का होना है। मानव उत्पत्ति की शुरुआत से देखें तो वर्चस्व का भाव वहीं से शुरू हो चुका था।

वैमनस्य का दूसरा कारण लोभ है। बेहतर पाने का सपना हर मनुष्य में विद्यमान रहता है और वह बेहतर की चाह में अपने आसपास की बंधी सीमा को तोड़ता है। यह इसलिए होता है, क्योंकि लोभ की प्रवृत्ति मनुष्य को घेर लेती है। बेहतर पाने के सपने और लोभ दोनों समानांतर चलते हैं। लोभी मनुष्य के अंदर 'सब्र' नामक बंधन टूट जाता है और वह मानव सब्र के टूटने पर सारे सामाजिक व मानवीय बंधनों को भी ताक पर रखकर अपने हितों की पूर्ति करता है। एक बार इस महत्वाकांक्षा रूपी जाल में व्यक्ति के फंसने के बाद उसके अंदर स्वाभाविक रूप से अधिक से अधिक हासिल करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है जो तृष्णा में परिणत होकर बुद्धि को कुंठित कर देती है। ऐसे में सामाजिक संबंधों और हितों का बिखराव समाज में कटुता लाता है और यही स्थिति खतरनाक होती है, क्योंकि समाज में लोभ की अधिकता वर्चस्व की जनक होती है और इसी वर्चस्व से 'वैमनस्य' पैदा होता है। आपसी वैमनस्य की बढ़ती प्रवृत्ति से निदान के लिए संतुलित रूप से निश्चित और सीमित दायरे में हितों की पूर्ति ही एकमात्र उपाय है।

शिवांशु राय

पूर्वाग्रह से पानी होगी मुक्ति

डॉ. नीलम महेंद्र

> महिलाओं की उपलब्धियों को मान्यता देने के बजाय अक्सर उसका श्रेय पुरुष सहकर्मियों को दिया जाना सही नहीं है

एक कहावत है कि समय के साथ बदल जाइए, वरना समय बदलाव के लिए अवसर नहीं देता। यह बात एक व्यक्ति से लेकर समाज तक सभी पर लागू होती है। परिवर्तनशील व्यक्ति और समाज ही सही मायनों में प्रगतिशील और विकसित हो सकते हैं। इसके बावजूद कई मोर्चों पर जड़ता कायम है। जैसे महिलाओं को लेकर सोच का स्तर अभी भी नहीं सुधर पाया है। आज महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही हैं। फिर भी विडंबना देखिए कि वर्ष 2019 में भी जब नोबेल जैसे पुरस्कार पाने वालों के नाम सामने आते हैं तो महिलाओं को लेकर खराब सोच ही सामने आती है।

वर्ष 1901 से 2018 के बीच भौतिकी के लिए 112 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया और तीन बार ही महिलाओं को यह पुरस्कार मिला। ऐसे ही रसायन शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी लगभग यही असंतुलन दिखता है। इनमें 688 बार नोबेल दिया गया जिसमें से केवल 21 बार महिलाओं को मिला। अगर विभिन्न क्षेत्रों में कुल नोबेल विजेताओं की बात की जाए तो अब तक 892 लोग इससे सम्मानित हुए हैं जिनमें 844 पुरुषऔर 48 महिलाएं हैं। विभिन्न वैश्विक मंचों पर जब लैंगिक समानता की बातें होती हैं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के किसी पुरस्कार के ये आंकड़े निश्चित ही वर्तमान कथित आधुनिक समाज की कड़वी सच्चाई सामने ले आते हैं।

अमेरिका की विज्ञान इतिहासकार मार्गरेट डब्लू रोसिटर ने 1993 में ऐसी सोच को माटिल्डा इफेक्ट नाम दिया था जब महिला वैज्ञानिकों के प्रति एक पूर्वाग्रह होता है जिसमें उनकी उपलब्धियों को मान्यता देने के बजाय उनके काम का श्रेय उनके पुरुष सहकर्मियों को दे दिया जाता है। सोसाइटी ऑफ स्टेम वीमेन की सह संस्थापक क्लोडिया रैनकिंस का कहना है कि ऐसी कई महिला वैज्ञानिक हुई हैं जिनके काम का श्रेय उनके बजाय उनके पुरुष सहकर्मियों को दिया गया। अगर आप इस कथन के विरोध में नोबेल पुरस्कार के शुरुआती दौर यानी 1903 में ही मैडम क्यूरी को नोबेल दिए जाने का तर्क प्रस्तुत करना चाहते हैं तो इसके पीछे की हकीकत जानना रोचक होगा। विकिरण की खोज मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने मिलकर की थी, लेकिन 1902 में जब इस कार्य के लिए नामांकन किया गया था तो नोबेल समिति द्वारा मैडम क्यूरी को नामित नहीं किया गया था। पियरे क्यूरी के विरोध के कारण मैडम क्यूरी को भी नोबेल दिया गया और इस प्रकार 1903 में वह नोबेल पाने वाली पहली महिला वैज्ञानिक और फिर 1911 में रेडियम की खोज करके दूसरी बार नोबेल पाने वाली पहली महिला बनीं।

स्पष्ट है कि प्रतिभा के बावजूद महिलाओं को लगभग हर क्षेत्र में कमतर ही आंका जाता है और उन्हें योग्यता के बावजूद जल्दी आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। वर्ष 2018 की नोबेल विजेता डोना स्ट्रिकलैंड इसकी उम्दा मिसाल हैं जो अपनी योग्यता के बावजूद कई वर्षों तक कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर ही कार्यरत रही थीं। इस पुरस्कार के बाद उन्हें पदोन्नति दी गई।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

आसान नहीं आरसेप की राह

मुक्त व्यापार समझौते की मुश्किलें शीर्षक से लिखे अपने आलेख में डॉ. भरत झुनझुनवाला ने आसियान देशों सहित छह अन्य भागीदार देशों के नेतृत्व में आकार ले रहे आरसेप से भारत के बाहर रहने के निहितार्थों की बखूबी विवेचना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरसेप की बैठक में एक महत्वपूर्ण बात कही कि जब वह आरसेप करार को सभी भारतीयों के हितों से जोड़कर देखते हैं तो उन्हें सकारात्मक जवाब नहीं मिलता। यह सही भी है, क्योंकि इस मुक्त व्यापार व्यवस्था के लागू होते ही भारत को अपने दरवाजे आसियान सहित चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों से होने वाले सस्ते आयातों के लिए खोलने पड़ते जो यहां पहले से ही मुसीबतों में फंसे भारतीय किसानों, छोटे उद्योगों और डेयरी उद्योग के लिए आत्मघाती हो सकता था। गौरतलब है कि व्यापार वार्ता में शामिल अन्य 15 देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा बहुत बड़ा है। बहरहाल भारत के इस बड़े कदम के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है, वह यह कि भारत के लिए अब आगे की राह क्या हो। लेखक का सुझाव सही है कि हमें अपने उत्पादकों के हित में श्रम मानकों में आवश्यक सुधार करने होंगे और भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर उद्यमिता व प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना होगा। यदि हम वैश्विक मानकों के अनुरूप उत्पादों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध करा सकें तो उनकी मांग बनी रहेगी।

चंदन कुमार, देवघर

पौधारोपण ही समाधान

आज देश के कोने-कोने से बढ़ते प्रदूषण की खबरें आ रही हैं। क्या यह प्रदूषण इन दिनों में ही हुआ है? हर रोज सैकड़ों लोग और पशु-पक्षी इसके कारण बेमौत मर रहे हैं। कुछ दिन हाय-तौबा तथा प्रदूषण की दुहाई देने के बाद लोग फिर इस भयंकर जहर को भूल जाते हैं। दिन-प्रतिदिन बढ़ते वाहनों, कारखाने आदि से निकलने वाले जहरीले धुएं से शहर ही नहीं, गांव-देहात भी अछूते नहीं रहे हैं। निरंतर पेड़ों की कटाई के कारण जल स्तर भी घट रहा है और बरसात बहुत कम होती है। जिस स्थान पर जंगल हुआ करते थे आज वहां भव्य इमारतें नजर आती हैं। मनुष्य के साथ-साथ पशु-पक्षियों पर भी इस बढ़ते प्रदूषण का प्रभाव पड़ रहा है। लोगों को त्वचा के साथ कैंसर आदि ऐसी अनेकों लाइलाज भयंकर बीमारी अपना शिकार बना रही हैं, परंतु इसकी जिम्मेदारी हम स्वयं नहीं लेकर इसका दोष दूसरों पर डालते रहते हैं। अभी भी समय रहते हम सभी को इस भयंकर समस्या से निपटने का प्रयास कर लेना चाहिए तभी जीवन बचाया जा सकता है। इसका एकमात्र उपाय अधिक से अधिक पौधारोपण ही इस समस्या का पूर्णतः हल है। हम सभी को वाहनों का कम उपयोग, स्वच्छता, जल संरक्षण आदि के साथ- साथ उन सभी बातों का ध्यान देना होगा जो प्रकृति के हितोपयोगी हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

आचार्य राम कुमार बघेल, पर्यावरण सचेतक, पलवल

नुकसान की भरपाई

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पुलिस-वकीलों के बीच जो झड़प हुई, उसके बाद जिस तरह से वाहनों को जलाया व तोड़फोड़ की गई, उसके लिए जांच के बाद जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। जो संपत्ति का नुकसान हुआ है, उसका आकलन कर, उसकी भरपाई दोषियों की चल-अचल संपत्ति से की जानी चाहिए। देश में हर किसी ने छोटे-मोटे विवादों के बाद सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना खेल समझ लिया है। सरकार को अब ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाना चाहिए। वोट की राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिए।

hemahariupadhyay@gmail.com

प्रदूषण पर आरोप-प्रत्यारोप

दिल्ली-एनसीआर में गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर है। इसका कारण लोनी के पास बसे मंडोला गांव के आसपास चोरी छिपे कुछ लोग ई-कचरा डाल रहे हैं और उसे जला भी दे रहे हैं। गाजीपुर, दिल्ली के कूड़ाघर पर आज 30 साल बाद भी कचरा डाला जा रहा है, जबकि कई साल पहले उसकी कूड़ा डालने की मियाद खत्म हो गई है। दिल्ली की उत्तर पश्चिमी सीमा पर भलस्वा में जीटी करनाल रोड मोड़ पर भी एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर है। इन सबसे

587 अरब डॉलर का व्यापार हुआ चीन-आसियान देशों के बीच वर्ष 2018 में, जबकि इसी अवधि के दौरान भारत-आसियान देशों का व्यापार महज 96 अरब डॉलर के आसपास ही रहा।

आजकल

आरसेप में शामिल नहीं होने के निहितार्थ

अनंत मित्तल
वरिष्ठ पत्रकार

आरसेप व्यापार समझौते में नहीं शामिल होने के संबंध में भारत की मुख्य आपत्ति समझौते के सदस्य देशों द्वारा आपस में निर्यात की मात्रात्मक सीमा तय नहीं किए जाने पर थी। भारत का सुझाव था कि आयात व निर्यात की कोई निश्चित सीमा पार होते ही सदस्य देश उस पर अंकुश लगाएं, ताकि माल की डंपिंग को रोका जा सके। डंपिंग का मतलब है लागत से कम दाम पर दूसरे देश में माल का निर्यात। इसका मकसद उस देश के उद्योग चौपट कर वहां के बाजार पर कब्जा करना होता है। यह एक आर्थिक युद्ध प्रणाली है जिसमें चीन को महारत हासिल है

सोलह देशों के क्षेत्रीय समग्र आर्थिक सहयोग यानी आरसेप व्यापार समझौते से भारत ने फिलहाल कन्नी काट ली है। इसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकाक से ट्वीट के जरिये देश और दुनिया को दी। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार मई 2019 में दोबारा सत्तारूढ़ होने पर समझौते के लिए आत्म विश्वास से लबरेज थी, मगर पिछले पांच माह में इसके व्यापक विरोध ने उसके इरादे कमजोर कर दिए। शायद इसीलिए व्यापार समझौते में शामिल नहीं होने की जानकारी प्रधानमंत्री ने खुद दी है, जबकि बातचीत का नेतृत्व वाणिज्य एवं रेल मंत्री पीयूष गोयल कर रहे थे। इसके बावजूद विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार जीएसटी की तरह आरसेप में भी जल्दबाजी कर रही थी और उसके दुष्परिणामों से घरेलू किसानों, व्यापारियों, उद्यमियों तथा नौजवानों को बचाने के लिए किया गया राजनीतिक विरोध रंग लाया है।

व्यापार रणनीति में चीन से मुंह की खाने की आशंका : चीन जिस देश में घुसता है वहां के बाजार में उसी का माल छा जाता है। चीन की इस बाजार रणनीति के कारण सिर्फ भारत ही नहीं, आसियान के सदस्य देश भी व्यापार घाटा झेल रहे हैं। भारत का चीन वैसे तो सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है, मगर उसके मुकाबले हमें सालाना 54 लाख करोड़ रुपये मूल्य का व्यापार घाटा झेलना पड़ रहा है। आशंका यह थी कि निरंकुश आरसेप मुकम्मल होते ही हमारे बाजार भी चीन में उत्पादित माल और न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया के डेयरी उत्पादों से लबालब हो जाएंगे। इसीलिए हम ऑटो ट्रिगर व्यवस्था लागू करवाना चाह रहे थे, जबकि चीन का कहना था कि मात्रात्मक बंदिश किसी भी रूप में लगी तो मुक्त व्यापार समझौता बेमानी हो जाएगा।

भारत की मांग यह भी है कि वस्तुओं के आयात से घाटे की भरपाई के लिए सेवाओं के व्यापार में हमारी विशेषज्ञता को वरीयता दी जाए। इसके लिए भी सदस्य देश राजी नहीं हुए। बहरहाल समझौते से भारत की तौबा के बावजूद चीन और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को उसमें आगे कभी भी शामिल होने का न्योता दिया है। इसकी वजह है भारत का विशाल एवं व्यवस्थित बाजार जिसमें आरसेप के 15 सदस्य देशों का माल खपने की असीम संभावना है। यह बात अलग है कि इनमें से चीन के अलावा सभी देशों से भारत ने पहले ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष मुक्त व्यापार समझौता कर रखा है।

समझौते में संशोधन की भारत की मांग : समझौते के प्रारूप में बाजार दखल, निवेश, व्यापारिक उपचार, प्रतियोगिता, ई-कॉमर्स संबंधी नियमों आदि के प्रावधानों में भी भारत संशोधन चाहता था। डाटा लोकलाइजेशन अर्थात ग्राहकों के निजी

> वर्ष 2012 से आरसेप की कवायद जारी थी जिस समझौते में शामिल होने से भारत ने फिलहाल इन्कार कर दिया है

विवरण को सदस्य देशों से बाहर ले जाने संबंधी प्रावधान पर भी हमें एतराज था। ई-कॉमर्स में इसका अन्य देशों ने भी विरोध किया था। यह प्रस्ताव इसलिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2018 को जारी आदेश के तहत सभी सिस्टम प्रदाताओं से अपने पेमेंट सिस्टम से संबंधित सभी डाटा भारत के भीतर ही संग्रहित करने को कहा था। बस सीमापार हुए लेन-देन के डाटा को ही विदेश स्थित सिस्टम में रखा जा सकता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भी ई-कॉमर्स नीति में डाटा के स्थानीयकरण पर कड़ी निगाह रख रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसी उद्देश्य के लिए निजी डाटा संरक्षण विधेयक तैयार कर रहा है।

भारत की आपत्ति का कारण : भारत की आपत्तियों की बड़ी वजह चीन सहित इन 15 देशों से समग्र व्यापार में हमारे द्वारा सालाना करीब 105 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का व्यापार घाटा झेल जाना है। अर्थात हम अपनी क्षमता बढ़ाएं तथा उत्पाद सस्ते करें तो उन देशों को इतनी बड़ी रकम के बराबर माल अथवा सेवाओं का निर्यात कर सकते हैं जिनसे व्यापार घाटा खा रहे हैं। निर्यात बढ़ने पर शहरी, अर्धशहरी आबादी ही नहीं, ग्रामीण कारीगरों को भी बड़े पैमाने पर रोजगार मिलने से देश में खुशहाली आएगी। फिर भी श्रीलंका से वर्ष 2000 में पहले मुक्त व्यापार समझौते के बाद से पिछले दो दशक में हम ऐसा नहीं कर पाए। इसीलिए समझौते से सबसे अधिक आशंकित दूध उत्पादक पशुपालक, खाने-पीने की चीजों के उत्पादक एवं काली मिर्च व इलायची उत्पादक किसान तथा इस्पात, प्लास्टिक उद्योग एवं उनसे सामान बनाने वाले उद्यमी थे।

सुगबुगाहट ये भी रही कि अक्टूबर में भारत दौरे में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझौते के बाद भारतीय बाजारों को चीन में बने माल से पटने नहीं देने का आश्वासन भी दिया, मगर मंदीग्रस्त घरेलू बाजार में समझौते की विपरीत प्रतिक्रिया और उसके राजनीतिक दुष्परिणामों से चिंतित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिलहाल बाहर रहने में ही भलाई दिखी। भाजपा का सहोदर स्वदेशी जागरण मंच भी आरसेप के खिलाफ अरसे से अलख जगाए हुए था। रही-सही कसर हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भाजपा को लगे झटके ने पूरी कर दी। यूं भी समझौते की सबसे ज्यादा जरूरत चीन को है। अमेरिका द्वारा तटकर दरें बढ़ाने के बाद चीन का विनिर्माण एवं निर्यात कारोबार लड़खड़ा गया और उसकी आर्थिक वृद्धि गिर रही है। ऐसे में समझौते के जरिये भारत में बेरोकटोक व्यापारिक दखल का मौका मिल जाता तो चीन के फिर से वारे-न्यारे हो ही जाते।

समझौते के लिए भारत सहित 16 सदस्य देशों के बीच वर्ष 2012 से बातचीत चल रही थी और चार नवंबर को बैंकाक में उनके राष्ट्राध्यक्षों को उस पर सहमति हस्ताक्षर करने थे। लेकिन भारत के एतराज के कारण समझौते पर सदस्य देशों में सहमति नहीं बन पाई और यह अगले वर्ष फरवरी तक लटक गया। ऐसा माना जा रहा है कि भारत के विशाल बाजार के कारण समझौते के लिए हमें पटाने की कोशिश जारी रहेगी। भारत एवं चीन सहित एशिया-प्रशांत क्षेत्र के जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और आसियान सहित कुल 16 देश समझौते में शामिल थे। भारत के पल्ला झाड़ने के बाद इनकी संख्या 15 रह गई।

आसियान देशों से बढ़े व्यापार

पुष्परंजन
वरिष्ठ पत्रकार

चार नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बैंकाक दौरा समाप्त हो गया। भारतीय प्रधानमंत्री पूरे आसियान शिखर बैठक पर छाए हुए थे, यह सबने देखा। करीब ढाई लाख प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने संख्या के लिहाज से कीर्तिमान स्थापित कर दिया। इससे इतर भारतीय उद्योग संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में मोदी ने भारत-थाइलैंड की सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख किया। मगर क्या इन सारी बातों का लाभ भारत-आसियान व्यापार को होना है?

शिखर बैठक में आसियान के दस सदस्य देशों के अलावा पांच विशेष अतिथि देश शामिल हुए थे। इससे अलग आसियान रीजनल फोरम पहले से बना है। यह 27 देशों का समूह है, जिसमें भारत व चीन भी शामिल हैं। बैंकाक शिखर बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसेप) पर सहमति बननी थी, उसे फरवरी 2020 तक के लिए टाल दिया गया है। आरसेप के नफा-नुकसान को लेकर बैंकाक समिट में भाग लेने वाले सदस्य देशों में असहमति बनी हुई थी।

आसियान का उदय 1967 में हुआ था। तब एशिया-प्रशांत के देश इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाइलैंड, फिलीपींस उपनिवेशवाद से मुक्त हुए थे। इन्हें राजनीतिक स्थिरता और विकास चाहिए था। करीब पांच दशक में आसियान से पांच और सदस्य कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, ब्रुनेई जुड़े और इन सबों ने वह कर दिखाया, जो लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया था। दक्षिण-पूर्व एशिया के दस देशों का संगठन 'आसियान' 1.4 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और 2.57 ट्रिलियन डॉलर की मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था है। आसियान का दूसरे छह क्षेत्रीय संगठनों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ऐसे प्रभावशाली ब्लॉक पर चीनी प्रभामंडल को कैसे निस्तेज करना है, यह भारतीय-अमेरिकी कूटनीति का कोर एजेंडा रहा है। वैसे भी चीन पिछले 28 वर्षों से कूटनीतिक रूप से आसियान देशों से जुड़ा रहा। उसकी मुख्य वजह भू-सामरिक परिस्थितियां भी रही हैं। उससे इतर चीन से आसियान देशों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 16 वर्ष हो चुके हैं। वर्ष 2018 में चीन-आसियान का व्यापार 587.8 अरब डॉलर को छू चुका था। इसी अवधि में उसके मुकाबले भारत-आसियान देशों का व्यापार 96.79 अरब डॉलर तक ही हो पाया। उद्योग-वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में हमारा व्यापार घाटा 21.85 अरब डॉलर का है। यह फासला ही मोदी कूटनीति कम कर दे, तो बहुत है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत-आसियान के बीच फ्री ट्रेड में कहां कमी रह जाती है, इसका हम पुनरीक्षण करेंगे। भारत, आसियान देशों का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पर वर्ष 2000 से निवेश की गति बारह फीसद रही है। 18 वर्षों में आसियान देशों से 514 अरब डॉलर का निवेश भारत में हुआ है। इसके बरक्स भारत से आसियान देशों में 38 अरब डॉलर का निवेश अप्रैल 2007 से मार्च 2015 के बीच रहा है।

भारत-आसियान के बीच सुस्त व्यापार की सबसे बड़ी वजह खराब कनेक्टिविटी है। भारत-आसियान पार्टनरशिप के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। मगर, लक्ष्य आधे-अधूरे हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण करीब दो हजार किलोमीटर 'इंफाल-मंडाले-बैंकाक राजमार्ग' का अब तक पूरा नहीं होना है। भारत-आसियान संबंधों को स्मरणीय बनाने के वास्ते इंडिया-आसियान कमोमोरेटिव समिट 25 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें कनेक्टिविटी, आर्थिक-सांस्कृतिक सहयोग व ब्लू इकोनॉमी पर जोर दिया गया था। बावजूद इसके निवेश की गति साढ़े बारह प्रतिशत से आगे कितनी बढ़ पाई? मोदी दस में से नौ आसियान देशों का दौरा कर चुके हैं। इससे यह संदेश तो गया कि पीएम मोदी 'एक्ट एशिया' नारे के अनुरूप एक्शन मोड में रहे हैं। दक्षेस देशों के शासन प्रमुख दिल्ली आकर पीएम मोदी के प्रथम शपथ समारोह के साक्षी बने थे। पर छह साल बाद दक्षेस कहां खड़ा है? यह भी बड़ा सवाल है।

- इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर

खरी-खरी

योजनाओं के भक्षण के प्रति व्यापक दृष्टि

विजी श्रीवास्तव

भूख, स्वाद व पसंद सबकी अपनी-अपनी होती है। लेकिन सर को जब भूख लगती है, वे कोई योजना कुतर लेते हैं। फाइल पर परोसी योजनाओं में से कहां, कितना, कब खाना है, इसके महाविशेषज्ञ हैं वे। योजनाओं की न्यूट्रिशनल वैल्यू के परम ज्ञाता। कितनी ही योजनाएं जीमने का कीर्तिमान है उनके नाम।

ऐसे व्यवहार कुशल, उदार व परोपकारी 'सर' मुश्किल से मिलते हैं। योजना भक्षण की बारीकियां कोई इनसे सीखे। गरम, ताजी कड़क योजना का छिलका कैसे उतारना है। पकाकर खाना है या कच्ची। कुचल के खाना है या काट के। छांट के खाना है या बांट के। खाना भर है या पी ही जाना है। पीना है तो घोलकर या घोंटकर। उन्हें जैसी भी भकोसना है, उससे क्या फर्क पड़ता है। बल्कि 'सर' योजनाओं के भीषण प्रवाह के लिए दधीचि न बनें और कुछ अंश की कटौती न करें, तो जिनके लिए योजनाएं हैं, वे उसमें डूब जाएं, खप जाएं या बह जाएं।

योजना अफसर को जनती है या अफसर योजना को! कह सकते हैं कि दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। नई योजनाएं बनाने, जारी रखने और उनके भक्षण की क्रियाएं कितनी जरूरी हैं, इसके लिए व्यापक दृष्टिकोण रखना जरूरी है। योजनाएं जिनके लिए हैं, अगर उन तक समूची पहुंचने लगें, फिर तो हो गया विकास! गलती से अगर वो बदल गए तो आगामी योजनाओं का क्या होगा? आदिवासी, आदिवासी न रहे। किसान, किसान न रहे। मजदूर, बेरोजगार, अनपढ़-गंवार आदि वैसे न रहें, इसके लिए योजना बनी है तो फिर अर्थहीन विकास क्या तेल लेने जाएगा! योजना के हर चरण को ऊंचा उठने के लिए किसान, मजदूर, आदिवासी की सीढ़ी चाहिए। किसान को बाकायदा किसान और अन्य को बाकायदा अन्य जैसे ही रहना होगा। उनकी पृष्ठभूमि को स्थाईत्व देना ही 'सर' का करतबपूर्ण कौशल है।

सर का डाइजेशन गजब का है। वे योजना भकोस कर डकार तक नहीं लेते। उनकी छोटी और बड़ी आंत दूर-दूर तक फैली हैं। जिनके कनेक्शन दूसरों के उदर से है। ये आगे चलकर एक टनल से जुड़े हैं। ऐसी बहुत सारी टनल्स, गटर में खुलती हैं। कई नादान फिजूल सवाल उठाते हैं कि विकास बरसों से वहीं का वहीं सिमटा है, तो इत्ती सारी योजनाएं जाती कहां हैं? इन्हें कौन बताएं कि टनल्स की आखिरी मंजिल कहां है!

ट्वीट-ट्वीट

करतारपुर गलियारे को खोला जाना भले ही हमारे लिए आस्था का विषय है, लेकिन इसे पाकिस्तान एक गहरी साजिश के तहत कर रहा है। करतारपुर वीडियो प्रचार में भिंडरावाला का पोस्टर दिखाना, पाकिस्तान की घटिया सोच को दर्शा रहा है!
दीपक चौरसिया@DChaurasia2312

आरसेप पर कोरे अर्थशास्त्र की नहीं, बल्कि राजनीतिक समझदारी की आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के व्यापक हित में सही फैसला लिया।
योगेंद्र यादव@_YogendraYadav

पुलिस स्वयं संरक्षण मांगे, वकील मांगते न्याय, अच्छे दिन प्रारंभ हो गए, ये है प्रथम अध्याय!
शशि थरूर@ShashiTharoor

एक ऐसे देश में जहां आए दिन अनेक राज्यों में अनेक जगहों पर पुलिसकर्मियों को जहां-तहां निशाना बनाया जाता हो, उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि यह अराजकता नहीं तो कम से कम अव्यवस्था की निशानी जरूर है।
प्रकाश सिंह@singh_prakash

हिमाचल प्रदेश डायरी

यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतने बड़े स्तर पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट गुरुवार से शुरू हो जाएगी। इस दो दिवसीय आयोजन को भव्यता इसलिए भी मिलेगी, क्योंकि आरंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कांगड़ा हवाई अड्डा प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार है। आयोजन बेशक दो दिनों का है, लेकिन इसके पीछे का श्रम दो दिन का नहीं है। एक लंबा सिलसिला था जिसे पार कर अब यह मुकाम आया है। इस आयोजन से कितना लाभ होगा, कितने रोजगार सृजित होंगे, यह हिसाब करने का वक्त अभी नहीं है। अभी तो दो प्रमुख बिंदु प्रदेश सरकार के खाते में जा रहे हैं। एक, इतने बड़े आयोजन को जमीन पर साकार करना और दूसरा यह कि केंद्र ने इस आयोजन के लिए अब तक करीब 11 करोड़ रुपये भी दिए हैं। कुछ खर्च हिमाचल प्रदेश सरकार भी करेगी, लेकिन बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार ने दे दिया है।

नामी उद्योगपतियों के आने से हिमाचल के पहाड़ों में संसाधनों में वृद्धि के सपनों को भी ताबीर मिलने की संभावनाएं जगी हैं। अब तक बागवानी और उसमें भी सेब पर निर्भर रहा है हिमाचल। या फिर पन-बिजली ने कुछ रवानी दी है। कृषि का हाल सबके सामने है। ले देकर पर्यटन ही ऐसा क्षेत्र बचता है, जिसमें प्रकृति भी साथ है, समय भी और अपेक्षाएं भी।

इससे पहले प्रदेश से बाहर औद्योगिक निवेश के लिए रोड शो होते रहे हैं। निवेशकों को लुभाने के प्रयास भी हुए लेकिन इतना प्रयास पहली बार हो रहा है, इस पर संदेह नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा कारज बिना विघ्न के संपन्न हो, सदिच्छा के साथ कार्य संपूर्ण हों, यह उम्मीद भी करनी चाहिए और प्रयास भी। मूलतः मनीऑर्डर अर्थव्यवस्था रहे प्रदेश को अब भी कई चीजों की जरूरत है।

इस प्रयास से यह होगा कि देश-विदेश के नामचीन चेहरे हिमाचल की क्षमता को पहचान सकेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नया उद्योग लगाने के लिए तीन साल तक अनापत्ति लेने की जरूरत को खत्म करके एक सकारात्मक

संकेत दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी को हिमाचल कई कारणों से याद करता है। उनमें से एक है हिमाचल को मिला औद्योगिक पैकेज। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिमाचल प्रदेश के लिए कोई इससे मिलती जुलती घोषणा कर दें तो हिमाचल प्रदेश निश्चित रूप से आगे बढ़ सकता है।

वास्तव में, हिमाचल प्रदेश की एक विशिष्ट स्थिति है। केवल हरियाली के साथ पेट भरे, यह संभव नहीं है। ये हरियाली बेहद जरूरी है, लेकिन हवा के साथ-साथ आर्थिकी की बयार भी लाए, यह सोचने का यही निर्णायक अवसर है। हिमाचल प्रदेश के लिए विकास समय की जरूरत है, लेकिन साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के तौर पर जो कुछ बच गया है, उसे बचाए रखना भी। आर्थिक रूप से कमजोर होना पहाड़ी प्रदेश के विकास में बड़ी बाधा भी है। केंद्र सरकार की मदद और उधार के पैसे से लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास सभी सरकारों का रहा है। उसमें कुछ नया नहीं है। प्रदेश में उद्योगों का विस्तार उस तरह नहीं हो पाया है, जिस तरह से पड़ोसी राज्य उत्तराखंड या उत्तर-पूर्व के राज्यों में हो रहा है। बेहतर सड़कें व रेलवे कनेक्टिविटी प्रदेश के लिए सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण निवेशक यहां आने से हिचकते रहे हैं। रेल नेटवर्क विस्तार भी उतना नहीं हो पाया। हवाई सेवा सीमित क्षेत्र तक ही सिमटी है।

इन्वेस्टर्स मीट की सफलता से निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास को पंख लगेंगे। रेल व हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए केंद्र के हामी भरने का भी निवेशकों में अच्छा संदेश जाएगा। केंद्र सरकार के सकारात्मक प्रोत्साहन से उद्योगों को बेहतर सुविधाएं देने के प्रदेश सरकार के दावे को बल मिलेगा। केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष भी प्रदेश के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की जरूरत है, ताकि वे प्रदेश की दिक्कतों को समझकर उनके हल की दिशा में प्रयास करें। यह किसी से छिपा नहीं है कि औद्योगिक पैकेज खत्म किए जाने के बाद से प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर ज्यादा प्रोत्साहन नहीं दिखा है। कई उद्योगों ने यहां से पलायन कर लिया और कुछ बंद हो गए। अब प्रदेश सरकार ने नीतियों में संशोधन कर निवेशकों का भरोसा जीतने की कोशिश की है। सड़क, रेल व हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए प्रदेश सरकार को मजबूती से केंद्र के समक्ष पक्ष रखना होगा। बड़े पैमाने पर होने वाले निवेश से प्रदेश की कई समस्याओं का हल होने की उम्मीद बंध रही है।

विपक्ष का काम सरकार की कमियों को गिनाना है। वैसे भी निंदकों का नजदीक रहना मुफीद होता है। लेकिन फिलहाल तो इस सकारात्मक कदम के सफल होने की कामना करनी चाहिए। मंजूर हाशमी ने इरादों के हवाले से ही कहा होगा -

यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है,
हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है।

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या आरसेप करार न करके मोदी सरकार ने सही किया है?

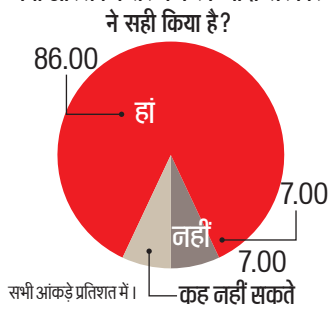

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या प्रदूषण से प्रभावित अन्य शहरों में ऑड-इवेन व्यवस्था आजमानी चाहिए?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

याराना इमरान से अरु भारत से घात,
इसीलिए तो खा रहे हैं सिद्धू जी मात।
हैं सिद्धू जी मात न कोई रहा पुछत्तर,
झेलेगा अब कौन गलतियां इनकी सत्तर।
बीजेपी-कांग्रेस सभी ने इनको जाना,
जाय निभाओ आप पाक से अब याराना।
- ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

बदले पुलिस की कार्यशैली

कैलाश बिश्नोई
अध्येता, दिल्ली विश्वविद्यालय

कानून व्यवस्था की दशा अधिक से अधिक दुरुस्त हो, इसके लिए पुलिस की कार्यशैली में कैसे बदलाव होना चाहिए कि पुलिस स्मार्ट और जवाबदेह बने, आज यह बड़ा सवाल है

देश में पुलिस सुधारों की तमाम कवायद के बावजूद अभी भी ज्यादातर पुलिसकर्मी ड्यूटी के बोझ से दबे हैं। औसतन 14 घंटे तक पुलिसकर्मियों को ड्यूटी करनी पड़ती है, यह बात सीएसडीएस और कॉमन कॉज की तरफ से जारी रिपोर्ट 'स्टेटस ऑफ पोलिसिंग इन इंडिया 2019' में सामने आई है। इस रिपोर्ट को 21 राज्यों के बारह हजार पुलिसवालों और उनके परिवार के दस हजार सदस्यों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है। इससे पुलिस विभाग के भीतर महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को लेकर 'पुरुष' पुलिसकर्मियों के पूर्वाग्रह, अपराध से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे की जर्जर हालत, आधुनिक तकनीकों की कमी के बारे में पता चलता है।

इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 46 फीसद पुलिसवालों ने कहा कि उन्हें जब सरकारी वाहन की आवश्यकता थी, तब वाहन मौजूद नहीं था। 41 फीसद मानते हैं कि वे अपराध स्थल पर इसलिए नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उनके पास स्टाफ नहीं था। सीएसडीएस की रिपोर्ट के अनुसार देश में महिला पुलिसकर्मी महज 7.28 प्रतिशत ही हैं। जबकि सरकार ने तय किया है कि हर राज्य में 33 फीसद महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए। लेकिन किसी भी राज्य में यह संख्या पूरी नहीं हुई।

स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सक्षम पुलिस तंत्र का होना जरूरी है। कानून- व्यवस्था की अच्छी स्थिति में ही देश का आर्थिक विकास हो पाता है। लेकिन भारतीय पुलिस आज भी 1861 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पुलिस अधिनियम के माध्यम से संचालित होती है। पुलिस प्रशासन का मूल काम समाज में अपराध को रोकना और कानून व्यवस्था को कायम रखना है। जबकि ब्रिटिश हुकूमत ने 1861 के पुलिस अधिनियम का निर्माण दरअसल भारतीयों के दमन और शोषण के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया था। इसलिए दमनकारी और शोषणकारी पुलिस अधिनियम की राह पर चलने वाली पुलिस व्यवस्था से स्वच्छ छवि की उम्मीद कैसी की जा सकती है? सच यह है कि इसी कारण से समाज में पुलिस का चेहरा बदनाम हुआ। हमारा दुर्भाग्य है कि हम अभी तक ब्रिटिश-कालीन पुलिस व्यवस्था में देश की मांग के अनुरूप सुधार करने में नाकाम रहे हैं। अधिकांश राज्य कुछ फेरबदल के साथ पुराने भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 का ही पालन करते हैं। हालांकि अब यह मांग जोर पकड़ने लगी है कि पुलिस अधिनियम, 1861 को किसी ऐसे कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए जो कि भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक स्वरूप और बदले हुए वक्त से मेल खाता हो।

पुलिस बल अत्यधिक कार्यबोझ से दबी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस बल अपनी क्षमता का मात्र 45 प्रतिशत ही राष्ट्र को दे पा रहे हैं। बुनियादी ढांचे की कमी, जनशक्ति एवं कार्यात्मक स्वायत्तता का अभाव, इसका मुख्य कारण है। संयुक्त राष्ट्र के मानक के अनुसार प्रति लाख नागरिक पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए, लेकिन भारत में यह आंकड़ा 144 ही है। एक तो पर्याप्त पुलिस बल नहीं है, दूसरे स्वीकृत क्षमता के करीब एक चौथाई पद खाली हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश में पुलिस के लगभग पांच लाख पद खाली पड़े हैं। यही नहीं, देश में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के कुल 4,883 पद अधिकृत हैं, लेकिन इनमें भी 900 से ज्यादा पद खाली हैं। लिहाजा पुलिस पर कार्य बोझ कम करने के लिए रिक्त सभी पदों को भरना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

देश भर में इस विभाग में लगभग 24 लाख कर्मचारी हैं। लेकिन देश का नागरिक पुलिस थाने में कदम रखने से भी कतराता है। उसे यह भरोसा नहीं है कि उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और उस दिशा में किसी तरह की कार्रवाई भी होगी। दरअसल पुलिस ने जनता का सहयोगी होने के अपने दायित्व को लगभग भुला दिया है। भारतीय पुलिस बल पर यह आरोप अक्सर लगाया जाता है कि यह अनुत्तरदायी तरीके से कार्य करती है। कई घटनाएं यह साबित करती है कि पुलिस या तो अपराध की ओर आंख मूंद लेती है या फिर लापरवाह, अरुचिपूर्ण और अपराध के खिलाफ उत्साहहीन तरीके से कार्य करती है। पुलिस द्वारा अपराध के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने में तमाम तरह के बहाने बनाए जाते हैं।

यहां सवाल यह भी है कि एक औपनिवेशिक मानसिकता से रची-बसी पुलिस व्यवस्था में कैसे नवीन लोकतांत्रिक और संवेदनशील गुण

प्रतीकात्मक

समाहित किए जाएं? इस दिशा में 2006 में पुलिस सुधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश व द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें महत्वपूर्ण हैं। सर्वोच्च अदालत का पुलिस सुधार मुख्यतः स्वायत्तता, जवाबदेही और लोकोन्मुख होने की ओर था। लेकिन राज्य सरकारों ने इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंताजनक है।

देश भर में पुलिस बलों में पर्याप्त और अपेक्षित कौशल तथा प्रशिक्षण की कमी रही है। ऐसे में वक्त की मांग को समझते हुए पुलिस भर्ती और प्रशिक्षण के लिए देशव्यापी 'एक्शन प्लान' बनाने की आवश्यकता है। यह समस्त अभियान तकनीक को केंद्र में रखकर चलाया जाए। एक ऐसे पुलिस वाले से हम ईमानदारी की उम्मीद नहीं रख सकते, जो स्वयं रिश्वत देकर पुलिस में भर्ती हुआ है। इसलिए पूरी भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता लानी होगी। प्रधानमंत्री ने पुलिस प्रशिक्षण में भावनात्मक पक्ष पर जोर दिए जाने की बात को स्वीकार किया है। उनके अनुसार सामान्य मनोविज्ञान एवं व्यावहारिक मनोविज्ञान को भी पुलिस प्रशिक्षण का अनिवार्य अंग बनाया जाना चाहिए।

भारत में पुलिस सुधार कानून एक लंबी बहस का हिस्सा जरूर रहे हैं, लेकिन सुधार ज्यादातर कागजों तक ही सीमित रह गए हैं जिस कारण पुलिस व्यवस्था को निष्पक्ष, कार्यकुशल, पारदर्शी और पूर्णरूप से उत्तरदायी नहीं बनाया जा सका है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में पुलिस प्रमुखों के एक सम्मेलन में पुलिस को स्मार्ट बनाने की बात की थी। पुलिस को स्मार्ट बनाने की कल्पना से जुड़े ये आदर्श वाक्य हैं- पुलिस संवेदनशील हो, आधुनिक और गतिशील हो, सतर्क और जिम्मेदार हो, भरोसेमंद एवं दायित्व का निर्वहन करने वाली हो और तकनीक में दक्ष व प्रशिक्षित हो।

24.44 लाख पर्यटक पहुंचे बीते एक साल के दौरान स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को देखने, जबकि इस दौरान ताज महल को देखने 64.58 पर्यटक आए। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की टिकटों की बिक्री से 63 करोड़, जबकि ताजमहल से 56 करोड़ रुपये आए।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 7 नवंबर 2019

कीटाहार को पोषाहार बनाने पर वैज्ञानिक कर रहे काम

जागरण विशेष ▸ जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण शोध एवं सतत विकास संस्थान की अगुआई में हो रहा अनुसंधान

दीप सिंह बोरा, अल्मोड़ा

भविष्य में खाद्य संकट की चुनौती से निपटने में कीटाहार कितना कारगर होगा, इसकी संभावनाएं तलाशने और ऐसी कीट प्रजातियों का वजूद बचाने की दिशा में भारत में अपने तरह का पहला प्रयास शुरू किया गया है। उत्तर-पूर्व के राज्यों में खाने योग्य कीटों पर शोध किया जा रहा है।

खाद्य संकट और खासतौर पर पोषण की कमी से निपटने के लिए देश-दुनिया में नित नए शोध हो रहे हैं। वैज्ञानिकों की नजर अब उन कीटों पर टिक गई है, जो पारंपरिक भोजन का अभिन्न हिस्सा ही नहीं, बल्कि पोषक तत्वों की पूर्ति भी कर सकते हैं। लगातार उपभोग से इन कीटों व जंतुओं का वजूद ही खतरे में न पड़ जाए, इसके लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने अनूठा अनुसंधान शुरू कर दिया है। खास बात कि राष्ट्रीय अध्ययन मिशन के तहत इस अनुसंधान की अगुआई उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थित जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण शोध एवं सतत विकास संस्थान कर रहा है। दरअसल, दुनिया की 80 फीसद आबादी परंपरागत भोजन के रूप में कीटों का सेवन करती है। भारत के बड़े हिस्से में तो नहीं, लेकिन देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, अरुणाचल व नगालैंड में पोषक तत्वों से युक्त कीटों का बाजार लगता है। वहीं, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा और झारखंड में भी भोजन व उपचार आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। पड़ोसी देश चीन में बहुतायत उपयोग के बाद भी निर्यात तक होता है। आने वाले समय में नियमित व अधिक भक्षण से इन कीटों की प्रजातियां खत्म न होने लगें, इसे लेकर वैज्ञानिक चिंतित भी हैं।

कीटों के जरिये प्रोटीन व अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति, भविष्य में एक बेहतर पोषाहार की संभावनाएं तलाशने, आजीविका से जोड़ने के साथ इन कीटों के संरक्षण के मकसद से ही राष्ट्रीय अध्ययन मिशन के तहत हिमालयी राज्यों में अनुसंधान शुरू किया गया है। नोडल संस्थान जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण शोध व सतत विकास संस्थान के प्रोजेक्ट पर मणिपुर में खाने योग्य कीटों पर सघन शोध किया जा रहा। इसमें कृषि एवं वानिकी कॉलेज केंद्रीय विवि पासीघाट अरुणाचल तथा अशोक ट्रस्ट पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण शोध संस्थान, बेंगलुरु के वैज्ञानिक अहम भूमिका निभा रहे हैं।

अब तक 439 विभिन्न कीट प्रजातियां चिह्नित : वैज्ञानिकों की मानें तो पूर्वोत्तर राज्यों के इन कीटों का आसान खाद्य पदार्थ के साथ उच्च ऊर्जा व प्रोट्रीन के प्रबल स्रोत के रूप में उपयोग हो सकता है। अब तक 439 विभिन्न कीट प्रजातियां चिह्नित की जा चुकी हैं। इन्हें संरक्षित कर खाद्य नमूने बना सतत उपयोग, उपभोग व प्रबंधन के साथ कीट पालन की वैज्ञानिक तकनीक विकसित की जाएगी। उम्मीद की जा रही कि पोषाहार के रूप में कीटाहार पर अनुसंधान मील का पत्थर साबित होगा।

बनेगा डिजिटल कीट पुस्तकालय व संग्रहालय : कौन से कीट जहरीले हैं और कौन सी किस्में खाने योग्य हैं, राष्ट्रीय हिमालयी मिशन के तहत देश की पहली ऑनलाइन कीट लाइब्रेरी व संग्रहालय भी तैयार किया जा रहा।

देश के पूर्वोत्तर राज्यों सहित एशिया की कई जनजातियों में कीटाहार प्रचलन में है। प्रतीकात्मक

दुनियाभर में कीटों की 1500 से ज्यादा प्रजातियां मानव खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग कर सकते हैं। भारत में ही करीब 100 से अधिक कीट प्रजातियां खाने योग्य हैं और अनेक प्रजातियों का रासायनिक अध्ययन भी किया जा रहा है। वहीं, परंपरात ज्ञान को संकलित कर कीट प्रजातियों से प्राप्त प्रोटीन को संग्रहित कर करने पर भी अनुसंधान किया जा रहा है।

– डॉ. पी शांति बाला, परियोजना वैज्ञानिक

राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन के तहत प्रोजेक्ट में पूर्वोत्तर राज्यों में यह अनुसंधान होना है, जहां विभिन्न कीट खाद्य का हिस्सा हैं। मकसद पोषण की कमी को पूरा कर कीटों का संरक्षण करना भी है।

– प्रो. किरीट कुमार, नोडल अधिकारी राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

हावड़ा-नई दिल्ली के बीच दौड़ेगी सेमी हाई स्पीड ट्रेन

तापस बनर्जी, धनबाद

▸ धनबाद के प्रधानखंता से पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक 417.2 किमी रेलवे ट्रैक के सिग्नलिंग सिस्टम समेत अन्य बदलाव को खर्च होंगे 1946.6 करोड़

हावड़ा से नई दिल्ली के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने को लेकर तैयारियों ने रफ्तार ले ली है। इसमें कानपुर-नई दिल्ली के साथ-साथ कानपुर-लखनऊ रेल मार्ग को भी शामिल किया गया है। 1525 किमी लंबे रेल मार्ग पर 160 से 200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने के लिए कई बदलाव होंगे। सिग्नल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल विभाग की ओर से होने वाले बदलाव के लिए प्राक्कलित राशि 6974 करोड़ है।

रेलवे ने नई दिल्ली से हावड़ा तक अलग-अलग जोन को इस प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। कहा गया है कि रेलवे बोर्ड और आरडीएसओ लखनऊ की ओर से किए गए परीक्षण में कई खामियां मिली हैं। उन खामियों को दूर करने संबंधी विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है। धनबाद के प्रधानखंता से पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक स्पीड बढ़ाने के लिए 1926.6 करोड़ खर्च का अनुमान है। इसके लिए धनबाद रेल मंडल से जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगी गई है। रेलवे के विभागीय अधिकारियों के अनुसार, प्रधानखंता से मुगलसराय के बीच 160 से 200 किमी की गति से ट्रेन चलाने के लिए 10 हाई थ्रस्ट क्लैंप टाइप प्वाइंट मशीन लगाई जा रही हैं। मतारी स्टेशन के पास मशीन लगाई जा चुकी है। इसकी मदद से ट्रैक को मजबूती मिलेगी।

160 किमी प्रति घंटा की गति या उससे अधिक रफ्तार से ट्रेन चलाने के लिए यह जरूरी होगा कि चालक को सिग्नल और इंटरलॉकिंग की जानकारी मिलती रहे। ऐसा न होने पर दुर्घटना की आशंका बनी रहेगी। इसके लिए इस रूट पर ट्रेन प्रोटेक्शन वॉर्निंग सिस्टम लगाए जाएंगे। इससे चालकों को दुर्घटना रहित रेल परिचालन में सहूलियत होगी।

सेमी स्पीड ट्रेनों के चलने के साथ ही यह व्यवस्था भी की जाएगी कि एक पटरी पर दो ट्रेनें न आ जाएं। इसके लिए ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर लगाए जाएंगे। एक्सल काउंटर एक से दूसरे स्टेशन तक जाने वाली ट्रेनों के एक्सल यानी पहिए गिन लेगा। सभी पहिए गुजर जाने के बाद ही सिग्नल बदला जा सकेगा। दो स्टेशन के बीच अगर ट्रेन दो हिस्से में बंट गई तो इसकी सूचना भी आसानी से मिल जाएगी।

ताकतवर हुआ डेंगू वायरस

ऋषि दीक्षित, कानपुर

▸ प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन कर रहा कम, कोशिका संरचना में भी ला रहा बदलाव

▸ हेमरेजिक फीवर और ऑटो इम्यून डिसआर्डर के मामले भी बढ़े

डेंगू वायरस ताकतवर हो गया है। इससे इस बार मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ा है। वह श्वेत रक्त कणिकाओं (लिंफोसाइट) पर हमला कर उनकी संरचना बदल रहा है। शरीर में एंटीबॉडीज बन रहे हैं। ऑटो इम्यून डिसआर्डर की आशंका बढ़ने लगी है। लिंफोसाइट और ल्यूकोसाइट की बढ़ी मात्रा कैंसर की आशंका दिखाती है, लेकिन लैब परीक्षण में प्रमाण नहीं मिल रहा है।

अध्ययन में मिले तथ्य डेंगू वायरस को पिछले वर्ष की तुलना में ताकतवर बता रहे हैं। मसलन, यह डेंगू वायरस मरीज को दो दिन में ही शॉक सिंड्रोम की गिरफ्त में ला रहा है। पिछले वर्षों में संदिग्ध मरीजों में 25 फीसद डेंगू पॉजिटिव होते थे। इस वर्ष साठ फीसद से अधिक हैं। 30 फीसद मरीजों में ही प्लेटलेट्स काउंट्स कम होते थे, इस वर्ष 90 फीसद में प्लेटलेट्स काउंट 15 हजार तक हैं। हीमोग्लोबिन भी कम है। प्लेटलेट्स पैक चढ़ाने पर भी मात्रा नहीं बढ़ रही है। जिन मरीजों की मौत हुई है, उनमें से कई में एंटीबॉडीज पॉजिटिव और इम्यून डिसआर्डर के लक्षण दिखे हैं। माइक्रोस्कोपिक परीक्षण में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संरचना में बदलाव दिख रहा है।

लखनऊ-कानपुर में सर्वाधिक केस : सरकारी आंकड़े में उत्तर प्रदेश में लखनऊ पहले और कानपुर दूसरे नंबर पर है। निजी लैब के डेंगू मरीजों के आंकड़े भी शामिल कर लें तो मरीजों का आंकड़ा तीन हजार से ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन शासन को केवल जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज और उर्सला अस्पताल की लैब के आंकड़े भेजे जा रहे हैं। कानपुर में 1630 डेंगू मरीज मिले हैं। 15 दिनों में 57 डेंगू मरीज दम तोड़ चुके हैं, हालांकि शासन मौत के इन आंकड़ों को नकार रहा है।

पिछले 15 दिनों में हेमरेजिक डेंगू के मरीज अधिक आ रहे हैं। अगर पहले किसी को डेंगू या फीवर हुआ है तो दूसरी बार का संक्रमण खतरनाक है।

– डॉ. एके आर्या, प्रोफेसर, बाल रोग, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज

शरीर पर बैक्टीरिया या वायरस के हमले में संक्रमण से बचाव का काम श्वेत रक्त कणिकाएं (डब्ल्यूबीसी) करती हैं, लेकिन कोशिकाओं की संरचना में बदलाव से प्रतिरोधक क्षमता (इम्यून सिस्टम) कमजोर हो रही है। ये कोशिकाएं प्रतिरक्षण के बजाए शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती हैं, जो जानलेवा साबित होता है। इसका इलाज इम्यूनोग्लोबुलिन एवं स्टेरायड से संभव है।

– प्रो. एमपी मिश्रा, निदेशक, राजकीय जेके कैंसर संस्थान सह वरिष्ठ पैथालॉजिस्ट

घूंघट से निकल लिख दी बिग मिलियन सेल की पटकथा

बदली तस्वीर ▸ स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम में रिकॉर्ड प्रदर्शन के बल पर देशभर में छाया उप्र का टप्पल ब्लॉक

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला समूह हर रोज बेच रहे 12.50 लाख रुपये का सामान

सुरजीत पुंढीर, अलीगढ़

स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम (स्टार्टअप विलेज आंत्रप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, एसवीईपी) में पहली बार देश में एक दिन में 12.50 लाख रुपये की बिक्री का रिकॉर्ड बना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का टप्पल ब्लॉक सुर्खियों में है। इस उपलक्ष्य में सरकार ने तीन नवंबर को एसवीईपी का पहला 'बिग मिलियन डे' यहां मनाया। टप्पल की महिलाओं ने घूंघट की ओट से निकल ग्राम्य विकास की नई इबारत लिख दी है।

नारी सशक्तीकरण

यह पहला अवसर है, जब देश में इस कार्यक्रम के तहत किसी ब्लॉक से एक दिन में 12 लाख रुपये से अधिक की बिक्री दर्ज की गई। टप्पल ब्लॉक में स्थापित 1155 कुटीर उद्योगों से 87 गांवों की करीब 10 हजार महिलाएं सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। छोटी-छोटी इकाइयों में यह महिलाएं जूते, चप्पल, रेडीमेड कपड़े, दोना-पत्तल, बैग, एलईडी बल्ब जैसे अनेक उत्पाद बना रही हैं।

▸ ब्लॉक में 1155 कुटीर उद्योगों से जुड़ी हैं 10 हजार महिलाएं

▸ जूते, चप्पल, रेडीमेड कपड़े, दोना-पत्तल, बैग, एलईडी बल्ब जैसे अनेक उत्पाद कर रहीं तैयार

▸ 2014-15 में हुई थी शुरुआत, पांच वर्ष की अवधि के दौरान इसका विस्तार 24 राज्यों तक हुआ

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में टप्पल गांव में हवाई चप्पल बनाने की एक इकाई में कार्यरत स्थानीय महिलाएं। जागरण

साल में करीब 40 करोड़ के उत्पाद तैयार होते हैं।

दीनदयाल अंत्योदय योजना (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के तहत स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम की शुरुआत 2014-15 में हुई। 2018-19 तक, पांच वर्ष की अवधि में इसका विस्तार 24 राज्यों के 125 विकासखंडों (ब्लॉक) तक हुआ। योजना का ध्येय ग्रामीण महिलाओं को स्वउद्यम (कुटीर) स्थापित करने के लिए मदद और संसाधन मुहैया कराना है। द्वितीय चरण में देश के सभी विकासखंडों तक इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। तीन नवंबर को उप्र का टप्पल एसवीईपी में एक दिन में सबसे अधिक कारोबार करने वाला ब्लॉक बन गया। वर्ष 2017 में यहां इस योजना से महिला समूहों का जुड़ना शुरू हो गया था। सरकार ने एसवीईपी में चयन के बाद महिला समूहों को प्रशिक्षण के साथ सस्ते ब्याज पर कर्ज भी दिया, तो कारोबारी गति और तेज हो गई। यही नहीं महिलाओं की आय भी लगातार बढ़ रही है। कुराना गांव की बबली कहती हैं कि उनका समूह बैग बनाकर आसपास के कस्बों में सप्लाई करता है। इससे पर्याप्त बचत हो जाती है। यही नहीं पहले देश में ऐसे कार्यक्रमों के प्रशिक्षण के लिए जहां आंध्र प्रदेश की महिला उद्यमियों को ही प्रमुख रूप से बुलाया जाता था, अब टप्पल से बुलाया जाता है। पिछले दिनों ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देशभर में एसवीईपी का सर्वे कराया, तो टप्पल सबसे अधिक कुटीर उद्योग चलाने वाला ब्लॉक मिला। एक दिन में 12 लाख रुपये से ज्यादा के सामान की बिक्री करने के लिए सरकार ने तीन नवंबर को टप्पल ब्लॉक में देश का पहला 'बिग मिलियन डे' मनाया। बिग मिलियन डे का चलन ई-कॉमर्स कंपनियों में ही देखने को मिलता था, जो रिकॉर्ड बिक्री पर इसे मनाती हैं। प्रकारांतर से ही सही, सरकारी स्तर पर यह पहली बार मनाया गया है। इसमें प्रदेश व केंद्र के प्रतिनिधि शामिल हुए।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

मैं 2016-17 में समूह से जुड़ी थी। शुरुआत में इतना पैसा नहीं था कि कोई बड़ा काम शुरू कर सकूं। फिर समूह को स्टार्टअप योजना में शामिल कर दिया गया। अब मैं घर पर चप्पल बनाने की यूनिट चला रही हूं। इसमें छह अन्य महिलाएं भी सहयोग करती हैं। करीब पांच हजार रुपये की बिक्री हर रोज हो जाती है।

– रानी देवी, संचालक अमन समूह, टप्पल

टप्पल के महिला समूह बेहतर काम कर रहे हैं। हर दिन इनके बनाए सामान की बिक्री 12 लाख के करीब है। स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम से जुड़े किसी भी विकासखंड के सापेक्ष यह आंकड़ा देश भर में सबसे अधिक है।

– जनार्दन यादव, जिला समन्वयक, एनआरएलएम, अलीगढ़

टप्पल ब्लॉक में सक्रिय स्वसहायता समूहों की महिलाओं का काम प्रशंसनीय है। इनकी मेहनत से यहां हर दिन करीब 12 लाख के सामान की बिक्री हो रही है। 12.50 की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज होने के उपलक्ष्य में तीन नवंबर को यहां बिग मिलियन डे मनाया गया।

– अनुनय झा, मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़, उप्र

जर्मनी की तर्ज पर उत्तराखंड में 'गंगा बॉक्स' होगा स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा

केदार दत्त, देहरादून

▸ पायलट प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कक्षा छह से 12 तक किया जाएगा शामिल

देवभूमि उत्तराखंड में अगले शैक्षणिक सत्र से कक्षा छह से 12 तक के विद्यार्थी राष्ट्रीय नदी गंगा के एंबेसडर बनेंगे। साथ ही वे तमाम गतिविधियों के जरिये न सिर्फ गंगा को समझेंगे, बल्कि इसके संरक्षण को जनजागरण में जुटेंगे। यह संभव होगा जर्मनी की डेन्यूब नदी की तर्ज पर तैयार ट्रेनिंग मॉड्यूल 'गंगा बॉक्स' से। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) और जर्मन सरकार की संस्था जीआइजेड की इस पहल को पायलट प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में धरातल पर उतारा जा रहा है। इस क्रम में उत्तराखंड के चयनित स्कूलों के शिक्षकों की ट्रेनिंग इस माह के आखिर में देहरादून में होगी। प्रशिक्षण के अन्य दौर भी चलेंगे, जिनमें विद्यार्थी भी शामिल होंगे। इसके बाद गंगा बॉक्स को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाएगा।

राष्ट्रीय नदी गंगा की स्वच्छता व निर्मलता को केंद्र सरकार गंभीरता से जुटी है। इस क्रम में एनएमसीजी की नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा से सटे शहरों में सीवरेज निस्तारण और गंदे नालों की टैपिंग से जुड़े कार्य चल रहे हैं। उत्तराखंड में भी गंगा के उद्गम गोमुख से लेकर हरिद्वार तक के 15 शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व नालों की टैपिंग के कार्य अब अंतिम चरण में हैं।

यह है 'गंगा बॉक्स' : जर्मनी की डेन्यूब नदी भी एक दौर में प्रदूषित थी। इसे साफ-सुथरा करने को जर्मन सरकार ने ठीक वैसी ही मुहिम चलाई जैसी वर्तमान में गंगा स्वच्छता को लेकर भारत में चल रही है। जर्मनी में मुहिम के तहत डेन्यूब नदी को स्कूलों से जोड़ा गया। इसे नाम दिया गया 'डेन्यूब बॉक्स'। अब इसी तर्ज पर मिशन क्लीन गंगा के तहत गंगा बॉक्स बनाया गया है। भारत में जीआइजेड की तकनीकी विशेषज्ञ डॉ. अंजना पंत बताती हैं कि यह गतिविधि आधारित मॉड्यूल है। इसमें विद्यार्थियों को न सिर्फ गंगा से जोड़ा जाएगा, बल्कि वे तमाम गतिविधियों के जरिये गंगा को जानेंगे, समझेंगे। इसके लिए सरल व रोचक सामग्री तैयार की गई है। बच्चे एंबेसडर बनकर अन्य लोगों को गंगा की निर्मलता के लिए प्रेरित करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में गंगा बॉक्स के संबंध में एनएमसीजी व जीआइजेड के बीच एमओयू हो चुका है।

ऐसे चलेगी मुहिम : उत्तराखंड में 'गंगा बॉक्स' कार्यक्रम को राज्य परियोजना प्रबंधन समूह यानी एसपीएमजी (नमामि गंगे) व शिक्षा विभाग के समन्वय से धरातल पर उतारा जाएगा। जीआइजेड के राज्य समन्वयक मिराज अहमद बताते हैं कि हाल में गंगा बॉक्स की लांचिंग दिल्ली में हुई। इस मौके पर राज्य के 20 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों व 40 शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई। अगले दौर का प्रशिक्षण इस माह के आखिर से शुरू होंगे।

शीतकाल के लिए बंद हुए तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट

▸ आठ नवंबर को मार्कंडेय मंदिर मक्कूमठ में अपनी शीतकालीन गद्दी पर विराजमान होंगे बाबा

▸ कपाट बंद होने के बाद पहले दिन रात्रि प्रवास के लिए चोपता पहुंची बाबा तुंगनाथ की उत्सव डोली

कपाट बंद होने के बाद बाबा तुंगनाथ की डोली शीतकालीन प्रवास के लिए मार्कंडेय मंदिर के लिए रवाना हुई। फोटो : मंदिर समिति

संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग

पंच केदार में शामिल तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट बुधवार को पौराणिक रीति-रिवाजों के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस मौके पर पर 650 से अधिक यात्रियों ने बाबा तुंगनाथ के दर्शन किए। अब शीतकाल के छह महीने बाबा मक्कूमठ स्थित मार्कंडेय मंदिर में ही अपने भक्तों को दर्शन देंगे।

उच्च हिमालय में समुद्रतल से 12073 फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान तुंगनाथ मंदिर में सुबह छह बजे से पुजारी समेत वेदपाठियों ने गर्भगृह में बाबा की विशेष पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इसके बाद स्वयंभू लिंग को समाधि दी गई और बाबा की भोगमूर्ति का शृंगार कर उसे डोली में विराजमान किया गया। डोली के बाहर आते ही प्रशासन, श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों और हक-हकूकधारियों की मौजूदगी में ठीक 11.30 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए।

इसके साथ ही मंदिर की तीन परिक्रमा करने के बाद बाबा की उत्सव डोली अपने प्रथम पड़ाव चोपता के लिए रवाना हुई। इस दौरान भक्तों के जयकारों से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। सात नवंबर को डोली भनकुंड में रात्रि प्रवास करेगी और आठ नवंबर को बाबा मार्कंडेय मंदिर स्थित अपनी शीतकालीन पर विराजमान हो जाएंगे।

माउंट एवरेस्ट के शिखर पर 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाएंगे हरियाणा के रोहताश

जागरण संवाददाता, हिसार

▸ नेपाल के बाबुश्री शेरपा के नाम है एवरेस्ट पर 21 घंटे रुकने का रिकॉर्ड

▸ हिसार के गांव मलापुर के पर्वतारोही ने मई 2018 को किया था एवरेस्ट फतह

माउंट एवरेस्ट फतह कर चुके हरियाणा के हिसार जिले के गांव मलापुर निवासी रोहताश खिलेरी अब नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। वह अप्रैल, 2020 में एवरेस्ट के शिखर पर लगातार 24 घंटे रुककर एक नया इतिहास बनाएंगे। हाल ही में कपिल शर्मा शो के हिस्सा बने पर्वतारोही रोहताश ने अपने अगले मिशन के बारे में जानकारी दी।

हिसार से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित गांव मलापुर के किसान सुभाषचंद्र के बड़े बेटे रोहताश खिलेरी ने 16 मई, 2018 को माउंट एवरेस्ट फतह किया था। फिलहाल वह सेवन समिट के मिशन पर हैं, जिनमें से वे अभी तक एशिया के माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका के माउंट किलीमंजारो और यूरोप महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एलब्रुश को फतह कर चुके हैं। रोहताश ने बताया कि वह पर्वतारोहण के क्षेत्र में कुछ अलग करना चाहते हैं। इसी कड़ी में वह माउंट एवरेस्ट के शिखर पर 24 घंटे रहकर नया रिकॉर्ड बनाएंगे। रोहताश बताते हैं कि 19 वर्ष पहले नेपाल के बाबुश्री शेरपा ने 1999 में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर रुककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसके बाद दो विदेशी लोगों ने इस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों की मौत हो गई थी।

काफी मुश्किल है मिशन : माउंट एवरेस्ट पर लगातार 24 घंटे रहना मुश्किल भरा होगा, क्योंकि वहां का तापमान माइनस 50 स 60 डिग्री होता है। इसके अलावा हवा की गति भी अधिक होती है। इस कारण वहां पर टेंट लगाना या रुकना बहुत ही कठिन होता है। इतनी ऊंचाई पर पर्याप्त ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती। रोहताश ने बताया कि उनका लक्ष्य काफी चुनौतियों से भरा है, लेकिन वह चाहते हैं कि तिरंगा लगातार 24 घंटे तक माउंट एवरेस्ट पर लहराए। इसके लिए वह कड़ी मेहनत कर रहे हैं। रोहताश बताते हैं कि वह हर रोज 15 किग्रा वजन के साथ लगभग दस किलोमीटर की रेस लगा रहे हैं। वहीं, फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने के लिए दो से तीन घंटे तक तैराकी व हर रोज सुबह तीन घंटे योग और मेडिटेशन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी अब तक की सफलता का श्रेय अपने गुरु एवं भारतीय सेना के कमांडो अशोक शुक्ल, इंटरनेशनल स्कीइंग प्लेयर विकास राणा और कोर फिटनेस जिम के डायरेक्टर अमन वर्मा, मैनेजर श्रीकांत गोर को दिया है, जिन्होंने हर कदम पर उनकी हौसला अफजाई की और उन्हें इस मुश्किल रास्ते को फतह करने की हिम्मत दी।

पर्वतारोही रोहताश खिलेरी। फाइल

कपिल शर्मा ने दीं शुभकामनाएं

पर्वतारोहण में विशेष उपलब्धियों व जुनून को देखते हुए रोहताश खिलेरी को अभी हाल ही में द कपिल शर्मा शो में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। शो को होस्ट कर कॉमेडियन कपिल शर्मा, क्रिकेटर हरभजन सिंह, उनकी पत्नी गीता बसरा और शो की जज अर्चना पूरन सिंह के साथ उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। इस शो में रोहताश ने अपने संघर्ष व उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए देश के समक्ष अपना विजन पेश किया था।

अनदेखी

1962 के भारत-चीन युद्ध से पहले इसी दुर्गम रास्ते से होता था भारत-तिब्बत के बीच व्यापार, मरम्मत के लिए वित्तीय स्वीकृति न मिलने से पर्यटकों की पहुंच से है दूर

मरम्मत के इंतजार में गर्तांगली की हेरिटेज सीढ़ियां

शैलेंद्र गोदियाल, उत्तरकाशी

समुद्रतल से 11 हजार फीट की ऊंचाई पर भारत-चीन सीमा पर स्थित गर्तांगली की हेरिटेज सीढ़ियां मरम्मत के इंतजार में हैं। गर्तांगली तक पहुंचने वाले रास्ते और सीढ़ियों की मरम्मत के लिए अभी तक वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल पाई है। जिस कारण लोक निर्माण विभाग अभी तक निविदा भी जारी नहीं कर सका। ऐसे में गर्तांगली अभी भी पर्यटकों की पहुंच से दूर है।

उत्तरकाशी जिले में जाड़ गंगा घाटी में स्थित सीढ़ीनुमा यह मार्ग दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में शुमार है। करीब 300 मीटर लंबी यह गली वर्ष 1962 तक भारत-तिब्बत व्यापार का प्रमुख मार्ग हुआ करती थी। कहा जाता है कि यह मार्ग 17वीं सदी में पेशावर से आए पठानों ने चट्टानों को काटकर बनाया था। वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध से पहले व्यापारी इस रास्ते से ऊन, चमड़े से बने वस्त्र व नमक लेकर बाड़ाहाट (उत्तरकाशी का पुराना नाम) पहुंचते थे। युद्ध के बाद इस मार्ग पर आवाजाही बंद हो गई, लेकिन सेना का आना-जाना जारी रहा। करीब दस वर्ष बाद 1975 में सेना ने भी इस रास्ते का इस्तेमाल बंद कर दिया। ऐसे में बीते 43 साल से मार्ग का रख-रखाव न होने के कारण सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसके अलावा सीढ़ियों के किनारे लगी सुरक्षा बाड़ की लकड़ियां भी सड़-गल चुकी हैं। ढाई वर्ष पूर्व प्रशासन ने इस मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया था। साथ ही पर्यटन विभाग ने इसकी मरम्मत के लिए 26 लाख की धनराशि गंगोत्री नेशनल पार्क को दी। यह राशि पार्क प्रशासन ने भैरव घाटी पुल से लेकर गर्तांगली तक रास्ता बनाने में खर्च की, लेकिन पहाड़ी को काटकर लोहे की मोटी-मोटी छड़ों के सहारे बनाए गए सीढ़ीनुमा रास्ते की मरम्मत करने से पार्क ने हाथ खड़े किए। इसके बाद यह कार्य लोनिवि को सौंप दिया गया। लोनिवि ने भी 65 लाख रुपये का प्राक्कलन तैयार कर शासन को भेजा, लेकिन अभी तक इस मामले में धनराशि स्वीकृत नहीं हो पाई है। नतीजा, न तो निर्माण कार्य शुरू हो सका है और न पर्यटक गर्तांगली जा पा रहे हैं।

उत्तरकाशी में 17वी शताब्दी में पहाड़ी को काटकर तिब्बत जाने के लिए तैयार की गईं गर्तांगली की हेरिटेज सीढ़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। जागरण

इस मामले में गंगोत्री नेशनल पार्क के उप निदेशक एनबी शर्मा का कहना है कि गर्तांगली की सीढ़ियां पहाड़ी को काटकर विशिष्ट तकनीकी से बनाई गई हैं। इस तकनीकी से निर्माण लोनिवि ही कर सकता है, जबकि लोनिवि के ईई आरएस खत्री ने बताया कि गर्तांगली की मरम्मत का प्राक्कलन शासन को भेजा जा चुका है। वित्तीय स्वीकृति मिलते ही कार्य की निविदा जारी कर दी जाएगी।

दैनिक जागरण
सबरंग
साहित्य के...
नई दिल्ली, गुरुवार, 7 नवंबर, 2019
सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें : sabrang@nda.jagran.com
https://www.facebook.com/jagransabrang/

कनॉट प्लेस हर किसी का मीटिंग प्वाइंट होता था

दिल्ली मेरी यादें

रवीन्द्रनाथ टैगोर अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार-2019 से सम्मानित डॉ हरिसुमन बिष्ट प्रतिष्ठित कथाकार, लेखक हैं। हिंदी अकादमी में सचिव रहते हुए उल्लेखनीय कार्य कर चुके बिष्ट की प्रमुख रचनाएं आसमान झुक रहा है, आछरी-माछरी, भीतर कई एकांत यात्रा-वृतांत आदि हैं। हिंदी अकादमी की त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका 'इन्द्रप्रस्थ भारती' का 27 वर्ष तक कुशल संपादन किया। आकाशवाणी तथा दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रमों के निर्माण के लिए विषय विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं दीं।

पहाड़ों से उतर जब दिल्ली की धरा पर आया तो मेरे स्मृति पटल पर पहाड़ के सुंदर गांव...शुद्ध वातावरण शांति सब सजे हुए थे। शहर और गांव के बीच एक बड़ी रेखा थी। लेकिन जैसे-जैसे मैं दिल्ली की तरफ कदम बढ़ाता गया, इसमें रमने लगा तो मुझे आनंद की अनुभूति होने लगी। मैं 1977 में यहां पढ़ाई और नौकरी दोनों ही मकसद से आया था। हालांकि मेरी पढ़ाई दिल्ली के किसी विश्वविद्यालय से नहीं हुई, उसका एक बड़ा कारण दिल्ली विवि और जेएनयू का माहौल भी था। मैं शायद उस माहौल के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाया था। एक साल सिर्फ जेएनयू से रशियन भाषा का कोर्स जरूर किया। बहरहाल मैंने एमए और पीएचडी की पढ़ाई दूसरे विश्वविद्यालयों से पूरी की। पिता जी और बड़े भाई पहले से ही पहाड़गंज में रहा करते थे। उन दिनों पहाड़गंज बहुत रिहाइश इलाका होता था। एक और रोचक बात थी पहाड़ों से आने वाले लोग सबसे पहले पहाड़गंज पर ही एक छोटा सा सेंटर होता था, उसी में रहते थे। इस सेंटर में जगह भले कम दिखती थी लेकिन दिल सभी का बड़ा होता था। यह बात मैंने दिल्ली के परिवेश में भी महसूस की। यहां पहले लोग मिलनसार होते थे, उनके घर भले छोटे हों लेकिन दिल बहुत बड़े होते थे। अब इसके विपरीत है।

मैं जब 1977 में दिल्ली आया था उससे पहले ही कई पत्रिकाओं में मेरी कविताएं प्रकाशित हो रही थीं। और तब तक बनारस का साहित्यिक माहौल दिल्ली पहुंच चुका था। हर साहित्यकार के घर महीने में एक बार गोष्ठी जरूर होती थी। इसके अलावा साहित्यिक अड्डे होते ही थे। जगह-जगह सभागार थे। जहां कुछ न कुछ साहित्यिक हलचल चलती ही रहती थीं। दिल्ली के लाल किला पर होने वाला कवि सम्मेलन मुझे बहुत प्रिय था। उस सम्मेलन की सबसे बड़ी खासियत थी कि उस दौर के हर बड़े साहित्यकार की उपस्थिति ने उस मंच का सौंदर्य बढ़ाया है। विश्वसनीयता और मान बढ़ाया है, जिसे आज भी उस दौर का हर साहित्यकार याद करता है। उसे हम साहित्य का स्वर्णिम युग कह सकते हैं जो अब हाथ से निकला जा रहा है। **लेखन के लिए जगह नहीं, सोच की जरूरत होती है** : साहित्य अकादमी में समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका में जब मैं नौकरी करने लगा था तब मुझे साहित्य की गोष्ठियों में, कनॉट प्लेस के कॉफी हाउस में जाने का खूब अवसर मिलता था। मेरा सौभाग्य रहा कि नामवर सिंह, केदारनाथ, जैनेंद्र, अज्ञेय, विष्णु प्रभाकर, पंकज बिष्ट, भीष्म साहनी, राजकुमार सैनी, चंद्रशेखर, कमलेश्वर जैसे साहित्यकारों को सुनने, उनकी गोष्ठियों में भाग लेने कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। तब गोष्ठियों में जो चर्चा होती थी वह विषयवार तो होती ही थी। इसके अलावा किसी भी छोटे-बड़े रचनाकार के लिखे को सभी के बीच पढ़ा जाता था उस पर बाद में चर्चा होती थी। सुधार किया जाता था। एक प्रसंग बताता हूं मैंने एक गोष्ठी में एक बार विष्णु प्रभाकर जी से पूछा कि आप कैसे लिखते हैं, क्योंकि आप अजमेरी गेट जैसी जगह पर रहते हैं और मैं पहाड़गंज में रहता हूं, इन जगहों पर लिखने के जैसा कोई माहौल नहीं है? बहुत भीड़भाड़ वाली जगह हैं। तब विष्णु प्रभाकर ने कहा कि 'लिखने के लिए किसी स्थान या जगह की जरूरत नहीं होती। मन के उद्गार जब पैदा होते हैं तो आप उनको लिख लीजिए, उनका संयोजन करना बाद की बात है। इसलिए मैं लिखता हूं और उसे रख देता हूं और दूसरे दिन उसे फिर पढ़ता हूं उसमें कुछ कमी लगती है, सुधार करते हुए उसे दूसरे कागज पर लिखता हूं और पहले कागज को फाड़ देता हूं। ऐसा ही तीसरे दिन उस रचना में फिर से सुधार करता हूं, उसे नए पेज पर उतार लेता हूं...और फिर इसके बाद मेरे हाथ अब उस रचना को फाड़ने से रुक जाते हैं तब मुझे लगता है मेरी रचना मुकम्मल हो गई'। ये फाड़ना और फिर दोबारा सोचकर लिखना यही सुधारीय सोच है। यही है लेखन के प्रति प्रतिबद्धता। लेकिन आज सिर्फ एक बार लिखने के बाद हम दोबारा उसमें किसी वरिष्ठ से प्रतिक्रिया भी स्वीकार नहीं करते हैं। जबकि साहित्य सृजन का यही मूल सिद्धांत है।

पैदल चलना शौक होता था : अब बात दिल्ली शहर की करूं तो उन दिनों किसी से भी मिलना है या कहीं भी जाना है तो एक सेंटर प्वाइंट कनॉट प्लेस ही हुआ करता था। पहले लोगों को पैदल चलने का बहुत शौक होता था। मैं पहाड़गंज से रीगल पैदल चला जाता था। उन दिनों लोग साइकिल भी खूब चलाते थे। सुबह और शाम के वक्त सड़कों पर साइकिलों का सैलाब सा उतरता था। लेकिन अब तो सड़कों पर गाड़ी भर गईं और फुटपाथ गायब हो गए। एक तरीके से पैदल चलने का मौलिक अधिकार खत्म सा हो गया। अब ट्रैफिक का डर है, प्रदूषण का डर है। अब सड़क बगैर डर के नहीं चल सकते। असुरक्षा का भाव रहता है।

मनु त्यागी से बातचीत पर आधारित

बातचीत

ऐतिहासिक व पौराणिक आख्यानों को आधुनिक संदर्भ में ढालकर 84 वर्षीय दया प्रकाश सिन्हा ने भारतीय संस्कृति और अस्मिता को अपने नाटकों के माध्यम से प्रतिष्ठित और पुनर्जीवित किया। उनके बहुचर्चित कथा एक कंस की, रक्त अभिषेक, सीढ़ियां...ऐसे नाटक हैं जो दिल्ली की सामाजिक, राजनीतिक परंपरा को परिलक्षित करते हैं। सिन्हा नाटककार, निर्देशक, रंगकर्मी, अभिनेता के साथ-साथ प्रशासक भी हुए। पृथ्वी थियेटर की नाट्य परंपरा से प्रेरित होकर उन्होंने इस विधा को आगे बढ़ाया। दिल्ली में उनकी यात्रा कैसी रही? हिंदी नाट्य साहित्य और मंचन विधा के बारे में विस्तार से **दया प्रकाश सिन्हा** से **मनु त्यागी** की बातचीत हुई प्रस्तुत हैं प्रमुख अंश :

दिल्ली हर परंपरा को समृद्ध करती है

● दिल्ली में आप आए तो सरकारी कर्मी के रूप में लेकिन एक नाटक कार के रूप में पहचान बन गई?

-हंसते हुए, मैं 1968 में दिल्ली आया था मजिस्ट्रेट बनकर। शुरुआत में दो-तीन साल काम बहुत अधिक नहीं होता था। थियेटर पढ़ाने का शौक था सो पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ नाटकों में एक्टिंग भी करने लगा था। 1971 में 'मेरे भाई, मेरे दोस्त' नाटक लिखा और उसमें अभिनय भी किया। एक दिन दर्शकदीर्घा में तीन बेहद खास लोग मौजूद थे, हरिवंश राय बच्चन, त्रिलोकनाथ चतुर्वेदी और जगदीश चंद माथुर। नाटक खत्म होने के बाद तीनों ने मुझे तीन तरह की बातें कहीं। जगदीश जी ने कहा-तुम्हे यश नहीं मिलेगा। मैंने पूछा क्यों, तो जवाब मिला-क्योंकि शैक्षणिक वर्ग के लोग नौकरशाहों से ईर्ष्या भाव रखते हैं। शायद उनके साथ ऐसा हुआ हो, क्योंकि वह भी आइएएस थे और नाटक भी लिखे थे। शायद इसी वजह से उन्होंने यह बात कही होगी। टीएन चतुर्वेदी ने मेरे सामने ट्रांसफर का प्रस्ताव रखा। वहीं हरिवंश राय बच्चन जी चाहते थे कि मैं हेमलेट नाटक को निर्देशित करूं। यहां तक तो बात ठीक थी लेकिन उनकी एक शर्त थी। वह चाहते थे कि मुख्य किरदार उनका बेटा अमिताभ बच्चन करे। मैं इसके लिए तैयार नहीं हुआ। मुझे तो बचपन से ही थियेटर का शौक था। नाटक पढ़ा नहीं, कढ़ा है। कॉलेज के समय में ही नाट्य लेखन, अभिनय और निर्देशन तीनों काम किए। 1957 में सांझ सवेरा नाम से पहला नाटक लिख चुका था। तब मेरी उम्र 22 साल थी। उसमें भी खुद ही अभिनय किया था। स्वाभाविक है कि नौकरी पेशा होते हुए भी अपने लेखन और नाटकों के मंचन को कैसे थाम लेता। यह तो मैं अपने साथ ही अन्याय करता। दिल्ली आकर जो सिलसिला शुरू हुआ तो 1968 से 76 तक मैंने आठ नाटक लिखे। इन सभी नाटकों का लेखन, स्वरूप मेरे भीतर तैयार हो चुका था। किसी-किसी नाटक को लिखने में तो 30 साल लग गए।

● हिंदी साहित्य परंपरा के बारे में बताइए? खड़ी बोली कैसे हिंदी बन गई?

-हमारा हिंदी साहित्य तकरीबन 200 साल पुराना है। खड़ी बोली से हिंदी निकली। कविता भी बृज भाषा में ही होती थीं। राम-कृष्ण की जन्मभूमि के कारण, तीर्थ स्थान होने के कारण जितने में रचनाकार, साहित्यकार, कथाकार, कलाकार हुए, वे सब या तो अयोध्या में एकत्रित हो गए या फिर मथुरा में। इसलिए खड़ी, बृज बोली प्रचलित हो गई। सभी तरह की रचना, साहित्य इन्हीं भाषाओं में रचे जा रहे थे। लेकिन खड़ी बोली के विस्तार का कारण क्या था? मुस्लिम लोग बाहर से आए उनका संवाद यहां के लोगों से दिल्ली के आसपास के लोगों से हुआ, उनके जितने भी सहायक आदि थे, वे सब खड़ी बोली बोलते थे। मुसलमान पारसी, तुर्की, अफगानी बोलते थे। हिंदुस्तान की भाषा होने के कारण उनकी खड़ी बोली को मुसलमान हिंद की भाषा कहने लगे। बाद में वही खड़ी बोली हिंदी के रूप में स्थापित हो गई। इसमें खूब साहित्य रचा गया।

● दिल्ली के साहित्य चरित्र किस तरह से बदला?

-आजादी के बाद हिंदी का खूब महत्व बढ़ा। कई बड़ी पत्रिकाएं भी थीं। पंत जी, बच्चन जी सब थे। एक संभ्रांत वर्ग था उस समय। इसलिए हिंदी भी इस वर्ग की भाषा थी। लेकिन जैसे-जैसे संभ्रांत वर्ग ने हिंदी को छोड़ अंग्रेजी का दामन थामा, वैसे-वैसे हिंदी हर रूप में पिछड़ती चली गई। हिंदी का सिनेमा के रूप में तो विस्तार हुआ, लेकिन वह गुणवत्ता नहीं आई।

● 30 साल, इतना समय लगने की कोई खास वजह?

-हम जब भी लेखन करते हैं-चाहे उपन्यास हो, कहानी या कोई अन्य रचना। वह आपके दिमाग में एकदम नहीं गढ़ी जाती है। आप उसे शब्दों में तुरंत नहीं तुरुप देते हैं। इसी तरह मेरे नाटकों के प्लॉट तो बहुत पहले तैयार हो गए थे मन मे, लेकिन उसे कागज पर उतरने और मंचन में काफी समय लगा। 'कथा एक कंस की' का विचार मन में आने के 30 साल बाद इसे कलमबद्ध कर सका और मंचन तो और भी बाद में हुआ। इसी तरह 'सीढ़ियां' नाटक का 14 साल की कल्पना के बाद मंचन किया जा सका।

● पहली बार दिल्ली कैसी लगी? इस शहर ने कैसे स्वागत किया था?

-चूंकि मैंने गांव नहीं देखा था, गांव से नहीं आया था। इलाहाबाद आज जिसे प्रयागराज कहते हैं, उस माटी से आया था। वहीं विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी तो दिल्ली कुछ अजूबा शहर नहीं लगी। लोगों के व्यवहार में भी कोई खास अंतर नहीं था। वही जातिवाद उत्तर प्रदेश में था और वही दिल्ली में भी। लोग उसी सोच व धारणा से किसी से मिलते थे। हिंदुस्तान तो वही है न। गाड़ी थी, सहायक थे, पुलिस थी। तो ऐसे व्यक्ति को किसी शहर के बदल जाने पर कहां दिक्कत होती है। मैं ब्रॉड विजन के साथ दिल्ली आया था। वैसे भी नौकरी से पहले 1959 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) में पहले बैच में मेरा भी दाखिला हो गया था, लेकिन उसी साल सिविल सेवा की परीक्षा भी पास कर ली तो स्वाभाविक है वही करता।

● इस शहर को नाट्य साहित्य का रूप कैसे दिया? या कहें दिल्ली नाटकों के चरित्र में कैसे समाई?

-मेरा एक बहुत प्रचलित नाटक है 'कथा एक कंस की।' यह नाटक कंस को एक डिक्टेटर-एक तानाशाह के रूप में दर्शाता है। इसमें स्टालिन, हिटलर जैसे तानाशाहों का भी जिक्र है। 1974 की बात है। एनएसडी को इस नाटक का मंचन करना था, लेकिन वह आपातकाल का दौर था। चूंकि इंदिरा गांधी को एक तानाशाह के रूप में देखा जा रहा था, इसलिए माहौल को देखते हुए मेरे नाटक का भी मंचन नहीं किया गया। नाटक में दिल्ली से लेकर पूरी दुनिया की तानाशाही परंपरा का संदेश था। इसी तरह एक और नाटक है 'सीढ़ियां' जो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की कहानी को मंच पर साकार करता है। मुगलिया सल्तनत के आखिरी वक्त की परिकल्पना। कुदसिया बेगम और जावेद की प्रेमकथा के रूप में...। किंतु जब लिखने लगा, तो प्रेमकथा गौण हो गई। वह युग उभर कर ऊपर आया, जिसमें सामान्य स्त्री का प्रेम भी अवमूल्यित हो जाता है। वह एक सामान्य पुरुष से नहीं, एक अपुरुष से प्रेम कर जीवन को परिणति देती है। सलीम का चरित्र, तस्वीर के बीच में आ गया और गहरे शोख रंग उसमें भरने लगे। उसकी सफलता के लिए कुदसिया बेगम का सीढ़ियां लांघना, हमें आज के समाज से एकदम जोड़ता है। शताब्दियों के अंतराल के बीच सेतु-जैसा। वैसे भी मेरे नाटक विचार प्रधान रहे हैं। घटना और चरित्र प्रधान कम।

● थियेटर के रूप-स्वरूप एनएसडी के बारे में कुछ बताइए?

-हिंदी भाषी क्षेत्र में थियेटर की परंपरा नहीं है। संस्कृत के समय थी नाटक की परंपरा, जब कालीदास, भास जैसे नाम थे। मगर 12वीं शताब्दी में मुसलमानों के आक्रमण के बाद यह समाप्त हो गई। संगीत इसलिए बच गया, क्योंकि दूर-दूर गांव जो बचे हुए थे, उन मंदिरों में आरती हुआ करती थीं, शास्त्रीय गायन होता था। और नृत्य कोठों की बदौलत बच गया। लेकिन नाटक अपना अस्तित्व नहीं बचा सका। मुगल शासकों के बाद जब 18वीं शताब्दी में अंग्रेज आए तो शेक्सपीयर को लेकर आए। उनकी छावनियों में उसी के नाटक हुआ करते थे। पारसी ठेकेदार भी हुआ करते थे। उन्होंने भी वे नाटक देखे और उसकी नकल में पारसी थियेटर की स्थापना हुई। पारसी थियेटर स्वयंभूत नहीं था, एक नकल थी। हमारे पास परंपरा नहीं थी। जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु ने नाटक लिखे, लेकिन उनके पास मंच नहीं था, इसलिए प्रचलित नहीं हुए। नाट्य साहित्य मंचन से ही सिद्ध होता है। 1930 में बोलने वाला सिनेमा आया। पारसी थियेटर समाप्त हो गया। जब देश आजाद हुआ था उस समय थियेटर नहीं था। सिर्फ कुछ नाट्य साहित्य था। आजादी के कुछ सालों बाद नाट्य लेखन, मंचन शुरू हुआ। उस दौर में जगदीश चंद्र माथुर, रामकुमार, लक्ष्मीनारायण लाल, उपेंद्र आदि के नाम आते हैं। उनके बाद मोहन राकेश वगैरह आए। इसके दस साल बाद मेरी पीढ़ी आई। एक अच्छा दौर चलता गया, लेकिन मौलिक हिंदी नाट्य लेखन का दुर्भाग्य बना रहा। यह सिर्फ अनुवाद पर ही टिका रहा।

● नाट्य साहित्य परंपरा का विस्तार कब हुआ?

-नाटक ज्यादातर अंग्रेजी से अनुवाद हुआ। लेकिन थियेटर को वास्तव में किसी ने समझा, हमारी नाट्य संस्कृति के विशुद्ध रूप को अपनाया, तो वह पृथ्वी थियेटर था। 1952 से 67 तक तो नाट्य क्रांति सी की। खूबसूरत नाट्य साहित्य को रचा और उनका मंचन किया। यह अतुलनीय है। एक जागृति कही जा सकती है उस दौर में। मैं भी उसी से प्रेरित हुआ था।

● और इसका साहित्य कैसे लिखा गया? उसके बारे में बताइए। नाट्य साहित्य और मंचन की तारतम्यता को कैसे बनाते हैं?

-दो आयामी विधा है। नाट्य साहित्य और मंचीय कला। दो तरह के नाटक होते हैं। एक जो मंच पर खूब हंसाता है। और दूसरा जो साहित्यिक होते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। ऐसे नाटकों की भाषा भी देस-काल के मुताबिक ही होगी, इनकी शैली व्यवस्थित होती है। ऐसे नाटकों का मंचन आसान नहीं होता। लेकिन सफल नाटक की परिभाषा क्या है? उसके लिए दोनों ही आयाम में सफल होना। नाट्य साहित्य जितना सुंदर हो, उसका मंचन भी उतना ही आकर्षक होना चाहिए। संदेश परक होना चाहिए। इस पर सिर्फ शेक्सपीयर के नाटक खरे उतरते हैं। मैंने नाटक को हमेशा मंच सिद्ध कल्पना में सोचकर ही शब्दों में ढाला है। पहले उसके दृश्य मेरे जेहन में आते हैं, इसके बाद ही लिखता हूं। डॉयलाग तो अच्छे लगते हैं, लेकिन यदि मंचन में सफल न हों तो? क्या फायदा।

● 1967 की दिल्ली और आज की दिल्ली में क्या परिवर्तन देखते हैं?

-तब मन से मंचन होता था, लेकिन सिर्फ शौकिया मंचन होता है। सबसे बड़ी बात यह भी है नाट्य मंचन के लिए जगह कहां हैं? प्रेक्षागृह कहां हैं? किसी ने भी मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया। कुछ जो हैं भी तो उनका शुल्क इतना ज्यादा होता है कि हर किसी के लिए वहां मंचन संभव नहीं। इसीलिए दर्शक भी नहीं हैं। सरकारी ग्रांट भी मिलता है पर उसका कोई लाभ नहीं। यहां तो वैसे भी हम एक तो अनुवादीय नाटक पर टिके हैं, उस पर भी 25-30 सफल शो हो जाते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। नाट्य साहित्य और मंचन के संस्कार तो न्यूयॉर्क और लंदन में हैं। जहां माउस ट्रैप के 30-40 हजार शो हो जाते हैं, तब भी थियेटर हाउसफुल रहता है। हमे तो दर्शक तलाशने पड़ते हैं। अब दिल्ली का चरित्र बहुत बदल गया है। यहां का समाज, यहां की राजनीति का हृदय परिवर्तन सा हो चुका है। उप्र-बिहार मंडल कमीशन आया था तो उसके बाद होल सेल में माइग्रेशन हुआ और लोगों की बाढ़ दिल्ली में आई। कभी दिल्ली की सियासत में पंजाबियत झलकती थी, आज उप्र-बिहार की झलक बन गई है।

● अभी तो याददाश्त भी तंदरुस्त है और फिट भी दिख रहे हैं। तो मन की कल्पनाएं क्या लिखने को प्रेरित करती हैं?

-ठहाके के साथ, कोशिश करता हूं खुद को फिट रखने की। फिलहाल मैं काफी समय से रहीम पर सोच रहा हूं। जल्द ही उन पर नाटक लिखूंगा।

अब भी कमी खलती है पुस्तक केंद्र की

साहित्यिक धरोहर

दिल्ली में अब भी बहुत कम ऐसी जगह हैं जहां साहित्य की हर विधा की पुस्तकें मिलती हों। सामने लॉन हो जहां बैठकर चाय कॉफी का लुत्फ लिया जा सके। कॉफी हाउस की जगह पर पालिका बाजार बनने के बाद मोहन सिंह प्लेस के कॉफी हाउस में साहित्यकारों की बैठकी जमा करती थी। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां साहित्यकारों के अलावा रंगकर्मी से लेकर संस्कृति कर्मी तक जुटा करते थे। ये जगह थी श्रीराम कला केंद्र के भूतल पर स्थित वाणी पुस्तक केंद्र। उससे सटा एक कैफेटेरिया भी था और सामने लॉन। वाणी पुस्तक केंद्र में देशभर की साहित्यिक पत्रिकाएं एक जगह मिल जाया करती थीं। कैफेटेरिया में चाय-कॉफी। साहित्य चर्चा के लिए बेहद मुफीद जगह भी और वातावरण भी। वाणी पुस्तक केंद्र के मालिक अरुण माहेश्वरी के मुताबिक ये केंद्र सन 2000 में खुला था। पत्रकार सुरेंद्र प्रताप सिंह को कहीं से ये जानकारी मिली कि श्रीराम कला केंद्र वाले अपने परिसर में एक पुस्तक की दुकान चलवाना चाहते हैं। सुरेंद्र प्रताप सिंह ने इसकी चर्चा अपने मित्र पत्रकार राजकिशोर से की। राजकिशोर ने इस पुस्तक केंद्र के लिए वाणी प्रकाशन के मालिक अरुण माहेश्वरी को तैयार कर लिया। इस तरह से इस केंद्र की शुरुआत हो गई। इस केंद्र का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और फिल्मकार महेश भट्ट ने किया था। शुभारंभ के मौके पर उस वक्त अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे मनोज बाजपेयी ने कवि चंद्रकांत देवताले की कविताओं का पाठ किया था। चंद्रशेखर पुस्तक प्रेमी थे। चंद्रशेखर को जब इस बात का पता लगा कि मंडी हाउस के पास एक ऐसा पुस्तक केंद्र खुल रहा है तो वो इसका शुभारंभ करने के लिए फौरन तैयार हो गए थे। वो समय पर आए और काफी देर तक वहां रुके भी। हिंदी साहित्य जगत के तमाम बड़े लेखक, रंगकर्मी और संस्कृतिकर्मी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

वर्ष 2000 में श्रीराम कला केंद्र में वाणी पुस्तक केंद्र की जब शुरुआत हुई तो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर उसमें बतौर अतिथि उपस्थित हुए थे। उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया था।

साहित्य की धरोहर- यही तो जगह है जहां कभी साहित्य की बैठकी हुआ करती थीं। अब भले यह जगह अतीत का हिस्सा बन गई हो लेकिन साहित्य प्रेमियों के मन में इसकी स्मृतियां आज भी बसी हैं। फोटो सौजन्य : अदिति

इसके शुभारंभ समारोह को लेकर कई दिलचस्प बाते रहीं। अरुण माहेश्वरी ने दैनिक जागरण के साथ अपनी बहुत सारी यादें साझा की। एक दिलचस्प बात उन्होंने बताई। उद्घाटन समारोह के लिए उन्होंने फिल्मकार महेश भट्ट से चर्चा की। महेश भट्ट ने उनको कविता पाठ के लिए मनोज बाजपेयी का नाम सुझाया और कहा कि ये लड़का मुंबई में फिल्मों में नाम करने लगा है। महेश भट्ट ने कहा था कि वो एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा। तब तक मनोज की दो तीन फिल्में आ चुकी थीं। महेश भट्ट ने मनोज बाजपेयी का नंबर दिया और फिर अरुण माहेश्वरी के निमंत्रण पर मनोज बाजपेयी दिल्ली आ गए। मनोज दिल्ली एयरपोर्ट से खुद ही टैक्सी लेकर हिमाचल भवन पहुंच गए थे। उस वक्त मनोज बाजपेयी को हिमाचल भवन में ठहराया गया था क्योंकि वो जगह समारोह स्थल के बहुत पास था। कार्यक्रम के दौरान मनोज बाजपेयी ने चंद्रकांत देवताले की कविताओं को पाठ किया था, जिसको उपस्थित सभी लोगों ने काफी सराहा था। कार्यक्रम के बाद उन्होंने मनोज बाजपेयी को धन्यवाद दिया और कुछ तोहफा देने की इच्छा जताई। मनोज ने तब अरुण माहेश्वरी से कहा था कि अगर तोहफा देना है तो उदय प्रकाश का संग्रह 'तिरिछ' दे दीजिए। ये संग्रह मंगवाकर मनोज बाजपेयी को गिफ्ट दिया गया था। उस वक्त उदय प्रकाश की कहानी 'तिरिछ' की काफी चर्चा थी।

ये तो रही उद्घाटन समारोह की दिलचस्प कहानी लेकिन उसके बाद श्रीराम कला केंद्र स्थित ये पुस्तक केंद्र दिल्ली की साहित्यिक बिरादरी का प्रमुख केंद्र बन गया। इसकी वजह वहां साहित्यिक पत्रिकाओं की उपलब्धता तो थी ही वहां का माहौल भी रचनात्मक था। ये जगह दिल्ली की सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र में भी थी। करीब दस साल तक ये वाणी पुस्तक केंद्र चलता रहा था लेकिन एक दिन अचानक लैंड एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इमारत के मालिकों को परिसर में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने पर रोक लगाने का नोटिस दे दिया। थोड़े दिन की बातचीत के बाद दिल्ली का ये साहित्यिक कोना बंद कर दिया गया। पुस्तक केंद्र बंद होने के कुछ दिनों बाद तक कैफेटेरिया चलता रहा लेकिन फिर वो भी बंद हो गया। उसके बंद होने के बाद तो लेखकों के मिलने जुलने का एक स्थान खत्म हो गया। दरअसल इस स्थान की उपयोगिता इस वजह से भी थी कि जो भी श्रीराम कला केंद्र में नाटक देखने आता था उनके लिए भी ये जगह मुफीद थी। लेकिन एक सरकारी नोटिस ने इस बेहतरीन साहित्यिक केंद्र को बंद कर दिया।

अनंत विजय

गांधी से लेकर तिलक तक की पसंद

फुर्सत का ज्ञान

दिल्ली का दिल बेशक कनॉट प्लेस है, लेकिन दिल्ली की पहचान चांदनी चौक से है। यहां का कपड़ा मार्केट, आभूषण, लजीज जायकों वाली गलियां, चाट-पकौड़े सब कुछ इतना प्रसिद्ध है कि देश के अन्य राज्यों से भी लोग यहां खरीदारी करने और व्यंजनों का सुस्वाद लेने आते हैं। लेकिन जो लोग किताबों के शौकीन हैं, दुर्लभ किताबें पढ़ना जिनका शौक है और जो शोधार्थी हैं, उनके लिए भी चांदनी चौक में प्राचीनतम पुस्तकालय मौजूद है। जहां बैठ वे अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मारवाड़ी सार्वजनिक पुस्तकालय की, जो इतिहास की दृष्टि से अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। यहां साहित्य की दुर्लभ पुस्तकें व पत्रिकाएं भी उपलब्ध हैं।

शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहायक : मारवाड़ी समाज से आने वाले केदारनाथ गोयंका ने महसूस किया कि दिल्ली में एक ऐसे स्थान की जरूरत है, जिसके माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके। साथ ही देश-दुनिया में घटने वाली घटनाओं की जानकारी लोगों तक शीघ्र उपलब्ध हो सके। इसी सोच के साथ उन्होंने 1915 में मारवाड़ी सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की। 36 वर्षों से पुस्तकालय की देखरेख कर रहे संचालक राम नरेश शर्मा के मुताबिक यहां रोजाना करीब 100 से अधिक पाठक दूर-दराज से किताबें पढ़ने आते हैं और करीब 300 से ज्यादा लोगों ने इसकी सदस्यता ली हुई है। यह दिल्ली की सबसे प्राचीन पुस्तकालय है।

पुरानी दुर्लभ किताबों का भंडार : इस पुस्तकालय में दुखी सीकर जून 1938, औरंगजब छठा भाग, मुंगेर संवत 1987, सोलंकियों का प्राचीन इतिहास, वीर विनोद मेवाड़ का इतिहास संवत 1943, चांद का मारवाड़ी अंक 1929, सरस्वती सचित्र मासिक पत्रिका भाग-17 जुलाई-दिसंबर 1916, माधुरी हिंदी सरकार की सर्वश्रेष्ठ सचित्र मासिक पत्रिका अगस्त 1931 जनवरी 1932, कामायनी 1912, भारत में अंग्रेजी राज दूसरी जिल्द 1938, स्कंदपुराण तृतीय भाग 1961, पृथ्वीराज रासो भाग-1 1904, संसदीय वाद-विवाद 1950 आदि उपलब्ध हैं। वहीं, अंग्रेजी की किताबों में क्रैंब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम-4 1937, ऐनल्ज एंड एंटीक्वीटीज ऑफ राजस्थान 1832, रोमांस ऑफ द फोर्ट ऑफ ग्वालियर 1931, सेंसस ऑफ इंडिया 1931 आदि यहां मौजूद हैं।

चुनिंदा किताबें इसे बनाती हैं खास : कांग्रेस का इतिहास, लोकसभा वाद-विवाद, भृंगु संहिता, विश्व विजय पंचाग, स्त्री दर्पण, हस्तलिखित पुस्तकें, वेद पुराण, कल्याण अंक आदि पुस्तकें इस पुस्तकाल को दिल्ली के अन्य पुस्तकालयों से विशिष्ट बनाती हैं। पुस्तकालय में करीब 35 हजार पुस्तकें, प्राचीन पत्रिकाएं, 700 संदर्भ ग्रंथ और 21 पांडुलिपियां हैं।

नेताओं का भी रहा आना-जाना : महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विजय लक्ष्मी पंडित, अरूणा आसफ अली, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, मदन मोहन मालवीय, यूनेस्को के पूर्व परामर्शदाता निदेशक एडवर्ड सिडनी आदि पुस्तकालय में अपने ज्ञान को समृद्ध करने आते रहते थे। महात्मा गांधी ने तो यहीं बैठकर आजादी की रूपरेखा भी तैयार की। वह घंटों यहां बैठकर किताबें पढ़ा करते थे और आजादी को लेकर कई बैठकें भी की। आजादी के बाद भी कई बड़े नेता और लेखक यहां पढ़ने आते रहे हैं।

पाठकों के लिए उपलब्ध सुविधाएं : यह पुस्तकालय मारवाड़ी चैरीटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है, जिसका खर्चा नगर निगम व मारवाड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलता है। पुस्तकालय के सभागार में नाटक, साहित्यिक गोष्ठियां, कवि सम्मेलन व अन्य कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित होते रहते हैं। वर्ष 2015 से पुस्तकालय को डिजिटल रूप प्रदान किया गया। यहां पाठकों के लिए वातानुकूलित संगोष्ठी कक्ष व अध्यन कक्ष भी है। पुस्तकालय की लोकप्रियता ही है कि यहां हर उम्र के लोग अध्ययनरत दिखाई देते हैं।

रितु राणा

मारवाड़ी सार्वजनिक पुस्तकालय में अध्ययन करते लोग। जागरण

खुलने का समय

सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक पुस्तकालय में अध्ययन के लिए जा सकते हैं। सोमवार और सरकारी अवकाश पर पुस्कालय बंद रहता है।

ऐसे पहुंचें

मारवाड़ी सार्वजनिक पुस्तकालय तक चांदनी चौक बस स्टैंड व मेट्रो स्टेशन से पैदल पहुंचा जा सकता है।

डिन के बिना नहीं होगी टैक्स मामलों में गिरफ्तारी

नई दिल्ली : टैक्स कानूनों को करदाताओं के हित में और सरल बनाते हुए सरकार ने डिन के बिना नोटिस, समन या गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे समन, असेस्ट मेमो या जांच संबंधी आदेश जारी करने के लिए डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (डिन) का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें। यह व्यवस्था शुक्रवार से लागू हो जाएगी। (प्रेट्र)

कंपनी के सह-संस्थापकों ने इन्फोसिस को इस मुकाम तक लाने में पूरी जिंदगी दांव पर लगाई है। मेरे मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा है। मैं अपने बयानों से जांच को प्रभावित नहीं करना चाहता।

— नंदन नीलेकणि
चेयरमैन, इन्फोसिस

सेंसेक्स 40,469.78 ▲ 221.55	निफ्टी 11,966.05 ▲ 48.85	सोना प्रति दस ग्राम ₹38,870 ▼ ₹301	चांदी प्रति किलोग्राम ₹46,509 ▼ ₹906	$ डॉलर ₹70.97 ▲ ₹0.28	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल $ 63.17

भगवान भी इन्फोसिस के आंकड़ों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते : चेयरमैन

टीस ▶ कहा – कंपनी की बेहद सक्षम वित्तीय टीम आरोपों से अपमानित महसूस कर रही

कंपनी ने कहा – एक सह-संस्थापक के शामिल होने के कयासों पर वह स्तब्ध

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश की दूसरी सबसे बड़ी आइटी कंपनी इन्फोसिस पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर चेयरमैन नंदन नीलेकणि ने कड़ा प्रहार किया है। विश्लेषकों के साथ बैठक में बुधवार को उन्होंने कहा है कि कंपनी इतने ऊंचे मानकों का पालन करती है कि भगवान भी उसके वित्तीय आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा, 'इन्फोसिस बेहद ऊंची प्रक्रिया का पालन करती है। यहां तक कि भगवान भी कंपनी के आंकड़ों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हमारे पास वित्त की बेहद मजबूत टीम है और वह इन आरोपों से खुद को अपमानित महसूस कर रही है। हालांकि मैं इस मामले में चल रही जांच को अपने विचारों से प्रभावित नहीं करना चाहता।' नीलेकणि के मुताबिक वे जांच रिपोर्ट के आने का इंतजार करेंगे।

इन्फोसिस ने बुधवार को यह भी कहा कि व्हिसलब्लोअर्स के आरोपों के पीछे कंपनी के एक सह-संस्थापक और कुछ कर्मचारियों का हाथ होने के कयासों से वह स्तब्ध है। इस तरह के कयास कुछ बेहद सम्मानित व्यक्तियों की छवि धूमिल करने के प्रयास हैं। नीलेकणि ने कहा कि कंपनी के सह-संस्थापकों ने इन्फोसिस को इस मुकाम तक लाने में पूरी जिंदगी लगा दी है। उन सभी संस्थापकों के प्रति उनके मन में अटूट और अपार श्रद्धा है।

गौरतलब है कि अक्टूबर में कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया था कि उसे कुछ व्हिसलब्लोअर्स की तरफ से कंपनी के शीर्ष प्रबंधन द्वारा वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं। इनमें से एक शिकायत पर 20 सितंबर की तारीख अंकित थी, जबकि एक पर कोई तारीख नहीं थी। कंपनी को शिकायतें 30 सितंबर को मिली थीं। ये शिकायतें ऑडिट कमेटी के समक्ष 10 अक्टूबर को और गैर-कार्यकारी निदेशक बोर्ड के समक्ष 11 अक्टूबर को रखी गई थीं। कंपनी ने 11 अक्टूबर को ही चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए थे।

इस बीच, कंपनी ने यह भी कहा है कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए) तथा कर्नाटक के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) ने व्हिसलब्लोअर्स के आरोपों पर जानकारियां मांगी हैं।

प्रतीकात्मक

पहले भी लगते रहे हैं आरोप

कंपनी पर इससे पहले भी वित्तीय अनियमितता के आरोप लग चुके हैं। हाल में ही कंपनी द्वारा इजरायल की ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी कंपनी पनाया की खरीद के समय भी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। उस दौरान भी व्हिसलब्लोअर की ओर से ही शिकायत आई थी। इसे कंपनी की इंटरनल कमेटी ने निराधार बताया था। इसके अलावा 2017 में कंपनी के फाउंडर्स और पूर्व-प्रबंधन के बीच तनाव पैदा हो गया था। उस मामले में कंपनी के तत्कालीन सीईओ विशाल सिक्का ने इस्तीफा दे दिया था।

ये हैं आरोप

- जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान अधिक मुनाफा दिखाने के लिए व्हिसलब्लोअर्स से वीजा लागतों को कम करने के लिए कहा गया
- 353 करोड़ रुपये के रिवर्सल को भी नजरंदाज करने के लिए दबाव डाले जाने की बात कही गई है
- अधिकारियों ने मुनाफा बढ़ाकर स्टॉक्स की ऊंची कीमत बनाए रखने के लिए गैरकानूनी कदम उठाए
- वेरिजॉन, इंटेल और संयुक्त उपक्रमों जैसे बड़े सौदों में हेराफेरी की गई, ऑडिटर्स और कंपनी बोर्ड से संवेदनशील जानकारियां छिपाई गईं
- सीईओ सलिल पारेख ने कर्मचारियों से कहा था कि बोर्ड के सामने बड़ी डील के आंकड़े और महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारियां नहीं रखी जाएं

जेपी इन्फ्रा के लिए बोली नहीं लगा सकेगा जेपी ग्रुप

प्रतीकात्मक

- एनक्लैट के फैसले के खिलाफ जेपी ग्रुप की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
- सिर्फ एनबीसीसी और सुरक्षा रियल्टी से ही स्वीकारे जाएंगे संशोधित प्लान
- कोर्ट ने इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया को 90 दिन में पूरा करने का निर्देश दिया

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड की बोली में शामिल होने की जेपी ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया है। बुधवार को अदालत ने 90 दिन में प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया और कहा कि सिर्फ एनबीसीसी और सुरक्षा रियल्टी से ही संशोधित रिजॉल्यूशन प्लान स्वीकार किए जाएंगे।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ एनक्लैट के फैसले के खिलाफ जेपी समूह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 30 जुलाई को एनक्लैट ने कर्ज में डूबी जेपी इन्फ्रा के लिए नई बोलियां आमंत्रित करने की अनुमति देते हुए प्रवर्तक जेपी समूह को इसमें हिस्सा लेने से प्रतिबंधित कर दिया था।

याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, वह घर खरीदारों, जेपी समूह और संबंधित बैंकों के साथ पूरा न्याय करने के लिए 'असाधारण स्थिति' में यह निर्देश दे रही है। पीठ ने आइआरपी को कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया को 90 दिन के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। इसमें से पहले 45 दिन में सुरक्षा रियल्टी और एनबीसीसी से संशोधित रिजॉल्यूशन प्लान मंगाया जा सकेगा। अदालत ने कहा, ये दोनों जेपी इन्फ्राट्रेक के लिए अंतिम बोली लगाने वालों में थे। दोनों ने पहले भी रिजॉल्यूशन प्लान पेश किया था और अगर जरूरी हो तो वे बातचीत के बाद कर्जदाताओं की समिति के समक्ष अपनी संशोधित योजना पेश करें और अपनी रिपोर्ट एनसीएलटी को सौंपे। एनसीएलटी या एनक्लैट के समक्ष अंतरिम निर्देश के लिए लंबित अर्जी समेत अन्य कोई भी आवेदन इन दो बोलीकर्ताओं से संशोधित योजना स्वीकारने और उस पर आगे बढ़ने की प्रक्रिया में बाधक नहीं होगा।

पीठ ने कहा कि दूसरे चरण की 45 दिन की अवधि 21 दिसंबर से शुरू होगी। इसमें निर्णय करने वाले प्राधिकार को उचित आदेश पारित करने का समय दिया गया है।

ट्रेड वार से भारत को 5,360 करोड़ रुपये का लाभ

नई दिल्ली, प्रेट्र : अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से चल रहे ट्रेड वार के कारण भारत को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मोर्चे पर फायदा हो रहा है। भारत ने चालू वर्ष की पहली छमाही (जनवरी-जून) में अमेरिका को 75.5 करोड़ डॉलर (करीब 5,360 करोड़ रुपये) का अतिरिक्त निर्यात किया है। संयुक्त राष्ट्र की व्यापार एवं निवेश इकाई अंकटाड की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत से अमेरिका को केमिकल, मेटल और अयस्कों का अतिरिक्त निर्यात हुआ है। असल में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार के चलते दोनों देशों के बीच व्यापार में भारी कमी आई है, जिसका फायदा भारत को मिल रहा है। अंकटाड के मुताबिक भारत ने केमिकल (24.3 करोड़ डॉलर), धातु एवं अयस्क (18.1 करोड़ डॉलर), इलेक्ट्रिकल मशीनरी (8.3 करोड़ डॉलर) और विभिन्न मशीनरी (6.8 करोड़ डॉलर) की अतिरिक्त बिक्री करके यह लाभ कमाया। इसके अलावा कृषि, खाद्य उत्पाद, फर्नीचर, कपड़े और परिवहन उपकरणों का निर्यात भी बढ़ा है।

अमेरिका-चीन में द्विपक्षीय व्यापार घटा : रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वार के कारण दोनों देशों के आपसी व्यापार में भारी गिरावट आई है। इसलिए अमेरिका में उन देशों से आयात बढ़ा है, जो सीधे तौर पर ट्रेड वार से नहीं जुड़े हैं। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और चीन के बीच चीन ट्रेड वार की वजह से 2019 की पहली छमाही में करीब 2,100 करोड़ डॉलर का व्यापार प्रभावित हुआ है।

चीन के उत्पादों पर अतिरिक्त अमेरिकी शुल्क ने अन्य देशों को अमेरिकी बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया है। इससे इन देशों का अमेरिका को व्यापार बढ़ा है। ताइवान, मेक्सिको और यूरोपीय संघ को इसका काफी फायदा हुआ। अंकटाड ने कहा कि दक्षिण कोरिया, कनाडा और भारत को व्यापार में कम लाभ हुआ है, लेकिन फिर भी यह पर्याप्त है।

घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को बनाना होगा प्रतिस्पर्धी : फियो

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- आरसेप में शामिल नहीं होने के फैसले को सही ठहराया

आरसेप से बाहर रहने के सरकार के फैसले को बड़े निर्यात संगठनों ने वाजिब ठहराते हुए कहा है कि घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को अन्य देशों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत है। निर्यात संगठनों के फेडरेशन फियो ने कहा है कि कर्ज और लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करके घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों के उत्पादों को वैश्विक बाजार में मुकाबला करने में आसानी होगी।

फियो के प्रेसिडेंट शरद कुमार सराफ ने कहा है कि मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों को राज्यों में लगने वाले टैक्स और लेवी पर छूट देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है। फियो का सुझाव है कि सरकार का लक्ष्य प्रति वर्ष जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग की हिस्सेदारी में एक परसेंट की वृद्धि होना चाहिए। इससे अगले 10 वर्षों में जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग की हिस्सेदारी को 25 परसेंट के स्तर तक पहुंचाया जा सकेगा।

सरकार ने घरेलू उद्योग और किसानों से जुड़ी चिंताओं के आधार पर फिलहाल आरसेप से बाहर रहने का फैसला किया है। आगे चलते हुए यदि आरसेप सदस्य भारत की चिंताओं को एजेंडा में शामिल करने को तैयार होते हैं तो यह निर्णय बदल भी सकता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह स्वीकार करते हुए कहा भी कि अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं में दरवाजे कभी बंद नहीं किए जाते।

जानकारों का मानना है कि जब तक भारत आरसेप से बाहर है, तब तक घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के मुकाबले में खड़ा होने के लिए तैयार किया जा सकता है। इसके लिए सरकार की तरफ से उद्योगों की लागत कम करने के उपायों पर सर्वाधिक जोर दिया जा रहा है।

उधर ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने आरसेप से बाहर रहने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को साहसी और देशहित में बताया है। टीपीसीआइ के चेयरमैन मोहित सिंगला के मुताबिक घरेलू उद्योगों का संरक्षण देश का सार्वभौमिक अधिकार है।

बीमारी की शक्ल ले रही ऑनलाइन शॉपिंग

जेएनएन, नई दिल्ली : पिछले कुछ समय के दौरान भारतीय बाजार में ऑनलाइन शॉपिंग ने रफ्तार में जो तेजी पाई है, उससे ग्राहकों को निश्चित तौर पर खरीदारी के बेहतर विकल्प चुनने में मदद मिली है। लेकिन जानकारों का मानना है कि सवा अरब से ज्यादा आबादी वाले इस देश में ऑनलाइन शॉपिंग एक बुरी लत की शक्ल लेती जा रही है। अग्रणी मार्केट रिसर्च फर्म गार्टनर ने ऑनलाइन खरीदारी के खतरों के प्रति लोगों को आगाह किया है।

फर्म ने आशंका जताई है कि जिस तरह से डिजिटल माध्यम में गलत तरीके से खरीद-फरोख्त का हो रही है, उसको देखते हुए 2024 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को इसे 'एडिक्टिव डिसऑर्डर' यानी बुरी लत वाला विकार घोषित करना पड़ेगा। फर्म ने कहा है कि डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से होने वाला उपभोक्ता खर्च 2022 तक 10 परसेंट की दर से वृद्धि जारी रखेगा। ऑनलाइन रिटेलर आपसी स्पर्धा और ग्राहकों को आकर्षित करने के जो तरीके अपना रहे हैं, उससे लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। गार्टनर की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑनलाइन रिटेलर लोगों को निशाना बनाकर क्षमता से अधिक खरीदारी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

प्याज आयात नियमों में मिली ढील

घरेलू बाजार में कई देशों से जल्द होने लगेगा आयात, दाम में आएगी कमी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

चालू खरीफ सीजन में प्याज की पैदावार में आई भारी गिरावट के चलते यह 80 रुपये प्रति किलो तक बिकने लगा है। इसके मद्देनजर सरकार ने महंगाई को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने की तैयारी की है। इसके लिए आयात नियमों में पर्याप्त ढील दी गई है, ताकि प्याज की क्वालिटी समेत अन्य कई तरह की जांच-परख में अतिरिक्त समय न लगे।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले व खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने बुधवार को प्याज की आपूर्ति बढ़ाने के लिए समीक्षा बैठक की। पासवान ने माना कि खरीफ सीजन के प्याज के उत्पादन में 30 से 40 फीसद तक की कमी आने की आशंका है। दरअसल, बेमौसम बारिश की वजह से खेतों में खड़ी फसल को ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके चलते घरेलू बाजार में कीमतें चढ़ गई हैं। पासवान के मुताबिक विदेश से प्याज आयात करने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। अफगानिस्तान, मिस्र, तुर्की और ईरान के दूतावासों को प्याज आयात में तत्काल मदद करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नवंबर के आखिर तक प्याज का भाव नीचे आएगा। उन्होंने उपभोक्ताओं से इस स्थिति से निपटने में सहयोग की अपील की। प्याज की आपूर्ति बढ़ाने के उपायों के बारे में मंत्री ने बताया कि सबसे पहले प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

व्यापारियों व जमाखोरों पर लगाम कसने के लिए स्टॉक सीमा तय कर दी गई है। जबकि सरकारी गोदामों में पड़े प्याज के स्टॉक को 23.90 रुपये प्रति किलो की दर से उपभोक्ताओं को बेचा जा रहा है। पासवान ने कहा कि बफर स्टॉक में 57 हजार टन प्याज था, जो रियायती दरों पर बेचा जा रहा है। इस स्टॉक का 25 फीसद हिस्सा खराब हो गया। केंद्रीय बफर स्टॉक में अभी भी 1,525 टन प्याज बचा हुआ है। पासवान ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि उसने प्याज की क्वालिटी पर सवाल उठाकर खरीदने से मना कर दिया। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि वर्ष 2019 के खरीफ सीजन में प्याज के उत्पादन में 20 लाख टन की कमी आई है। महाराष्ट्र में बारिश के चलते उत्पादन में गिरावट आई है। दिल्ली में प्याज की महंगाई राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील है।

कई राज्यों में असमय बारिश ने की है फसल को खराब, इस महीने के अंत तक भाव गिरेंगे। प्रतीकात्मक

सोना 301 रुपये फिसला, चांदी 906 रुपये टूटी

नई दिल्ली, प्रेट्र : ग्लोबल बाजारों में सुस्ती के चलते घरेलू सराफा बाजार बुधवार को एकदम मंद रहे। दिन के कारोबार में सोना 301 रुपये फिसलकर 38,870 रुपये प्रति 10 ग्राम का रह गया। चांदी में भी 906 रुपये की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। कारोबार के आखिर में चांदी 46,509 रुपये प्रति किलोग्राम की रह गई। मंगलवार को चांदी 47,415 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी।

ऊर्जा के नए विकल्प तैयार कर रहा भारत : प्रधान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- देश स्टील की खपत में वृद्धि के लिए तैयार, पांच वर्षों में 100 अरब डॉलर निवेश की तैयारी

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए ऊर्जा संसाधन के नए विकल्प विकसित कर रहा है। ये ऐसे विकल्प हैं, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ पर्यावरण के अनुकूल होंगे। साथ ही देश में तेल व गैस का बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए अगले पांच वर्षों में 100 अरब डॉलर (करीब सात लाख करोड़) के निवेश की तैयारी है।

केपीएमजी एनरिच 2019 कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए प्रधान ने कहा कि रिफाइनिंग, पाइपलाइन, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और एलएनजी टर्मिनल पर साल 2024 तक 100 अरब डॉलर के निवेश की संभावनाएं देश देख रहा है। इसमें से 60 अरब डॉलर गैस इन्फ्रास्ट्रक्चर पर निवेश होने की संभावना है।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऊर्जा के वैश्विक परिदृश्य में तेजी से बदलाव हो रहा है। भारत इस बदलाव का साक्षी बन रहा है। हम ऊर्जा उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की तकनीक को वरीयता दे रहे हैं। हम विश्व के सबसे बड़े उपभोक्ता देश के साथ पर्यावरण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को किसी स्तर पर नहीं छोड़ते।

पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य : पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को अगले पांच साल में पांच लाख करोड़ डॉलर का आकार देने का लक्ष्य रखा है। इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आर्थिक निवेश, डिजिटल इकोनॉमी की बड़ी भूमिका रहेगी।

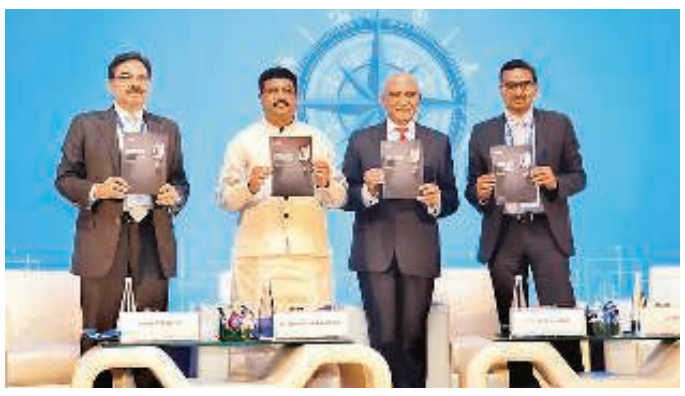
गैस इन्फ्रा पर बड़े निवेश की तैयारी कर रहा है भारत। जागरण

टैक्स रिफॉर्म से मिलेगा प्रोत्साहन

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले पांच साल में निवेश प्रोत्साहन के लिए बैंक्रप्सी कोड, टैक्स रिफॉर्म, इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (आइपीआर) में सुधार जैसे बड़े कदम उठाए हैं। इससे उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिल रहा है। स्टील पर एक अन्य कार्यक्रम में प्रधान ने कहा कि देश स्टील की खपत में लंबी छलांग को तैयार है। सेक्टर में अब निवेशकों को आगे आकर देश की विकास गाथा में भागीदार बनना चाहिए। इस्पात क्षेत्र सरकार की विभिन्न नीतियों और उद्योग की उद्यमशीलता की भावना से समर्थित अधिक जीवंत, कुशल, पर्यावरण के अनुकूल और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन रहा है।

फ्लिपकार्ट की दिवालिया प्रक्रिया पर हाई कोर्ट का स्थगन

नई दिल्ली, प्रेट्र : कर्नाटक हाई कोर्ट ने ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू करने के एनसीएलटी के फैसले पर स्थगन आदेश दिया है। एक बयान में फ्लिपकार्ट ने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के 24 अक्टूबर, 2019 के एक फैसले से राहत के लिए उसने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कंपनी के एक सप्लायर क्लाउडवॉकर स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजीज की याचिका पर एनसीएलटी ने फ्लिपकार्ट के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया था।

क्लाउडवॉकर स्ट्रीमिंग ने एनसीएलटी में याचिका दायर कर कहा था कि फ्लिपकार्ट ने उसके 18 करोड़ रुपये बकाये पर डिफॉल्ट किया है। इस पर एनसीएलटी की बेंगलुरु खंडपीठ ने आइबीसी, 2016 के तहत फ्लिपकार्ट के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया।

सेंसेक्स नई ऊंचाई पर, निफ्टी 12,000 को छूकर लौटा

- कई कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजों पर सेंसेक्स 221 अंक चढ़ा
- निफ्टी 49 अंकों के सुधार के साथ 11,966 अंकों पर स्थिर हुआ

मुंबई, प्रेट्र : इसी सप्ताह सोमवार को सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने वाला बीएसई सेंसेक्स बुधवार को 221.55 अंक यानी 0.55 प्रतिशत उछाल के साथ 40,469.78 अंकों की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। बीएसई के 30 शेयरों वाले इस प्रमुख सूचकांक में कारोबार की शुरुआत तेजी के साथ हुई। इंट्रा-डे में इसने 40,600 का स्तर पार किया। लेकिन आखिरी कुछ समय के दौरान मुनाफावसूली के चलते यह उससे थोड़ा नीचे बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में भी बुधवार को निवेशकों की सकारात्मक गहमागहमी रही। एनएसई का 50-शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी इंट्रा-डे में 12,000 अंक का मनोवैज्ञानिक स्तर भी पार करने में कामयाब रहा। लेकिन आखिरी कुछ समय की बिकवाली के चलते इस सूचकांक की छलांग भी थोड़ी सीमित हो गई। कारोबार के आखिर में निफ्टी 48.85 अंकों यानी 0.41 प्रतिशत सुधार के साथ 11,966.05 अंकों पर बंद हुआ।

जानकारों का कहना है कि कई कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजों ने पिछले कुछ समय के दौरान घरेलू शेयर बाजारों को बड़ी छलांग लगाने का मौका दिया है। इसके साथ ही विदेशी बाजारों से भी सकारात्मक रुख ही दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए और सुधारों की उम्मीद अभी बाकी रखी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को ही कहा था कि सरकार रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने के लिए आरबीआइ के साथ मिलकर काम कर रही है। इन सभी कारकों ने मिलकर घरेलू शेयर बाजारों का सकल रुख सकारात्मक बनाया हुआ है। सेंसेक्स पैक में बुधवार को सबसे ज्यादा 2.64 प्रतिशत तक की तेजी आइसीआइसीआइ बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक केक शेयरों में देखी गई। टाटा मोटर्स, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, यस बैंक और हिंदुस्तान यूनीलिवर के शेयर भी चढ़े। के शेयरों में देखी गई। हालांकि भारती एयरटेल, आरआइएल, बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी, एचसीएल टेक, आइटीसी और सन फार्मा के शेयरों को 3.31 प्रतिशत तक की गिरावट झेलनी पड़ी।

दिन के कारोबार के बारे में जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि दिग्गज कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजों ने सकल विकास के प्रति निवेशकों का सकारात्मक रुख बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। सरकार की तरफ से मदद की उम्मीदों पर ही रियल्टी और फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में जबर्दस्त प्रदर्शन देखा गया।

सेक्टोरल इंडेक्स के लिहाज से बीएसई रियल्टी, बैंकेक्स, फाइनेंस, मेटल और आइटी सेक्टर ने बेहतर प्रदर्शन किया।

इन शेयरों में रही गहमागहमी

सिप्ला : इस फार्मा कंपनी के शेयरों में बुधवार को बीएसई में 2.76 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया। कंपनी ने दिन में ही बताया था कि दूसरी तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ 25 प्रतिशत चढ़ा है। बीएसई में बुधवार को कंपनी के शेयर 480.50 रुपये और एनएसई पर तीन प्रतिशत उछाल के साथ 482 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए।

बजाज इलेक्ट्रिकल्स : कंपनी के शेयरों को इसके कमजोर तिमाही नतीजों का झटका लगा और बीएसई में इसके शेयर 8.60 प्रतिशत टूटकर 349.10 रुपये के भाव पर बंद हुए। एनएसई में कंपनी के शेयरों का बंद भाव 8.64 प्रतिशत गिरावट के साथ 348.90 रुपये रहा।

पीसी ज्वैलर्स : पूंजी बाजार नियामक सेबी के साथ एक मामले में सुलह करने की खबरों के बाद कंपनी के शेयरों में अच्छी तेजी देखने में आई। बीएसई में बुधवार को कंपनी के शेयर 8.04 प्रतिशत उछाल के साथ 34.95 रुपये और एनएसई में 8.50 प्रतिशत सुधार के साथ 35.10 रुपये के स्तर पर बंद हुए।

अध्ययन

रोजाना 15 मिनट अतिरिक्त वॉकिंग करते हुए दे सकते हैं अर्थव्यवस्था में, दुनिया की अर्थव्यवस्था को सालाना सात लाख करोड़ का हो सकता है फायदा

पैदल चलने से सुधर सकती है अर्थव्यवस्था की सेहत

लंदन, रायटर : रोजाना कुछ देर पैदल चलने से आपकी ही नहीं अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधर सकती है। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है। इसके मुताबिक, अगर व्यायाम को लेकर लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशानिर्देशों का पालन करें, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को सालाना 100 अरब डॉलर (करीब सात लाख करोड़ रुपये) का फायदा हो सकता है।

हेल्थ इंश्योरेंस ग्रुप वाइटेलिटी और थिंक टैंक रैंड यूरोप ने लोगों की गतिविधियों से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर का अध्ययन किया। इसमें कहा गया कि अगर कंपनियां अपने कर्मचारियों को व्यायाम पर डब्ल्यूएचओ के निर्देश मानने के लिए राजी कर लें तो अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा पहुंच सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा नहीं बस रोजाना 15 मिनट अतिरिक्त वॉकिंग करना या लगातार एक किलोमीटर तक जॉगिंग कर लेना भी पर्याप्त है। रैंड यूरोप के प्रेसिडेंट हैंस पंग ने कहा कि आपकी शारीरिक निष्क्रियता और उत्पादकता में कमी के बीच गहरा संबंध है। नीति निर्माताओं और कंपनियों को इस दिशा में विचार करना चाहिए कि कैसे अपने लोगों की उत्पादकता बढ़ाएं।

क्या है डब्ल्यूएचओ का निर्देश? : डब्ल्यूएचओ का दिशानिर्देश है कि सभी वयस्क लोगों को हफ्ते में कम से कम 150 मिनट का हल्का व्यायाम या 75 मिनट का तेज व्यायाम करना चाहिए। पिछले साल आए एक अध्ययन के मुताबिक, अमेरिका में 40 फीसद, ब्रिटेन में 36 फीसद और चीन में 14 फीसद वयस्क स्वस्थ बने रहने के लिहाज से बहुत कम या नहीं के बराबर व्यायाम करते हैं।

ऐसे हुआ अध्ययन : अध्ययन में सात देशों के 1,20,000 लोगों से जुड़े आंकड़ों को शामिल किया गया। इन आंकड़ों का एक मॉडल पर विश्लेषण किया गया। इसके आधार पर 23 देशों व वैश्विक स्तर पर लोगों की शारीरिक सक्रियता से होने वाले आर्थिक फायदे का अनुमान लगाया गया।

बेहतर स्वास्थ्य से आयु बढ़ती है और अर्थव्यवस्था में ज्यादा समय तक योगदान दिया जा सकता है। प्रतीकात्मक

ये मिले नतीजे

इसमें पाया गया कि अगर 18 से 64 साल के सभी वयस्क रोजाना 15 मिनट ज्यादा वॉकिंग कर लें, तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को सालाना 100 अरब डॉलर का फायदा हो सकता है। शारीरिक रूप से निष्क्रिय रहने वाला कोई 40 वर्षीय व्यक्ति रोजाना 20 मिनट जॉगिंग कर अपनी उम्र को औसतन 3.2 साल तक बढ़ा सकता है।

ऐसे होता है फायदा

अध्ययन में कहा गया है कि अगर लोग व्यायाम और वॉकिंग-जॉगिंग जैसी गतिविधियों को जीवनशैली का हिस्सा बना लें, तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। इससे लोगों की औसत आयु भी बढ़ती है। उम्र लंबी होने से लोग अर्थव्यवस्था में ज्यादा समय तक अपना योगदान दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वस्थ व्यक्ति की उत्पादकता भी अन्य से बेहतर रहती है।

34 महीने जेल की सजा सुनाई गई है मलेशिया में एक बिल्ली को कपड़े सुखाने की मशीन में डालने वाले एक शख्स को। पिछले साल इस व्यक्ति ने कपड़े सुखाने वाली सार्वजनिक मशीन में बिल्ली को डाल दिया था। अगले दिन बिल्ली मरी मिली थी। पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी।

अफगानिस्तान में भारत की कूटनीतिक उपस्थिति से भयभीत है पाकिस्तान

अफगानिस्तान पर अपनी ताजा रिपोर्ट में अमेरिकी संसद की स्वतंत्र और द्विदलीय कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस (सीआरएस) ने कहा है कि अफगानिस्तान में भारत की सामरिक, कूटनीतिक और वाणिज्यिक उपस्थिति से पाकिस्तान भयभीत है। रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने दशकों से अफगान मामलों में एक सक्रिय, लेकिन नकारात्मक भूमिका निभाई है और इस्लामाबाद काबुल में एक कमजोर सरकार चाहता है।

भय का कारण

रिपोर्ट के मुताबिक, अफगानिस्तान में भारत की कूटनीतिक और वाणिज्यिक उपस्थिति और इसके लिए अमेरिका का समर्थन पाकिस्तान की चिंता को बढ़ाता है। भारत ने यहां भारी निवेश किया हुआ है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में भारत का असर कम हो और पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल न हो। वहीं भारत की कोशिश है कि उसके अफगान सरकार के साथ अच्छे ताल्लुक बरकरार रहें और तालिबान का असर इतना न बढ़े कि वो भारत के लिए मसला पैदा करे।

ऐसे उपजे संबंध

अफगानिस्तान में भारतीय हित पाकिस्तान के साथ व्यापक क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता से उपजा है, जो मध्य एशिया के साथ मजबूत और प्रत्यक्ष वाणिज्यिक और राजनीतिक संबंध स्थापित करने के भारतीय प्रयासों को बाधित करता है।

भारत विरोधी ताकतों को समर्थन

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में मौजूद अफगान तालिबान जैसे भारत विरोधी आतंकी संगठनों को समर्थन देना जारी है।

आतंकियों को पनाह

रिपोर्ट में कहा गया है कि, पाकिस्तान तालिबानी और हक्कानी नेटवर्क के आतंकवादियों को अपने यहां सुरक्षित पनाह दे रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने लंबे समय से पाकिस्तान में आतंकी पनाहगाहों को अफगानिस्तान की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना है।

दिखाई नकारात्मक सक्रियता

सीआरएस की रिपोर्ट के मुताबिक एक अहम पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान ने इतने सालों में अफगानिस्तान के मामलों में अपने मंसूबों को साधने के लिए नकारात्मक सक्रियता दिखाई। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने अफगान के विद्रोही समूहों के साथ अच्छे संबंध रखे। इसमें खासकर हक्कानी नेटवर्क के साथ पाकिस्तान के खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के अच्छे रिश्ते हैं।

चाहता है कमजोर सरकार

सीआरएस ने कहा, पाकिस्तान कमजोर और अस्थिर अफगानिस्तान में ऐसी सरकार चाहता है, जो उसके इशारों पर चले। पाक वहां पश्तून जातीय के नेतृत्व वाली सरकार बनाने के प्रयास में है। क्योंकि पाकिस्तान में पश्तून एक बड़ा अल्पसंख्यक है।

सरकार गिरने की जताई आशंका

सीआरएस ने अपनी रिपोर्ट में अफगान मिलिट्री विद्रोही होने और सरकार के गिरने की आशंका भी जाहिर की है। सीआरएस ने चेतावनी दी है कि अमेरिका-तालिबान वार्ता रद्द होने के बाद तालिबान फिर से पूरे देश में अपना कब्जा जमा सकता है।

विवाद

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते अधिकतर समय तनाव भरे रहे हैं। अगर ऐतिहासिक तौर पर देखें तो दोनों पड़ोसियों के बीच कई मामले अनसुलझे हैं। दोनों के बीच 1,600 मील लंबी सीमा को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। वहीं पाकिस्तान में एक लाख से अधिक अफगान शरणार्थियों की उपस्थिति से अफगानिस्तान-पाकिस्तान संबंध और भी जटिल हो गए हैं।

न्यूज गैलरी

संरा में कश्मीर मसले पर पाक को करारा जवाब

संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर में महिला अधिकारों का मामला उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया है। कहा कि यह बात वह देश कह रहा है जिसका आतंकवाद को दूसरे देशों में भेजने का पुराना रिकॉर्ड है। जहां पर तुच्छ राजनीतिक फायदों के लिए महिलाओं की आवाज को बेरहमी से दबा दिया जाता है। भारत की यह कड़ी प्रतिक्रिया पाकिस्तान की प्रतिनिधि मलीहा लोधी के वक्तव्य पर आई। लोधी ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद की स्थितियों का वर्णन करते हुए आरोप लगाया था कि कश्मीर में महिलाओं के बुनियादी अधिकार खत्म हो गए हैं और वे घरों में कैद होकर रह गई हैं। स्थानांतरित हो चुकी लोधी का संयुक्त राष्ट्र में यह आखिरी भाषण था। (प्रेट्र)

नीदरलैंड्स में शिक्षकों की हड़ताल, स्कूल बंद

हेग : यूरोपीय देश नीदरलैंड्स में बुधवार को शिक्षकों की हड़ताल से हजारों स्कूल बंद रहे। एक दिनी हड़ताल के तहत देशभर में चार हजार से ज्यादा स्कूलों के शिक्षकों ने जगह-जगह प्रदर्शन किए। शिक्षकों ने यह हड़ताल नई भर्ती, वेतन वृद्धि और काम के हालात में सुधार की मांगों को लेकर की थी। इससे पहले देश में किसानों और निर्माण क्षेत्र के कामगारों ने भी बड़ी हड़ताल की थी। (एपी)

इराक में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, 13 मरे

बगदाद : पिछले 24 घंटे के दौरान इराकी सुरक्षाबलों द्वारा की गई कार्रवाई में 13 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। आठ लोगों की मौत जहां सोमवार को हुई वहीं मंगलवार तड़के पांच लोगों की मौत हुई। मृतकों में एक व्यक्ति वह भी है जो एक प्रदर्शनकारी के जनाजे में शामिल था। बता दें कि सरकार के खिलाफ अक्टूबर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में अब तक 260 इराकियों की मौत हो चुकी है। आरोप है कि सरकार भ्रष्ट है और वह विदेशियों के हित में काम कर रही है। (रायटर)

पाक ने चीन के आगे फिर फैलाए हाथ

आर्थिक संकट ▶ सीपीईसी से जुड़े प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए मांगा 63 हजार करोड़ का कर्ज

गत वर्ष भी चीन ने वाणिज्यिक कर्ज के तौर पर इमरान को दिए थे 4.6 करोड़ डॉलर

इस्लामाबाद, एएनआइ : बदहाल अर्थव्यवस्था से जूझ रहे पाकिस्तान ने चीन के आगे फिर हाथ फैलाए हैं। उसने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) से जुड़े प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए चीन से नौ अरब डॉलर (करीब 63 हजार करोड़ रुपये) का कर्ज मांगा है। प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबारने के लिए गत वर्ष भी चीन गए थे। तब पाकिस्तान को चीन से जमा और वाणिज्यिक कर्ज के तौर पर 4.6 करोड़ डॉलर मिले थे।

डॉन अखबार के अनुसार, सीपीईसी पर संयुक्त सहयोग समिति (जेसीसी) की यहां मंगलवार को हुई नौवें दौर की बैठक में पाकिस्तान और चीन के प्रतिनिधियों ने ग्वादर स्मार्ट सिटी मास्टर प्लान को स्वीकृति दी। स्वास्थ्य और कारोबार के क्षेत्र में दो समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा चीन से मिले 294 अरब पाकिस्तानी रुपये से बने मुल्तान-सुक्कुर हाईवे का उद्घाटन किया गया। जेसीसी बैठक की सह अध्यक्षता पाकिस्तान के योजना मंत्री मखदूम खुसरो बख्तयार और चीन के राष्ट्रीय विकास व सुधार आयोग के उपाध्यक्ष निंग जिझे ने की। बख्तयार ने कहा, 'प्रधानमंत्री के हालिया चीन दौरों और चीनी नेतृत्व के साथ हुई उनकी बातचीत से कृषि, उद्योग और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिला है। पाकिस्तान ने सीपीईसी अथॉरिटी स्थापित की है। यह सीपीईसी से जुड़े सभी प्रोजेक्ट के लिए सिंगल विंडो की तरह काम करेगी।'

बता दें सीपीईसी परियोजना के तहत पश्चिमी चीन के काशगर को पाकिस्तान में अरब सागर तट पर स्थित ग्वादर बंदरगाह से मिलाया जाना है।

सीपीईसी को नई दिशा देंगे चीन-पाक

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, चीन और पाकिस्तान में 60 अरब डॉलर की लागत वाले सीपीईसी प्रोजेक्ट को नई दिशा देने पर सहमति बनी है। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी खबर में बताया कि जेसीसी की नौवें दौर की बैठक में सीपीईसी को तांबा, सोना, तेल और गैस खनन क्षेत्रों से जोड़ने पर निर्णय लिया गया। बख्तयार ने कहा कि पाकिस्तान के तेल और गैस सेक्टर में आगामी तीन साल में दस अरब डॉलर का चीनी निवेश होने की उम्मीद है।

सीपीईसी के तहत चीन के काशगर को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से मिलाया जाना है। फाइल

अफगानिस्तान में पाक निभा रहा नकारात्मक भूमिका

वाशिंगटन, प्रेट्र : पाकिस्तान दशकों से अफगानिस्तान में सक्रिय लेकिन नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। इसी के चलते वह अफगानिस्तान में कमजोर सरकार चाहता है। नहीं चाहता कि पड़ोसी देश मजबूत और स्थिर बने। यह बात अमेरिकी संसद की ताजा रिपोर्ट में कही गई है।

अमेरिकी संसद की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष शोध संस्था (सीआरएस) की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का सबसे प्रमुख पड़ोसी है। लेकिन वह उसके खिलाफ दशकों से नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के अफगानिस्तान के आतंकी संगठनों से संबंध हैं, खासतौर से हक्कानी नेटवर्क जिसे अमेरिका ने विदेशी आतंकी संगठन (एफटीओ) घोषित कर रखा है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका से लड़ने वाले आतंकियों को पाकिस्तान में शरण मिलने के आरोप लगा चुके हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में कमजोर सरकार चाहता है जिससे कि वह अशांत और अव्यवस्थित बना रहे। ऐसे में पाकिस्तान के लिए वहां पर दखलंदाजी की गुंजाइश बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि अफगानिस्तान में अशांति का असर पाकिस्तान पर नहीं पड़ रहा। वह (पाकिस्तान) भी इस्लामी आतंकवाद की चपेट में आ गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शरणार्थियों को लेकर भविष्य में तनातनी होने की आशंका है क्योंकि अशांत अफगानिस्तान से सीमा पार कर लोगों का पाकिस्तान में आना आसान है। लाखों अफगान शरणार्थी पाकिस्तान में रह रहे हैं। दोनों देशों के बीच 1,600 किलोमीटर लंबी सीमा है।

भारत से आशंकित रहती है पाक सेना : रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की सेना भारत की रणनीतिक घेराबंदी से हमेशा आशंकित रहती है। उसे अफगानिस्तान में भारत की मजबूती परेशान करती है।

पूर्वी पीएम नवाज शरीफ को अस्पताल से मिली छुट्टी

लाहौर, आइएएनएस : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अदालत से जमानत मिलने के बाद उनकी बेटी मरयम नवाज को भी रिहा कर दिया गया है। शरीफ को मंगलवार को ही छुट्टी मिल गई थी लेकिन उन्होंने बेटी मरयम के बिना घर जाने से इन्कार कर दिया था। अस्पताल में भर्ती मरयम ने कोर्ट के आदेशानुसार जमानत राशि और पासपोर्ट कोर्ट में जमा नहीं करवाए थे, इसकी वजह से उनकी रिहाई में देरी हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने बताया कि शरीफ अपने घर पर ही रहेंगे, जहां निजी चिकित्सक डॉ अदनान मलिक उनकी देखभाल करेंगे। अदनान की देखरेख में घर पर ही आईसीयू यूनिट स्थापित की गई है। भ्रष्टाचार के मामले में सात साल जेल की सजा काट रहे शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों के चलते जमानत दी है। इस्लामाबाद हाइकोर्ट ने उनकी सजा आठ सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है।

आइएस-खुरासान ने 2018 में भारत में की थी आत्मघाती हमले की कोशिश : रुसेल

वाशिंगटन, प्रेट्र : खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) के खुरासान ग्रुप ने पिछले साल भारत में एक आत्मघाती हमले की कोशिश की थी। अमेरिकी सांसदों को यह जानकारी एक आतंकवाद रोधी अमेरिकी अफसर ने दी है।

अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक से संबद्ध नेशनल काउंटर टेरेरिज्म सेंटर में कार्यकारी निदेशक रुसेल ट्रेवर्स ने बुधवार को बताया कि आइएस के सभी गुटों और नेटवर्कों में निश्चित रूप से आइएस-खुरासन सबसे अधिक घातक और चिंताजनक है। ट्रेवर्स ने भारतीय मूल की सिनेटर मैगी हसन के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि करीब चार हजार से अधिक लोग आइएस-खुरासान का हिस्सा हैं। उसने अफगानिस्तान के बाहर भी कई भीषण हमले करने के प्रयास किए हैं। उन्होंने पिछले साल भारत में भी एक आत्मघाती हमला करने की नाकाम कोशिश की थी। हालांकि भारत में आइएस-खुरासान की हमले की साजिश के संबंध में उन्होंने और कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने बताया कि हम देखते आए हैं कि वर्ष 2016, 17 और 18 में आइएस-खुरासान ने कई हमले करने के दावे किए हैं।

भारतीय मूल की मैगी हसन ने पिछले महीने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की यात्रा की थी। इसी दौरान उन्हें पता चला कि वहां अमेरिकी सेना आइएस-खुरासान के बढ़ते असली खतरे को लेकर कितनी चिंतित है। आइएस-खुरासान का मुख्य अड्डा अफगानिस्तान है। मैगी हसन ने बताया कि अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सेना से आइएस-खुरासान के खतरे का पता चला बल्कि उनकी साजिश अमेरिका पर भी आतंकी हमला करने की है। पिछले ही हफ्ते हसन ने कहा था कि विश्व भर में आइएस की कम से कम 20 शाखाएं हैं। इनमें से कुछ तो आतंकी हमले के लिए अत्याधुनिक तकनीकों और ड्रोन जैसे विमानों का इस्तेमाल कर रही हैं। सीनेटर हसन ने कहा कि सीरिया और इराक में आतंकी संगठन आइएस के खिलाफ अमेरिका की जीत के बावजूद यह अब भी अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। तब ट्रैवर्स ने बताया कि कुछ साल पहले आइएस ने न्यूयार्क पर आतंकी हमला करने की साजिश रची थी जिसे अमेरिकी एजेंसी एफबीआइ ने नाकाम कर दिया था। इसके बाद वर्ष 2017 में स्टॉकहोम में आइएस ने आतंकी हमला किया जिसमें पांच लोग मारे गए थे।

वहीं, दूसरी ओर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल इंडियन मुजाहिदीन का गढ़ बन चुका है।

रुसेल ट्रेवर्स। रायटर

आतंकी साजिश

- अमेरिका के आतंकरोधी सेंटर से जुड़े अधिकारी ने सांसदों को दी जानकारी
- अमेरिकी सिनेटर ने कहा-आइएस अब भी अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है

ईरान के फोरडो संयंत्र में तेज हुआ काम, रूस और फ्रांस ने जताई चिंता

दुबई, रायटर : ईरान ने दुनिया के शक्तिशाली देशों के साथ हुए परमाणु समझौते से दूर हटते हुए अपने भूमिगत फोरडो परमाणु संयंत्र में गतिविधियां बढ़ा दी हैं। साथ ही ईरान ने परमाणु संयंत्रों के निरीक्षण को गई संयुक्त राष्ट्र की निरीक्षक को हिरासत में ले लिया है और उनके पासपोर्ट व अन्य यात्रा दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं। रूस और फ्रांस ने हालात पर चिंता व्यक्त की है।

ईरान ने कहा कि महिला निरीक्षक को नातांज संयंत्र में जाने से रोका गया, क्यों वह वहां पर संदिग्ध सामान लेकर जा रही थीं। जांच में उनके पास सामान होने का पता चला गया, उसी के बाद उन्हें रोक लिया गया। 2015 में परमाणु समझौता होने के बाद परमाणु ऊर्जा एजेंसी के किसी निरीक्षणकर्ता के साथ पहली बार ऐसा वाकया पेश आया है। अपने फोरडो संयंत्र में ईरान ने यूरेनियम गैस को सेंट्रीफ्यूज में डालने का प्रयोग करने जा रहा है। ईरान अपने इस संयंत्र को 2009 से ही लगातार छिपाए हुए है। यहां की गतिविधियों के बारे में दुनिया को ज्यादा नहीं मालूम।

एके-203 असाल्ट राइफल का सह-उत्पादन बढ़ाएगा रूस

- इसी वर्ष फरवरी में भारत और रूस ने 7.5 लाख एके-203 राइफल निर्माण का समझौता किया था

मॉस्को, आइएएनएस : रूस एके-203 असाल्ट राइफल के सह-उत्पादन की प्रक्रिया को तेज करने पर सहमत हो गया है। रक्षा मंत्री बनने के बाद राजनाथ सिंह पहली बार रूस यात्रा पर पहुंचे हैं। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि भारत और रूस ने इसी वर्ष फरवरी में संयुक्त रूप से 7.5 लाख एके-203 राइफल निर्माण करने का समझौता किया था।

तीन दिनों की रूस यात्रा पर आए राजनाथ ने बुधवार को अपने रूसी समकक्ष जनरल सेर्गेय शोइगु से मुलाकात की। यह मुलाकात मॉस्को में सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग की 19वीं बैठक के दौरान हुई। रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया है, 'रूस के साथ हमारी साझेदारी मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाएगी। डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 के लिए रक्षा मंत्री शोइगु से मजबूत समर्थन मिला। मैंने कलाशनिकोव संयुक्त उपक्रम के शीघ्र संचालन के लिए रूस के समर्थन का स्वागत किया।' एके-203 असाल्ट राइफल शुरू में सीमा पर और अशांत क्षेत्रों में तैनात भारतीय जवानों को दिया जाएगा। यह अपने देश में बने आइएनएसएएस राइफलों की जगह लेगा। उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरवा में स्थित सरकारी आयुध कारखाने को संयुक्त उपक्रम के लिए चुना गया है। एके-203 के लिए रूसी फर्म के साथ 50.5 फीसद भागीदारी रखी गई है। राइफलों का उत्पादन पांच चरणों में होगा जिसमें पहले चरण में स्वदेशी हिस्सों की भागीदारी पांच से बढ़ाकर 15 फीसद की जाएगी। पांचवें और अंतिम चरण में इसमें 100 फीसद भारतीय पुर्जे लगाए जाएंगे।

निर्यात के लिए संयुक्त निर्माण इकाई का आह्वान किया : भारत ने रूस के रक्षा उद्योग से रक्षा क्षेत्र में निर्यात के लिए उपकरणों के संयुक्त निर्माण का आह्वान किया है। इससे तीसरी दुनिया के देशों को निर्यात में बल मिलेगा। मॉस्को में रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ 'रूस रक्षा उद्योग सहयोग सम्मेलन' में राजनाथ ने कहा कि दोनों देशों को मिलकर रक्षा उत्पादन करना चाहिए। साथ ही इन उत्पादों के निर्यात लिए एक मंच भी खड़ा करना चाहिए।

राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप की पार्टी को झटका

न्यूयॉर्क, आइएएनएस : अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। केंटकी राज्य में गवर्नर की कुर्सी गंवाने के साथ पार्टी को वर्जीनिया की विधायिका में भी भारी नुकसान हुआ है। केंटकी में गवर्नर पद के लिए दोबारा चुनाव लड़ रहे रिपब्लिकन पार्टी के मैट बेवीन को 5,100 वोटों के अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने यहां 30 फीसद के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। बेवीन की हार इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि ट्रंप ने उनका चुनाव प्रचार किया था।

वर्जीनिया की विधायिका के निचले और उच्च सदन दोनों में रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान हुआ है। इसके चलते कई दशकों बाद विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रांत की विधायिका में बहुमत हासिल कर लिया है। डेमोक्रेटिक नेता राल्फ नार्थहम पहले ही राज्य के गर्वनर पद पर थे। इन असफलताओं के बीच सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी मिसीसिपी में गर्वनर पद बचाने में कामयाब रही। लेफ्टिनेंट गर्वनर टेट रिव्स छह फीसद वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर दोबारा वापसी करने में सफल हुए।

हांगकांग में लोकतंत्र की मांग वालों पर जल्द हो सकती है सख्त कार्रवाई

- चीनी उप प्रधानमंत्री से हांगकांग की नेता की वार्ता के बाद संकेत

हांगकांग, रायटर : चीन ने हांगकांग में लोकतंत्र की मांग वाले आंदोलन के खिलाफ जल्द ही कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। चीन सरकार ने कहा कि हांगकांग में कड़ी कार्रवाई का समर्थन किया जाएगा। चीन का यह नया रुख हांगकांग में बुधवार को स्थानीय विधायक पर चाकू से हुए हमले के बाद सामने आया है। जिस विधायक पर हमला हुआ, उन्हें चीन समर्थक माना जाता है। हांगकांग चीन के अंतर्गत स्वायत्त क्षेत्र है, जो समझौते के तहत उसे ब्रिटेन से 1997 में प्राप्त हुआ है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने चीनी समकक्ष शी चिनफिंग को हांगकांग विषय को शांति, धैर्य और वार्ता के जरिये सुलझाने की सलाह दी है।

बीजिंग में हांगकांग की सर्वोच्च नेता कैरी लैम के साथ बैठक के बाद चीन के उप प्रधानमंत्री हान झेंग ने कहा, सरकार विरोधी तत्व चीन के एक देश-दो शासन पद्धति के फॉर्मूले को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 1997 से हांगकांग में शासन का यही सिद्धांत लागू है। हान ने कहा, हांगकांग की सामाजिक समस्या को सुलझाने के लिए वहां की सरकार के उठाए जाने वाले सभी कदमों में चीन साथ है। भविष्य में इन कदमों के तहत और कड़ाई की जाएगी।

हान ने सामाजिक समस्या के तौर पर हांगकांग में निवास की समस्या का भी जिक्र किया। समुद्र के किनारे बसे हांगकांग में जमीन काफी महंगी है और वहां रहने के ठिकाने का इंतजाम बहुत मुश्किल है। कैरी लैम ने अक्टूबर में ही स्वायत्त क्षेत्र के लिए भूमि और आवास संबंधी सुधार कार्यक्रम की घोषणा की है।

रक्षा मंत्री वेई ने किया अपने देश की नीति का बचाव

चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंग ने हांगकांग और शिनजियांग को लेकर अपने देश की नीति का बचाव किया है। कहा है कि ताइवान और दक्षिण चीन सागर को लेकर भी चीन की नीति उसके हितों पर आधारित है। ये विषय उसकी संप्रभुता से जुड़े हुए हैं। इनको लेकर चीन की भी तरह का समझौता नहीं करने वाला। फेंग ने यह बात अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से टेलीफोन पर हुई बातचीत में कही है।

चीन समर्थक नेता पर हमला

हांगकांग में बुधवार को स्थानीय विधायक जूनियस हो पर चाकू से हमला हुआ। हमले में जूनियस के साथ मौजूद दो लोग भी घायल हुए हैं। जूनियस के सीने के पास चाकू का घाव हुआ है। सभी घायल खतरे से बाहर हैं। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले के उद्देश्य के बारे में अभी पता नहीं चला है। हो को चीन समर्थक माना जाता है और हांगकांग में चल रहे चीन विरोधी आंदोलन पर वह अक्सर उपहास किया करते थे। यह हमला 24 नवंबर को होने वाले जिला परिषद चुनाव से पूर्व हुआ है। जूनियस चुनाव के प्रचार के सिलसिले में निकले हुए थे तभी उन पर हमला हुआ।

सख्ती का असर

इस साल अमेरिका में भारतीय आइटी कंपनियों के चार गुना आवेदन खारिज किए गए, वर्ष 2015 में छह फीसद आवेदन हुए थे रद

एच-1बी वीजा आवेदन खारिज होने के मामले बढ़े

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की सख्त इमीग्रेशन नीतियों के कारण भारतीय आइटी कंपनियों के एच-1बी वीजा आवेदन खारिज होने के मामले काफी बढ़ गए हैं। यह वीजा भारतीय आइटी पेशेवरों में खासा लोकप्रिय है।

थिंक टैंक नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकी पॉलिसी के अनुसार, इस साल भारतीय आइटी पेशेवरों के एच-1बी वीजा आवेदन खारिज होने के मामलों में चार गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2015 में भारतीयों के महज छह फीसद आवेदन खारिज हुए थे, लेकिन यह दर मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में बढ़कर 24 फीसद हो गई। वीजा मामलों को देखने वाले विभाग अमेरिकी सिटिजनशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआइएस) के आंकड़ों का अध्ययन कर थिंक टैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा।

भारतीय आइटी कंपनियां ज्यादा प्रभावित : इस अध्ययन से जाहिर होता है कि अमेरिका में स्थित भारतीय आइटी कंपनियां ट्रंप प्रशासन की सख्ती से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। इनमें प्रमुख रूप से टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी, विप्रो और इंफोसिस जैसी भारतीय आइटी कंपनियां शामिल हैं।

प्रतीकात्मक

क्या है एच-1बी वीजा : भारतीय पेशेवरों के बीच खासे लोकप्रिय एच-1बी वीजा के जरिये अमेरिकी कंपनियों को उन क्षेत्रों में अत्यंत कुशल विदेशी पेशेवरों को नौकरी पर रखने की अनुमति मिलती है जिनमें अमेरिकी पेशेवरों की कमी है। यह वीजा तीन साल के लिए जारी होता है और छह साल तक इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इस पर लगाम कस दी गई।

आम श्रेणी में 65 हजार वीजा : अमरिकी संसद से यूएससीआइएस को आम श्रेणी में 65 हजार एच-1बी वीजा जारी करने की मंजूरी मिली है।

इन पर सख्ती		
भारतीय कंपनी	2015	2019
टेक महिंद्रा	04	41
टाटा कंसल्टेंसी	06	34
विप्रो	07	53
इंफोसिस	02	45
इन पर नरमी		
अमरिकी कंपनी	2015	2019
अमेजन	01	06
माइक्रोसॉफ्ट	01	08
इंटेल	01	07
गूगल	01	03

(वीजा आवेदन खारिज होने के आंकड़े फीसद में)

इसके अतिरिक्त 20 हजार एच-1बी वीजा उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अमेरिका के उच्च शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की है।

थाइलैंड में विद्रोहियों के हमले में 15 की मौत

बैंकॉक, एएफपी : थाइलैंड के अशांत दक्षिणी इलाके में विद्रोहियों के हमले में 15 लोगों की मौत हो गई। सेना प्रवक्ता प्रमोत प्रोम ने बुधवार को यहां बताया कि याला प्रांत की दो जांच चौकियों पर घात लगाकर किए गए इस हमले में चार लोग घायल भी हुए हैं। इसे पिछले 15 सालों का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है।

आशंका जताई जा रही है कि इस हमले में मुस्लिम विद्रोहियों का हाथ हो सकता है। थाइलैंड के तीन दक्षिणी प्रांत हिंसा की चपेट में हैं। मलय-मुस्लिम विद्रोही यहां ज्यादा स्वायत्तता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 15 सालों में मलय-मुस्लिम बहुल दक्षिणी इलाके में हिंसा के दौरान करीब सात हजार लोगों की जान गई है। स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

करीब तीन महीने पहले देश की राजधानी बैंकॉक में कई छोटे बम धमाके हुए थे। तब राजधानी में एक बड़े सम्मेलन का आयोजन हो रहा था। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो समेत कई विदेशी राजनयिक भी इस सम्मेलन में मौजूद थे।

फेसबुक यूजर्स का डाटा जुटा रहे थे 100 एप

- सोशल मीडिया दिग्गज ने खुद दी इसकी जानकारी
- सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वीडियो स्ट्रीमिंग से जुड़े थे ज्यादातर एप

सैन फ्रांसिस्को, आइएएनएस : सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक के खिलाफ यूजर्स की निजता के उल्लंघन और डाटा चोरी के कई मामले सामने आ चुके हैं। खुद फेसबुक ने बुधवार को इस तरह के एक नए मामले की जानकारी दी। कंपनी के अनुसार, करीब 100 एप डेवलपर ने कई महीनों तक फेसबुक यूजर्स का निजी डाटा इकट्ठा किया। कंपनी ने इनमें से 11 एप की पुष्टि की है, जिनके जरिये बीते 60 दिनों में यूजर्स के नाम, प्रोफाइल पिक्चर और ग्रुप में उनके क्रियाकलापों से संबंधित जानकारियां इकट्ठा की गई थीं।

इनमें से ज्यादातर वीडियो स्ट्रीमिंग या सोशल मीडिया मैनेजमेंट एप थे। इन्हें सोशल मीडिया साइटों पर ग्रुप चलाने वाले एडमिन की सहूलियत के लिए डिजाइन किया गया था ताकि ग्रुप के सदस्य आसानी से वीडियो आदि शेयर कर पाएं। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मामले में अब तक निजता उल्लंघन या डाटा चोरी का सुबूत नहीं मिला है। लेकिन कंपनी की ओर से एप डेवलपरों को डाटा डिलीट करने का निर्देश दिया गया है। इसे सुनिश्चित कराने के लिए कंपनी ऑडिट भी करेगी। फेसबुक के प्लेटफॉर्म पार्टनरशिप विभाग के निदेशक कांस्टेनटिनो पापमिल्डिटस ने कहा, 'हम यूजर्स के डाटा की सुरक्षा को लेकर सजग हैं। इस दिशा में सुधार के प्रत्येक प्रयास किए जा रहे हैं।'

ब्रिटेन स्थित कंपनी कैंब्रिज एनालिटिका द्वारा 8.7 करोड़ यूजर्स का डाटा चोरी करने के मामले में फेसबुक पहले ही गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है। फेडरल ट्रेड कमीशन ने इस मामले में कंपनी पर पांच अरब डॉलर (करीब 35 हजार करोड़ रुपये) का जुर्माना भी लगाया है।

'महा' खतरे के बीच जवाबी हमले को तैयार भारत

पहले टी-20 में बांग्लादेश से उलटफेर का शिकार हुई थी टीम इंडिया, राजकोट में दूसरे टी-20 के लिए आज आमने-सामने होंगी दोनों टीमें

राजकोट, प्रेट्र : क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में एक बार फिर दबाव में आया भारत गुरुवार को यहां बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में जीत के साथ सीरीज बराबर करने के इरादे से उतरेगा। इस मैच में चक्रवातीय तूफान महा का खतरा भी मंडरा रहा है। भारत को दिल्ली में वायु प्रदूषण के बीच रविवार को पहले टी-20 मैच में उलटफेर का शिकार होना पड़ा था और टीम को सात विकेट से शिकस्त खानी पड़ी थी। अब रोहित शर्मा की अगुआई वाली भारतीय टीम जवाबी हमले के लिए तैयार है।

बांग्लादेश के लिए यह नतीजा बेहतरीन है जो वेतन और अन्य मुद्दों को लेकर खिलाड़ियों की हड़ताल के बाद यहां आया है। भारत को पिछले कुछ समय में टी-20 प्रारूप में वैसी सफलता नहीं मिली है जैसी टीम ने वनडे और टेस्ट क्रिकेट में हासिल की है और यह इस साल के नतीजों में भी झलकता है। भारत को इस साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर हार का सामना करना पड़ा जबकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज बराबर रही। भारत ने टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका का क्लीन स्वीप किया था। नियमित कप्तान विराट कोहली सहित कुछ सीनियर खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में युवा खिलाड़ियों के पास यह सीरीज अपनी क्षमता दिखाने का मौका है।

हारने पर बढ़ेगी मुश्किल : भारत अगर बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज गंवाता है तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उसकी नजरें अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए टीम तैयार करने पर टिकी हैं। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय बल्लेबाजों को रनों के लिए जूझना पड़ा था।

अंतिम-एकादश में हो सकता है बदलाव : यह देखना होगा कि टीम प्रबंधन शिवम दुबे को एक और मौका देता है या केरल के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को अंतिम एकादश में शामिल करता है। कर्नाटक के बल्लेबाज मनीष पांडे को भी मौका मिल सकता है। भारत की अनुभवहीन गेंदबाजी भी टीम प्रबंधन के लिए चिंता का विषय है। तेज गेंदबाज खलील अहमद ने दिल्ली में चार ओवर में 37 रन लुटाए थे और 19वें ओवर में उनकी गेंदों पर विरोधी टीमें ने लगातार चार चौके मारे थे। दूसरे टी-20 में उनकी जगह शार्दुल ठाकुर को अंतिम एकादश में शामिल किया जा सकता है। चहल, क्रुणाल पांड्या और वॉशिंगटन सुंदर की स्पिन तिकड़ी को विरोधी टीम की रन गति पर अंकुश लगाने के अलावा विकेट भी चटकाने होंगे।

डीआरएस ने बढ़ाई रोहित की चिंता : भारतीय टीम रविवार को रिव्यू लेने में फंस गई थी। एलबीडब्ल्यू आउट होने के बाद रोहित ने रिव्यू बर्बाद किया तो दूसरी पारी में 9.3 ओवर में रोहित ने डीआरएस नहीं लिया। चहल की यह गेंद मुश्फिकुर रहीम के पैड में लगी और उन्होंने एलबीडब्ल्यू की अपील भी की। अंपायर ने नॉटआउट दिया, लेकिन टीम ने रिव्यू नहीं लिया। अगर भारत रिव्यू लेता तो मुश्फिकुर आउट हो जाते। वहीं, इसी ओवर की आखिरी गेंद पर पंत ने सौम्य सरकार के खिलाफ कैच आउट की अपील की। चहल रिव्यू नहीं चाहते थे, लेकिन पंत के जोर देने पर रोहित ने रिव्यू लिया, लेकिन यह रिव्यू भी बर्बाद हो गया। रोहित को दूसरे मैच में सोच समझकर डीआरएस लेना होगा।

राजकोट में सौराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम की पिच देखते भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ● एएनआइ

02 छक्के लगाने के साथ बांग्लादेश के टी-20 कप्तान महमूदुल्लाह क्रिकेट के इस सबसे छोटे प्रारूप में छक्कों का अर्धशतक पूरा कर लेंगे। वह टी-20 में यह उपलब्धि हासिल करने वाले बांग्लादेश के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। महमूदुल्लाह से पहले तमीम इकबाल ने 41 छक्के जड़े हैं

02 टी-20 मैच ही एससीए स्टेडियम में खेले गए हैं। 2017 में न्यूजीलैंड ने 196 रन बनाए जबकि 2013 में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201 रनों का स्कोर खड़ा किया। भारतीय टीम न्यूजीलैंड से मैच हार गई थी जबकि ऑस्ट्रेलिया को उसने शिकस्त दी थी

04 पिछले टी-20 मैचों में से तीन में भारतीय टीम को शिकस्त मिली है। ये सभी मैच रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने खेले हैं

06 टी-20 मैच बांग्लादेश की टीम ने नए कप्तान महमूदुल्लाह की कप्तानी में खेले हैं जिसमें मेहमान टीम सिर्फ दो मैच जीत सकी है

04 लगातार टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच बांग्लादेश की टीम के पास पहली बार जीतने का मौका है

07 पिछले टी-20 मैचों में से बांग्लादेश की टीम ने पांच में जीत हासिल की है

106 छक्कों के साथ रोहित के नाम टी-20 क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के भी दर्ज हैं। इसके अलावा उन्होंने सबसे अधिक चार शतक भी लगाए हैं

100 वां टी-20 खेलेंगे रोहित। 99 मैचों में रोहित शर्मा के नाम 2452 रन दर्ज हैं। वह टी-20 में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं

03 या इससे ज्यादा मैचों की टी-20 सीरीज को बांग्लादेश की टीम सिर्फ दो बार ही जीत पाई है

जब पिच देखने पहुंचे रोहित

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बुधवार को अभ्यास सत्र के दौरान अकेले ही सौराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम की पिच को देखने पहुंच गए। पिच को देखने के बाद रोहित ने पिच क्यूरेटर और वहां मौजूद अधिकारियों से कुछ बातचीत भी। रोहित भी पहले मैच में बल्लेबाजों की मददगार पिच पर सस्ते में आउट होकर पवेलियन लौट गए थे।

पिच और हालात

उम्मीद के मुताबिक चक्रवात महा मैच के दिन गुरुवार शाम सौराष्ट्र तक पहुंच सकता है। ऐसे में दिन भर बादल छाए रहने की संभावना है और शाम को भारी बारिश भी हो सकती है। स्टेडियम की पिच को कवर से ढका हुआ है। इन हालात को देखते हुए तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है।

चक्रवात महा पर होगी सभी की निगाह

मैच के दिन गुरुवार को सभी की निगाह चक्रवात महा पर रहेगी जो मैच का खेल बिगाड़ सकता है। पहला टी-20 मैच में दिल्ली में खेला गया था जहां दोनों टीमों को वायू प्रदूषण से जूझना पड़ा था। इस दौरान बांग्लादेश की टीम ने मास्क पहनकर अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया था।

दुबे को शास्त्री की सलाह

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में फीका पदार्पण करने वाले ऑलराउंडर शिवम दुबे बुधवार को सौराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम में अभ्यास सत्र के लिए पहुंचे तो उनके साथ मुख्य कोच रवि शास्त्री भी रहे। जब वह बल्लेबाजी का अभ्यास कर रहे थे तो शास्त्री उन्हें कुछ सलाह दे रहे थे। दुबे दिल्ली टी-20 मैच में एक रन ही बना पाए थे।

दोनों टीमें : भारत : रोहित शर्मा (कप्तान), शिखर धवन, लोकेश राहुल, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, रिषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, क्रुणाल पांड्या, युजवेंद्रा सिंह चहल, राहुल चाहर, दीपक चाहर, खलील अहमद, शिवम दुबे, शार्दुल ठाकुर।

बांग्लादेश : महमूदुल्लाह (कप्तान), मुहम्मद नईम, अफिफ हुसैन, मुसद्दक हुसैन, अनिमुल इस्लाम, लिटन दास, मुश्फिकुर रहीम, अराफत सनी, अल अमिन हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, शैफुल इस्लाम, अबु हैदर, मुहम्मद मिथुन, ताइजुल इस्लाम।

सर्वाधिक टी-20 मैच खेलने वाले भारतीय

खिलाड़ी	मैच	रन	सर्वाधिक स्कोर	औसत
रोहित शर्मा	99	2452	118	31.84
एमएस धौनी	98	1617	56	37.60
सुरेश रैना	78	1605	101	29.18
विराट कोहली	72	2450	नाबाद 90	50.00
युवराज सिंह	58	1177	नाबाद 77	28.02

सर्वाधिक टी-20 मैच खेलने वाले ओवरऑल खिलाड़ी

खिलाड़ी	मैच	रन	सर्वाधिक स्कोर	औसत
शोएब मलिक	111	2263	75	30.58
शाहिद अफरीदी	99	1416	नाबाद 54	17.92
रोहित शर्मा	99	2452	118	31.84
एमएस धौनी	98	1617	56	37.60
रॉस टेलर	93	1726	63	26.15

बांग्लादेश की युवा टीम में नजर आ रहा है दम

दूसरी तरफ नौ टी-20 मैचों में भारत के खिलाफ पहली जीत दर्ज करने के बाद बांग्लादेश की टीम सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी। पहले मैच में टीम के सबसे बड़े स्टार मुश्फिकुर रहे जिन्होंने 149 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नाबाद 60 रन बनाए। सीनियर बल्लेबाजों तमीम इकबाल और शाकिब की गैरमौजूदगी में टीम को रहीम से एक और अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। बांग्लादेश के गेंदबाजों विशेषकर स्पिनर अनिमुल इस्लाम और तेज गेंदबाज शैफुल इस्लाम ने पहले मैच में प्रभावित किया और वे इस लय को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे।

पंत-धौनी की तुलना बंद हो

के श्रीकांत

कलम से

मुझे लगता है कि दिल्ली में मिली हार को लेकर बहुत ज्यादा हाय-तौबा नहीं होनी चाहिए। टी-20 विश्व कप को देखते हुए इस तरह के प्रयोगों की जरूरत है और अगर आप अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ नहीं खेल रहे हो, तो हार को एक सीख के तौर पर लेना चाहिए। हालांकि टीम प्रबंधन को सही संयोजन जल्द से जल्द खोजना होगा। काम का बोझ भी एक अहम पहलू है, इसलिए टीम प्रबंधन को इस बारे में भी सोचना होगा। पहले की तरह इस बार भी भारतीय टीम पावरप्ले में रनों की गति को नहीं बढ़ा पाई।

मुझे धवन की एप्रोच देखकर ज्यादा निराशा हुई। सीनियर खिलाड़ी होने के बावजूद वह अपना प्राकृतिक खेल नहीं खेल पा रहे हैं। मैं उनकी जगह सीधे केएल राहुल को टीम में शामिल करता। रोहित और राहुल दोनों आक्रामक बल्लेबाज हैं और पावरप्ले में तेजी से रन बना सकते हैं। नंबर तीन पर विराट कोहली के बाद मैं चौथे नंबर पर रिषभ पंत को रखना चाहूंगा। कम से कम कुछ समय तक उन्हें मौका मिलना ही चाहिए। यह स्पष्ट है कि टी-20 में शीर्ष चार ही

अहम भूमिका निभाते हैं। एक बार जब टीम में सभी को अपनी जगह पता होगी, तो विश्व कप में भारत का प्रदर्शन अच्छा ही होगा। मेरे खेल के दिनों में कपिल देव और सुनील गावस्कर हमेशा मेरा समर्थन किया करते थे। वे अक्सर कहते थे कि मैदान में जाओ और खेलो, यह चिंता छोड़ दो कि टीम में तुम्हारी जगह पक्की है या नहीं। पंत को भी इसी तरह के समर्थन की जरूरत है। टेस्ट क्रिकेट में साहा को लेकर आने के पीछे की वजह को मैं समझ सकता हूं, लेकिन सफेद गेंद के प्रारूप में पंत पहली पसंद होने चाहिए। धौनी से उनकी तुलना को बिलकुल बंद कर देना चाहिए। धौनी जैसे खिलाड़ी पीढ़ियों में आते हैं और उनसे तुलना युवाओं के लिए ठीक नहीं। (टीसीएम)

दिग्गज नपे, लेकिन मयंक पारिख बचे

अभिषेक त्रिपाठी ● नई दिल्ली

अद्भुत मामला

- फिर बीसीसीआइ के पदाधिकारियों तक पहुंची शिकायत
- नए अधिकारियों के सामने पुराने मामलों को हल करने की चुनौती

बीसीसीआइ को सौरव गांगुली की अध्यक्षता वाली नई टीम तो मिल गई है लेकिन इस टीम के सामने अभी भी कुछ पुरानी समस्याएं मुंह खोले बैठी हैं। मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) के आधिकारिक हस्ताक्षरकर्ता मयंक पारिख द्वारा छह क्लबों की मिलकियत का मुद्दा भी इनमें से एक है।

बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने नवनियुक्त अध्यक्ष सौरव गांगुली को पत्र लिखकर पारिख के हितों के टकराव के मसले पर ध्यान देने का अनुरोध किया है। दरअसल पारिख मुंबई में छह क्लब चलाते हैं और वह मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) से जुड़े हुए भी हैं जबकि नियमों के मुताबिक बोर्ड से जुड़े रहने के दौरान ना तो उनके पास वोटिंग का अधिकार है और ना ही वह किसी उपसमिति में भाग ले सकते हैं। अधिकारी ने आरोप लगाया है कि पारिख को बीसीसीआइ में मौजूद कुछ लोगों का साथ मिल रहा है जिसकी वजह से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पारिख के शुभचिंतकों को यह जानने की जरूरत है कि पूर्व भारतीय कप्तान और 100 से ज्यादा टेस्ट खेल चुके दिलीप वेंगसरकर केवल एक क्लब की मिलकियत रखते हैं लेकिन उनका क्लब मुंबई की क्रिकेट के विकास में पारिख के क्लबों से ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाता है। बहुत लोगों को लगता है कि बीसीसीआइ और एमसीए में पारिख को शह देने वालों की संख्या ज्यादा है जो हमेशा उनका बचाव करते हैं।

अधिकारी ने इस पत्र में आगे लिखा है कि कुछ ऐसे ही मामले में हैदराबाद क्रिकेट संघ में क्लब की मिलकियत रखने की वजह से दिवंगत डा. एमवी श्रीधर को इस्तीफा देना पड़ा था। इस मामले को 2017 में भी उठाया गया था। पारिख के मसले को इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) की सदस्य डायना इडुल्डी के माध्यम से बोर्ड के सामने रखने की कोशिश की गई लेकिन बीसीसीआइ की बैठकों में इस पर कोई चर्चा नहीं की गई। बीसीसीआइ के सीईओ राहुल जौहरी और कानूनी टीम को इसकी दो लाइन की रिपोर्ट बोर्ड के आधिकारिक पेज पर साझा करने में जून 2019 तक का समय लग गया। इस देरी की वजह निश्चित ही जौहरी और कानूनी टीम से पूछी जानी चाहिए। बीसीसीआइ का संविधान साफ कहता है कि हितों के टकराव का मसला नैतिक अधिकारी या लोकपाल के पास भेजा जाना चाहिए लेकिन हैरानी की बात है कि जौहरी या कानूनी टीम ने इसे मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता के ईमेल लिखे जाने से पहले तक आगे नहीं बढ़ाया गया।

साथ ही अधिकारी ने हितों के टकराव के कुछ मसलों का हवाला भी दिया और बताया है कि कैसे पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने अपना पद छोड़ दिया था। अधिकारी ने इस पत्र में लिखा है कि सीओए को जानकारी मिली थी कि गावस्कर एक खेल प्रबंधन करने वाली कंपनी में साझेदार हैं लेकिन उन्होंने हितों के टकराव से बचने के लिए कंपनी से अपने शेयर हटा लिए थे। जौहरी और कानूनी टीम ने जाहिर कर दिया कि वे पारिख के मामले में उन्हें सहयोग कर रहे हैं। भारतीय टीम प्रबंधन द्वारा ईमेल के माध्यम से पारिख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई बल्कि उन्हें भारत-ए के साथ रखा गया था। तब मैनेजर के खिलाफ खिलाड़ियों को हवाई यात्रा में टिकटों को लेकर, होटल में खान-पान और रहन-सहन को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद उस मसले को दुरुस्त करने के लिए क्रिकेट प्रबंधक अधिकारी और संचालन प्रबंधक को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भेजना पड़ा था।

इस पत्र में आरोप लगाया गया है कि अगर बीसीसीआइ से पारिख को शह नहीं मिली होती तो अब तक वह नहीं बच पाता और उनकी जगह कोई और होता तो वह अपनी नौकरी गंवा चुका होता। अधिकारी ने लिखा कि पारिख को बिना किसी काम किए पैसे मिल रहे हैं और 18 महीनों बाद भी अब तक उन्हें कोई काम नहीं सौंपा गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि गांगुली की नई टीम पारिख के मामले का निपटारा कैसे करती है। गांगुली, सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण ने कुल मिलाकर 1300 मैच खेले हैं और 64000 से ज्यादा रन बनाए हैं लेकिन ये भी बीसीसीआइ संविधान के हिसाब से हितों के टकराव के मसले से दो-चार हुए लेकिन सीओए के नेतृत्व में काम कर रहे अधिकारियों ने इस तरह का रवैया अपनाया जैसे पारिख के छह क्लबों का मामला हितों के टकराव के अंदर नहीं आता है।

अब सबक लें मेजबान

वीवीएस लक्ष्मण

वेरी-वेरी स्पेशल

मुश्फिकुर रहीम और बांग्लादेश को भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में नौ प्रयासों में अपनी पहली जीत के लिए काफी कुछ श्रेय जाता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे सबक हैं जिनसे सीख लेकर मेजबान टीम इस प्रारूप में अपनी लगातार दूसरी हार से बच सकती है। टीम को प्रतिस्पर्धात्मक स्कोर तक पहुंचाने के लिए समान रूप से सेट बल्लेबाजों को 17वें या 18वें ओवर तक गहराई से बल्लेबाजी करनी चाहिए।

टीम में शामिल युवा खिलाड़ियों को हर मैच को मुख्य टूर्नामेंट के लिए ऑडिशन के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह निश्चित रूप से उन्हें अनिश्चितता की ओर और उस स्वाभाविक खेल से दूर ले जाएगा, जिसकी बदौलत उन्होंने इस खेल की इतनी सेवा की है और जो उन्हें इस स्तर पर लाया है। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने अपनी प्रतिभा की झलक दिखाई, लेकिन वे ज्यादा देर तक नहीं चल सके। शिखर धवन ने जोरदार शुरुआत दी, लेकिन वह रिषभ पंत के साथ गफलत का शिकार होकर रन आउट हो गए। बांग्लादेश युवा लेग स्पिनर अमिनुल इस्लाम ने जिस तरह का दिल और प्रतिभा दिखाई उससे मैं काफी प्रभावित हुआ। वह एक अनुकूल पिच पर गेंद को फ्लाइट करने से नहीं डर रहे थे और उन्हें इसके पुरस्कार के रूप में राहुल और श्रेयस के अहम विकेट मिले।

यकीनन, क्रुणाल पांड्या और वाशिंगटन सुंदर की शानदार पारियों के बिना भारत 148 के स्कोर तक नहीं पहुंच पाता। क्रुणाल और सुंदर ने टी-20 में अपनी बल्लेबाजी पर काफी मेहनत की और अब उन्हें इसका पुरस्कार मिल रहा है। ब्रेक के समय लय भारत के साथ थी और उन्होंने गेंद के साथ अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन मुश्फिकुर की एक मास्टर क्लास पारी की वजह से वे ठगे से रह गए। स्पिनरों पर उन्होंने पारंपरिक शॉट और रिवर्स स्वीप खेले, जबकि तेज गेंदों को उन्होंने क्रीज के अंदर जाकर देर से खेला। बांग्लादेश ने चुनौती स्वीकार कर ली है और अब राजकोट में दूसरे मैच में भारत को जवाब देना होगा।

उत्तर प्रदेश के निर्देश ने लिए पारी में 10 विकेट

तेजपुर (असम), प्रेट्र : ऑफ स्पिनर निर्देश बैसोया ने बुधवार को बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए यहां अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी के मुकाबले में एक पारी में सभी 10 विकेट अपने नाम किए। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले निर्देश ने यह कारनामा मेघालय की ओर से खेलते हुए नगालैंड के खिलाफ किया। उन्होंने 21 ओवर में 10 मेडन फेंकते हुए 51 रन देकर सभी 10 विकेट झटके। उनके इस प्रदर्शन की बदौलत नगालैंड की टीम मैच के पहले दिन सिर्फ 113 रन पर ढेर हो गई।

निर्देश के प्रदर्शन की चारों तरफ चर्चा हो रही है। उनके इस प्रदर्शन ने दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबले की याद दिला दी। कुंबले ने 1999 में दिल्ली टेस्ट में इसी तरह का कारनामा अंजाम देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 74 रन देकर 10 विकेट झटके थे, जिसके चलते भारत ने वह टेस्ट 212 रन से जीता था। मणिपुर के तेज गेंदबाज रेक्स सिंह ने पिछले साल कूच बेहार ट्रॉफी के मैच में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने की उपलब्धि हासिल की थी।

एआइटीए पर भड़के भूपति

मामला

- महेश ने कहा, डेविस कप कप्तानी से हटाए जाने से कोई दिक्कत नहीं
- राष्ट्र सेवा से इन्कार की खबर को बताया निराधार

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय टेनिस स्टार महेश भूपति का कहना है कि डेविस कप कप्तान के तौर पर उन्हें हटाए जाने से कोई दिक्कत नहीं हैं, लेकिन उन्हें टेनिस महासंघ द्वारा लगाया गया यह आरोप स्वीकार नहीं है कि उन्होंने राष्ट्र की सेवा करने से इन्कार कर दिया।

भूपति ने बुधवार को कहा कि वह अभी भी भारत की डेविस कप टीम के कप्तान हैं और पाकिस्तान के खिलाफ तटस्थ स्थान पर होने वाले डेविस कप मुकाबले के लिए उपलब्ध हैं। अखिल भारतीय टेनिस संघ (एआइटीए) ने भूपति की जगह रोहित राजपाल को गैर खिलाड़ी कप्तान चुना है। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ (आइटीएफ) ने डेविस कप मुकाबला इस्लामाबाद की जगह तटस्थ स्थान पर कराने का फैसला किया। भूपति ने कहा कि 12 ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने और देश के लिए 25 वर्षों तक खेलने के बावजूद किसी के द्वारा यह कहने के बाद मैं चुप नहीं रहूंगा कि मुझे इसलिए हटाया गया क्योंकि मैंने राष्ट्रीय की सेवा करने से इन्कार कर दिया। मुझे हटाए जाने से कोई दिक्कत नहीं है। वह इसे ऐसा कह सकते हैं कि अब नए कप्तान की जरूरत है, लेकिन यह कोई नहीं कह सकता कि मैंने राष्ट्र सेवा से इन्कार किया। मुझे सही में लगता था कि पाकिस्तान की यात्रा सुरक्षित नहीं है जिसकी बाद में आइटीएफ ने भी पुष्टि की। भूपति ने आगे कहा कि मुझे एआइटीए की ओर से नहीं बताया गया कि मैं अब कप्तान नहीं हूं। रोहित इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार थे, इसलिए उन्हें कप्तान बनाया गया।

हालांकि, एआइटीए के महासचिव हिरनमय चटर्जी ने कहा कि मैंने निजी तौर पर चार नवंबर को भूपति को यह बताने के लिए फोन किया था कि हमने नए कप्तान को चुन लिया है। भूपति ने आगे कहा कि मैं भारत में बड़े स्तर पर खेलों से जुड़ा रहा हूं। मैंने करमन कौर और सुमित (नागल) के लिए पैसे इक्कठे किए हैं। अगर एआइटीए मुझे नहीं रखना चाहता है तो मैं उनसे अपने संपर्क तोड़ सकता हूं।

मालूम हो कि भूपति और रोहन बोपन्ना समेत छह खिलाड़ियों ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर पाकिस्तान दौरे से नाम वापस ले लिया था। भूपति ने कहा कि एआइटीए ने उन्हें बताया कि पाकिस्तान जाने में असमर्थता जताने के कारण उन्हें गैर खिलाड़ी कप्तान पद से हटाकर राजपाल को नियुक्त किया गया है। एआइटीए के इस फैसले से दिग्गज टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना हैरान हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से इस फैसले के बारे में राय नहीं पूछे जाने पर नाराजगी जताई है। बोपन्ना ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं हैरान हूं कि आइटीएफ का अंतिम फैसला आने से पहले ही एआइटीए ने कप्तान बदलने का फैसला ले लिया। इस बारे में किसी खिलाड़ी से राय नहीं ली गई।

भारतीय कप्तान बोले हमें अपनी बल्लेबाजी में बदलाव करने की जरूरत नहीं नजर आती है

पिच पर निर्भर करेगा अंतिम एकादश: रोहित शर्मा

राजकोट डायरी

राजकोट, प्रेट्र : भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले दूसरे टी-20 मैच के लिए तेज गेंदबाजों के संयोजन में बदलाव का संकेत दिया है। उन्होंने बल्लेबाजी लाइन-अप का बचाव किया, जिसमें सीनियर सलामी बल्लेबाज शिखर धवन पिछले कुछ समय से जूझ रहे हैं।

रोहित ने कहा, 'हमारी बल्लेबाजी अच्छी दिखती है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी बल्लेबाजी में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। हम पिच का आकलन करेंगे और उसी के आधार पर हम देखेंगे कि बतौर टीम हम क्या कर सकते हैं। पिछले मैच में हम जिस तेज गेंदबाजी संयोजन के साथ खेले थे, वह दिल्ली की पिच के हिसाब से था। हम फिर पिच देखेंगे और सोचेंगे कि अपने गेंदबाजी लाइन-अप में क्या करने की जरूरत है।'

रोहित को उम्मीद है कि राजकोट की पिच कोटला से कहीं बेहतर होगी। उन्होंने कहा, 'पिच अच्छी दिखती है। राजकोट में हमेशा ही बल्लेबाजी के लिए अच्छी पिच रही है और इससे गेंदबाजों को भी थोड़ी मदद मिलती है। यह अच्छी पिच होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने जो दिल्ली में देखा, यह उससे बेहतर होगी। आपको यह जरूर बता सकता हूं कि हमारे तरीके में थोड़ा बदलाव होगा। पिछले मैच में हम पिच के अनुसार खेले थे। पिच जैसा बर्ताव कर रही थी, हम उसके हिसाब से खेल रहे थे, लेकिन अगर राजकोट की पिच अच्छी है तो हमारा तरीका भी गेंदबाजी और बल्लेबाजी विभाग में थोड़ा अलग होगा। बल्लेबाजों को अपना काम करने की जरूरत होगी और गेंदबाजों को अहम विकेट हासिल करने होंगे। इसी के हिसाब से खेलेंगे। हम किसी एक विभाग पर ध्यान नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हम बतौर टीम हारे थे, व्यक्तिगत रूप से नहीं। हम काफी विभाग में थोड़े कम रहे गए। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी गलतियों पर ध्यान लगाएं और सुनिश्चित करें कि यह गलतियां दोबारा नहीं दोहराई जाएं। यह अच्छी टीम का संकेत है।'

टी-20 सीरीज में जीत बांग्लादेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण : महमूदुल्लाह

राजकोट : बांग्लादेश के कप्तान महमूदुल्लाह ने बुधवार को कहा कि मेजबान भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज में जीत बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी, जो हाल में विषम परिस्थितियों से गुजरा है, जिसमें स्टार खिलाड़ी शाकिब अल हसन पर प्रतिबंध लगना भी शामिल है। महमूदुल्लाह ने कहा, 'अगर आप हाल के घटनाक्रम पर गौर करो, बांग्लादेश क्रिकेट में जो हुआ उसे देखते हुए सीरीज में जीत बांग्लादेश क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण है और इससे बांग्लादेश क्रिकेट टीम का मनोबल भी बढ़ेगा। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि भारत को हराने के लिए हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी क्योंकि हम जानते हैं कि उनकी टीम स्वदेश और विदेश में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, इसलिए हमें पहली गेंद से ही अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। निश्चित तौर पर यह शानदार मौका है, विशेषकर जबकि हमने सीरीज का पहला मैच जीता है, इसलिए यह बहुत अच्छा अवसर है और मुझे लगता है कि खिलाड़ी ऊर्जावान हैं और उम्मीद है कि हम दूसरे मैच में अच्छा खेल दिखाएंगे। हम सभी दूसरे मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर कोई कड़ी मेहनत कर रहा है।'

डे-नाइट टेस्ट में धौनी के कमेंट्री करने की संभावना नहीं

नई दिल्ली, जेएनएन : पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धौनी के करीबी सूत्रों के अनुसार, उनके बांग्लादेश और भारत के बीच डे-नाइट टेस्ट मैच में कमेंट्री में पदार्पण करने की संभावना नहीं है। भारत इसी महीने बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डेंस में अपना पहला डे-नाइट टेस्ट मैच खेलेगा। पहले कहा जा रहा था कि इस मैच में धौनी कमेंट्री करते हुए देखे जा सकते हैं। मैच के प्रसारणकर्ता स्टार स्पोर्ट्स ने बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली के सामने डे-नाइट टेस्ट मैच के लिए प्रस्ताव रखा था कि पूर्व कप्तानों को कमेंट्री का मौका दिया जाए, लेकिन बोर्ड ने अभी जवाब नहीं दिया है। धौनी जुलाई में विश्व कप सेमीफाइनल के बाद से भारत के लिए कोई मैच नहीं खेले हैं और बीसीसीआइ के अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची में शामिल हैं। इस खिलाड़ी के करीबी सूत्र से जब धौनी के इस मैच में कमेंट्री करने की संभावना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'धौनी कमेंट्री कर ही नहीं सकते। बीसीसीआइ के मौजूदा संविधान के अनुसार धौनी का कमेंट्री करना हितों का टकराव होगा।'

साइना हारीं, कश्यप व प्रणीत आगे बढ़े

फुजोउ (चीन), प्रेट्र : ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय शटलर साइना नेहवाल बुधवार को स्थानीय खिलाड़ी काई यान यान के हाथों पहले दौर में ही उलटफेर का शिकार होकर चाइना ओपन से बाहर हो गईं। वहीं पी कश्यप और बीसाई प्रणीत अपने-अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में पहुंच गए हैं।

काफी समय से फिटनेस की समस्याओं से जूझ रहीं विश्व की नौवें नंबर की खिलाड़ी साइना को महज 24 मिनट में 9-21, 12-21 से हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर, साइना के पति व कोच पी कश्यप ने थाइलैंड के सिथिकोम थैमसिन को मात देकर अगले दौर में जगह बनाई। इस भारतीय शटलर ने 43 मिनट में थाई प्रतिद्वंद्वी को 21-14, 21-3 से मात दी। अब अगले दौर में उनका सामना सातवीं वरीयता प्राप्त डेनमार्क के एक्सिलसन से होगा।

विश्व चैंपियनशिप के कांस्य विजेता बीसाई प्रणीत 52 मिनट तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में इंडोनेशिया के टॉमी सुगारितो को 15-21, 21-12, 21-10 से हराकर दूसरे दौर में पहुंच गए। विश्व के 11 नंबर के प्रणीत अब अगले मुकाबले में चौथी वरीयता प्राप्त डेनमार्क के एंडर्स एनटॉनसेन से भिड़ेंगे। वहीं समीर वर्मा शुरुआती दौर में हांगकांग के ली चुइक यू से 18-21, 18-21 से हार गए। मिक्स्ड डबल्स में प्रणव जेरी चोपड़ा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी भी चीनी ताइपे वांग ची लिन और चेंग ची या से 14-21,14-21 से हारकर बाहर हो गई।

गिल बोले, ड्रेसिंग रूम साझा करने से सीखने को मिला

मुंबई, प्रेट्र : युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने कहा कि कप्तान विराट कोहली सहित सीनियर खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने से उन्हें काफी कुछ सीखने में मदद मिली। गिल ने अभी तक दो वनडे खेले हैं जिनमें 16 रन बनाए हैं। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए रिजर्व सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम में रखा गया था। गिल को हालांकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में खेलने का मौका नहीं मिला।

रिषभ पंत अभी युवा खिलाड़ी है। वह अभी सीख रहा है और उसकी तुलना किसी से नहीं की जाए। उसे अपने खेल पर काम करने की जरूरत है।
– डीन जोन्स, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर

न्यूज गैलरी

महेश्वरी ने स्टीपलचेज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया

गुंटूर : तेलंगाना की जी महेश्वरी ने 35वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन बालिका अंडर-20 3000 मीटर स्टीपलचेज खिताब जीतकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। महेश्वरी ने 10 मिनट 34.10 सेकेंड का समय निकाला और वह टूर्नामेंट में पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से 12.71 सेकेंड आगे रहीं। महेश्वरी ने पहले के 10:53.91 के राष्ट्रीय जूनियर रिकॉर्ड को आसानी से पीछे छोड़ा जो नंदिनी गुप्ता ने 2017 में लखनऊ में बनाया था। नालुबोथु शानमुगा श्रीनिवास ने लड़कों के अंडर-18 की 200 मीटर दौड़ में कमाल दिखाते हुए मीट रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 21.34 सेकेंड से पिछले साल रांची में बनाए गए निसार अहमद के समय से 0.16 सेकेंड का बेहतर समय निकाला। बुधवार के दिन का एक अन्य मीट रिकॉर्ड उत्तराखंड की अंकिता ने बालिका अंडर-18 की 1500 मीटर दौड़ में बनाया। (प्रेट्र)

दीक्षा और रिद्धिमा को पहले दौर में बढ़त

नोएडा : दीक्षा डागर और रिद्धिमा दिलवारी ने बुधवार को यहां समान तीन अंडर 69 का स्कोर बनाया जिससे वह महिला प्रो गोल्फ टूर के 14वें चरण के पहले दौर में संयुक्त बढ़त पर हैं। नोएडा गोल्फ कोर्स में त्वेशा मलिक और गौरिका बिश्नोई ने समान 71 का कार्ड खेला और संयुक्त तीसरे स्थान पर हैं। अब जबकि चार खिलाड़ी सब पार के स्कोर पर हैं तो अंतिम दो दौर में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। अमनदीप द्राल ने 75 का कार्ड खेला और वह पांचवें स्थान पर हैं। नेहा त्रिपाठी, आस्था मदान और स्मृति मेहरा 77 के स्कोर के साथ संयुक्त छठे स्थान पर हैं। (प्रेट्र)

मुंबई के कमजोर डिफेंस की परीक्षा लेगा गोवा

मुंबई : मुंबई सिटी एफसी इंडियन सुपर लीग (आइएसएल) के छठे सत्र में गुरुवार को यहां एफसी गोवा के खिलाफ होने वाले मुकाबले में अपना डिफेंस मजबूत करने के इरादे के साथ मैदान पर उतरना चाहेगा। मुंबई सिटी ने पिछले सत्र में चार बार एफसी गोवा का सामना किया था, जिसमें से तीन बार गोवा ने जीत दर्ज की थी जबकि एक ही बार मुंबई को जीत मिली थी। गोवा ने उन चार मैचों में मुंबई के कमजोर डिफेंस का फायदा उठाकर 12 गोल दागे थे। मुंबई सिटी एफसी के मुख्य कोच जॉर्ज कोस्टा की टीम को लीग के इस सत्र में अपने पिछले घरेलू मुकाबले में ओडिशा एफसी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। (आइएएनएस)

चेल्सी ने अजाक्स को बराबरी पर रोका

यूएफा चैंपियंस लीग ▶ शुरुआत में तीन गोल से पिछड़ा था चेल्सी, मैच 4-4 से हुआ ड्रॉ

अजाक्स के दो खिलाड़ियों को दिखाया गया रेड कार्ड

पेरिस, एएफपी : यूएफा चैंपियंस लीग में मंगलवार को तीन गोल से पिछड़ने के बावजूद चेल्सी ने नौ खिलाड़ियों से खेल रहे अजाक्स को 4-4 की बराबरी पर रोक दिया, जहां उसके लिए जॉर्जिन्हो (चौथे और 71वें मिनट) ने पेनाल्टी किक पर दो गोल किए। इस नाटकीय मुकाबले में अजाक्स के दो खिलाड़ियों को बाहर किया गया, जबकि चेल्सी ने दो आत्मघाती गोल किए।

स्टैंफर्ड ब्रिज में ग्रुप-एच में खेले गए मुकाबले में डॉनी वान डि बिक (55वें मिनट) ने हकीम जेरिच के पास पर गोल करके दूसरे हाफ के 10वें मिनट में ही अजाक्स को 4-1 की बढ़त पर ला खड़ा किया, जिससे नीदरलैंड्स का यह शीर्ष क्लब एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इंग्लिश क्लब ने दूसरे हाफ में जबरदस्त वापसी की। मुकाबले की शुरुआत चेल्सी के लिए खराब रही और दूसरे ही मिनट में उसके स्टार खिलाड़ी टैमी अब्राहम आत्मघाती गोल कर बैठे।

इसके बाद अजाक्स के क्विंसी प्रोमेस (20वें मिनट) के गोल करने के बाद चेल्सी के केपा अरिजाबलागा (35वें मिनट) आत्मघाती गोल कर बैठे, जिससे हाफटाइम तक अजाक्स 3-1 से आगे हो गया। चौथा गोल खाने के बाद सीजर अजपिलिक्यूटा (63वें मिनट) ने गोल करके चेल्सी की वापसी कराई। इसके बाद मुकाबले में नाटकीय मोड़ आया। खेल के 68वें मिनट में इटली के रेफरी जियंलुका रोची ने पहले अजाक्स के डैले ब्लाइंड को रेड कार्ड दिखाकर बाहर भेजा और फिर जोएल वेल्टमैन को दूसरा येलो कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर किया। इससे अजाक्स की टीम नौ खिलाड़ियों तक सीमित हो गई। खेल के चौथे मिनट में पेनाल्टी किक पर गोल करने वाले जॉर्जिन्हो ने एक बार फिर पेनाल्टी किक पर गोल करके चेल्सी की उम्मीदों को बल दिया। इसके बाद युवा रीस जेम्स (74वें मिनट) ने गोल करके चेल्सी को बराबरी दिलाई। इसी बीच अजपिलिक्यूटा ने एक गोल दागा, लेकिन अब्राहम द्वारा हैंडबॉल किए जाने की वजह से उसे अयोग्य करार दिया।

गोल करने के बाद जश्न मनाते चेल्सी के रीस जेम्स। रायटर

अन्य नतीजे

जेनिट	0-2	आरबी लीप्जिग
ल्योन	3-1	बेनफिका
वेलेंसिया	4-1	लिली

बार्सिलोना का गोलरहित ड्रॉ : ग्रुप-एफ में स्पेनिश क्लब बार्सिलोना को स्वाविया प्राग के खिलाफ गोलरहित (0-0) बराबरी से संतोष करना पड़ा। कैंप नाउ में खेले गए इस मुकाबले में बार्सिलोना के स्टार स्ट्राइकर लियोन मेसी एक बेहतरीन गोल करने के मौके से चूक गए। इससे पहले बार्सिलोना पिछले सात वर्षों में कभी भी चैंपियंस लीग में अपने घरेलू मैदान पर गोल करने से वंचित नहीं रहा था। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में जर्मन क्लब बोरुसिया डोर्टमंड ने इंटर मिलान को 3-2 से हरा दिया, जहां विजेता टीम की ओर से अचरफ हकीमी ने दो गोल दागे। इस ग्रुप में बार्सिलोना आठ अंकों के साथ अभी भी शीर्ष पर है। हालांकि टीम को लियोन मेसी ने निराश किया जो कई बार गोल करने के मौके को भुना नहीं पाए और विपक्षी टीम के डिफेंस में सेंध नहीं लगा सके।

लिवरपूल की मुश्किल जीत : एनफील्ड में ग्रुप-ई में खेले गए मुकाबले में गत चैंपियन लिवरपूल ने रेसिंग गेंक को 2-1 से हरा दिया। लिवरपूल को जॉर्जिनियो विज्नाल्डम ने शुरुआती बढ़त दिलाई, लेकिन एमबवाना समाता ने गोल करके स्कोर को हाफ टाइम से पहले बराबरी पर ला दिया। इसके बाद ओक्जाडे चैंबर्लिन ने लिवरपूल के लिए निर्णायक गोल दागा। इसी ग्रुप के अन्य मुकाबले में नापोली और सल्जबर्ग के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ, जिससे लिवरपूल तालिका में नौ अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गया।

भारतीय निशानेबाजों ने आठ और पदक जीते

दोहा, प्रेट्र : भारतीय निशानेबाजों ने बुधवार को यहां एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के दूसरे दिन आठ पदक हासिल किए, लेकिन टोक्यो ओलंपिक के लिए दांव पर लगे कम से कम तीन कोटे से चूक गए। इस तरह भारत की पदकों की संख्या 13 हो गई है क्योंकि निशानेबाजों ने मंगलवार को पांच पदक अपने नाम किए थे। भारत के चार स्वर्ण, तीन रजत और छह कांस्य पदक हैं। केनान चेनाई पुरुष ट्रैप क्वालीफिकेशन में 122 अंक से दूसरे स्थान पर रहे थे लेकिन छह पुरुषों के फाइनल में छठे स्थान पर रहे। वह फाइनल में पहले 25 शॉट में केवल 13 पर सफल निशाना लगा पाए।

कुवैत, चीनी ताइपे और कतर ने तीन कोटे स्थान हासिल किए। केनान, मानवजीत सिंह संधू और पृथ्वीराज की भारतीय पुरुष ट्रैप टीम ने कुल 357 अंक के स्कोर से रजत पदक प्राप्त किया जिससे टीम कुवैत से छह अंक से पीछे रही जिसने स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में अनीश भानवाला क्वलीफिकेशन में 574 के स्कोर से 11वें स्थान पर रहे। इससे उनकी इस स्पर्धा में उपलब्ध टोक्यो ओलंपिक 2020 के चार में से एक कोटा हासिल करने की उम्मीद भी टूट गई। वह थाइलैंड के प्रतिस्पर्धी से ओलंपिक कोटा चूके जो 10वें स्थान पर रहकर दांव पर लगे चौथे कोटे को हासिल करने में सफल रहे। स्पर्धा के अन्य कोटे जापान, कोरिया और पाकिस्तान के नाम रहे। चीन के विश्व चैंपियन लिन जुनमिन ने स्पर्धा का स्वर्ण जीता जबकि चीन ने सभी व्यक्तिगत पदक हासिल किए। अनीश, भावेश, आदर्श सिंह की तिकड़ी ने 1716 अंक के संयुक्त स्कोर से टीम कांस्य पदक जीता।

कोलकाता टेस्ट में सोने के सिक्के से होगा टॉस

खेल संवाददाता, कोलकाता

कोलकाता के ईडन गार्डेंस में होने वाले भारत के पहले डे-नाइट टेस्ट मैच का टॉस सोने के सिक्के से होगा, जबकि चांदी के सिक्के प्रतीक चिन्ह के रूप में मेहमानों को भेंट किए जाएंगे।

भारत और बांग्लादेश के बीच कोलकाता में 22 नवंबर से डे-नाइट टेस्ट खेला जाएगा। इस मैच को देखने के लिए तमाम हस्तियों के साथ-साथ मेहमान टीम की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी पहुंचेंगी। बीसीसीआइ के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने हसीना को न्योता भेजा था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) ने उनके शानदार स्वागत की तैयारी शुरू कर दी। उनके भोजन के लिए 50 पकवान के नाम तय कर लिए गए हैं।

इंदौर टेस्ट के 40 फीसद से ज्यादा टिकट बिके

इंदौर, प्रेट्र : भारत और बांग्लादेश के बीच यहां होलकर स्टेडियम में 14 नवंबर से शुरू होने वाले टेस्ट मैच को लेकर दर्शकों में अच्छा रुझान देखा जा रहा है। इस मुकाबले के 40 फीसद से ज्यादा टिकट महज चार दिन में बिक गए हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) के अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर ने बुधवार को बताया कि भारत-बांग्लादेश टेस्ट मैच के अब तक करीब 7000 टिकट बिक चुके हैं। शेष 9000 टिकट भी जल्द बिकने की उम्मीद है। हम प्रतिदिन टिकट बेचने पर भी विचार कर रहे हैं।

बचपन के कोच से अलग होने का फैसला सही था : मनिका

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत की स्टार महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने बचपन के कोच संदीप गुप्ता से अलग होने के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि पुणे को अभ्यास केंद्र बनाने से उन्हें काफी फायदा मिला।

बत्रा को बखूबी पता है कि द्रोणाचार्य अवॉर्डी गुप्ता से अलग होने के उनके फैसले को लेकर लोग काफी बातें करेंगे, लेकिन उसका मानना है कि उसके खेल को सुधारने के लिए यह जरूरी फैसला था। गुप्ता के मार्गदर्शन में खेल रही बत्रा के रिश्ते उनसे इतने खराब हो गए कि अब आपस में बातचीत भी नहीं है। वह पिछले महीने आइटीटीएफ रैंकिंग में 18 पायदान चढ़कर 61वें स्थान पर पहुंच गईं। मनिका ने कहा, 'अब मैं अपने खेल को लेकर आत्मविश्वास से ओतप्रोत हूं। मुझे गर्व महसूस हो रहा है। पुणे में माहौल काफी पॉजीटिव है और मेरे अभ्यास के साझेदार भी मेरे साथ काफी मेहनत कर रहे हैं।'

वेस्टइंडीज ने अफगानिस्तान को दी शिकस्त

विकास मिश्र, लखनऊ

वेस्टइंडीज ने बुधवार को यहां अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम की दूधिया रोशनी में अफगानिस्तान को सात विकेट से करारी शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की महत्वपूर्ण बना ली। अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 45.2 ओवर में 194 रनों पर आउट हो गई। जवाब में वेस्टइंडीज ने खराब शुरुआत के बावजूद शाई होप (नाबाद 77) और रोस्टन चेस (94) की बेहतरीन पारियों की बदौलत 46.3 ओवर में सिर्फ तीन विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

छोटे लक्ष्य के सामने वेस्टइंडीज ने 25 रन तक दो विकेट गंवा दिए। इसके बाद होप और चेस ने कैरेबियाई टीम को मुश्किल दौर से बाहर निकालते हुए आसान जीत दिलाई। होप ने 133 गेंदों पर पांच चौके जड़े। चेस ने 115 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौके लगाए। इससे पहले वेस्टइंडीज के कप्तान कीरोन पोलार्ड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अफगानिस्तान के लिए रहमत शाह 61 और इकराम अलीखिल ने 58 रनों का महत्वपूर्ण योगदान देकर टीम को 150 के पार पहुंचाया। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 111 रन जोड़े।

शॉट खेलते इकराम अलीखिल। एएफपी

विविध

इंटरनेट स्वतंत्रता के मामले में दस सबसे खराब देशों में पाक

इंटरनेट वॉचडॉग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इंटरनेट और डिजिटल मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में पाकिस्तान दुनिया के सबसे खराब 10 देशों में शामिल है। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट अधिकार समूह, फ्रीडम हाउस ने मंगलवार को द क्राइसिस ऑफ सोशल मीडिया शीर्षक से अपनी फ्रीडम ऑन द नेट रिपोर्ट 2019 के लिए जारी की है, जिसमें जून 2018 के बीच वैश्विक इंटरनेट स्वतंत्रता में समग्र गिरावट दर्ज की है। रिपोर्ट में भारत को कुल मिलाकर 55 अंक दिए गए और देश में इंटरनेट स्वतंत्रता की स्थिति को आंशिक रूप से मुक्त बताया गया।

पिछले साल की तुलना में एक पायदान नीचे

डॉन न्यूज ने रिपोर्ट के हवाले से खबर दी कि संस्था ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान को 100 सबसे बुरे देशों (इंटरनेट स्वतंत्रता की नजर से) में 26वें स्थान पर रखा है। पिछले साल की रैंकिंग की तुलना में पाकिस्तान एक स्थान और नीचे खिसका है। देश ने इंटरनेट तक पहुंच में बाधा के मामले में 25 में से पांच अंक, कंटेंट सीमित किए जाने के मामले में 35 में से 14 और उपयोगकर्ता अधिकार सूचकांक के उल्लंघन के मामले में 40 में से मात्र सात अंक प्राप्त किए हैं।

सिर्फ 16 देशों ने दिखाया सुधार

रिपोर्ट ने 65 देशों का आकलन किया और उनमें से 33 ने जून 2018 के बाद से इंटरनेट स्वतंत्रता में समग्र गिरावट दिखाई। केवल 16 देशों ने इंटरनेट स्वतंत्रता की स्थिति में सुधार दिखाया।

सबसे फिसड्डी देश

इंटरनेट स्वतंत्रता के मामले में सबसे बड़ी गिरावट दिखाने वाले कुछ देशों में सूडान, कजाखिस्तान, ब्राजील, बांग्लादेश और जिंबाब्वे शामिल हैं।

दक्षिण-एशियाई देशों की इंटरनेट स्वतंत्रता की स्थिति

देश	अंक	इंटरनेट स्वतंत्रता की स्थिति
भारत	55	आंशिक मुक्त
बांग्लादेश	44	आंशिक मुक्त
म्यांमार	36	मुक्त नहीं
श्रीलंका	49	मुक्त नहीं
पाकिस्तान	26	मुक्त नहीं

आइसलैंड रहा सबसे आगे

आइसलैंड इंटरनेट स्वतंत्रता के मामले में अव्वल रहा। आइसलैंड ने 95 अंक हासिल कर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया।

इथियोपिया ने दिखाया सुधार

2019 में अपने इंटरनेट स्वतंत्रता स्कोर में सबसे बड़ा सुधार दर्ज करने वाले देश में इथियोपिया शामिल रहा।

अमेरिका में दिखी गिरावट

रिपोर्ट के मुताबिक, लगातार तीसरे साल भी अमेरिका में इंटरनेट स्वतंत्रता में गिरावट देखी गई। अमेरिका का कुल स्कोर 77 रहा।

नवरुणा अपहरण कांड सुलझाने को 10 लाख का इनाम घोषित

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर

- सीबीआइ ने मुजफ्फरपुर में पोस्टर चस्पाकर आम लोगों से मांगी मदद
- 18 सितंबर 2012 को हुआ था अपहरण, 26 नवंबर को मिली थी लाश
- 21 को खत्म हो रही है जांच के लिए दी गई सुप्रीम कोर्ट की अवधि

बिहार में चर्चित मुजफ्फरपुर के नवरुणा अपहरणकांड व घर के सामने लाश मिलने की जांच कर रही सीबीआइ की ओर से मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए दस लाख रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। बुधवार को शहर में इस बाबत पोस्टर चस्पा किए गए। इनमें बताया गया है कि नवरुणा (12) का अपहरण 18/19 सितंबर 2012 को जवाहरलाल रोड स्थित उसके पैतृक आवास से कर लिया गया। 26 नवंबर 2012 को घर के सामने लाश मिली। यदि कोई भी व्यक्ति नवरुणा के अपहरण व हत्या की गुत्थी सुलझाने में सीबीआइ को मदद करेगा तो उसे दस लाख का इनाम दिया जाएगा।

पिता ने ब्यूरोक्रेट्स पर साधा निशाना : पोस्टर चस्पा किए जाने की सूचना मिलने के साथ नवरुणा के पिता अतुल्य चक्रवर्ती ने कहा कि मेरी बेटी का केस भी बिहार के चर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड की तरह चलने लगा। सीबीआइ जांच कम करती है, समय ज्यादा लेती है। इस केस को प्रभावित करने में पुलिस के कई बड़े अधिकारी लगे हैं। पीएमओ के भी एक अधिकारी इसमें शामिल हैं। ऐसे में क्या उम्मीद करें। यहां तो एजेंसी हमारा नार्को टेस्ट कराने के लिए दबाव बनाती रही और आरोपित बचते रहे। 20 सितंबर 2019 को पूछताछ के लिए सीबीआइ ने बुलाया था। बीमारी की वजह से मैं जा नहीं पाया। उसरे बाद सीबीआइ की ओर से कोई पहल नहीं की गई।

सुप्रीम कोर्ट में चल रहा मामला : नवरुणा का अपहरण उसके आवास से 18 सितंबर 2012 को कर लिया गया था। प्राथमिकी दर्ज हुई थी। 26 नवंबर को उसकी घर के सामने लाश मिली थी। मामला गंभीर होने के बाद फरवरी 2014 में सीबीआइ ने इस मामले की जांच शुरू की।

मुजफ्फरपुर में नवरुणा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए लगाया गया इनाम की घोषणा वाला पोस्टर। जागरण

फरवरी 2014 से मामले की जांच चल रही है। अब तक सौ से ज्यादा लोगों की गवाही हो चुकी है। इनाम से संबंधित पोस्टर चस्पा किए गए हैं ताकि जांच को पूरा किया जा सके। कुछ और सूचनाएं सामने आएं।
– अजय कुमार, डीएसपी, सीबीआइ, पटना

इस बीच इस पूरे प्रकरण की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सीबीआइ ने कोर्ट से कई बार जांच के लिए वक्त मांगा। इस बीच कोर्ट में चल रहे अवमानना वाद में कोर्ट ने सीबीआइ को तीन महीने का वक्त जांच पूरी करने के लिए दिया। 21 नवंबर 2019 को यह अवधि पूरी हो रही है।

उत्तराखंड में अधिकारी को सस्ती बिजली पर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नैनीताल

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तराखंड ऊर्जा निगम के अधिकारी-कर्मचारियों के सस्ती बिजली देने व आम आदमी के लिए बिजली की दरें बढ़ाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वतः संज्ञान लेकर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए ऊर्जा निगम को विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। हाई कोर्ट में बुधवार को जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

याचिका में कहा गया है कि ऊर्जा निगमों के अधिकारियों से एक माह का बिजली बिल मात्र चार-पांच सौ व कर्मचारियों का मात्र सौ रुपये लिया जा रहा है। जबकि इनका बिल लाखों में आता है। इसका बोझ सीधे जनता पर पड़ रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ऊर्जा निगमों के तमाम अधिकारियों के आवासों में मीटर तक नहीं लगे हैं। यदि लगे भी हैं तो खराब स्थिति में हैं। उदाहरणार्थ जीएम का 25 माह का बिल चार लाख 20 हजार आया था, उसके बिजली के मीटर की रीडिंग 2005 से 2016 तक नहीं ली गई थी। वहीं कारपोरेशन ने वर्तमान कर्मचारियों के अलावा रिटायर कर्मचारियों व उनके आश्रितों को मुफ्त बिजली दी है। जिसका सीधा भार जनता की जेब पर पड़ रहा है। याचिकाकर्ता के अनुसार उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश घोषित है, लेकिन यहां हिमाचल प्रदेश से महंगी बिजली है। जबकि हिमाचल में बिजली उत्पादन कम होता है।

सब्सिडी देकर शराब फैक्ट्रियां खोलने पर उत्तराखंड सरकार को नोटिस

जासं, नैनीताल : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भारी भरकम सब्सिडी देकर पहाड़ में शराब फैक्ट्रियां खोलने को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की। इसमें राज्य सरकार, आबकारी विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत समस्त शराब कंपनियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पक्षकारों को शपथपत्र के माध्यम से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट में बुधवार को देहरादून निवासी नंदकिशोर की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि पर्वतीय इलाकों में शराब की फैक्ट्री लगाने पर सरकार द्वारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, राज्य कर, स्टांप ड्यूटी, बिजली खर्च में छूट के साथ 75 फीसद आबकारी देयकों में रियायत दी जा रही है। जबकि कंपनियां अपने फायदे को मिलाने के बाद 520 रुपये प्रति पेटी की दर से शराब थोक में बाजार में उतार रही हैं। वहीं शराब कंपनियों को 400 से 900 रुपये तक की बोतल बाजार में बेचने पर 2500 से 4200 रुपये तक सब्सिडी प्रति पेटी दी जा रही है। एक साल में यदि कंपनियां दस लाख पेटी उत्पादन करती हैं तो दो सौ करोड़ सब्सिडी सरकार को देनी होगी।

अब हरिद्वार और ऋषिकेश कुंभ क्षेत्र में गंगा में नहीं होगा खनन

राज्य ब्यूरो, देहरादून

- हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र को छोड़ गंगा व उसकी सहायक नदियों में खनन की कवायद में जुटा वन विकास निगम

उत्तराखंड में हरिद्वार और ऋषिकेश में कुंभ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गंगा और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में खनन नहीं होगा। जिला खनन न्यास समिति की इस संस्तुति को देखते हुए उत्तराखंड वन विकास निगम अब कुंभ क्षेत्र को छोड़ गंगा व उसकी सहायक नदियों में उपखनिज चुगान के लिए कवायद में जुट गया है। इसके अलावा प्री-मानसून व पोस्ट मानसून में नदियों के तल में आरबीएम (रिवर बेस्ड मटीरियल) का अध्ययन भी कराया जा रहा है। निगम के प्रबंध निदेशक मोनिष मलिक के मुताबिक नियमानुसार ही उपखनिज का चुगान किया जाएगा। राज्य की विभिन्न नदियों में उपखनिज चुगान का जिम्मा उत्तराखंड वन विकास निगम के पास है। कुमाऊं की गौला व नंधौर और गढ़वाल की मालन नदी में निगम इस साल खनन शुरू कर चुका है, लेकिन हरिद्वार में गंगा व उसकी सहायक नदियों में खनन को लेकर असमंजस था। हरिद्वार में गंगा में खनन को लेकर उठ रहे विरोध के सुरों को देखते हुए अब इसमें कुंभ क्षेत्र को खनन से मुक्त रखने का निश्चय किया गया है।

कोलकाता विज्ञान महोत्सव में बना खगोल भौतिकी की सबसे बड़ी कक्षा का रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- पहले दिन 45 मिनट की क्लास में स्पेक्ट्रोस्कोपी सभा के दौरान उपस्थित रहे 1598 से अधिक छात्र

कोलकाता के साइंस सिटी में पांचवां इंडिया इंटरनेशनल सांइस फेस्टिवल 2019 का आगाज मंगलवार को हुआ। इस महोत्सव ने पहले ही दिन बुधवारको कई रिकॉर्ड बनाए। यहां खगोल भौतिकी की ट्रेनिंग में एक साथ 1,598 छात्रों की भागीदारी और स्पेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया गया। यहां पर सबसे बड़ी कक्षा आयोजित होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया।

बुधवार को खगोल भौतिकी पर यहां 45 मिनट का सबसे लंबा पाठ चला। साथ ही इस दौरान स्पेक्ट्रोस्कोप की सभा में एक स्थान पर कुल 1598 से अधिक छात्रों ने शामिल हो कर नया रिकार्ड बनाया। बता दें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल-2019 की इस साल की थीम है राइजेन (इंडिया-रीसर्चस, इनोवेशन एंड साइंस इंपावरिंग द नेशन)।

खगोलशास्त्री स्पेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल पृथ्वी से लाखों प्रकाशवर्ष दूर स्थित पदार्थों के तापमान, रासायनिक गठन इत्यादि जानने के लिए करते हैं। अब स्पेक्ट्रोस्कोप को कोई भी एक छोटे से कार्डबोर्ड के बॉक्स की सहायता से बना सकता है। इसमें एक छोटा छिद्र किया जाता है, जिसके माध्यम से रोशनी इसमें प्रविष्ट करती है। इसके अंदर एक कांपेक्ट डिस्क की सहायता से उक्त रोशनी को डिफरेक्शन प्रक्रिया के माध्यम से विभक्त किया जाता है। इस प्रयास को मशहूर वैज्ञानिक मेघनाथ साहा और सीवी रमन को समर्पित किया गया है। बता दें आइआइएसएफ-2019 का मेजबान कोलकाता दुनिया के कई प्रसिद्ध वैज्ञानिक संस्थानों का घर है, जहां दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक कार्यरत हैं।

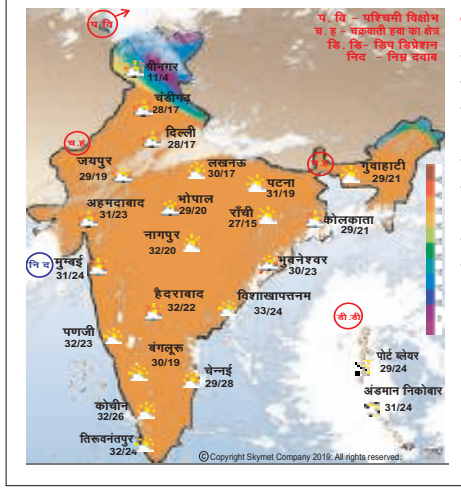

मौसम विशेष

राजस्थान, हरियाणा व पंजाब में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा होगी। दिल्ली व आस-पास के क्षेत्रों में गरज के साथ वर्षा होगी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू-कश्मीर में अनेक स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ मध्यम वर्षा तथा पर्वतीय स्थानों पर बर्फबारी होने की संभावना है।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	31/23	आंबा अहमदाबाद	32/22
कोलकाता	27/22	आंबा बड़ौदा	32/23
चेन्नई	32/24	आंबा नागपुर	32/21
हैदराबाद	32/23	आंबा इन्दौर	28/20
बंगलूरू	30/19	आंबा रांची	29/15
त्रिवेन्द्रम	33/25	आंबा पटना	30/16
भुवाहाटी	29/22	आंबा जमशेदपुर	30/18
गंगटोक	11/02	ग पुणे	30/20

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 7 नवंबर 2019
आजकल
16
www.jagran.com

दुनिया का सबसे पुराना अखबार लंदन गजट प्रकाशित हुआ

1665 में आज ही लंदन गजट पहली बार प्रकाशित हुआ था। उस समय इस अखबार को द ऑक्सफोर्ड गजट कहा जाता था। अंग्रेजी भाषा में छपने वाला यह अखबार आज भी हर रोज प्रकाशित होता है। यह ब्रिटेन में सबसे पुराना लगातार प्रकाशित होने वाला अखबार है।

The London Gazette.

रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई

1917 में आज ही लेनिन की बोल्शेविक पार्टी की अगुवाई में रूस के मजदूर वर्ग और मेहनतकश लोगों ने जार के शासन का तख्तापलट करने के लिए बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत की थी। इस क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है।

सर सीवी रमन ने किया था रमन प्रभाव का आविष्कार

भारत के महान भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 1888 में आज ही तमिलनाडु में हुआ था। उन्हें 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भौतिक विज्ञान में उनके इस आविष्कार को रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। वह नोबेल पुरस्कार जीतने को लेकर इतने आश्वस्त थे कि घोषणा से चार महीने पहले ही उन्होंने स्वीडन का टिकट बुक करा लिया था। 1954 में उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से भी पुरस्कृत किया। 21 नवंबर, 1970 को उनका निधन हो गया।

इधर-उधर की

दक्षिण कोरिया में जिंदा लोगों का अंतिम संस्कार

सियोल, एजेंसी : दक्षिण कोरिया में लोग जिंदगी को बेहतर ढंग से समझने के लिए मौत का अहसास कर रहे हैं। पिछले सात साल में करीब 25,000 लोग जीवित रहते हुए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। दरअसल, ह्योवोन हीलिंग नामक कंपनी ने 2012 में लिविंग फ्यूनरल नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम के तहत लोग करीब 10 मिनट तक एक बंद ताबूत में कफन ओढ़कर लेट जाते हैं। इस दौरान वे सभी रस्में पूरी की जाती हैं, जो किसी व्यक्ति की असल मौत के वक्त होती हैं। कंपनी का दावा है कि लोग स्वेच्छा से उनके पास आते हैं और जीवन खत्म होने से पहले मौत का एहसास करके वे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं।

लोगों की मनोदशा बता सकते हैं उनके ट्वीट्स

अध्ययन
- यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिलवेनिया के शोधकर्ताओं ने किया शोध
- कहा-सोशल मीडिया के पोस्ट पढ़कर हो सकती अकेलेपन से जूझ रहे लोगों की पहचान

वाशिंगटन, प्रेट्र : अकेले रहने से डिप्रेशन, हृदय संबंधी रोग, डिमेंशिया और कई अन्य तरह की बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं। इससे बचने का एक उपाय यह हो सकता है कि हम हर संभव लोगों के बीच रहें, ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाएं और उनसे खूब बातें करें। पर हर बार ऐसा संभव नहीं हो पाता। अकेले रहने वाला व्यक्ति अपने में ही मशगूल रहता है, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों की जल्दी पहचान भी नहीं हो पाती। अब एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने अकेलेपन का शिकार हुए की पहचान का एक नया तरीका खोजा है।

शोधकर्ताओं का दावा है कि लोगों की सोशल मीडिया की पोस्ट को पढ़कर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन-सा यूजर अकेलापन महसूस कर रहा है या अकेला है। लोगों के ट्वीट्स का अध्ययन कर शोधकर्ताओं ने कहा कि ऐसे लोगों को सहारा देने से उनका जीवन सुगम बनाया जा सकता है और कई गंभीर बीमारियों के चपेट में आने से लोग बच सकते हैं।

इस अध्ययन में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिलवेनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने उन विषयों को रेखांकित किया है, जिनका संबंध अकेलेपन से होता है। शोधकर्ताओं ने कहा,' ट्विटर यूजर की वॉल में पोस्ट की गई सामग्री के विषय को पढ़ने के बाद यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यूजर की मनोदशा क्या है।' पोस्ट की गई सामग्री की भाषा के विश्लेषण के आधार पर शोधकर्ताओं ने पाया कि एकाकीपन की प्रवृत्ति उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है, जो अपने रिश्तों, मानसिक परेशानियों और अनिद्रा जैसे विषयों पर ज्यादा पोस्ट करते हैं।

बीएमजे ओपन नामक जर्नल में प्रकाशित निष्कर्षों से उन यूजरों की पहचान आसान हो सकती है, जो अकेले हैं, चाहे वे अकेलापन महसूस करने के बारे में स्पष्ट रूप से ट्वीट न करते हों। ऐसे यूजरों को अकेलेपन से उबरने में मदद की जा सकती है।

पेंसिलवेनिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और इस अध्ययन के प्रमुख लेखक शरद चंद्र गुंटुकु ने कहा, 'अकेलेपन से जुड़ी समस्याओं को प्रकट होने में दशकों लग जाते हैं। इसलिए इसे जानलेवा कहा जा सकता है क्योंकि यह धीरे-धीरे व्यक्ति को अपनी जद में लेता है।' उन्होंने कहा कि यदि हम अकेले रहने वाले लोगों की पहचान करने में सक्षम हो जाएं तो इस समस्या को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। उनकी मानसिक स्थिति के बारे में अनुमान लगाकर उन्हें गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से बचाया जा सकता है। गुंटुकु ने कहा, 'किसी भी यूजर के ट्वीट्स का अध्ययन कर हमें लोगों की मदद करने का मौका मिल सकता है और यह तरीका सबसे ज्यादा प्रभावी भी है।'

फिल्म रिव्यू

सस्पेंस की डोज में रोमांच कम

बाइपास रोड

मुख्य कलाकार : नील नितिन मुकेश, अदा शर्मा, गुल पनाग, शमा सिकंदर, रजित कपूर, सुधांशु पांडे, मनीष चौधरी
निर्देशक : नमन नितिन मुकेश
अवधि : दो घंटे 17 मिनट

प्रख्यात गायक नितिन मुकेश के बेटे नील नितिन मुकेश ने 'बाइपास रोड' से फिल्म निर्माण में कदम रखा है। फिल्म का स्क्रीनप्ले, कहानी और डायलॉग भी उन्होंने लिखे हैं। फिल्म का निर्देशन दस साल छोटे उनके भाई नमन नितिन मुकेश ने किया है। बतौर निर्देशक यह उनकी पहली फिल्म है। वह थ्रिलर जॉनर के महारथी अब्बास मस्तान को असिस्ट कर चुके हैं। उनका प्रभाव फिल्म में दिखता है। कहानी का आरंभ शीशे को तोड़ते हुए एक आदमी के स्वीमिंग पुल में गिरने से होता है। कहानी फिर दो महीने पीछे जाती है। अपना फैशन लेबल चलाने वाले विक्रम कपूर का बाइपास रोड पर एक्सीडेंट होता है। उसी रात नामी गिरामी मॉडल सारा का भी मर्डर होता है। सारा विक्रम की कंपनी के लिए मॉडलिंग करती थी। हादसे में विक्रम की जान बच जाती है, लेकिन वह अपने पांवों पर चलने में सक्षम नहीं होता। पुलिस विक्रम के साथ सारा की हत्या के तारों को जोड़ते हुए तफ्तीश करती है। व्हील चेयर पर चलने को मजबूर विक्रम पर हमले की कोशिश होती है। वह अपने ही ऑफिस में काम करने वाली राधिका से प्यार करता है। शक की सुई को कई किरदारों की ओर घुमाया जाता है। सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों का रहस्य गूढ़ होना आवश्यक होता है। किरदारों में कई परतें होती हैं। उसकी तह में जाने को लेकर कौतूहल, रोमांच और उत्सुकता को बनाए रखना बहुत अहम होता है। यहां लेखकों ने किरदारों को गढ़ने में समय नहीं गंवाया है। हालांकि शतरंज के खेल की तरह ही यहां पर मोहरों (किरदारों) की चाल रोमांचित करने की बजाय बीच-बीच में बोझिल लगने लगती है। नमन नितिन मुकेश ने होम प्रोडक्शन की फिल्म होने के कारण भाई को काफी स्पेस दिया है। बाकी किरदारों के निर्वहन में लेखक, निर्देशक थोड़ा चूक गए हैं। कहानी के स्तर पर कई कमियां हैं।

मसलन विक्रम के सौतेली मां से नफरत के कारणों को कहानी नहीं छूती। सौतेली मां के अफेयर की भी पड़ताल नहीं करती। इंटरवल के बाद कहानी में थोड़ा कसाव आता है। संगीत की मदद से डर पैदा करने की कोशिश यहां भी हुई है। विक्रम की भूमिका में नील नितिन मुकेश विकलांग होकर भी फाइटिंग के दृश्यों में प्रभावित करते हैं। राधिका की भूमिका में अदा शर्मा खास प्रभावित नहीं करतीं। रोमांटिक दृश्यों में दोनों के बीच केमिस्ट्री का अभाव झलकता है। लेखक-निर्देशक सुधांशु पांडे और गुल पनाग के चरित्र के निर्वाह में चूक गए हैं। चुस्त एडीटिंग की मदद से फिल्म की अवधि को कम किया जा सकता था। हिंदी की अशुद्धियां अखरती हैं।

स्मिता श्रीवास्तव

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

दुर्गम स्थानों पर मदद पहुंचाएगा 'रोबो-बी'

आविष्कार ▸ हार्वर्ड माइक्रोरोबोटिक लैबोरेट्री के वैज्ञानिकों ने तैयार किया रोबोट

आर्टिफिशियल एक्ट्यूएटर की मदद से भरता है उड़ान

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबोट विकसित करने में कामयाबी हासिल की है, जो मधुमक्खी की तरह उड़ान भरने में सक्षम है और दीवारों से टकराने के बाद भी आसानी से अपना रास्ता बदल कर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह रोबोट दुर्गम स्थानों पर आसानी से पहुंचने के साथ-साथ वहां फंसे हुए लोगों को बचाने में बचाव दल के लिए मददगार भी साबित हो सकता है। रोबो-बी नामक इस रोबोट के पास उड़ान भरने और लचीलेपन के लिए कोमल आर्टिफिशियल मांसपेशियां (एक्ट्यूएटर) हैं। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये एक्ट्यूएटर्स 'रोबो-बी' को मधुमक्खी तरह मंडराने में मदद करते हैं।

इसे विकसित करने वाले अमेरिका के हार्वर्ड माइक्रोरोबोटिक लैबोरेट्री के शोधकर्ताओं ने अध्ययन कर दावा है कि पहली बार ऐसा रोबोटिक उपकरण तैयार किया गया है जो आसानी से दुर्गम स्थानों में जा सकेगा और एक निश्चित समय में अपने काम को पूरा कर सकता है। हार्वर्ड माइक्रोरोबोटिक लैबोरेट्री के जॉन ए पॉलसन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस (एसईएएस) के शोधकर्ताओं ने कहा, 'सॉफ्ट रोबोटिक्स को बनाना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता जितना इन्हें नियंत्रित करना होता है। ये उपकरण यदि एक निश्चित माप से ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो इनकी गतिविधियों को कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। ऐसी स्थिति में कई बार पूरा सिस्टम दोबारा तैयार करना पड़ जाता है।'

एसईएएस के पोस्टडॉक्टोरल फैलो और इस अध्ययन के मुख्य लेखक यूफेंग चेन ने कहा, 'मोबाइल रोबोट्स तैयार करने के लिए माइक्रोरोबोटिक्स के क्षेत्र में अब बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त होने वाले सॉफ्ट एक्ट्यूएटर्स काफी लचीले होते हैं और ये शोधकर्ताओं की आधी चुनौती कम कर देते हैं।' उन्होंने कहा कि हालांकि कई लोग मानते हैं कि इसका उपयोग फ्लाइंग रोबोट्स के तौर पर तो किया जा सकता है पर इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। नए एक्ट्यूएटर्स में ऐसी क्षमता है कि किसी भी सूरत में रोबोट को नियंत्रित किया जा सकता है। इसे तैयार करने के लिए शोधकर्ताओं ने ऐसी नरम सामग्री का प्रयोग किया है, जो मजबूत तो है ही, साथ ही इसमें करंट का प्रवाह भी होता भी है। बिजली के संपर्क में आते ही ये एक्ट्यूएटर्स गतिविधि करना शुरू कर देते हैं। इसकी एक खासियत यह भी है कि किसी भी सतह से टकराने पर ये टूटते नहीं हैं। शोधकर्ताओं ने कहा, कि सॉफ्ट रोबोटिक्स के क्षेत्र में 'रोबो-बी' भविष्य में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी मदद से रोबोटिक आर्मी की अवधारणा को भी साकार किया जा सकता है। ये रोबोट इतने छोटे हैं कि आसानी से दुश्मन को नजर नहीं आ सकते। इनकी मदद से देश की सीमा पर हो रही गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। लेकिन इससे पहले इन पर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की मदद से और काम करने की जरूरत है।

इस अध्ययन के मुख्य लेखक यूफेंग ने कहा , 'रोबो-बी को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने स्टील की छड़ों की मदद से एक आयताकार सांचा तैयार किया और उसके चारों कोनों पर हल्की मोटरों को एक्ट्यूएटर से जोड़ दिया। '

अमेरिका की हार्वर्ड माइक्रोरोबोटिक लैबोरेट्री के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किया गया 'रोबो बी'। फाइल

निगरानी करने में है सक्षम

शोधकर्ताओं ने कहा, 'रोबो-बी दुर्गम स्थानों पर भी आवश्यक सामग्री पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। साथ ही ऐसे स्थानों में फंसे हुए लोगों को बचाने में बचाव दल के लिए मददगार भी साबित हो सकते हैं। इसके अलावा इनका प्रयोग निगरानी के लिए भी किया जा सकता है।

शोध अनुसंधान

नियमित व्यायाम से कम होता है अवसाद का खतरा

व्यायाम से शरीर ही नहीं मानसिक सेहत में भी सुधार होता है। हालिया शोध के मुताबिक, व्यायाम से अवसाद का खतरा कम हो जाता है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं ने बताया कि हफ्ते में कम से कम चार घंटे व्यायाम करने वालों में अवसाद के लक्षण उभरने के मामलों में 17 फीसद तक की कमी आ सकती है। अध्ययन को विज्ञान पत्रिका डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी में प्रकाशित किया गया है। इसके लिए करीब 8,000 लोगों से जुड़े डाटा का अध्ययन किया गया। इन लोगों ने व्यायाम व अन्य गतिविधियों से जुड़ी अपनी लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी दी थी। अगले दो साल तक इन सभी की शारीरिक गतिविधियों और इनमें अवसाद के लक्षणों पर नजर रखी गई। वैज्ञानिकों ने पाया कि शारीरिक रूप से ज्यादा सक्रिय रहने वालों में अवसाद के मामले कम देखने को मिले। - प्रेट्र

सामान्य वजन के पीछे छिपी हो सकती है गंभीर बीमारी

हालिया शोध के मुताबिक, पूरी तरह फिट व्यक्ति भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। आमतौर पर आदर्श वजन की तुलना में 85 फीसद या उससे कम वजन वाले लोगों में एनोरेक्सिया नर्वोसा की आशंका रहती है। यह बीमारी कम खाने-पीने, ज्यादा व्यायाम करने और वजन बढ़ने के डर से जुड़ी है। गंभीर स्थिति में यह जानलेवा भी हो सकती है। 2013 में इससे जुड़ा अलग मामला सामने आया जिसे एटिपिकल एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा गया। इससे ग्रसित मरीज का वजन सामान्य जैसा ही रहता है, लेकिन उसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा के अन्य सभी लक्षण रहते हैं। ऐसे लोगों में उनके शरीर के वजन से नहीं बल्कि वजन में अचानक गिरावट जैसे लक्षणों से बीमारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। मोटापे के बढ़ते मामलों के कारण बच्चों को अक्सर वजन कम करने की सीख दी जाती है। ऐसे में उनके एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रसित होने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए समय रहते इसके लक्षणों को समझना जरूरी है। - एएनआइ

चीन ने प्रक्षेपित किया नेविगेशन उपग्रह

बीजिंग, आइएएनएस : नेविगेशन के क्षेत्र में चीन ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए लांग मार्च नंबर 3बी रॉकेट से अपना 49वां पेइतो नेविगेशन उपग्रह प्रक्षेपित किया। चीन ने इससे वर्ष 2020 तक विश्व व्यापी पेइतो उपग्रह नेविगेशन नेटवर्क की स्थापना की नींव डाल दी है। यह उपग्रह पृथ्वी की जिस कक्षा में स्थापित किया गया है, वहां किसी दूसरे देशों की नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है। चीनी अधिकारियों का कहना है कि इस उपग्रह की स्थापना से देश के मौसम का पूर्वानुमान और बेहतर तरीके से लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही इस प्रक्षेपण के साथ नेविगेशन नेटवर्क की स्थापना का काम और तेज कर दिया गया है।

म्यांमार का प्रकाश महोत्सव

म्यांमार के उत्तरपूर्वी शान प्रांत के तांगुगी में लाइटिंग फेस्टिवल पर आतिशबाजी की चिंगारियों के बीच जश्न मनाते लोग। इस उत्सव पर लोग घरों में पटाखे और आतिशबाजी तैयार करते हैं। उन्हें चमकीले रंगे के गुब्बारे में भरकर उड़ा दिया जाता है। आतिशबाजी में आग लगने के बाद चिंगारियां आसमान से नीचे गिरती हैं तो एक अद्भुत नजारा दिखाई देता है। एएफपी

ब्रिटेन में फूंका जाता है बुराई का पुतला

ब्रिटेन में वार्षिक बोनफायर नाइट फेस्टिवल सबसे लोकप्रिय आयोजन है। इसे गॉइ फॉक्स उत्सव भी कहा जाता है। त्योहार को सेलीब्रेट करने के लिए लुईस शहर में नाइट परेड निकाली गई। इसमें देश-दुनिया की सबसे विवादास्पद सामाजिक अथवा राजनीतिक हस्ती का पुतला दहन करने की भी परंपरा है। इसकी शुरुआत 16 वी शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हुई थी। यह उत्सव कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट के बीच संघर्ष की याद दिलाता है। रायटर

स्क्रीन शॉट

मुन्ना और सर्किट की जोड़ी फिर दिखेगी एक साथ

'मुन्नाभाई एमबीबीएस' और वर्ष 2006 में रिलीज हुई फिल्म 'लगे रहो मुन्नाभाई' के बाद इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म को लेकर कई खबरें आती रही हैं। दोनों ही फिल्मों में मुन्ना और सर्किट की जोड़ी को पसंद किया गया था। यह किरदार निभाने वाले संजय दत्त और अरशद वारसी की जोड़ी एक बार फिर साथ वापसी करेगी। अरशद वारसी का कहना है कि संजू और वह एक फिल्म साथ में करने वाले हैं, जिसकी शूटिंग अगले साल मार्च या अप्रैल से शुरू हो जाएगी। लेकिन वह फिल्म मुन्नाभाई का सीक्वल नहीं होगी। मुन्नाभाई फिल्म के सीक्वल को लेकर अरशद ने बताया कि राजकुमार हिरानी से जब भी वह और संजू पूछते हैं, तो वह फिल्म बनाने को लेकर कभी मना नहीं करते। वह हमेशा यही कहते हैं कि सौ प्रतिशत फिल्म बनेगी। अरशद ने बताया कि राजकुमार हिरानी ने दो-तीन स्क्रिप्ट लिख रखी है। उनमें से कौन सी बनेगी, पता नहीं। वह फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। वह काफी व्यस्त भी हैं।

जिस फिल्म में संजय और अरशद की जोड़ी साथ आ रही है, वह साजिद-फरहाद का प्रोजेक्ट होगा। अरशद का कहना है कि वह पहले शेड्यूल के लिए बुडापेस्ट जाएंगे। मजेदार स्क्रिप्ट होगी, जिसमें संजय दत्त एक अंधे डॉन का किरदार निभाएंगे, जबकि उनकी आंखें बनेंगे अरशद। अरशद का कहना है कि फिल्म मजेदार इसलिए होगी, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है कि वह अंधे हैं और न मैं किसी को बता सकता हूं।

अगले वर्ष क्रिसमस पर रिलीज होगी 'लाल सिंह चड्ढा'

आमिर खान इन दिनों अपनी फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' की शूटिंग में व्यस्त हैं। यह फिल्म वर्ष 1994 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म 'फॉरेस्ट गंप' की हिंदी रीमेक है। बुधवार को आमिर ने सोशल मीडिया पर फिल्म का म्यूजिकल मोशन पोस्टर साझा किया। आमिर ने लिखा, 'क्या पता हम में है कहानी या कहानी में हम हैं...'। यह फिल्म अगले वर्ष क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। खबर है कि 'लाल सिंह चड्ढा' में आमिर खान, सलमान खान और शाह रुख खान पहली बार एक साथ स्क्रीन पर नजर आ सकते हैं, हालांकि इसकी अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है।

अपनी फिल्मों के सीक्वल में न होने को मिस करते हैं अक्षय कुमार

इन दिनों फिल्मों का सीक्वल बनना आम बात हो गई है। अब तक अक्षय कुमार की कई फिल्मों की सीक्वल बन चुकी हैं, जिनमें 'वेलकम बैक', 'नमस्ते इंग्लैंड' जैसी फिल्में शामिल हैं। कुछ महीने पहले ही अक्षय कुमार अभिनीत सुपरहिट फिल्म 'भूल भुलैया' का सीक्वल 'भूल भुलैया 2' बनाने की घोषणा की गई थी। इस फिल्म में अक्षय की जगह कार्तिक आर्यन मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। अक्षय खुद के इन सीक्वल फिल्मों में न होने को मिस करते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि 'भूल भुलैया 2' में मुझे काम नहीं मिला। अगर उस फिल्म में मुझे काम मिला होता तो मैं क्यों नहीं करता। बकौल अक्षय, 'मैं वेलकम, नमस्ते लंदन और भूल भुलैया के सीक्वल का हिस्सा न बन पाने पर उन्हें मिस करता हूं।'

शूटिंग का लुत्फ

प्रियंका का कैश वाला डेजर्ट!

प्रियंका चोपड़ा इन दिनों दिल्ली में अपनी आगामी फिल्म 'द व्हाइट टाइगर' की शूटिंग कर रही हैं। शूटिंग के साथ वह दिल्ली की चाट का लुत्फ भी उठा रही हैं। उन्होंने दो बेहद मजेदार तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। इन तस्वीरों में प्रियंका के सामने टेबल पर एक डेजर्ट रखा है, जिसके किनारों पर पांच सौ रुपयों के 6 नोट लगे हुए हैं। हालांकि ये नोट नकली हैं। इस तस्वीर को साझा करते हुए प्रियंका ने लिखा है, 'मेरे डेजर्ट में कैश है।' फिल्म में उनके को-स्टार राजकुमार राव ने यह तस्वीर खींची है, जिसका जिक्र प्रियंका ने अपनी पोस्ट में भी किया है।

भूल सुधार : कल के मनरंजन में कंगना-अश्विनी अय्यर की खबर में गलती से बायोग्राफी छप गया था, जबकि इसे बायोपिक होना चाहिए था। इस गलती के लिए हमें खेद है।

अध्ययन

शोधकर्ताओं का दावा है कि पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को पा लेने के बाद भी स्थिति में निकट भविष्य में सुधार होने की संभावना नहीं..

2300 तक 20 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा समुद्र का स्तर

बर्लिन, प्रेट्र : जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए किए गए ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को यदि पा लिया जाए और वैश्विक तापमान स्थिर हो जाए तो भी समुद्र का स्तर बढ़ता रहेगा। एक नए अध्ययन में यह दावा किया गया है।

191 देशों के बीच 2015 में हुआ पेरिस जलवायु समझौता इसके अगले वर्ष से प्रभावी हो गया था। इसके तहत वैश्विक तापमान को औद्योगिक क्रांति से पूर्व के स्तर से दो डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है और संभव हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए प्रयास किया जाना है। संयुक्त राष्ट्र के विज्ञान परामर्श निकाय 'इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज' (आइपीसीसी) के मुताबिक, इन लक्ष्यों को पाने के लिए कार्बन उत्सर्जन में 2050 तक 40 से 70 फीसद तक की कटौती जरूरी है।

जर्मनी के पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक टीम ने अध्ययन के दौरान पाया कि समझौते के शुरुआती 15 साल की अवधि के दौरान होने उत्सर्जन से समुद्र का स्तर 2300 तक लगभग 20 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने अनुमानों में शायद अंटार्कटिका की बर्फ की चादरों के पिघलने के प्रभावों को नहीं जोड़ा गया।

शोधकर्ताओं ने कहा, 'पेरिस समझौते की अवधि के दौरान कार्बन उत्सर्जन से वर्ष 2300 तक समुद्र के स्तर में 20 सेंटीमीटर की वृद्धि हो सकती है। यह आंकड़ा समुद्र के जल स्तर में होने वाली कुल वृद्धि (एक मीटर) का 20 फीसद है। उन्होंने कहा कि एक मीटर की वृद्धि के लिए वर्ष 1750 तक हुआ उत्सर्जन जिम्मेदार है।'

प्रतीकात्मक

पांच शीर्ष देश हैं जिम्मेदार

पीएनएएस नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया है कि 20 सेंटीमीटर के समुद्र स्तर में वृद्धि का लगभग आधा श्रेय दुनिया के शीर्ष पांच प्रदूषण फैलाने वाले देश (अमेरिका, चीन, भारत, रूस और यूरोपीय संघ) को दिया जा सकता है। अमेरिका की ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के जलवायु वैज्ञानिक और सह-लेखक पीटर क्लार्क ने कहा, 'भले ही हम पेरिस समझौते के इन प्रारंभिक लक्ष्यों को पूरा कर लें, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी होगी ही।' उन्होंने कहा कि हम वायुमंडल में जितनी ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करेंगे उसका उतना ही प्रभाव हमें दीर्घकाल में समुद्र के स्तर में वृद्धि के तौर पर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए यदि आप फ्रिज से आइस क्यूब निकाल कर कहीं और रख देते हैं तो आपने गौर किया हो कि वह तुरंत नहीं पिघलती है। उसे थोड़ा समय लगता है। ठीक उसी प्रकार गर्मी बढ़ने पर ग्लेशियर भी धीरे-धीरे पिघलकर समुद्र का जल स्तर बढ़ाते हैं।